रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 1980/भाद्र 29, 1902
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 1980/BHADRA 29, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1980

का० आ० 2423.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 92-पुथुप्पाली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मैथ्यु पी० जे०, पल्लीक्कुन्नेल, लक्काट्टूर डाक०, (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मैथ्यु पी० जे० को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि०स०/92/80(27)]

आदेश से,

धर्मवीर, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1980

S.O. 2423.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mathew P. J., Pallikkunnel, Lakkattoor P. O., (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 92-Puthuppally Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mathew P. J. to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/92/80(27)]

By order,

DHARAM VIR, Under Secy.
to the Election Commission of India

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1980

का० आ० 2424.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग में काम कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा के परामर्श से, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) पांचवां संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"51क. किसी व्यक्ति को उपदान प्राप्त करने से विवर्जन

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवा काल में सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में, नियम 51 के निबन्धनों के अनुसार उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र है, सरकारी सेवक की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है तो उपदान में उसके अंश को प्राप्त करने का उसका दावा उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, संबद्ध व्यक्ति :—

(क) सरकारी सेवक की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह उपदान का अपना अंश पाने से विवर्जित कर दिया जाएगा जो कुटुम्ब के किसी अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हैं, संदेय होगा,

(ख) सरकारी सेवक की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उपदान का उसका अंश उसे संदेय हो जाएगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध नियम 51 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट असंवितरित उपदान को भी लागू होंगे।

3. उक्त नियम के नियम 54 के उपनियम (11ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(11-ग)—(क) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में, इस नियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन पाने के लिए पात्र है, सरकारी सेवक की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति दावा, जिसके अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र अन्य सदस्य या सदस्यों के दावे भी हैं, उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा ।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, संबद्ध व्यक्ति :—

(i) सरकारी सेवक की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता [redacted] कुटुम्ब पेंशन पाने से विवर्जित कर [redacted] सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से [redacted] के अन्य पात्र सदस्य को संदेय होगी,

(ii) सरकारी सेवक की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब पेंशन उसे संदेय होगी ।

(ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपबंध किसी सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति के पश्चात् संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन को भी लागू होंगे ।"

[सं० 1(5)-ई०वी०(बी०)/पेन्शन(ए)/78]

हजारा सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 25th August, 1980

S.O. 2424.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Fifth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules), after rule 51, the following rule shall be inserted, namely :—

"51A Debarring a person from receiving gratuity.

(1) If a person, who in the event of death of a Government servant while in service is eligible to receive gratuity in terms of rule 51, is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence, his claim to receive his share of gratuity shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-rule (1), the person concerned—

(a) is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, he shall be debarred from receiving his share of gratuity which shall be payable to other eligible members of the family, if any,

(b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the Government servant, his share of gratuity shall be payable to him.

(3) The provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2) shall also apply to the undisbursed gratuity referred to in sub-rule (2) of rule 51."

3. In rule 54 of the said rules, after sub-rule (11B), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(11C) (a) If a person, who in the event of death of a Government servant while in service, is eligible to receive family pension under this rule, is charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, in [redacted] other eligible member or members of th[redacted]mily to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned—

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, such a person shall be debarred from receiving the family

pension which shall be payable to other eligible member of the family, from the date of death of the Government servant,

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the Government servant, the family pension, shall be payable to such a person from the date of death of the Government servant.

(c) The provision of clause (a) and clause (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of a Government servant after his retirement."

[No. 1(5)-EV(B)/Pen.(A)/78]

HAZARA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1980

का० आ० 2425.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के कालम 2 में निर्दिष्ट कलकत्ता स्थित न्यायालय में, उक्त तालिका के कालम 3 में उल्लिखित विशेष पुलिस स्थापना के मामले के सम्बन्ध में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर की गई अपीलों का संचालन करने के लिए श्री दुर्गापद दत्त, अधिवक्ता, कलकत्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना मामला संख्या
1	2	3
1	सत्र न्यायाधीश, जिला 24 परगना अलीपुर, कलकत्ता	श्री ए० के० दत्ता, आई० ए० एस० तथा अन्यों के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 24/75-कलकत्ता आपराधिक अपील संख्या 39/80, 40/80 तथा 41/80)

[सख्या 225/44/80-ए०वी०डी० (II)]

New Delhi the 27th August, 1980

S. O. 2425.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri Durgapada Dutta, Advocate Calcutta, as a Special Public Prosecutor for conducting the appeals filed by the accused persons in the Court at Calcutta specified in column 2 of the Table below in relation to Special Police Establishment case shown in column 3 thereof :

TABLE

Serial No.	Name of the Court	SPE case No.
(1)	Sessions Judge, District 24-Parganas Alipore, Calcutta..	RC 24/75-Calcutta against Shri S.K. Datta, IAS & Others. (Cr. Appeals No. 39/80, 40/80 and 41/80)

[No. 225/44/80-AVD.II]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1980

का० आ० 2426.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम 2 में निर्दिष्ट विशाखापटनम स्थित न्यायालय में तालिका के कालम 3 में निर्दिष्ट दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के मामलों के सम्बन्ध में राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करने के लिए श्री डी० सत्यनारायण, अधिवक्ता, हैदराबाद को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	विशेष पुलिस स्थापना मामला सं०
1	2	3
1.	विशेष पुलिस स्थापना के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, विशाखापटनम	श्री एस० सुब्बाराव के विरुद्ध नियमित मामला संख्या 11/69-हैदराबाद

[सख्या 225/47/80-ए०वी०डी० (II)]

टी० के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1980

S.O. 2426.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri D. Satyanarayana, Advocate, Hyderabad as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution on behalf of the State in the Court at Visakhapatnam as specified in column (2) of the Table below in relation to the Delhi Special Police Establishment cases shown in column (3) thereof :—

TABLE

S.No.	Name of the Court	SPE Case No.
(1)	(2)	(3)
1.	Court of Special Judge for SPE cases, Visakhapatnam.	RC No. 11/69-HYD against Shri S. Subba Rao.

[No. 225/47/80-AVD.II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1980

आय-कर

का० आ० 2427—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् —

(i) यह कि मद्रास प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा ।

(ii) यह कि उक्त संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

(iii) यह कि उक्त संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी और लेखाओं का विवरण प्रत्येक वर्ष आय-कर आयुक्त, मद्रास को भेजेगा ।

संस्था

सड़क परिवहन संस्थान, मद्रास

यह अधिसूचना 9-4-1979 से 8-4-1982 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[संख्या 3414 (फा० सं० 203/102/79-आई० टी० ए० (II)]
हरि नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th May, 1980

(INCOME TAX)

S.O. 2427.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions:—

(i) That the Institute of Road Transport, Madras, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences (other than agriculture/Animal husbandry/fisheries and medicines).

(ii) That the said institution will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

(iii) that the said institute will submit the annual return and statement of accounts to the Commissioner of Income-tax, Madras, every year.

INSTITUTION

THE INSTITUTE OF ROAD TRANSPORT, MADRAS

This notification is effective for a period of 3 years from 9th April, 1979 to 8th April, 1982.

[No. 3414/F. No. 203/102/79-ITA.II]
HARI NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1980

आय-कर

का० आ० 2428.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हज़रत पीरमोहम्मद शाह दरगाह शरीफ़ ट्रस्ट, अहमदाबाद,.....
.....
को निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[संख्या 3594 (फा० सं० 197/142/79-आ०क०(ए1)]
बी० एम० सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 1980

(INCOME-TAX)

S.O. 2428.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Hajrat Pirmohmed Shah Durgah Sharif Trust Ahmedabad, for the purpose of the said section for the assessment years 1973-74 to 1980-81.

[No. 3594/F. No. 197/142/79-IT(AI)]
B. M. SINGH, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1980

का० आ० 2429.—केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक और प्रायोजक बैंक के परामर्श से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के बोर्ड के, अधिवेशनों से सम्बन्धित नियमों का संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) संशोधन नियम 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे ।

2. नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के बोर्ड के अधिवेशनों से सम्बन्धित नियम उनके सामने सारणी के स्तम्भ (3) में की गई प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किए जायेंगे ।

सारणी

क्रम सं०	प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के बोर्ड से सम्बन्धित नियमों के संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3
1.	प्रथमा बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में :— (1) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (2) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;

(1)	(2)	(3)
1. प्रथमा बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976—(जारी)		(III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
2 गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों में :— (I) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
3. हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों मे :— (I) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
4. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों में :— (I) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की

(1)	(2)	(3)
4. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976—(जारी)		होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
5. गौड ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों में :— (I) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(ग) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नही किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
6. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमो में :— (I) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नही किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी," (II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
7. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों में :— (I) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नही किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक

(1)	(2)	(3)
		सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	यथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
9 तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	यथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
10. पुरी ग्राम्य बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	यथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो

(1)	(2)	(3)
		प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
11. जम्मू रूरल बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में :—	(1) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
12 चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन), नियम, 1976	कथित नियमों में :—	(i) नियम 6 में —
		(क) उप-नियम (1) के (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है," शब्द रखे जाएंगे ।
13. बाराबंकी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में:—	(i) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"

(1)	(2)	(3)
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
14. गुड़गांव ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या
15 रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976		कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।

(1)	(2)	(3)
16.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर 'और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
17.	मल्लाभूम ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
18.	बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जायेंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन-निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर

(1)	(2)	(3)
		"और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
19. नागार्जुन ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1976	कथित नियमों में:—	
	(i) नियम 6 में :—	
		(क) उप नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
20. प्रारज्योतिष गांवलिया बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:—	
	(i) नियम 6 में :—	
		(क) उप नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
21. लायलासीमा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:—	
	(i) नियम 6 में :—	
		(क) उप नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"

(1)	(2)	(3)
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उपनियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
22. मालप्रभा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :—	(i) नियम 6 में :—
		(क) उपनियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उपनियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
23. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :—	(i) नियम 6 में :—
		(क) उपनियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उपनियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
24. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:—	(i) नियम 6 में :—
		(क) उपनियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित

(1)	(2)	(3)
		निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
25. मारवाड़ ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:—
		(i) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
26. भगीरथ ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:—
		(i) नियम 6 में:—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेश ों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर

(1)	(2)	(3)
		"और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
27. श्रीविशाखा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:—	
	(i) नियम 6 में:—	
	(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—	
	"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"	
	(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—	
	"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"	
	(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;	
	(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।	
28. कावेरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:—	
	(i) नियम 6 में:—	
	(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—	
	"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"	
	(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—	
	"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"	
	(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;	
	(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।	
29. शेखावटी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:—	
	(i) नियम 6 में:—	
	(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—	
	"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।"	
	(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—	
	"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"	
	(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;	
	(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।	

(1)	(2)	(3)
29.	शेखावटी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
30.	सतलज ग्राम्य बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर" और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
31.	बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी; (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
32.	मगध ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में — (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों

(1)	(2)	(3)
32. मगध ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977—जारी		की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
33 कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेन्ट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
34. साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी।" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड

(1)	(2)	(3)
		के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
35. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
36. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों के बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार
37. लिपुरा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार

(1)	(2)	(3)
		की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे । (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनु-मोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
38. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :— (1) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधि-वेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनु-मोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
39. हिमाचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधि-वेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनु-मोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
40. बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे	

(1)	(2)	(3)
		में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्.— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनु-मोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
41. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधि-वेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनु-मोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
42. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(ii) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (2) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनु-मोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गण-पूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।

(1)	(2)	(3)
43.	पांड्यान ग्राम बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:— (1) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो होगी"। शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
44.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:— (1) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो" होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे।
45.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977	कथित नियमों में:— (1) नियम 6 में:— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदे श के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा

(1)	(2)	(3)
		अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
46. बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ; (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
4. संथाल परगना ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में — (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ; (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
48. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1977		कथित नियमों में:— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे मे अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;"

(1)	(2)	(3)
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
49. कृष्णा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979	कथित नियमों में:—	(i) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(ब) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
50. कूच ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979	कथित नियमों में:—	(i) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(ब) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है" ।
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
51. जामनगर ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1980	कथित नियमों में:—	(i) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(ब) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित

(1)	(2)	(3)
		निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
		"(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;"
		(ii) नियम 8 में बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
52. मलधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979		कथित नियमों में :—
		(I) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;"
		(II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
		(III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
53. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979		कथित नियमों में :—
		(I) नियम 6 में—
		(क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।"
		(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
		"(2) यदि बोर्ड का अजेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;'
		(II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
		(III) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।

(1)	(2)	(3)
54	सारस्वत ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979	कथित नियमों में :— (1) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;" (II) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (III) नियम 10 के उप नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
55.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979	कथित नियमों में :— (1) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ; (iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उतने निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।
56.	शारदा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1979	कथित नियमों में :— (i) नियम 6 में— (क) उप-नियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— "(घ) उस कारबार के सिवाए जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।" (ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(2) यदि बोर्ड का अर्जेंट अधिवेशन बुलाना आवश्यक है तो प्रत्येक निदेशक को कम से कम एक सप्ताह की सूचना दी जाएगी ;" (ii) नियम 8 में "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार की होगी" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के

(1)	(2)	(3)
		एक तिहाई या चार की इनमें से जो अधिक हो, होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
		(iii) नियम 10 के उप-नियम (2) में "और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो" शब्दों के स्थान पर "और उनमें निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है जितने बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० एफ० 14-2/77-आर०आर०बी०]
बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 30th August, 1980

S.O. 2429.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the Sponsor Bank concerned, hereby makes the following rules to amend the rules relating to meetings of the Board of Regional Rural Banks, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gramin Banks (Meetings of Board) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The rules relating to meetings of the Board of Regional Rural Banks specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Short titles of the rules relating to the Boards of Regional Rural Banks	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Prathama Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted' (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constituted a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
2.	Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(1) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
3.	Haryana Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules, – (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by he majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
4.	Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors of four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
5.	Gaur Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a mjority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 4, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constituted a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
6.	Bhojpur Rohtas Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the Total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
7.	Samyut Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher' shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
8.	Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be subsitutued, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board' 'shall be substituted.
9.	Tungabhadra Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
		"(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
10. Puri Gramya Bank (Meetings of Board Rules) 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;
11. Jammu Rural Bank (Meetings of Board Rules) 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8 , for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
12. Champaran Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;

(1)	(2)	(3)
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director".; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words " and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
13. Barabanki Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely: – "(d) No business, other than that for which the meeting was convened shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be sub-stituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors" the, words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
14. Gurgaon Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words " and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
15. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than

(1)	(2)	(3)
		seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
16.	Farrukhabad Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
17.	Mallabhum Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10 in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
18.	Bolangir Anchalik Gramya Bank (Meetings of Board Rules) 1976.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.";

(1)	(2)	(3)
		(ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words, "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
19. Nagarajuna Grameena Bank (Meetings of Board Rules), 1976.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
20. Pragjyotish Gaonlia Bank (Meetings of Board Rules), 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such busines has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of director's as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
21. Rayalaseema Grameena Bank (Meetings of Board Rules), 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following, sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;

(1)	(2)	(3)
		(iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
22.	Malaprabha Grameena Bank (Meetings of Board Rules), 1977.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule the following clause shall be substituted, namely: - "(d) No business, other than that for which the meting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: - "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four, the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
23.	Mayurakshi Gramin Bank (Meetings of Board Rules), 1977.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— (d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman"; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted' namely:— (2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board , a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (i) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
24.	Marathwada Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1) , the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director," (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
		that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the followng sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority ofd irectors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
26. Bhagirath Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,—	(i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;
27. Sri Visakha Grameena Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,—	(i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "/(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8 for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
28. Cauvery Grameena Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,—	(i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1) the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
29. Shekhawati Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rules (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
30. Cuttack Gramya Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
31. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
		"(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule(2), for the words "and approved by the majority of directors ", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
32. Magadh Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
33. Koraput Panchabati Gramya Bank, (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule, (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A" quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such numebr of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
34. South Malabar Gramin Bank (Meetings of Board Rule) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the

(1)	(2)	(3)
		Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majorty of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
35. North Malabar Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
36. Rewa Sidhi Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rules 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— " No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A Quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Baord" shall be substituted
37. Tripura Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a noice of not less than

(1)	(2)	(3)
		seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
38. Kosi Khsetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following, sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8 for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of diredtors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
39. Himachal Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, na mely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman"; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
40. Ballia Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules, (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1) the following clause shall be substituted namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director"; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the

(1)	(2)	(3)
		total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
41. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— (d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one weeks' notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— (2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director"; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2) for the words "and approved by the majority of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
42. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6 — (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in wirting to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2 for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
43. Pandyan Grama Bank (Meetings of Board Rules) 1977		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one weeks' notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2) for the words "and approved by the majority of directors" the words and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
44.	Vaishali Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, oher than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one weeks' notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
45.	Monghyr Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
46.	Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
47.	Santhal Parganas Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.	In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was

(1)	(2)	(3)
		convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number o directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2) for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board shall be substituted.
48. Hardoi Unnao Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1977.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substitued, namely :— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;
49. Krishna Grameena Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		(iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted. In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman;." (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors of four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
50. Kutch Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors

(1)	(2)	(3)
		present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.;"
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
		"(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.";
		(ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;
		(iii) in rule 10, in sub-rule 2 for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the board" shall be substituted.
51. Jamnagar Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		In the said rules,—
		(i) in rule 6—
		(a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:—
		"(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.";"
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
		"(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.";"
		(ii) in rule 8 for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four" the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;
		(iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words " and approved by the majority of directors" the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
52. Marudhar Kashetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		In the said rules,
		(i) in rule 6—
		(a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—
		"(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.";"
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
		"(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.";"
		(ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted;
		(iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
53. Madhubani Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		In the said rules,—
		(i) in rule 6—
		(a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—
		"(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.";"

(1)	(2)	(3)
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director".; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
54. Nalanda Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2) for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
55. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board Rules) 1979.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman."; (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely : — "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.
56. Sharda Gramin Bank (Meeting of Board Rules) 1979.		In the said rules,— (i) in rule 6— (a) for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:— "(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the direcotrs present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.";

(1)	(2)	(3)
		(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:— "(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director."; (ii) in rule 8, for the words "A quorum for a meeting of the Board shall be four", the words "A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher" shall be substituted; (iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words "and approved by the majority of directors", the words "and approved by such number of directors as are necessary to constitute a quorum for a meeting of the Board" shall be substituted.

[No. F. 14-2/77-R.R.B.]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1980

का०आ० 2430.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार धुप्पड़ को फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 5-9-1980 से प्रारम्भ होकर 4-9-1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री अशोक कुमार धुप्पड़ अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-4/80-आर०आर०बी०]

New Delhi, the 4th September, 1980

S.O. 2430.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar Dhupar as the Chairman of the Faizabad Kshetriya Gramin Bank, Faizabad and specifies the period commencing on the 5th September, 1980 and ending with the 4th September, 1983 as the period for which the said Shri A. K. Dhuppar shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-4/80-RRB]

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

का० आ० 2431.— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० के० सक्सेना को फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 6-9-1980 से प्रारम्भ होकर 5-9-1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस० के० सक्सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-7/80-आर०आर०बी०]
इन्द्राणी सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2431.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Saxena as the Chairman of the Fatehpur Kshetriya Gramin Bank, Fatehpur and specifies the period commencing on the 6th September, 1980 and ending with the 5th September, 1983 as the period for which the said Shri S. K. Saxena shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-7/80-RRB]
INDARANI SEN, Under Secy.

कार्यालय, आयकर आयुक्त केन्द्रीय-1

नई दिल्ली, 2 जून, 1980

विषय :—क्षेत्राधिकार—नई दिल्ली में दो नए केन्द्रीय मंडलों का सृजन।

का० आ० 2432.— आयकर अधिनियम 1961 (1961 की 43) की धारा 124 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त (केन्द्रीय एक), नई दिल्ली निर्देश देते हैं कि नई दिल्ली में अधिकारी केन्द्रीय मंडल के नाम से निम्नलिखित दो नए मंडल बनाए जाएंगे :—

1. आयकर अधिकारी, केन्द्रीय मंडल 25 नई दिल्ली।

2 आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 26, नई दिल्ली।

उपर्युक्त केन्द्रीय मंडल के आयकर अधिकारी, आयकर आयुक्त अथवा बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 127 की उपधारा (1) के अधीन सौंपे गए मामलों के संबंध में अपने कार्य का निष्पादन करेंगे।

यह आदेश दिनांक 5-6-80 से प्रभावी होगा।

[फा० नं० एस० आई०/सी० आई० टी० (केन्द्रीय)/सी०/80-81/980]

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX (CENTRAL-I)

New Delhi, the 2nd June, 1980

Sub :—Jurisdiction—Creation of two new Central Circles at New Delhi.

S.O. 2432.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Income-tax Delhi (Central-I) New Delhi hereby directs that two new Central Circles known as Income-tax Officers Central Circles as indicated below shall be created at New Delhi.

1. Income-tax Officer, Central Circle-XXV, New Delhi.
2. Income-tax Officer, Central Circle-XXVI, New Delhi.

The Income-tax Officers of Central Circles cited above shall perform their functions in respect of such cases as are assigned to them by the Commissioner of Income-tax or the Board, as the case may be, under sub-section (1) of Section 127 of the Income-tax Act, 1961.

This order shall come into force with effect from 5th June, 1980.

[F. No. SI/JUR(1)/C/80-81/980]

विषय :—क्षेत्राधिकार :—आयकर अधिकारी, केन्द्रीय मंडल दो एवं मेरठ के प्रभारों का समापन।

का० आ० 2433.— आयकर अधिनियम 1961 (1961 की 43) की धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर आयुक्त दिल्ली (केन्द्रीय-एक), निदेश देते हैं आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल दो एवं तीन के प्रभार जो पहले बनाए गए थे, समाप्त कर दिए गए माने जाएं।

यह आदेश दिनांक 5-6-80 से प्रभावी होगा।

[फ० नं० एस० आई०/ज्यरि० (1)/सी/80-81/983]

Sub :—Jurisdiction—Abolition of Charges of the Income-tax Officers Central Circles II to IV. Meerut.

S.O. 2433.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Income-tax, Delhi (Central-I) New Delhi hereby directs that the charges of the Income-tax Officers Central Circles II and III Meerut created earlier stand abolished.

This order shall come into force with effect from 5th June, 1980.

[F. No. SI/Jur(1)/C/80-81/983]

विषय :—क्षेत्राधिकार—निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के दो नए रेंजों का सृजन

का० आ० 2434.—आयकर अधिनियम 1961 की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त (1961 की 43) शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयकर आयुक्त दिल्ली (केन्द्रीय) नई दिल्ली का निदेश है कि निरीक्षीय सहायक आयुक्त (केन्द्रिय) रेंज–6ए नई दिल्ली के नाम से दिल्ली में एक नया रेंज बनाया जाएगा ।

यह आदेश दिनांक 5-6-80 से प्रभावी होगा ।

[फ० न० एस०आई०/सी०आई०टी० (केन्द्रीय) 1/सी/80-81/984]

Sub :—Jurisdiction—Creation of two new ranges of Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax (Central), New Delhi.

S.O. 2434.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Income-tax, Delhi (Central), New Delhi hereby directs that a new Range known as Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax (Central) R-VI, New Delhi shall be created at Delhi.

This order shall come into force with effect from 5th June, 1980.

[F. No. SI/CIT(C)I/C/80-81/984]

विषय : क्षेत्राधिकार–निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) रेंज मेरठ के प्रभार का समापन

का०आ० 2234.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 की 43) की धारा 123 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयकर आयुक्त दिल्ली (केन्द्रीय, 1) नई दिल्ली निदेश देते हैं कि सं० एस० आई० ज्यूरि (1)/सी०/78-79/978 दिनांक 29-5-78 के अनुरूप बनाया गया निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज (सी) मेरठ का प्रभार समाप्त समझा जाय ।

यह आदेश दिनांक 5-6-80 से प्रभावी होगा ।

[फ० न० एस० आई०/ज्यूरि० (1)/सी०/80-81/985]

Sub :—Jurisdiction—Abolition of Charge of Inspecting Asstt. Commissioner (C) R-Meerut.

S.O. 2435.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Commissioner of Income-tax Delhi (Central-I) New Delhi hereby directs that the charge of the Inspecting Astt. Commissioner of Income-tax (C) Range-Meerut created vide Notification No. SI|Jur|(1)|(C)|78-79|978, dated 29th May, 1978, stands abolished.

This order shall come into force with effect from 5th June, 1980.

[F. No. SI/JUR(1)/C/80-81/985]

का०आ० 2436.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इससे पहले की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुये आयकर आयुक्त दिल्ली (सेंट्रल) नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम 2 में वर्णित रेंजों के निरीक्षीय को क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों अथवा व्यक्तियों या आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे ।

अनुसूची

क्रम सं०	नि० स०आ० आयुक्त रेंज एवं मुख्यालय का नाम	मण्डल का नाम
1	2	3
1.	निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त (सेंट्रल) रेंज 1 नई दिल्ली	1. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 1, नई दिल्ली 2. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 2, नई दिल्ली 3 आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 4, नई दिल्ली 4. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 5, नई दिल्ली 5. आयकर अधिकार केन्द्रीय मंडल 6, नई दिल्ली 6. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 7, नई दिल्ली 7. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 10, नई दिल्ली
2.	निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त (सेन्ट्रल) रेंज 4, नई दिल्ली	1. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 3, नई दिल्ली 2. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 8, नई दिल्ली 3. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 9, नई दिल्ली
3.	निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त (सेंट्रल) रेंज 6, नई दिल्ली	1. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 25, नई दिल्ली 2. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 25, नई दिल्ली 3. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 1, मेरठ 4. आयकर अधिकारी केन्द्रीय मंडल 4, मेरठ

यह अधिसूचना दिनांक 5-6-80 से प्रभावी होगा ।

[फा० सं० एस० आई/ज्युजि (1)/सी/80-81/986]

कंवल कृष्ण, आयुक्त

S.O. 2436.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of previous notification, the Commissioner of Income-tax Delih (Central-I), New Delhi, hereby directs that the Inspecting Asstt. Commissioners of Income-tax of the Ranges mentioned in column 2 of the schedule given below, shall perform all the functions of the I.A.C. of Income-tax in respect of such cases or of such persons or of such income or classe incomes as fall within the jurisdiction of the Income-tax Officers, Central Circles shown in column 3 thereof.

SCHEDULE

S. No.	Name of the IAC Range & H. Qrs.	Name of the Circle
1	2	3
1.	Inspecting Asstt., Commissioner of Income-tax (Central) Range-I, New Delhi.	(i) Income-tax Officer Central Circle-I, N. Dehli. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-II, N. Delhi. (iii) Income-tax Office Central Circle-IV, N. Delhi. (iv) Income-tax Officer, Central Circle-V, N. Delhi. (v) Income-tax Officer, Central Circle-VI, N. Delhi. (vi) Income-tax Officer, Central Circle-VII, N. Delhi. (vii) Income-tax Officer, Central Circle-X, N. Delhi.
2.	Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax (Central) Range-IV.	(i) Income-tax Officer, Central Circle-III, N. Delhi. (ii) Income-tax Officer, Central Circle-VIII, N. Delhi. (iii) Income-tax Officer, Central Circle XI, N. Delhi.
3.	Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax (Central) R-VI, New Delhi.	(i) Income-tax Officer, Central Cir. XXV, N. Delhi. (ii) Income-tax Officer, Cen. Cir.-XXVI, N. Delhi. (iii) Income-tax Officer, Cen. Cir-I, Meerut. (iv) Income-tax Officer, Cen. Cir. IV, Meerut.

This notification will take effect from 5-6-80.

[F. No. SI/Jur (1)/C/80-81/986]
KANWAL KRISHAN, Commissioner

आयकर विभाग, केरल

कोचिन, 12 अगस्त, 1980

का० आ० 2437.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) का आदेश एफ० सं 385/63/73-ऐ० टी० (बी) दिनांक 10-8-1977 में समाविष्ट प्राधिकार और निदेश के अनुसरण में, आयकर आयुक्त, केरल-I, केरल प्रभार-I और II के निर्धारितियों के संबंध में निम्नलिखित सूचनायें प्रकाशित करते हैं, ये सूचनायें वित्तीय वर्ष 1978-79 के संदर्भ हैं।

अनुसूची-I ए० इसमें जिन व्यक्तियों या हिन्दु अविभक्त कुटुम्बों पर दो लाख रुपये से अधिक आय पर कर निर्धारित किया गया है, उनका नाम, पता और अन्य विवरण विनिर्दिष्ट किये गये है।

अनुसूची-II बी० इसमें जिन कंपिनयों, फर्मों तथा व्यक्तियों के संगम पर दस लाख रुपये से अधिक आय पर कर निर्धारित किया गया है उनका नाम, पता और अन्य विवरण विनिर्दिष्ट किये गये है।

अनुसूची-II आय की विवरणी ठीक समय के भीतर प्रस्तुत करने में जो असफल हो गये है या लेखा बहियां पेश करने में जो असमर्थ हुए हैं या आय छिपाने के कारण वित्तीय वर्ष 1978-79 में रु० 5,000 या उससे अधिक जिन पर शास्ति लगाया गया है या गत वर्षों के शास्तियों के विरुद्ध दिये गये अपील या पुनरीक्षण के फैसले में 1978-79 वित्तीय वर्ष में जिन पर रु० 5,000 या उससे अधिक शास्ति निश्चित किया गया है उन व्यक्तियों का नाम, पता व अन्य विवरण इसमें विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

अनुसूची-III इस सूची में जिन व्यक्तियों ने एक लाख या उससे अधिक कर की राशि अदा करने में असमर्थ हो गये है और यह समय वित्तीय वर्ष 1978-79 के अन्तिम दिन तक दो या उससे अधिक वर्ष हो गये हैं, उन व्यक्तियों का नाम, पता और अन्य विवरण निर्दिष्ट किये गये है।

अनुसूची I-ए और अनुसूची-IIबी में दिये गये विवरण इस प्रकार हैं:—

(i) स्थिति (ii) निर्धारण वर्ष (iii) निर्वाचित आय (iv) निर्धारित आय (v) आयकर देय और (vi) आयकर प्रदत्त।

अनुसूची-II में दिये गये विवरण इस प्रकार है:—(i) स्थिति (ii) निर्धारण वर्ष (iii) शास्ति की राशि और (iv) शास्ति का स्वभाव।

अनुसूची-III में दिये गये विवरण इस प्रकार है:—

(i) ब्याज सहित कर (ii) शास्ति और (iii) कुल (सभी रकम रुपये में है)।

स्थिति की सूचनायें इस प्रकार है :—

'ऐ';—व्यक्तियों के लिए, 'एच० यू० एफ०' हिन्दु अविभक्त कुटुम्बों के लिए, 'कं०' कंपिनयों के लिए 'एफ' फर्मों के लिए और 'ए० ओ० पी०' व्यक्तियों के संगम के लिए।

अनुसूची-I ए

(1) भरतन पिल्लै० पी०, कोल्लम (i) ऐ (ii) 1978-79 (iii) 3,96,860 (iv) 4,22,370 (v) 2,72,139 (vi) 2,71,139 (2) क्लीटस० बी०, ओषियानिक एक्सपोर्टिंग कंपनी, शक्तिकुलडगरा (i) ऐ (ii) 1976-77 (iii) 2,21,865 (iv) 2,44,480 (v) 1,64,872 (vi) 1,47,357 (3) गोपिनाथन पिल्लै० पी०, काष्यू एक्सपोर्टर, कोल्लम (i) ऐ (ii) 1978-79 (iii) 11,48,560 (iv) 12,90,350 (v) 8,75,460 (vi) 8,75,460 (4) गोपिनाथन नायर० के०, काष्यू एक्सपोर्टर, कोल्लम (i) ऐ (ii) 1977-78 (iii) 65,560 (iv) 2,53,390 (v) 1,47,075 (vi) 1,47,075 और (ii) 1978-79 (iii) 32,38,300 (iv) 36,04,280 (v) 24,68,879 (vi) 24,68,879 (5) गोविन्दन ऐ० बी० एलैट फेब्रिक्स, त्रिश्शूर (i) ऐ (ii) 1976-77 (iii) 3,63,280 (iv) 3,69,036 (v) 2,56,285 (vi) 2,56,285 (6) जोण इनोक, वेस्लेण मेडिकल्स, कोल्लम (i) ऐ (ii) 1978-79 (iii) 3,60,150 (iv) 3,74,480 (v) 2,40,224 (vi) 2,40,224 (7) जेकब० ए० मेसेर्स कुरियन एब्रहाम प्लान्ट कंपनी, कोट्टयम (i) ऐ (ii) 1978-79 (iii) 2,36,930+कृषि आय 23,970 (iv) 2,46,510+कृषि आय 23,970 (v) 1,56,339 (vi) 1,56,399 (8) कुंजान्डी० के० के०, एलैट फाब्रीक्स, त्रिश्शूर (i) ऐ (ii) 1976-77 (iii) 2,43,340 (iv) 2,45,290 (v) 1,66,423 (vi) 1,66,423 (9) कृष्णन टी० पी०, तोप्पिल हाउस, पूलेनी, मेलूरऐ (i) (ii) 1977-78 (iii) 7,56,150 (iv) 7,56,100 (v) 4,76,146 (vi) 4,76,146 (10) कृष्णन पी० द्वारा, धामवा टयेर्स, कन्नूर (i) ऐ (ii) 1976-77 (iii) 2,18,020 (iv) 2,18,020 (v) 1,44,434 (vi) नहीं (2) राजमणि अम्मा० एन०, राज काष्यू कंपनी

कोल्लम० (i) ऐ० (ii) 1978-79 (iii) 4,75,670 (iv) 5,10,970 (v) 3,27,326 (vi) 3,27,326 (12) एच० एच० रामवर्मा फस्ट प्रिन्स, कौटियार पालस, तिरुवनन्तपुरम (i) ऐ० (ii) 1977-78 (iii) 2,17,440 (iv) 2,23,200 (v) 1,00,618 (vi) 1,00618 और (ii) 1978-79 (iii) 2,40,750 (iv) 2,40,850 (v) 1,15,998 (vi) 1,15,998 (13) राधव मेनोन० ए० सी०, द्वारा, मेरकन्टेल मरैन सर्विसेज, कोचिन-3 (i) ऐ० (ii) 1976-77 (iii) 2,25,030 (iv) 2,45,900 (v) 1,65,902 (vi) 1,29,254 (14) राघवन टी० आर०, एलैट फाब्रिक्स, त्रिशूर (i) ऐ० (ii) 1976-77 (iii) 2,17,840 (iv) 2,28,560 (v) 1,49,970 (vi) 1,49,970 (15) रामन के० के०, एलैट फाब्रिक्स, त्रिशूर (i) ए० (ii) 1976-77 (iii) 2,16,330 (iv) 2,18,290 (v) 1,51,825 (vi) 1,51,825 (16) शत्रुघ्नन पिल्लै, काश्यू एक्सपोर्टर, कोल्लम (i) ऐ० (ii) 1978-79 (iii) 5,25,820 (iv) 5,72,890 (v) 3,72,668 (vi) 3,72,668 (17) शेलवकुमार सी०, कृते स्वर्गीय चेल्लप्पन चेट्टियार, शिवकुमार आइल मिल्स, मैयानाड, कोल्लम (i) ऐ० (ii) 1977-78 (iii) 2,09,030 (iv) 2,16,090 (v) 1,18,914 (vi) 1,18,914 (18) वामन प्रभू० सी० एन० टयर डीलर, पल्लुरुत्ती (i) ऐ० (ii) 1976-77 (iii) 5,87,770 (iv) 5,89,190 (v) 4,30,473 (vi) 4,30,473 और (ii) 1977-78 (iii) 1,72,897 (iv) 3,11,820 (v) 1,82,291 (vi) 1,82,291

अनुसूची-I बी

(i) बामियपट्म टेक्सल वर्क्स लिमिटेड, पाप्पिनिशेरी (i) कं० (ii) 1978-79 (iii) 10,50,830 (iv) 10,50,840 (v) 6,06,834 (vi) 6,06,834 (2) कात्तलिक सिलिरयन बैंक लिमिटेड, त्रिशूर (i) कं० (ii) 1975-76 (iii) 19,39,950 (iv) 19,28,690 (v) 11,13,819 (vi) 11,13,819 (3) एलैट फाब्रिक्स, त्रिशूर (i) एफ० (ii) 1976-77 (iii) 12,32,050 (iv) 12,43,670 (v) 3,12,929 (vi) 3,12,929 (4) मेसेर्स हैलिब्यूरिया टी एस्टेट्स लिमिटेड, कोट्टयम (i) कं० (ii) 1977-78 (iii) 10,09,690 (iv) 10,09,690 (v) 5,55,330 (vi) 5,50,330 (5) मेसेर्स केरला नट फुड कंपनी०, कोल्लम (i) एफ० (ii) 1975-76 (iii) 2,86,670 (iv) 10,01,410 (v) 66,340 (vi) 66,340 (6) मेसर्स केरला स्टेट बाम्बू कारपरेशन लिमिटेड, अंगमाली (i) कं० (ii) 1977-78 (iii) 11,14,168 (iv) 11,49,370 (v) 7,75,315 (vi) 6,63,760 (7) कुमार इन्डस्ट्रीस, एडत्तरा, पालघाट डिस्ट्रिक्ट (i) एफ० (ii) 1978-79 (iii) 1,40,400 (iv) 16,06,940 (v) 3,99,210 (vi) 3,99,210 (8) मेसेर्स के० के० कुंजान्ती, ऐ० बी० गोविन्दन एन्ड कंपनी, त्रिशूर (i) एफ० (ii) 1976-77 (iii) 15,76,960 (iv) 15,95,010 (v) 4,32,913 (vi) 4,05,418 (9) मेसेर्स सौत इन्डियन बैंक लिमिटेड, त्रिशूर (i) कं० (ii) 1976-77 (iii) 50,55,180 (iv) 50,55,460 (v) 29,17,952 (vi) 29,17,952 (10) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकूर, तिरुवनंतपुरम (i) कं० (ii) 1976-77 (iii) 2,26,21,875 (iv) 1,86,61,830 (v) 68,98,739 (vi) 68,98,739 (2) ट्रावनकूर केमिकल्स एन्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी०, लिमिटेड, कलमशेरी (i) कं० (ii) 1977-78 (iii) 33,19,480 (iv) 38,86,210 (v) 21,49,743 (vi) 21,49,743 (12) ट्रावनकूर टैटानियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम (i) कं० (ii) 1973-74 (iii) 83,41,800 (iv) 33,41,800 (v) 8,70,143 (iv) 8,70,143 ।

अनुसूची-II

(1) भारत सी फुड्स, कोच्चिन-2 (i) एफ (ii) 1972-73 (iii) 47,000 (iv) आय का छिपाना (2) जोसफजोण, कुन्नत्त फैनान्शियल कोरपरेशन, तुरवूर (i) ऐ० (ii) 1971-72 (iii) 9,818 (iv) आय विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब और (ii) 1972-73 (iii) 18,858 (iv) आय विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब और (ii) 1973-74 (iii) 20,406 (vi) आय विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब (3) मिश्रा चिट्स एन्ड काश क्रेडिट्स (पी) लिमिटेड, कोचिन-1 (i) कं० (ii) 1971-72 (iii) 55,100 (iv) संदेय अग्रिम कर का प्राक्कलन देने में और कर अदा करने में असफलता और (ii) 1971-72 (iii) 22,030 (iv) आय विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता और (ii 1972-73 (iii) 8,262 (iv) आय विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता (4) मेसेर्स ओ० के० इन्डस्ट्रीस कोच्चिन-1 (i) एफ० (ii) 1972-73 (iii) 40,900 (iv) आय का छिपाना (5) के० वी० रमेश, लिगल हेयर ऑफ डा० के० एस० वासुदेवन, मलबार केमिकल्स, पालघाट (i) ऐ० (ii) 1973-74 (iii) 19,100 (iv) आय छिपाना।

अनुसूची-III

(1) अब्दुल मजीद पी० ए०, मेसेर्स पी० ए० अब्दुलरहिमानकुट्टी आन्ड सन्स, कोच्चिन-1 (i) 1,29,000 (ii) नहीं (iii) 1,29,000 (2) मेसेर्स ए० परीद पिल्लै एन्ड ब्रदेर्स, आलुवा (i) 5,54,247 (ii) नहीं (iii) 5,54,247 (3) मेसेर्स भारत सी फुड्स, कोच्चिन-2 (i) 1,18,051 (ii) नही (iii) 1,18,051 (4) एम० चेल्लप्पन पिल्लै, चवरा (i) 4,73,456 (ii) 932 (iii) 4,74,388 (5) वी० दामोदरन, तिरुवनन्तपुरम (i) 2,66,000 (ii) 1,39,000 (iii) 4,05,000 (6) डा० जोर्ज तोमस, कोट्टयमवू (i) 6,82,157 (ii) 1,31,682 (iii) 8,13,839 (7) के० ए० हम्सा कोया, कोच्चिन-1 (i) 2,28,000 (ii) 67,000 (iii) 2,95,000 (8) जोसफ पी० ऐ० वैकम (i) 93,303 (ii) 30,000 (iii) 1,23,303 (9) जयानन्दन एन० एस० आटिंगल (i) 1,42,265 (ii) 14,250 (iii) 1,56,515 (10) स्व० एम० कुंजाक्की, आलप्पुषा (1) 1,04,172 (ii) 29,400 (iii) 1,33,572 (ii) कादर पिल्लै ए० कोकनट आइल मर्चन्ड, आलुवा (i) 1,03,559 (ii) नहीं (iii) 1,03,559 (12) कुलत्तुंगल मोटोर कोरपरेषन, तिरुवनन्तपुरम (i) 2,51,081 (ii) नहीं (iii) 2,51,081 (13) ए० पी० मोहम्मद हाजी, कालिकट (i) 5,88,529 (ii) 1,29,342 (iii) 7,17,871 (14) वी० जे० मात्यू, तलश्शेरी (i) 1,00,326 (ii) 9,456 (iii) 1,09,782 (15) एम० एस० एम० सलिहीन साहिब एन्ड ब्रदर्स, कोडुवायूर (i) 1,81,204 (ii) 5,000 (iii) 1,86,204 (16) मोहम्मद मीराखान पी० एम०, मुन्डकयम (i) 1,37,259 (ii) 53,075 (iii) 1,90,334 (17) मित्रा चिट्स एन्ड काष क्रेडिट (पी) लिमिटेड, कोच्चिन-1 (i) 4,81,520 (ii) 86,727 (iii) 5,68,247 (18) क्याप्टन सी० उम्मन, मावेलिक्करा (i) 1,64,063 (ii) 235 (iii) 1,64,298 (19) परीद पिल्लै० ए०, आलुवा (i) 1,27,433 (ii) नहीं (iii) 1,27,433 (20) प्रसन्नकुमार० एन० एस०, आटिंगल (i) 95,397 (ii) 29,097 (iii) 1,24,494 (21) के० पोन्नन, तिरुवनंतपुरम (i) 76,394 (ii) 41,741 (iii) 1,18,135 (22) आर के० वी० मोटार्स न्ड टिंबर्स (पी) लिमिटड, तिरुवनन्तपुरम (i) 3,77,000 (ii) 51,000 (iii) 4,28,000 (23) आर० एस० ए० रामकृष्ण चेट्टियार, तिरुवनन्तपुरम (i) 86,291 (ii) 17,018 (iii) 1,03,309 (24) एन० एस० राजन, आटिंगल (i) 2,57,000 (ii) 15,000 (iii 2,72,000 (25) पी० वी० रघुनाथ, कोच्चिन-2 (i) 97,000 (ii) 1,29,000 (iii) 1,26,000 (26) स्व० वी० एन० श्रीधरन उण्णी, आटिंगल (i) 9,40,000 (ii) 1,69,000 (iii) 11,09,000 (27) श्रीकृष्ण फार्मेसी, आटिंगल (iii) 4,00,302 (ii) 59,113 (iii) 4,59,415 (28) स्व० पी० के० सुब्बिया पिल्लै, तिरुवनन्तपुरम (i) 1,19,450 (ii) नही (iii) 1,19,450 (29) आर० श्रीधरन पणिक्कर, नितरुवनन्तपुरम (i) 9,90,000 (ii) 1,81,000 (iii) 11,71,000।

[सी० सं० 211/79-80/आर]

एम० एस० उण्णिनायर, आयुक्त

INCOME-TAX DEPARTMENT, KERALA

Cochin, the 12th August, 1980

S.O. 2437.—Pursuant to the authorisation and direction of the Government of India under section 287 of the Income-tax Act, 1961 contained in orders F.No.385/63/73-IT(B) dated 10th August, 1977 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), the Commissioner of Income-tax, Kerala-I hereby publishes the following information in respect of the assessees of the Charges of the Commissioners of Income-tax, Kerala-I & II with reference to the financial year 1978-79.

SCHEDULE I A. contains the names and addresses and other particulars specified below in respect of Individuals and Hindu Undivided Families assessed on an income of more than Rs. 2 lakhs.

SCHEDULE I B. contains the names and addresses and other particulars specified below in respect of Companies, Firms and Association of persons assessed on an income of more than Rs. 10 lakhs.

SCHEDULE II. contains names and addresses and other particulars specified below in respect of persons on whom a penalty of not less than Rs.5,000/- was imposed during the financial year 1978-79 for failure to file return of income in time or to produce books of account, or for concealment of income, or in whose cases such penalties have been confirmed in appeal or revision during the financial year 1978-79, to an extent of Rs.5,000/-or more.

SCHEDULE III. contains the names and addresses and other particulars specified below in respect of persons who have been in default of payment of tax, amounting to Rs.1 lakhs or more for over two years as on the last day of the financial year 1978-79.

The particulars given in Schedule I A and Schedule I B are (i) status (ii) assessment year (iii) income returned (iv) income (v) income-tax payable and (vi) income-tax paid.

The particulars given in Schedule II are (i) status (ii) assessment year (iii) amount of penalty and (iv) nature of penalty.

The particulars given in Schedule III are (i) tax including interest (ii) penalty and (iii) total (all amounts in rupees).

Status is indicated by 'I' for Individuals, 'H.U.F.' for Hindu Undivided Family, 'Co.' for Companies, 'F' for Firms and 'A.O.P.' for Association of Persons.

SCHEDULE-I A

(1) Bharathan Pillai, P., Quilon. (i) I (ii) 1978-79 (iii) 3,96,860 (iv) 4,22,370 (v) 2,71,139 (vi) 2,71,139 (2) Cletus, V., Oceanic Exporting Co., Sakti Kulangara. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 2,21,865 (iv) 2,44,480 (v) 1,64,872 (vi) 1,47,357 (3) Gopinathan Pillai.P., Cashew Exporter, Quilon. (i) I (ii) 1978-79 (iii) 11,48,560 (iv) 12,90,350 (v) 8,75,460 (vi) 8,75,460 (4) Gopinathan Nair, K., Cashew Exporter, Quilon. (i) I (ii) 1977-78 (iii) 65,560 (iv) 2,53,390 (v)1,47,075 (vi) 1,47,075 AND (ii) 1978-79 (iii) 32,38,300 (iv) 36,04,280 (v) 24,68,879 (vi) 24,68,879 (5) Govindan. I.V., Elite Fabrics, Trichur. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 3,63,280 (iv) 3,69,036 (v) 2,56,285 (vi) 2,56,285 (6) John Enoch, Western Medicals, Quilon. (i) I (ii) 1978-79 (iii) 3,60,150 (iv) 3,74,480 (v) 2,40,224 (vi) 2,40,224 (4) Jacob. A., M/s. Kurian Abraham & Co., Kottayam. (i) I (ii) 1978-79 (iii) 2,36,930 | agricultural income 23,970 (iv) 2,46,510 | agricultural income 23,970 (v) 1,56,399 (vi) 1,56,399 (8) Kunjandi, K.K., Elite Fabrics, Trichur. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 2,43,340 (iv) 2,45,290 (v) 1,66,423 (vi) 1,66,423 (9) Krishnan. T.P., Thoppil House, Pooleni, Melloor. (i) I (ii) 1977-78 (iii) 7,56,100 (iv) 7,56,100 (v) 4,76,146 (vi) 4,76,146. (10) Krishnan. P., C/o Vasava Tyres, Cannanore. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 2,18,020 (iv) 2,18,020((v) 1,44,434 (vi) NIL. (11) Rajamani Amma. N., Raja Cashew Co., Quilon. (i) I (ii) 1978-79 (iii) 4,75,670 (iv) 5,10,970 (v) 3,27,326 (vi) 3,27,326. (12) H.H. Ramavarma Ist Prince, Kaudiar Palace, Trivandrum, (i) I (ii) 1977-78 (iii) 2,17,440 (iv) 2,23,200 (v) 1,00,618 (vi) 1,00,618 AND (ii) 1978-79 (iii) 2,40,750 (iv) 2,40,850 (v) 1,15,998 (vi) 1,15,998. (13) Raghava Menon., A.C., C/o Merchantile Marine Services, Cochin-3. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 2,25,030 (iv) 2,45,900 (v) 1,65,902 (vi) 1,29,254 (14) Raghavan. T.R., Elite Fabrics, Trichur. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 2,17,840 (iv) 2,28,560 (v) 1,49,970 (vi) 1,49,970. (15) Raman. K. K., Elite Fabrics, Trichur. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 2,16,330 (iv) 2,18,290 (v) 1,51,825 (vi) 1,51,825. (16) Sathrugnan Pillai, Cashew Exporter, Quilon. (i) I (ii) 1978-79 (iii) 5,25,820 (iv) 5,72,890 (v), 3,72,668 (vi) 3,72,668. (17) Selvakumar. C., for late Chellappan Chettiar, Sivakumar Oil Mills, Mayyanad, Quilon. (i) I (ii) 1977-78 (iii) 2,09,030 (iv) 2,16,090 (v) 1,18,914 (vi) 1,18,914. (18) Vamana Prabhu. C.N., Tyre Dealer, Palluruthy. (i) I (ii) 1976-77 (iii) 5,87,770 (iv) 5,89,190 (v) 4,30,473 (vi) 4,30,473 AND (ii) 1977-78 (iii) 1,72,897 (iv) 3,11,820 (v) 1,82,291 (vi) 1,82,291.

SCHEDULE-I B

(1) Baliapatam Tile Works Ltd., Pappinisseri. (i) Co. (ii) 1978-79 (iii) 10,50,830 (iv) 10,50,840 (v) 6,06,834 (vi) 6,06,834 (2) Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur. (i) Co. (ii) 1975-76 (iii) 19,39,950 (iv) 19,28,690 (v) 11,13,819 (vi) 11,13,819 (3) Elite Fabrics, Trichur. (i) F(ii) 1976-77 (iii) 12,32,050 (iv) 12,43,670 (v) 3,12,929 (vi) 3,12,929 (4) M/s. Haileburea Tea Estates Ltd., Kottayam. (i) Co. (ii) 1977-78 (iii) 10,09,690 (iv) 10,09,690 (v 5,55,330 (vi) 5,50,330. (5) M/s. Kerala Nut Food Co., Quilon (i) F (ii) 1975-76 (iii) 2,86,670 (iv) 10,01,410 (v) 66,340 (vi) 66,340. (6) M/s. Kerala State Bamboo Corporation Ltd., Angamali. (i) Co. (ii) 1977-78 (iii) 11,14,168 (iv) 11,49,370 (v) 7,75,315 (vi) 6,63,760. (7) Kumar Industries, Edathara, Palghat Dt. (i) F (ii) 1978-79 (iii) 1,40,400 (iv) 16,06,940 (v) 3,99,210 (vi) 3,99,210 (8) M/s. K.K. Kunjandi, I.V. Govindan & Co., Trichur. (i) F (ii) 1976-77 (iii) 15,76,960 (iv) 15,94,010 (v) 4,32,913 (vi) 4,05,418. (9) M/s. South Indian Bank Ltd., Trichur. (i) Co. (ii) 1976-77 (iii) 50,55,180 (iv) 50,55,460 (v) 29,17,952 (vi) 29,17,952 (10) State Bank of Travancore, Trivandrum. (i) Co. (ii) 1976-77 (iii) 2,26,21,870 (iv) 1,86,61,830 (v) 68,98,739 (vi) 68,98,739 (11) Travancore Chemical and Manufacturing Co., Ltd., Kalamassery. (i) Co. (ii) 1977-78 (iii) 33,19,480 (iv) 38,86,210 (v) 21,49,743 (vi) 21,49,743 (12) Travancore Titanium Products Ltd., Trivandrum, (i) Co. (ii) 1973-74 (iii) 83,41,800(iv) 83,41,800 (v) 8,70,143 (vi) 3,70,143.

SCHEDULE-II

(1) Bharat Sea Foods, Cochin-2. (i) F (ii) 1972-73 (iii) 47,000 (iv) Concealment of income. (2) Joseph John, Kunnathu Financial Corporation, Thuravur. (i) I (ii) 1971-72 (iii) 9818 (iv) delay in filing return of income. AND (ii) 1972-73 (iii) 18,858 (iv) delay in filing return of income. AND (ii) 1973-74 (iii) 20,406 (iv) delay in filing return of income. (3) Mitra Chits & Cash Credits (P) Ltd., Cochin-1. (i) Co. (ii) 1971-72 (iii) 55,100 (iv) Failure to file voluntary estimate of advance tax and to pay tax. AND (ii) 1971-72 (iii) 22,030 (iv) Failure to file return of income. AND (ii)1972-73 (iii) 8,262 (iv) Failure to file return of income (4) M/s. O. K. Industries, Cochin-1. (i) F (ii) 1972-73 (iii) 40,900 (iv) Concealment of income. (5) K.V. Ramesh, Legal heir of Dr. K.S. Vasudevan, Malabar Chemicals, Palghat. (i) I (ii) 1973-74 (iii) 19,100 (iv) Concealment of income.

SCHEDULE-III

(1) Abdul Majeed P.A., M/s. P.A. Abdulrahimankutty & Sons, Cochin-1. (i) 1,29,000 (ii) Nil (iii) 1,29,000 (2) M/s. A. Pareed Pillai & Bros., Alwaye. (i) 5,54,247 (ii) Nil (iii) 5,54,247. (3) M/s. Bharat Sea Foods, Cochin-2. (i) 1,18,051 (ii) Nil (iii)

1,18,051. (4) S. Chellappan Pillai, Chavara. (i) 4,73,456 (ii) 932 (iii) 4,74,388. (5) V. Damodaran, Trivandrum((i) 2,66,000 (ii) 1,39,000 (iii) 4,05,000. (6) Dr. George Thomas, Kottayam. (i) 6,82,157 (ii) 1,31,682 (iii) 8,13,839. (7) K.A. Hamza Koya, Cochin-1. (i) 2,28,000 (ii) 67,000 (iii) 2,95,000. (8) Joseph.P.I., Vaikom. (i) 93,303 (ii) 30,000 (iii) 1,23,303 (9) Jayanandan, N.S. Attingal. (i) 1,42,265 (ii) 14,250 (iii) 1,56,515. (10) Late M. Kunchacko, Alleppey. (i) 1,04,172 (ii) 29,400 (iii) 1,33,572. (11) Kader Pillai. A. Coconut Oil Merchant, Alwaye. (i) 1,03,559 (ii) Nil (iii) 1,03,559.(12) Kulathungal Motor Corporation, Trivandrum. (i) 2,51,081 (ii) Nil (iii) 2,51,081. (13) A.P. Mohamed Hajee, Calicut. (i) 5,88,529 (ii) 1,29,342 (iii) 7,17,871. (14) V.J. Mathew, Tellicherry (i) 1,00,326 (ii) 9,456 (iii) 1,09,782. (15) M.S.M. Saliheen Sahib & Bros., Koduvayur. (i) 1,81,204 (ii) 5,000 (iii) 1,86,204. (16) Mohamed Meerakhan. P.M., Mundakayam. (i) 1,37,259 (ii) 53,075 (iii) 1,90,334. (17) Mitra Chits & Cash Credit (P) Ltd., Cochin-1. (i) 4,81,520 (ii) 86,727 (iii) 5,68,247. (18) Captain C. Commen, Mavelikkara. (i) 1,64,063 (ii) 235 (iii) 1,64,298. (19) Pareed Pillai. A., Alwaye. (i) 1,27,433 (ii) Nil. (iii) 1,27,433. (20) Prasannakumar. N.S., Attingal. (i) 95,397 (ii) 29,097 (iii) 1,24,494. (21) K. Ponnan, Trivandrum. (i) 76,394 (ii) 41,741 (iii) 1,18,135. (22) R.K.V. Motors & Timbers (P) Ltd., Trivandrum, (i) 3,77,000 (ii) 51,000 (iii) 4,28,000. (23) R.S.A. Ramakrishna Chettiar, Trivandrum. (i) 86,291 (ii) 17,018 (iii) 1,03,309. (24) N.S. Rajan, Attingal. (i) 2,57,000 (ii) 15,000 (iii) 2,72,000. (25) P.V. Raghunath, Cochin-2. (i) 97,000. (ii) 1,29,000 (iii) 1,26,000. (26) Late B.N. Sreedharan Unni, Attingal. (i) 9,40,000 (ii) 1,69,000 (iii) 11,09,000 (27) Sreekrishna Pharmacy, Attingal, (i) 4,00,302 (ii) 59,113 (iii) 4,59,415. (28) Late P.K. Subbiah Pillai, Trivandrum. (i) 1,19,450 (ii) Nil (iii) 1,19,450. (29) R. Sreedhara Panicker, Trivandrum. (i) 9,90,000 (ii) 1,81,000 (iii) 11,71,000.

[C. No. 211/79-80/R]

M. S. UNNINAYAR, Commissioner

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का० आ० 2438.—भारत सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1128, तारीख 21 अप्रैल, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम करी पाउडर निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(ग) "प्राधिकृत पैकर" से कोई व्यक्ति या व्यक्ति निकाय अभिप्रेत है जिसे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया या मानक श्रेणी के अनुसार वस्तु को चिन्हित और श्रेणीकृत करने के लिए प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र दिया गया है ;

(घ) "प्राधिकरण का प्रमाण-पत्र" से कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा करी पाउडर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1956 के अनुसार करी पाउडर के श्रेणीकरण की वांछा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है ;

(ङ) "करी पाउडर" से साफ सूखे और अच्छे मसालों को पीस कर प्राप्त पाउडर अभिप्रेत है, जिनमें स्टार्च तथा साधारण खाद्य नमक हो परन्तु जिसमें करी पेस्ट नहीं है ;

(च) "निरीक्षण अधिकारी" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यताप्राप्त करी पाउडर के निरीक्षण के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए करी पाउडर का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिसूचना सं० का० आ० 1127, तारीख 21 अप्रैल, 1973 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : —(1) निर्यात के लिए आशयित करी पाउडर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केवल प्राधिकृत पैकर द्वारा श्रेणीकृत और पैक किया जाएगा ।

(2) प्राधिकृत पैकर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह करी पाउडर के नमूने और श्रेणीकरण के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ करे और परीक्षण आदि के लिए अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करे जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) करी पाउडर के निर्यात करने की वांछा रखने वाली प्राधिकृत पैकर निकटतम निरीक्षण अधिकारी को ऐसे ब्यौरों के साथ लिखित सूचना देगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ताकि वह निरीक्षण अधिकारी नियम 3 के अनुसार करी पाउडर के लॉटों का श्रेणीकरण और चिह्नांकन कर सके ।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्रत्येक सूचना :—

(क) निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित पैकिंग केन्द्रों पर श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने से कम से कम 2 दिन पहले दी जाएगी ।

(ख) अन्य स्थानों पर जो निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालयों पर स्थित नहीं है श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने से 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

(5) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण अधिकारी करी पाउडर के परेषणों का निरीक्षण कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार यह इस दृष्टि से करेगा कि वे नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं ।

(6) यदि निरीक्षण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार है तो वह कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करी पाउडर के डिब्बों या पैकेजों पर चिपकाने के लिए एग्मार्क लेबल जारी करेगा :

परन्तु यदि निरीक्षण अधिकारी का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह एग्मार्क लेबल जारी करने से इंकार कर देगा और प्राधिकृत पैकर को शीघ्र ही यह तथ्य उसके कारणों सहित लिखित रूप में सूचित करेगा ।

(7) करी पाउडर के श्रेणीकृत और लेबल लगे हुए प्रवेषणों का निर्यात करने की वांछा रखने वाला प्राधिकृत पैकर उसकी निर्यात योग्यता के प्रमाण स्वरूप श्रेणीकरण के प्रमाण-पत्र के लिए निरीक्षण अधिकारी निकटतम कार्यालय में ऐसे ब्यौरों के साथ लिखित आवेदन करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा नियम 3 के अनुसार विहित किए जाएं ताकि वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी कर सके ।

(8) उप-नियम (7) के अधीन प्रत्येक आवेदन :—

(क) निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित पैकिंग केन्द्रों पर उप-नियम (7) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से दो दिन पूर्व दिया जाएगा ;

(ख) अन्य स्थानों पर जो निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित नहीं है उप-नियम (7) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से तीन दिन पूर्व दिया जाएगा ।

(9) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षण अधिकारी करी पाउडर के श्रेणी कृत परेषणों का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक श्रेणीकृत लॉट के लिए अलग से एक जांच नमूना लेगा ।

(10) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट परेषणों के जांच नमूने के पश्चात् और जांच नमूनों के परीक्षण करने के पश्चात् यदि निरीक्षण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि नियम श्रेणी, मान्यताप्राप्त विनिर्देशों अनुसार है तो वह परेषण (परेषणों) के संबंध में उनकी निर्यात योग्यता के प्रमाण-स्वरूप श्रेणीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा :—

परन्तु यदि निरीक्षण अधिकारी का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह प्राधिकृत पैकर को शीघ्र ही यह तथ्य उसके कारणों सहित लिखित रूप में सूचित करेगा और वह उक्त श्रेणीकरण का प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा ।

5. निरीक्षण के स्थान :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक निरीक्षण प्राधिकरण के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्राधिकृत परिसरों पर किया जाएगा और जांच निरीक्षण या जांच नमूना निर्यात से पूर्व किसी भी स्थान पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या निरीक्षण अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है ।

6. एगमार्क लेबलों के प्रभार का संदाय :—प्राधिकृत पैकर एगमार्क लेबलों के प्रभार का जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं संदाय ऐसी रीति से करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

7. परीक्षण या जांच नमूनों का पुनः परीक्षण :—(1) यदि प्राधिकृत पैकर निरीक्षण अधिकारी के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह संबद्ध निरीक्षण अधिकारी से परेषणों के पुनः परीक्षण का प्रबंध करने के लिखित रूप में अनुरोध करने का हकदार होगा और उसके पश्चात् एक और परीक्षण नमूना या जांच नमूना लिया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विश्लेषण के परिणामों का पूर्ववर्ती नमूनों के साथ औसत निकाला जाएगा और औसत परिणाम श्रेणी अभिधानों का अवधारण करने के लिए लिया जाएगा ।

8. अपील :—यदि कोई प्राधिकृत पैकर नियम 4 के उप-नियम (7) या उप-नियम (10) के अधीन परेषण का श्रेणीकरण करने या प्रमाण-पत्र जारी करने के निरीक्षण अधिकारी के इंकार से व्यथित है तो वह आगामी कार्य दिवस के सायं पांच बजे तक निरीक्षण अधिकारी से मामले को कृषि विपणन सलाहकार को निर्देशित किए जाने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है और कृषि विपणन सलाहकार अपने द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मामले पर सलाह देने के लिए सलाहकार पैनल का गठन कर सकता है ।

[सं० 1(13)/73-नि०नि० तथा नि०उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

645 GI/80—7

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2438.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1128, dated the 21st April 1973, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Curry Powder (Quality Control and Inspection) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Qualiy Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(c) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certification of authorisation by the Agricultural Marketing Adviser, for getting the commodity graded and Agmarked in accordance with the grade standard and procedure prescribed under the rules ;

(d) "Certification of Authorisation" means the certificate issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised in this behalf to a person or body of persons desirous of grading curry powder as per the curry powder and Marking Rules, 1956.

(e) "curry powder" means powder obtained by grinding clean, dried and sound spices and condiments which may contain added starch and edible common salt, but does not include curry paste.

(f) "Inspecting Officer" means the officer authorised by the Agricultural Marketing Adviser for inspection of curry powder recognised as the Agency under section 7 of the Act.

3. Basis of inspection.—Inspecion of Curry Powder intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the standard specifications, recognised by the Cenral Government under notification No. S.O. 1127 dated 21st April, 1973.

4. Procedure of inspection.—(1) Curry Powder meant for export shall be graded and packed only by the authorised packer in accordance with the instructions issued in this behalf by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) It shall be the responsibility of the authorised packer to make such arrangements for grading and sampling of curry powder and also, provide requisite facilities for testing etc. as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) An authorised packer intending to export curry powder shall give intimation in writing along with such details as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser to the nearest Inspecting Officer to enable him to grade and mark curry powder lots in accordance with rule 3.

(4) Every intimation under sub-rule (3) shall be given :—
(a) not less than two days before the grading and marking is to be carried out at the packing centres situated at the Head quarters of the Inspecting Officer ;

(b) not less than ten days before the grading and marking is to be carried out at other places, which are not situated at the Headquarters of the Inspecting Officer.

(5) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (3), the Inspecting Officer shall inspect the consignments of curry powder as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser with a view to seeing that the sample

complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3.

(6) The Inspecting Officer shall issue Agmark labels for affixing the same on the containers or packages of curry powder as per instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser in case he is satisfied that the consignment(s) is as per specifications referred to in rule 3 :

Provided that if the Inspecting Officer is not so satisfied he shall refuse to issue the said Agmark labels and convey the fact immediately in writing to the authorised packer along with the reasons thereof.

(7) An authorised packer intending to export the graded and labelled consignments of curry powder shall apply to the nearest office of the Inspecting Officer for a certificate of grading in token of its exportworthiness in writing along with such details as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser in accordance with rule 3 to enable him to issue such certificate.

(8) Every application under sub-rule (7) shall be given—

(a) not less than two days before the certificate, referred to in sub-rule (7) is to be issued at the packing centres situated at the Headquarter of the Inspecting Officer ;

(b) not less than three days before the certificate referred to in sub-rule (7) is to be issued at other places, which are not situated at the Headquarters of the Inspecting Officer.

(9) On receipt of the application referred to in sub-rule (7) the Inspecting Officer shall inspect the graded consignments of curry powder and draw a separate check sample for each graded lot.

(10) If, after check sampling of the consignments referred to in sub-rule (7) and after examination of the check samples, the Inspecting Officer is satisfied that the grade assigned is as per recognised specifications he shall issue a certificate of Grading in respect of that consignment(s) in token of their exportworthiness :

Provided that if the Inspecting Officer is not so satisfied he shall immediately intimate the fact in writing to the authorised packer along with the reasons therefor, and shall not issue the said certificate of Grading.

5. Places of inspection.—Initial inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the authorised premises mentioned in the certificate of authorisation and check inspection or check sampling can be done by Agricultural Marketing Adviser or an Inspecting Officer at any place before export.

6 Payment of charges for Agmark labels.—The authorised packer shall pay the Agmark label charges which are notified by the Government of India from time to time, in the manner specified by the Agricultural Marketing Adviser.

7. Re-examination of the test or check samples.—(1) If the Authorised packer is not satisfied with the results of the Inspecting Officer he shall be entitled to request the concerned Officer in writing to arrange for re-examination of the consignments and one more test sample or a check sample, shall thereafter, be withdrawn and tested.

(2) The results of analysis under sub-rule (1) shall be averged with those of the previous sample and average result shall be taken for determining the grade designation.

8. Appeal.—If any authorised packer is aggrieved by the refusal of the Inspecting Officer to grade a consignment or to issue a certificate under sub-rule (7) or sub-rule (10) of rule 4, he may request the Inspecting Officer, in writing, latest by 5.00 p.m. on the following working day to refer the matter to the Agricultural Marketing Adviser, who may constitute an Advisory panel to advise him on the dispute in accordance with the procedure laid down by him. The decision of the Agricultural Marketing Adviser shall be the final.

[No. 1(13)/73-EI & EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director.

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का०आ० 2439.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों को उनके निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2472 तारीख 14 जुलाई, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 जुलाई, 1979 में प्रकाशित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां उन व्यक्तियों को जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है 18 जुलाई, 1979 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और जनता से 8 सितम्बर, 1979 तक या उससे पूर्व आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है इसके द्वारा :

(1) अधिसूचित करती है कि एल्यूमिनियम के बर्तन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे,

(2) एल्यूमिनियम के बर्तनों के निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है तो, निर्यात से पूर्व, ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तनों पर लागू किया जाएगा ।

(3) (क) सुसंगत भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक को,

(ख) इस आदेश से उपाबद्ध अनुबन्ध I में दिए गए न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए विदेशी क्रेता निर्यातकर्ता के बीच निर्यात संविदा के सहमत विनिर्देशों को निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को,

और

ऐसी निर्यात संविदाओं के लिए निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच सहमत संविदात्मक विनिर्देश जो राजपत्र में इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से तुरन्त पूर्व किए गए थे तथा उसके पश्चात् उक्त तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर निर्यात किए गए थे, ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तनों के निर्यात को तब तक प्रतिसिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि एल्यूमिनियम के बर्तनों के परीक्षण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा निर्यात योग्य हैं या उनपर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सील या चिह्न चिपकाए गए हैं ।

2. इस आदेश की कोई भी बात :

(क) ऐसे परीक्षणों पर जो राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से शीघ्र पूर्व ही संबंधित निर्यातकर्ता या विनिर्माता के परिसरों से जा चुके हैं, तथा

(ख) भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्र या मार्ग द्वारा एल्यूमिनियम के बर्तनों के प्रमाणिक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी ।

3. इस आदेश में "एल्यूमिनियम के बर्तनों से" एल्यूमिनियम या इसके मिश्र धातु पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम से विनिर्मित कोई भी बर्तन जो खाने, पीने पकाने या परोसने या भोजन या पानी सहित पेय तथा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए भंडारीकरण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं । जिसमें प्रेशर कुकर तथा ऐसे अन्य अपकरण सम्मिलित नहीं हैं ।

4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

अनुबन्ध 1

[पैरा (3)(क) देखिए]

एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए न्यूनतम विनिर्देश

1.0 **सामग्री**

1.1 पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम के बर्तनों के एल्यूमिनियम की मात्रा 99.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी जब तक कि पिटवां या ढलवां बर्तनों की बाबत किसी भी सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देश में अनुज्ञात न हो सके ।

1.2 पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम के मिश्र धातु के बर्तनों के लिए रासायनिक मिश्रण निर्यात कर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा में हुई सहमति के अनुसार होगा किसी भी ऐसे विशिष्ट अनुबंध के न होने पर सामग्री सुसंगत भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हो जो नवीनतम हो ।

1.3 बर्तनों की मोटाई निर्यातकर्ता तथा विदेशीक्रेता के मध्य हुए करार के अधीन होगी । निर्यात संविदा में किसी भी विशिष्ट अनुबंध में न होने पर बर्तनों की परिरुपित मोटाई सुसंगत भारतीय मानक या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगी ।

1.4 हत्थी लेगे एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए हत्थी जब लगाई जाती है तो वे एल्यूमिनियम या अन्य उच्च ज्वलनशील सामग्री की होगी तथा जब वह खाद्य सामग्री से स्पर्श करेगी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी ।

2. **आकार तथा विमाएं**

बर्तनों के आकार तथा विमाएँ निर्यात कर्ता तथा विदेशी क्रेता के मध्य हुए करार के अधीन होंगे ।

निम्नलिखित सहयताएँ या वे जो साधारण इंजीनियरी सहयताओं से सुसंगत भारतीय मानक में उल्लिखित हों विमाओं के लिए लागू होंगी :—

से अधिक	तक तथा सहित	सहयता
मि०मी०	मि०मी०	मि०मी०
—	30	± 1
30	100	± 2
100	200	± 3
200	—	± 5

3.0 **कार्य कौशल तथा फिनिश :**

बर्तनों के किनारे तेज नहीं होंगे उनकी फिनिश चारों तरफ से चमकीली होगी जब तक कि विदेशी क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंधित न हो परिरुपित बर्तन दरारों, सिलवटों, गिरावटों, विकृतियों, गढ़ों, खरोंचों, गड्ढों औजार के गहरे निशानों तथा अन्य सतही दोषों जिसमें प्रहार से हुए छिद्र जैसे ढलवां दोष भी है से मुक्त होंगे ।

4.0 **परीक्षण**

4.1. पानी रिसने का परीक्षण—बर्तनों में जब किनारे तक पानी भरा जाएगा तो वे कहीं से रिसना नहीं चाहिए ।

4.2. मोड़ परीक्षण—पिटवां एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए प्रयोग की गयी सामग्री का नमूना 180° के कोण से मोड़ा जाएगा और बहुत नजदीकी से हथौड़ा मारा जाएगा । जिससे नमूना टूटेगा नहीं या उसपर दरार का चिह्न नहीं पड़ेगा । ऐसे मामलों में जहां शर्त के बारे में विशेष रूप से अनुबंध हो वहां मोड़ परीक्षण किसी राष्ट्रीय मानक के नवीनतम विवरण के अनुसार किया जाएगा । ऐसे ढलवां बर्तनों तथा पिटवां बर्तनों पर जिनकी चद्दर की मोटाई 2.6 मि०मी० (12 एस डब्ल्यू जी) से अधिक है मोड़ परीक्षण लागू नहीं होगा ।

4.3 सीसा तथा तांबा अंश परीक्षण—बर्तनों के विनिर्माण के लिए प्रयोग की गयी सामग्री में सीसा अंश 0.05% से अधिक नहीं होगा तांबा अंश 0.2% से अधिक नहीं होगा ।

4.4. ऐनोडिक लेप का मोटाई परीक्षण—बर्तन पर ऐनोडिक लेप की मोटाई जब मानक निरावृत पद्धति द्वारा निर्धारित की गई हो आई० एस० 1868 : 1968 (या इसके नवीनतम विवरण) के अनुसार 5 माइक्रोन से कम नहीं होगी । यह परीक्षण केवल एनोड किए गए बर्तनों पर लागू होगा ।

4.5 बर्तन या हैंडल के स्थायी विकृति को दर्शाए बिना सामान्य प्रयोग की अवस्था में बर्तन पर पानी क्षमता के भार के तीन गुणा के बराबर बर्तन में भार को उठाने के लिए हैंडल पर्याप्त सुदृढ होंगे ।

5. **चिह्नांकन**

जब तक विदेशी क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबन्ध न किया गया हो बर्तनों के तल पर विनिर्माता का नाम व्यापार चिह्न या पहचान चिह्न सुपाठ्य और इस रीति से चिह्नांकित किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि चिह्न का निशान दूसरी तरफ दिखाई न दे ।

6.0 **नमूना लेना तथा अनुरूपता की कसौटी**

6.1 प्रत्येक परेषण के निरीक्षण के लिए नमूना लेना तथा अनुरूपता के लिए कसौटी नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे ।

6.2 किसी भी परेषण में एक ही सामग्री तथा डिजाइन के सभी बर्तनों को आकार का ध्यान रखे बिना एक साथ इकठ्ठा करके एक लॉट बनाया जाएगा किन्तु विनाशकारी परीक्षण में सामग्री के एक ही बैच से विनिर्मित सभी प्रकार और आकार के बर्तन इकठ्ठा करके एक लॉट बनाया जाएगा ।

सारणी

लॉट आकार	नमूना आकार		दोषों की अनुमेय संख्या	
	खंड 2.0, 3.0, 5.0, 6.0 तथा खंड 41 के लिए	उपखंड 4.2, 4.3, 4.4, तथा 4.5 के लिए	स्तम्भ 2 के लिए	स्तम्भ 2 के ख के लिए
क	ख			
15 तक	2	1	0	
16 से 25	3	1	0	
26 से 100	5	1	0	
101 से 150	8	2	0	
151 से 300	13	2	0	
301 से 500	20	3	1	
501 से 1000	32	3	2	
1001 से 3000	50	4	3	
3001 से ऊपर	80	5	5	

[सं० 6(3)/79-नि० नि० तथा नि०उ०]

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2439.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Aluminium Utensils to quality control and inspection prior to their export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 14th July, 1979, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2472 dated the 14th July, 1979;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public likely to be affected thereby on the 18th July, 1979;

And whereas objections and suggestions were invited from the public on or before the 8th September 1979;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby:

(1) notifies that Aluminium Utensils shall be subjected to quality control and inspection prior to export;

((2) specifies the type of inspection in accordance with the Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules 1980 as the type of quality control and inspection which would be applied to such aluminium utensils prior to export;

(3) recognises—

(a) relevant Indian or any other National Standard;

(b) the specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between the foreign buyer and the exporter subject to a minimum specifications set out in Annexure I to this Order ; and

(c) the contractual specifications as agreed upon between the foreign buyer and the exporter for such export contracts as were entered into immediately prior to the publication of this Order in the Official Gazette and thereafter exported within a span of sixty days from the said date; as the standard specifications for such aluminium utensils.

(4) Prohibits the export in the course of international trade, of any such aluminium utensils unless the same are either accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignments of aluminium utensils satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy or affixed with a seal or mark recognised by the Central Government under Section 8 of the said Act.

2. Nothing in the Order shall apply to :—

(a) Such consignments as might have already left the premises of the manufacturer or exporter concerned immediately prior to the date of publication of this Order in the Official Gazette; and

(b) the export by land, sea or air of bona fide samples of aluminium utensils to prospective buyers.

3. In this Order "Aluminium Utensils" shall mean any aluminium were manufactured from aluminium or its alloy, wrought or cast, which can be used for eating, drinking, cooking, serving or storing of food or drinks including water and similiar other purposes and does not include Pressure Cookers and such other appliances.

4. The Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

ANNEXURE I

[See para (3)(c)]

MINIMUM SPECIFICATION FOR ALUMINIUM UTENSILS

1.0 Material

1.1 Aluminium content of wrought or cast aluminium utensils shall be not less than 99.0 per cent unless otherwise permitted in any of the relevant Indian Standard Specification on wrought or cast utensils.

1.2 Chemical composition for wrought or cast aluminium alloy utensils shall be as agreed upon in the export contract between the foreign buyer and the exporter. In the absence of any such specific stipulation, the material shall conform to the latest issue of the relevant Indian or any other national standard.

1.3 The thickness of the utensils shall be subject to agreement between the foreign buyer and the exporter in the absence of any specific stipulation in the export contract, the finished thicknes of the utensils shall conform to the relevant Indian standard or any other national standard.

1.4 For aluminium utensils fitted with handles— handles when fitted, shall be of aluminium or other suitable non-inflammable material not detrimental to health when contacted with food items.

2.0 Shapes and Dimensions

The shapes and dimensions of utensils shall be subject to agreement between the foreign buyer and the exporter. The following tolerances or those mentioned in the relevant Indian Standard on general engineering tolerances shall be applicable for the dimensions :—

Over	Upto and including	Tolerance
mm	mm	mm
—	30	±1
30	100	±2
100	200	±3
200	—	±5

3.0 Workmanship and Finish

Edges of the utensils shall not be left sharp. They shall be finished bright all over unless otherwise stipulated by the foreign buyer. Finished utensils shall be free from cracks, wrinkles, spills, wavy surfaces, burrs, distortion, dents, scratches, pittings, deep tool marks and other surface defects including casting defects like blow holes etc.

4.0 Test

4.1 Water leakage test—Utensils shall not leak when filled with water to the brim.

4.2 Bend test—A sample of material used for wrought aluminium utensils shall be bent through an angle 180 degree and hammered close whereupon the sample shall not fracture or show signs of cracking. In case where the condition is specifically stipulated, bend test shall be done in accordance with the provisions of the latest version of any national standard No bend test shall be applicable for cast utensils and wrought utensils having a thickness of sheet greater than 2.6 mm (12 SWG).

4.3 Lead and copper content test—Lead contents of the material used for manufacture of the utensils shall not exceed 0.05 per cent and copper shall not exceed 0.2 per cent.

4.4 Anodic coating thickness test—Anodic coating thickness on the utensils when determined by a standard stripping methods according to IS : 1868 : 1968 (or its latest version) shall be not less than 5 microns. This test shall be applicable only for anodized utensils.

4.5 Handles shall be sufficiently strong to support a weight in the utensils equivalent to three times the weight of the water capacity of the utensil in the position of normal use without visible permanent deformation of the handles or utensil.

5. **Marking**

Unless otherwise stipulated by the foreign buyer, utensils shall be legibly marked at the bottom with the manufacturer's name, trade mark or identification mark in such a manner as to ensure that the impression of the marking shall not show up on the other side.

6.0 **Sampling and criteria for conformity**

6.1 Sampling for inspection of each consignment and the criteria for conformity shall be in accordance with the Table given below.

6.2 In any consignment, all the utensils of the same material and design irrespective of size shall be grouped together to constitute a lot except for destructive test where all the types and sizes manufactured from the same batch of material shall be grouped together to constitute a lot.

TABLE

Lot Size	Sample Size		Permissible number of defectives	
	For clauses 2.0, 3.0, 5.0, 6.0 and sub-clause 4.1	For sub-clauses 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5	For A of Col. 2	For B of Col. 2.
	A	B		
Upto 15	2	1	0	
16 to 25	3	1	0	
26 to 100	5	1	0	
101 to 150	8	2	0	
151 to 300	13	2	0	
301 to 500	20	3	1	
501 to 1000	32	3	2	
1001 to 3000	50	4	3	
3001 and above	80	5	5	

[No. 6(3)/79-EI&EP]

का० आ० 2440 :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एल्यूमिनियम के बर्तन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ।

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ।

(ग) "एल्यूमिनियम के बर्तनों" से एल्यूमिनियम के बर्तन या इनकी मिश्रित धातु पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम से विनिर्मित कोई बर्तन जो खाने, पीने, पकाने, परोसने य भोजन या पानी सहित पेय तथा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए भंडारकरण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिनमें प्रेशर कुकर तथा ऐसे अन्य उपकरण सम्मलित नहीं हैं ।

3. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण :—(1) क्वालिटी नियंत्रण :—निर्यात के लिए आशयित एल्यूमिनियम के बर्तनों का क्वालिटी नियंत्रण इस दृष्टि से किया जाएगा कि वे इससे उपाबद्ध अनुसूची I में दिए गए नियंत्रण के स्तरों के साथ विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं, अर्थात् :—

(i) क्रय की गई सामग्री तथा घटक नियंत्रण

(क) प्रयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों के गुण-धर्मों को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा तथा आने वाले लाटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण करते हुए विनिर्माता क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा तथा आने वाले लाटों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण के पर्याप्त साधन रखेगा ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो प्रदायकर्ता का परीक्षण या निरीक्षण प्रमाणपत्र होगा जिस में क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि की जाएगी जिस दशा में उक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाणपत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए विनिर्माता कालिक जांच (अर्थात् एक ही माल के ही प्रदायकर्ता के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक तीन मास में एक बार) करेगा या क्रय की गयी सामग्री या घटकों का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या परीक्षण गृह में या किसी अन्य प्रयोगशाला में नियमित रूप से निरीक्षण या परीक्षण किया जाएगा ।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना लेना लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत माल या घटकों को पृथक करने के लिए तथा अस्वीकृत माल या घटकों के व्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) ऊपर विनिर्दिष्ट नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख विनिर्माता द्वारा नियमित तथा व्यवस्थित ढंग से रखे जाएंगे ।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माता विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए व्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपस्कर उपकरण और साधनों की पर्याप्त सुविधाएँ होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता पर्याप्त अभिलेख रखेगा ।

(iii) उत्पाद नियंत्रण

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो स्वयं अपनी पर्याप्त सुविधाएं होंगी या उसकी

पहुंच वहाँ तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हों।

i) सुसंगत भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानक विनिर्देश को;

(ii) इससे उपाबद्ध अनुसूची II में दिए गए न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए निर्यात-कर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा के सहमत विनिर्देशों को निर्यात कर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को;

(iii) ऐसी निर्यात संविद के लिए निर्यात-कर्त्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच सहमत संविदात्मक विनिर्देशों को जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से दुरस्त पूर्व किए गए थे तथा उसके पश्चात् उक्त तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निर्यात किए गए ।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लेना (जहाँ कहीं अपेक्षित हो) लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(ग) किए गए परीक्षणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा यथोचित अभिलेख नियमित रूप से रखे जाएंगे ।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण

(क) विनिर्माता, उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करने के लिए व्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) उत्पाद को भंडारीकरण तथा अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा ।

(v) मौसम संबंधी नियंत्रण

उत्पादन तथा निरीक्षण में प्रयुक्त मापकों और उपकरणों की कालिक जांच या अंशशोधन किया जाएगा और विनिर्माता द्वारा वृत कार्ड के रूप में अभिलेख रखें जाएंगे ।

(vi) पैकिंग नियंत्रण

विनिर्माता निर्यात किए जाने वाले पैकेजों के लिए व्यौरेवार पैकिंग विनिर्देश बनाएगा तथा उनका पूर्णतया पालन करेगा ताकि निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके—

(क) पैकेज की फिनिश अच्छी तरह से की जाएगी तथा देखने में सुन्दर होगा ।

(ख) पैकेज की भीतरी वस्तुओं को इस प्रकार से पैक किया जाएगा कि वे निम्नलिखित परीक्षणों को सहन कर सकें ।

(i) निपात परीक्षण (सिर भार) के लिए कुल भार केवल 37 किलोग्राम तक एक पैकेज 190 सें० मी० की ऊंचाई से एक बार सबसे बड़ी समतल सतह पर, एक बार सबसे लम्बे किनारे पर तथा एक बार इसमें किसी भी किनारे पर गिराया जाएगा ।

(ख) रोलिंग परीक्षण कुल भार केवल 500 किलो ग्राम तक रोलिंग पैकेज इसके किसी भी ओर छह मीटर आगे की तरफ तथा छह मीटर पीछे की तरफ या बारह मीटर एक ही दिशा में लुढ़काया जाएगा ।

(ग) जल फुहार परीक्षण—पैकेज के प्रत्येक डिजाइन के लिए पैकेज के जल फुहार में जो अकस्मात आई मानसून मौछार के समतुल्य हो पांच मिन्ट तक रखा जाएगा ।

निरीक्षण

(2) निर्यात के लिए आशयित एल्यूमीनियम के बर्तनों को निरीक्षण इससे संलग्न अनुसूची II के अनुसार उन परेषणों में से नमूना लेकर किया जाएगा जिनका इस दृष्टि से निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा कि क्या परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

4. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित एल्यूमिनियम के बर्तनों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची III में दिए गए हैं कि वे या तो :—

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण अभ्यासों का प्रयोग किया गया है :

या

(ख) नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार किए गए निरीक्षण के आधार पर और नियम 3 के उपनियम (vi) के अधीन अधिकथित के अनुसार पैकिंग नियंत्रण पर अपेक्षाओं के आधार पर :

या

(ग) दोनों द्वारा ।

5. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1)(क) एल्यूमिनियम के बर्तनों का परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की लिखित सूचना किसी भी अभिकरण को देगा तथा ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा देगा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों के परेषण या तो नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण परिभाषों का प्रयोग करते हुए—बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं । तथा परेषण प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं या। निर्यात संविदा में वर्णित विनिर्देशों की घोषणा सभी तकनीकी विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए देगा जिससे कि अभिकरण नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार निरीक्षण कर सके ।

(ख) निर्यातकर्ता उसी समय प्रत्येक सूचना की एक प्रति परिषद् के निकटतम कार्यालय को देगा । परिषद् के कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं :—

मुख्य कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' (सातवीं मंजिल), 14/1- बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001.
क्षेत्रीय कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चैम्बर्स (चौथी मंजिल), 113, महर्षि. कार्वे रोड, मुम्बई-400004। निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, एरनाकुलम, कोचिन-682011 निर्यात निरीक्षण परिषद्, म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, 3, सरस्वती मार्ग, करौल बाग, नयी दिल्ली-1100005 ।

(2) निर्यात कर्ता अभिकरण को परेषण पर लगाए गए पहचान चिन्ह भी देगा ।

(3) उप-नियम (i) के अंतर्गत प्रत्येक सूचना तथा घोषणा निर्यात कर्ता के परिसर से या विनिर्माता के परिसर से परेषण भेजे जाने से कम कम सात दिन पूर्व अभिकरण के कार्यालय में पहुँचेगी ।

(4)(क) उपनियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण नियम 4 के अधीन तथा उपबंधित के अनुसार किए गए निरीक्षण तथा इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किया गाये अनुदेश, यदि कोई हो, के आधार पर अपना यह समाधान कर लेने पर कि परेषण का विनिर्माण इस पर लागू मानक विनिर्देशों के अनुसार किया गया है सात दिनों के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहाँ अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित देगा ।

(ख) ऐसे मामलों के सिवाय जहां निर्यातकर्ता स्वयं एल्यूमिनियम के बर्तनों का विनिर्माता है तथा निरीक्षण नियम 4 के उपखंड (क) या (ग) के उपबन्धों के अनुसार किया गया है अन्य सभी मामलों में निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अभिकरण तत्काल यह सुनिश्चित करने के लिए परेषण के पैकजों को इस ढंग से सीलबंद करेगा कि सीलबंद माल के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण को अभिकरण द्वारा सीलबंद नहीं किया जाएगा, तथापि ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

6. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का निरीक्षण :

(क) विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा ।

या

(ख) उस परिसर पर किया जाएगा जहाँ निर्यातकर्ता एल्यूमिनियम के बर्तनों का परेषण निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है ;

परन्तु यह तब जब कि वहाँ जाँच तथा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक पचास रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए के लिए पचास पैसे की दर से फीस प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को दी जाएगी ।

8. अपील :—(1) नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के अपील पैनल को अपील कर सकता है ।

(2) पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटाई जाएगी ।

अनुसूची–1

(नियम 3 देखिए)

क्र० सं०	परीक्षण/ निरीक्षण विशेषताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	लॉट आकार/ आवृत्ति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	सामग्री				
(क)	रसायनिक	मानक विनिर्देशों के अनुसार	एक	कच्चे माल के प्रत्येक कास्ट	उत्पादक के प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थन किया जाए इन विशेषताओं का सत्यापन पांच परेषणों में कम से कम एक बार किया जाएगा
(ख)	यांत्रिक गुण	यथोक्त	एक	एक ही प्रकार और आकार के उत्पाद का प्रत्येक बैच के लिए पहला आफ नमूना और उसके बाद प्रत्येक प्रकार की हर पचासवीं सं०	
2.	प्रक्रिया नियंत्रण				
(क)	कार्य कौशल तथा परिसाधन	यथोक्त	प्रत्येक		
(ख)	विताएं	यथोक्त	एक		
3.	ऐनोडीकरण, यदि लागू हो				
(क)	फिनिश	यथोक्त	प्रत्येक	एक ही प्रकार तथा आकार के उत्पाद का प्रत्येक बैच	
(ख)	लेप की मोटाई	यथोक्त	एक	यथोक्त	
(ग)	अन्य कोई परीक्षण	यथोक्त	एक		
4.	पैकिंग नियंत्रण				
(1)	निपात परीक्षण	यथोक्त	एक	प्रत्येक परेषण	
(2)	रोलिंग परीक्षण	यथोक्त	एक	यथोक्त	
(3)	जल फुहार परीक्षण	यथोक्त	एक	पैकेज का प्रत्येक डिजाइन	

अनुसूची 2

[नियम 3 (i) (iii) (ii) देखिए]

एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए न्यूनतम विनिर्देश

1.0 सामग्री

1.1 पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम के बर्तनों की एल्यूमिनियम की मात्रा 99.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी जब तक कि पिटवां या ढलवां बर्तनों पर किसी भी सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देश में अनुज्ञा नहीं दी गयी हो ।

1.2 पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बर्तनों के लिए रसायनिक मिश्रण निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा में हुई सहमति के अनुसार होगा किसी भी ऐसे विशिष्ट अनुबंध के न होने पर सामग्री ऐसे किसी भी मानक के अनुरूप होगी जो नवीनतम हों ।

1.3 बर्तनों की मोटाई निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच हुए करार के अधीन होगी । निर्यात संविदा में किसी विशिष्ट अनुबंध के न

होने पर संबंधित बर्तनों की फिनिश की हुई मोटाई भारतीय मानक या अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगी।

1.4 हैन्डल लगे एल्यूमिनियम के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों में जब हैन्डल लगाए जाएं, तो वे एल्यूमिनियम के या अज्वलनशील सामग्री के होंगे। खाने की वस्तुओं के साथ सम्पर्क में आने पर हानिकारक नहीं होंगे।

2.0 आकार और विमाएं

बर्तनों के आकार और विमाएं निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच हुए करार के अधीन होंगे। निम्नलिखित सहायताएं या वे जो साधारण इंजीनियरी सहायताओं पर सुसंगत भारतीय मानक में निर्दिष्ट हैं विमाओं के लिए लागू होंगी :—

से अधिक	तक तथा सहित	सहायता
मि०मी०	मि०मी०	मि०मी०
—	30	±1
30	100	±2
100	200	±3
200	—	±5

3.0 कार्य कौशल तथा फिनिश

बर्तनों के किनारे तेज नहीं होंगे। उनकी फिनिश चारों तरफ से चमकीली होगी जब तक कि विदेशी क्रेता द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो। परिरूपित बर्तन दरारों, सिलवटों, गिरावटों लहरदार सतह, विकृतियों, गर्तों, खरोचों, गड्ढों औजार के गहरे निशानों तथा अन्य सतही दोषों जैसे ढलवां दोष जिसमें प्रहार से हुए छिद्र जैसे ढलवां दोष भी हैं से मुक्त होंगे।

4.0 परीक्षण

4.1 पानी रिसने का परीक्षण बर्तन में किनारे तक पानी भरा जाएगा तो वह कहीं से रिसना नहीं चाहिए।

4.2 मोड़ परीक्षण—पिटवां एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए प्रयोग की गयी सामग्री का नमूना 180° कोण से मोड़ा जाएगा और बहुत नजदीकी से हथौड़ा मारा जाएगा जिससे नमूना टूटेगा नहीं या उस पर दरार का चिन्ह नहीं पड़ेगा। ऐसे मामलों में जहां शर्त के बारे में विशेष रूप से अनुबंध है वहां मोड़ परीक्षण किसी राष्ट्रीय मानक के नवीनतम विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऐसे ढलवां तथा पिटवां बर्तनों पर जिनकी चद्दर की मोटाई 2.6 मि०मि० (12 एस डब्ल्यू जी) से अधिक है, मोड़ परीक्षण लागू नहीं होगा।

4.3 सीसा तथा तांबा अंश परीक्षण—बर्तनों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री में सीसा 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा तांबा 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4.4 ऐनोडिक लेप का मोटाई परीक्षण—बर्तन पर ऐनोडिक लेप की मोटाई जब मानक सिरावृत पद्धति द्वारा निर्धारित की गई हो आई एस 1868: 1968 (या इसके नवीनतम विवरण) के अनुसार 5 माइक्रोन से कम नहीं होगी। यह परीक्षण केवल ऐनोड किए गए बर्तनों पर लागू होगा।

4.5 बर्तन या हैंडल की स्थायी विकृति को दर्शाए बिना सामान्य प्रयोग की अवस्था में बर्तन पर पानी क्षमता के भार के तीन गुणा के बराबर बर्तन में भार को उठाने के लिए हैंडल पर्याप्त सुदृढ़ होंगे।

5. चिन्हांकन

जब तक विदेशी क्रेता द्वारा अन्यथा अनुबंध न किया गया हो तो बर्तनों के तल पर विनिर्माता का नाम, व्यापार चिन्ह या पहचान चिन्ह सुपाठ्य और इस रीति से चिन्हांकित किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि चिन्ह का निशान दूसरी तरफ दिखाई न दे।

6.0 नमूना लेना तथा अनुरूपता के लिए कसौटी

6.1 प्रत्येक परेषण के निरीक्षण के लिए नमूना लेना तथा अनुरूपता के लिए कसौटी नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे।

6.2 किसी भी परेषण में एक ही सामग्री और डिजाइन के सभी बर्तनों को आकार का ध्यान रखे बिना एक साथ इकट्ठा करके एक लॉट बनाया जाएगा। किन्तु विनाशकारी परीक्षण में सामग्री के एक ही बैच से विनिर्मित सभी प्रकार और आकार के बर्तन इकट्ठा करके एक लॉट बनाया जाएगा।

सारणी

लॉट आकार	नमूना आकार		दोषों की अनुज्ञेय संख्या	
	खंड 2.0, 3.0, 5.0, 6.0 तथा उपखंड 4.1 के लिए	उपखंड 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, के लिए	स्तम्भ 2 के क के लिए	स्तम्भ 2 के ख के लिए
	क	ख		
15 तक	2	1	0	
16 से 25	3	1	0	
26 से 100	5	1	0	
101 से 150	8	2	0	
151 से 300	13	2	0	
301 से 500	20	3	1	
501 से 1000	32	3	2	
1001 से 3000	50	4	3	
3001 से ऊपर	80	5	5	

अनुसूची-3

(नियम 4 देखिए)

अधिनियम की धारा 6 के अधीन एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए मान्य विनिर्देश

(क) सुसंगत भारतीय या कोई अन्य राष्ट्रीय मानक विनिर्देश।

(ख) अनुसूची ii में उल्लिखित न्यूनतम विनिर्देश के अधीन रहते हुए निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा के सहमत विनिर्देशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों,

(ग) ऐसी निर्यात संविदाओं के लिए निर्यातकर्ता तथा विदेशी क्रेता के बीच सहमत संविदात्मक विनिर्देश जो राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन से तुरन्त पूर्व उसके पश्चात् उक्त तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर निर्यात किए गए थे।

[सं० 6(3)/79-नि० नि० तथा नि० उ०]

S.O. 2440.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act ;

(c) "Aluminium Utensils" shall mean any aluminium ware manufactured from aluminium or its alloy, wrought or cast, which can be used for eating drinking, cooking, serving or storing of food or drinks including water and similar other purpose and does not include Pressure Cookers and Such other appliances.

3. Quality Control and Inspection.—(1) Quality Control : The quality control of the aluminium utensils intended for export shall be done with a view to see that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act by effecting the following controls at different stages of manufacture together with the levels of control as given in the Schedule I annexed hereto, namely :—

(i) Boughtout Materials and components Control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and shall have adequate means of inspection or testing to ensure conformity of the incoming lots.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specification, in which case occasional checks (that is to say once in each quarter of the year for the same supplier of the same materials) shall be conducted by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates or the purchased materials or components shall be regularly inspected or tested either in a loboratory in the factory or in some other laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on a recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejcted materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the abovementioned control shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control :

(a) Detailed process specification shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipment, instrumentation and facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of veryfying the controls exercise during the process of manufacture.

(iii) Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities elsewhere to test the product as per the following specifications recognised under section 6 of the Act :—

*(i) the relevant Indian or any othtr National Standard specification ;

*(ii) the specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between the foreign buyers and the exporter subject to the minimum specifications as set out in Schedule II annexed hereto.

*(iii) the contractual specification as agreed upon between the foreign buyer and the exporter for such export contracts as were entered into immediately prior to the publication of this order in the official Gazette and thereafter exported within a span of sixty days from the said date.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(iv) Preservation Control :

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The product shall be well preserved both during storage and transist.

(v) Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards by the manufacturer.

(vi) Packing Control.—The manufacturer shall lay down a detailed packing specification for export packages and shall strictly adhere to the same, so that the following requirements are met :—

(a) The packages shall be well finished and have a good appearance.

(b) Inner contents of the package shall be so packed as to withstand the following tests :

(A) Drop test (for head loads upto 37 kgs. gross weight only)—One package shall be dropped from a height of 190 cms. once on the largest flat surface, once on the largest edge and once no any corner of its own.

(B) Rolling test (upto 500 kgs. gross weight only)—

One package shall be subjected to rolling on its sides either six metres forward and six metres backward or twelve metres in one direction only.

(C) Water spray test (for each design of package)—The package shall be exposed against a water spray equivalent to a sudden monsoon shower for five minutes.

(2) Inspection.—The inspection of Aluminium utensils meant for export shall be done by drawing samples as per Schedule II annexed hereto from the consignments for carrying out examinations and testing of the same with a view to see that the consignment conforms to the standards specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Basis of Inspection.—Inspection of Aluminium utensils intended for export shall be carried out witha view to see that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act which are reproduced in Schedule III appended to these rules either :—

(a) by ensuring that during the process of manufacture the quality control drills as specified in sub-rule (1) of rule 3 have been exercised ;

OR

(b) on the basis of inspecion carried out in accordance with sub-rule (2) of rule 3 and the requirements on Packing Control as laid down under sub-rule (vi) of rule 3 ;

OR

(c) by both.

5. Procedure of Inspection.—(1) (a) Any exporter intending to export a consignment of Aluminium untnsils shall give an intimation in writing to any one of the agencies of his intention so to do, and submit along with such inumation a declaration, either that the consignment of Aluminium utensils has been or is being manufactured by exercising quality control measures as per control referred to under sub-rule (1) of rule 3 and that the consignment conforms to the standard specification recognised for the purpose ; or, of the specifications stipulated in the export contract giving details of all the technical characterstics to enable the agency to carry out inspection in accordance with sub-rule (2) of rule 3.

(b) The exporter shall at the same time endorse a copy of each intimation to the nearest office of the Councils.

The address of the Council offices are as under :—

Head Office :

Export Inspection Council,
World Trade Centre (7th floor),
14|1B, Ezra Street,
Calcutta-700 001.

Regional Offices :

1. Export Inspection Council,
Aman Chambers, 4th floor,
113, M. Karve Road,
Bombay-400 004.

2. Export Inspection Council,
Manohar Building,
Mahatama Gandhi Road,
Ernakulam.
Cochin-682011.

3. Export Inspection Council,
Municipal Market Building,
3, Saraswati Marg,
Karol Bagh,
New Delhi-110005.

(2) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the agency not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, or exporter's premises.

(4)(a) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1), the agency on satisfying itself on the basis of inspection carried out as provided for under rule 4 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard, that the consignment has been manufactured according to the standard specification applicable to it within seven days shall issue a certificate declaring the consignment of Aluminium utnsils as exportworthy ;

Provided that where the agency is not satisfied it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(b) Except in cases where the exporter is himself the manufacturer of the consignment of Aluminium utensils and is the inspections is carried out according to the provisions of sub-clause (a) or (c) or rule 4, in all other cases, after completion of inspection the agency shall immediately seal the packages of the consignment in a manner so as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment, may not be sealed by the agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

6. Place of Inspection.—Inspection of Aluminium utensils for the purpose of these rules shall be carried out :

(a) at the premises of the manufacturer,

OR

(b) at the premises at which the consignment of Aluminium utensils is offered for inspection by the exporter provided adequate facilities for the purpose of inspection and testing exist therein.

7. Inspection fee.—A fee at the rate of fifty paise for one hundred rupees of the free on board value of the consignment subject to a minimum of rupees fifty for each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under these rules.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 5, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal prefer an appeal to an Appellate Panel consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of Panel shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

[See Rule 3 (1)]

Sl. No.	Test/Inspection characteristics	Requirements	No. of samples to be tested	Lot/size/ frequency	Remarks
1.	Material				
	(i) Chemical	As per standard specifications	One	For each case/heat of raw material	Whenever supported by producer's certificates, those characteristics shall be verified atleast once in five consignments.
	(ii) Mechanical properties				
2.	Process Control				
	(i) Workmanship and finish	-do-	Each	Each batch of production of one type of size	
	(ii) Dimensions	-do-	One	First-off sample and then every fifty nos. of each type and size.	
3.	Anodizing, if Applicable				
	(a) Finish	-do-	Each	Each batch of production of one type and size	
	(b) Thickness of coating	-do-	One	-do-	
	(c) Any other test	-do-	One	-do-	
4.	Packing Control				
	(i) Drop test	-do-	One	Each Consignment	
	(ii) Rolling test	-do-	One	-do-	
	(iii) Mater spraying test	-do-	One	Each design of package.	

SCHEDULE II

(See rule 3(1)(iii)(ii))

MINIMUM SPECIFICATION FOR ALUMINIUM UTENSILS

1.0 Material

1.1 Aluminium content of wrought or cast aluminium utensils shall not be less than 99.0 per cent, unless otherwise permitted by the relevant Indian Standard specification on wrought or cast utensils.

1.2 Chemical composition for wrought or cast aluminium alloy utensils shall be as agreed upon in the export contract between the foreign buyer and the exporter. In the absence of any such specific stipulation, the material shall conform to the latest issue of the relevant Indian or any other national standard.

1.3 The thickness of the utensils shall be subject to agreement between the foreign buyer and the exporter. In the absence of any specific stipulation in the export contract, the finished thickness of the utensils shall conform to the relevant Indian standard or any other national standard.

1.4 For aluminium utensils fitted with handles—handles when fitted, shall be of aluminium or other suitable non-inflammable material not detrimental to health when contacted with food items.

2.0 Shapes and Dimensions

The shapes and dimensions of utensils shall be subject to agreement between the foreign buyer and the exporter. The following tolerances or those mentioned in the relevant Indian Standard on general engineering tolerances shall be applicable for the dimensions :—

OVER	UPTO AND INCLUDING	TOLERANCE
mm	mm	mm
—	30	± 1
30	100	± 2
100	200	± 3
200	—	± 5

3.0 Workmanship and Finish

Edges of the utensils shall not be left sharp. They shall be finished bright all over unless otherwise stipulated by the foreign buyer. Finished utensils shall be free from cracks, wrinkles, spills, wavy surfaces, burrs, distortion, dents, scratches, pittings deep tools marks and other surface defects including casting defects like blow holes etc.

4.0 Test

4.1 Water leakage test—Utensils shall not leak when filled with water to the brim.

4.2 Bend test—A sample of material used for wrought aluminium utensil shall be bent through an angle 180° and hammered close, whereupon the sample shall not fracture or show signs of cracking. In case where the condition is specifically stipulated, bend test shall be done in accordance with the provisions of the latest version of any national standard. No bend test shall be applicable for cast utensil and wrought utensils having a thickness of sheet greater than 2.6mm (12 SWG).

4.3 Lead and cooper content test—Lead contents of the material used for manufacture of the utensils shall not exceed 0.05 per cent and copper shall not exceed 0.2 per cent.

4.4 Anodic coating thickness test—Anodic coating thickness on the utensil when determined by a standard stripping method according to IS 1868 : 1968 (or its latest version) shall be not less than 5 microns. This test shall be applicable only for anodized utensils.

4.5 Handles shall be sufficiently strong to support a weight in the utensils equivalent to three times the weight of the water capacity of the utensils in the position of normal use without visible permanent deformation of the handle or utensil.

5.0 Marking

Unless otherwise stipulated by the foreign buyer, utensils shall be legibly marked at the bottom with the manufacturer's name, trade mark or identification mark in such a manner as to ensure that the impression of the marking shall not show up on the other side.

6.0 Sampling and criteria for conformity

6.1 Sampling for inspection of each consignment and the criteria for conformity shall be in accordance with the Table given below.

6.2 In any consignment, all the utensils of the same material and design irrespective of size shall be grouped together to constitute a lot except for destructive test where all the types and sizes manufactured from the same batch of material shall be grouped together to constitute a lot.

TABLE

Lot Size	Sample size			Permissible number of defectives.	
	For clauses 2.0, 3.0, 5.0, 6.0 and sub-clause 4.1	For sub-clauses 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5		For A of Col. 2	For B of Col. 2.
		A	B		
Upto 15	2	1		0	
16 to 25	3	1		0	
26 to 100	5	1		0	
101 to 150	8	2		0	
151 to 300	13	2		0	
301 to 500	20	3		1	
501 to 1000	32	3		2	
1001 to 3000	50	4		3	
3001 and above	80	5		5	

SCHEDULE III

(See rule 4)

SPECIFICATIONS RECOGNISED FOR ALUMINIUM UTENSILS UNDER SECTION 6 OF THE ACT

(a) The relevant Indian or any other National Standard specification.

(b) The specifications declared by the exporter to be agreed specifications of the export contract between the foreign buyer and the exporter subject to the minimum specification as set out in Schedule II.

(c) The contractual specifications as agreed upon between the foreign buyer and the exporter for such export contracts as where entered into immediately prior to the publication of this Order in the Official Gazette and thereafter exported within a span of sixty days from the said date.

[No. 6(3)/79-EI&EP]

का० आ० 2441:—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार एल्यूमिनियम के बर्तनों के संबंध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4056 तारीख 22 दिसम्बर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-ii, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 22 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित किया ।

और सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, 11 फरवरी, 1980 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 जनवरी, 1980 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एल्यूमिनियम के बर्तनों के संबंध में भारतीय मान

संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह को यह द्योतक करने के प्रयोजन के लिए मान्यता देती है कि जहां एल्यूमिनियम के बर्तनों पर ऐसे चिन्ह चिपकाए जाते है, वे उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में "एल्यूमिनियम के बर्तनों" से एल्यूमिनियम या इसकी मिश्र धातु से पिटवां या ढलवां एल्यूमिनियम से विनिर्मित कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन अभिप्रेत है, जो खाने-पीने, भोजन के परोसने या भंडारीकरण या पानी सहित पेय तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें प्रेशर कुकर तथा ऐसे अन्य उपकरण सम्मिलित नहीं हैं ।

[सं० 6(3)/79-नि०सि० तथा नि०उ०]
सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 2441.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by the section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963) published a proposal to recognise the Indian Standard Institution Certification Mark in relation of Aluminium utensils as required by sub-rule (2) or rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Civil Supplies S.O. No. F|H 4056 dated the 22nd December 1979;

And whereas the objections and suggestions were invited till the 11th February, 1980 from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public 21st January, 1980;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the Indian Standards Institution Certification Mark with respect to Aluminium utensils for the purpose of denoting that where Aluminium utensils are affixed with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under clause (c) of section 6 of the said Act.

Explanation.—In this notification 'Aluminium utensils' shall mean any Aluminium ware manufactured from Aluminium or its alloy, wrought or cast, which can be used for eating, drinking, cooking, serving or storing of food or drinks including water and similar other purposes and does not include pressure cookers and such other appliances.

[No. 6(3)/79-EI&EP]
C. B. KUKRETI, Jt. Director

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1980-08-27

का०आ० 2442—जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में दिए गए हैं उनका अतिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिए गए विशिष्ट उत्पादों पर मुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 7 और 8 में बताए अनुसार पुनरीक्षित किया गया है । मुहर लगाने की पुनरीक्षित शुल्क 1979-07-01 से लागू होगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र संख्या का संदर्भ	अधि० सं० का सन्दर्भ	उत्पाद	विशिष्ट की IS : संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1961-12-16	एस ओ 2941 दिनांक 1961-12-07	प्लाईवुड की चाय की पेटियों की पट्टियां	IS : 10 (भाग 3)-1974 प्लाईवुड की चाय की पेटियों की विशिष्ट भाग 3 पट्टियां (चौथा पुनरीक्षण)	12 पट्टियों का एक सेट	1 1/2 पैसे
2.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-04-03	एस ओ 1468 दिनांक 1970-08-12	अप्रबलित पनारीदार और अर्ध पनारीदार ऐस्बेस्टास सीमेन्ट चद्दरें	IS : 459-1970 अप्रबलित पनारीदार और अर्ध पनारीदार ऐस्बेस्टस सीमेन्ट की चद्दरों की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	1. 30 पैसे प्रति इकाई पहली 10,000 इकाइयों के लिए, 2. 20 पैसे प्रति इकाई 10001वीं इकाई और आगे की इकाइयों के लिए ।
3.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1970-06-06	एस ओ 2020 दिनांक 1970-05-22	सीमेन्ट परीक्षण के लिए घन सांचे	IS : 516-1959 कंक्रीट सामर्थ्य की परीक्षण पद्धतियां	एक अदद	75 पैसे
4.	उद्योग मंत्रालय	भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-02-11	एस ओ 466 दिनांक 1967-01-27	वायुयान के लिए मध्यम सामर्थ्य प्लाईवुड	IS : 709-1974 वायुयान के लिए मध्यम सामर्थ्य की प्लाईवुड की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	10मी²	50 पैसे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1960-01-23	एस ओ 198 दिनांक 1960-01-13	शौचालयों तथा मूत्रालयों के लिए फ्लश की टंकियां (वाल्व रहित साइफन नुमा)	IS : 774-1971 शौचालयों और मूत्रालयों के लिए फ्लश की टंकियों (वाल्व रहित साइफन नुमा) की विशिष्टि	एक ग्रदद	1. 75 पैसे प्रति इकाई पहली 10,000 इकाइयों के लिए और 2. 50 पैसे प्रति इकाई 10001वीं इकाई और उससे अधिक के लिए
6	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1970-10-03	एस ओ 3249 दिनांक 1970-09-07	कार्बन अर्दन केयर के टाइल	IS . 777-1970 कांचाभ अर्दनकेयर के टाइलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 ग्रदद	1. 5 पैसे प्रति इकाई पहली 50,000 इकाइयों के लिए 2. 3 पैसे प्रति इकाई 50001वीं इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए।
7	उद्योग मंत्रालय	भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-02-11	एस ओ 466 दिनांक 1967-01-27	कंक्रीट प्रबलन के लिए सख्त खिंचे इस्पात के तारों की जाली	IS . 1566-1967 कंक्रीट प्रबलन के लिए सख्त खिंचे इस्पात के तारों की जालियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 3.00
8.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-12-22	एस ओ 3817 दिनांक 1962-12-10	जलसह बनाने तथा छेद भरने के लिए बिटुमिनी मसाले	IS : 1580-1969 जलसह बनाने तथा छेद भरने के लिए बिटुमिनी मसालों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 2.50
9	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-12-22	एस ओ 3817 दिनांक 1964-12-10	कंक्रीट में जोड़ बन्द करने के लिए गर्म लगने वाला मसाला	IS : 1834-1961 कंक्रीट में जोड़ बन्द करने के लिए गर्म लगाने वाले मसाले की विशिष्टि	एक मीटरी टन	रु० 5.00
10.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1969-12-26	एस ओ 4321 दिनांक 1964-12-16	कंक्रीट में बढ़ाव जोड़ के लिए पूर्व निर्मित फिलर लोचदार और अवहिर्वेधित (बिटुमेन मिश्रित तन्तु)	IS 1838-1961 कंक्रीट में बढ़ाव जोड़ के लिए पूर्व निर्मित फिलर, लोचदार और अवहिर्वेधित (बिटुमेन मिश्रित तन्तु) की विशिष्टि	एक मी²	20 पैसे
11.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-10-08	एस ओ 3014 दिनांक 1966-09-27	नल से बर्तनों में पानी भरने के लिए अल्प घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन पाइप	IS . 3076-1968 नल से बर्तनों में पानी भरने के लिए अल्प घनत्व वाले पोलीइथाइलीन पाइपों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक कि०ग्रा०	2 पैसे
12.	औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-04-24	एस ओ 1677 दिनांक 1971-03-31	सामान्य उपयोग के लिए वेल्डकृत इस्पात के तार की जालियां	IS : 4948-1974 सामान्य उपयोग के लिए वेल्डकृत इस्पात के तार की जालियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 5.00
13.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-12-04	एस ओ 5282 दिनांक 1971-11-11	लाशालनिए परीक्षण में उपयोग के लिए उपकरण	IS : 5514-1969 लाशालनिए परीक्षण में उपयोग के लिए उपकरणों की विशिष्टि	एक ग्रदद	75 पैसे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-12-04	एस ओ 5285 दिनांक 1971-11-11	चल बहाव वाले वायु पारगम्यता उपकरण (ब्लेन टाइप)	IS : 5516-1969 चल-बहाव वाले वायु पारगम्यता उपकरण (ब्लेन टाइप) की विशिष्ट	एक प्रवर	रु० 1.50

[सं० सी एन डी/13 : 10]

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 27th August, 1980

S.O. 2442.—In supersession of the notifications, deails of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various product referred in to Col 5 and 6 have revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1979-07-01:

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Ministry	Reference to the Govt. of India Gazette No.	Reference to Notification No.	Product	IS: No. & Title of the Specification	Unit	Marking fee per unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ministry of Commerce and Industry.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1961-12-16	S.O. 2941 dated 1961-12-07	Plywood tea-chest battens.	IS : 10 (Part III)—1974 Specification for plywood tea-chests: Part III Battens. (fourth revision).	One set of 12 Battens	1½ Paise
2.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-04-03	S.O. 1468 dated 1970-08-12	Unreinforced corrugated and semi-corrugated asbestos cement sheets.	IS: 459—1970 Specification for unreinforced corrugated and semi-corrugated asbestos cement sheets (second revision)	One Tonne	(i) 30 Paise per unit for the first 10,000 units and (ii) 20 Paise per unit for the 10001st unit and above.
3.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1970-06-06	S.O. 2020 dated 1970-05-22	Cube moulds for cement testing.	IS: 516—1959 Methods of test for strength of concrete	One piece	75 Paise
4.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 1967-02-11	S.O. 466 dated 1967-01-27	Medium strength aircraft plywood.	IS: 709—1974 Specification for medium strength aircraft plywwod. (first revision).	10 m^3	50 Paise
5.	Ministry of Commerce and Industry.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1960-01-23	S.O. 193 dated 1960-01-13	Flushing cistens for water closets and urinals (valveless siphonic type)	IS: 774—1971 Specification for flushing cisterns for water closets and urinals (valveless siphonic type) (third revision).	One Piece	(i) 75 Paise per unit for the first 10,000 units and (ii) 50 Paise per unit for the 10001st unit and above.
6.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 1970-01-03	S.O. 3249 dated 1970-09-07	Glazed earthenware tiles.	IS: 777—1970 Specification for glazed earthenware tiles. (first revision).	100 Pieces	(i) 5 Paise per unit for the first 50,000 units and (ii) 3 Paise per unit for the 50,001st unit and above.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-02-11	S.O. 466 dated 1967-01-27	Hard-drawn steel wire fabric for concrete reinforcement	IS: 1566—1967 Specification for hard-drawn steel wire fabric for concrete reinforcement. (first revision).	One Tonne	Rs. 3.00
8.	Ministry of Commerce and Industry.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-12-22	S.O. 3817 dated 1962-12-10	Bituminous compounds for waterproofing and caulking purposes.	IS: 1580—1969 Specification for bituminous compounds for waterproofing and caulking purposes. (first revision).	One Tonne	Rs. 2.50
9.	Ministry of Commerce and Industry.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-12-22	S.O. 3817 dated 1964-12-10	Hot applied sealing compounds for joint in concrete.	IS: 1834—1961 Specification for hot applied sealing compounds for joint in concrete.	One Tonne	Rs. 5.00
10.	Ministry of Industry and Supply.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-12-26	S.O. 4321 dated 1964-12-15	Preformed fillers for expansion joint in concrete non-extruding and resilient type (bitumen-impregnated fibre)	IS: 1838—1961 Specification for preformed fillers for expansion joint in concrete non-extruding and resilient type (bitumen-impregnated fibre)	One m^2	20 Paise
11.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-10-08	S.O. 3014 dated 1966-09-27	Low density polyethylene pipes for portable water supplies.	IS: 3076—1968 Specification for low density polyethylene pipes for portable water supplies. (first revision)	One Kg.	2 Paise
12.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-04-24	S.O. 1677 dated 1971-03-31	Welded steel wire fabric for general use.	IS: 4948—1974 Specification for welded steel wire fabric for general use (first revision)	One Tonne	Rs. 5.00
13.	Ministry of Industrial Development.	Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1971-12-04	S.O. 5282 dated 1971-11-11	Apparatus used in 'Le-Chatelier's test	IS: 5514—1969 Specification for apparatus used in 'Le-Chatelier's test	One Piece	75 Paise
14.	Ministry of Industrial Development.	Part-II, Section-3, Sub-section 1971-12-04	S.O. 5285 dated 1971-11-11	Variable flow type air permeability appraratus (Blaine type).	IS: 5516—1969 Specification for variable flow type air permeability apparatus (Baline type)	One piece	Rs. 1.50

[No. CMD/13 : 10]

का०आ० 2443.—निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं, उनके आंशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिए गए विभिन्न उत्पादों से सम्बन्धित मुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 7 और 8 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। मुहर लगाने का पुनरीक्षित शुल्क दिनांक 1977-07-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या का सन्दर्भ	अधिसूचना संख्या का सन्दर्भ	उत्पाद	विशिष्टि की IS संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1969-05-03	एस ओ 1638 दिनांक 1969-04-14	मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोर तार के लिए मृदु इस्पात	IS : 2879-1975 मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोर तार के लिए मृदु इस्पात की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीट्रिक टन	30 पैसे
2.	औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1974-09-07	एस ओ 2290 दिनांक 1974-08-21	फ्लैंज बनाने और दाब कार्य के लिए इस्पात	IS : 3747-1966 फ्लैंज बनाने और दाब कार्य के लिए इस्पात की विशिष्टि	एक मीट्रिक टन	30 पैसे
3.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-12-04	एस ओ 5283 दिनांक 1971-11-11	ठंडी वेल्डित इस्पात की पत्तियां (बक्सों पर जड़ने की)	IS : 5872-1973 ठंडी वेल्डित इस्पात की पत्तियों की (बक्सों पर जड़ने की) विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीट्रिक टन	30 पैसे
4.	,,	भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-10-21	एस ओ 3317 दिनांक 1972-09-25	अल्पदाब गैस सिलिंडरों के उत्पादन के लिए गर्म वेल्डित इस्पात की चद्दरें	IS : 6240-1971 अल्पदाब गैस सिलिंडरों के उत्पादन के लिए गर्म वेल्डित इस्पात की चद्दरों की विशिष्टि	एक मीट्रिक टन	30 पैसे

[संख्या सी एम डी/13 : 10]

S.O. 2443.—In partial modification of the notifications, details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 & 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1977-07-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Ministry	Reference to the Govt. of India Gazette No.	Reference to Notification No.	PRODUCT	IS: No. & Title of the Specification	Unit	Marking Fee per unit
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section 3 Sub-section (ii) dated 1969-05-03	S.O. 1638 dated 1969-04-14	Mild steel for metal arc welding electrode, core wire	IS: 2879—1975 Specification for mild steel for metal arc welding electrode core wire. (second revision)	One Tonne	30 Paise
2.	Ministry of Industrial Development, Science and Technology.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1974-09-07	S.O. 2290 dated 1974-08-21	Steel for flanging and pressing.	IS: 3747—1966 Specification for steel for flanging and pressing.	One Tonne	30 Paise

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Ministry of Industrial Development.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-12-04	S.O. 5283 dated 1971-11-11	Cold rolled steel strips (box strappings).	IS: 5872—1973 Specification for cold rolled steel strips (box strappings) (first revision)	One Tonne	30 Paise
4.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-01-21	S.O. 3317 dated 1972-09-25	Hot-rolled steel sheets for the manufacture of low pressure gas cylinders.	IS: 6240—1971 Specification for hot rolled steel sheets for the manufacture of low pressure gas cylinders.	One Tonne	30 Paise

[No. CMD/13:10]

का० आ० 2444.—जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में दिए गए हैं, उनका आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिए गए विभिन्न उत्पादों पर मुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 7 और 8 में बताए अनुसार पुनरीक्षित किया गया है । मुहर लगाने के पुनरीक्षित शुल्क स्तम्भ 9 में प्रत्येक के सामने दिखाई गई तिथियों से लागू होंगे ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या का संदर्भ	अधिसूचना संख्या का संदर्भ	उत्पाद	विशिष्टि IS : सं० और उसका शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	भाग II खण्ड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1961-09-23	एस०ओ० 2283 दिनांक : 1961-09-13	परिशोधित स्पिरिट	IS 323-1959 परिशोधित स्पिरिट की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1000 लिटर	(1) रु० 5.00 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिए (2) रु० 2.00 प्रति इकाई 1001 वीं इकाई और उससे अधिक के लिए	1978-11-01
2.	औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II खण्ड 3 उपखण्ड ii दिनांक 1967-09-09	एस० ओ 3126 दिनांक 1967-08-23	एसिटिक अम्ल	IS: 695-1975 एसिटिक अम्ल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक कि० ग्रा	10 पैसे	1979-04-01
3.	वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)	,,	,,	स्वचल वाहनों में निलम्बन के लिए पत्तीदार कमानियां	IS : 1135-1973 स्वचल वाहनों में निलम्बन के लिए पत्तीदार कमानियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटर टन	(1) रु० 3.00 प्रति इकाई पहली 1500 इकाइयों के लिए (2) रु० 2.00 प्रति इकाई 1501 वीं से 3000 तक की इकाइयों के लिए, और (3) रु० 1.00 प्रति इकाई 3001 वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1980-05-01
4.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग-: II खंड-3 उपखंड (ii) दिनांक: 1971-12-04	एस०ओ० 5283 दिनांक: 1971-11-11	सामान्य जलसह कैनवस डक और तिरपाल	IS 2089-1972 सामान्य जलसह कैनवस/डक और तिरपाल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 मी	रु० 1.00	1979-12-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	उद्योग मंत्रालय	भाग II खंड-3, उपखंड (ii) दिनांक 1964-07-17 1964-08-01	एस०ओ० 2597 दिनांक	घरेलू प्रेशर कुकर	IS : 2347-1974 घरेलू प्रेशर कुकरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक कुकर	(1) 20 पैसे प्रति इकाई पहली 20,000 इकाइयों के लिए, (2) 10 पैसे प्रति इकाई 20001 वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1979-12-01
6.	औद्योगिक विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	भाग II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1974-01-18 1974-02-02	एस० ओ 305 दिनांक	शल्य चिकित्सा वियोज्य ब्लेड (डार्ड पार्कर नुमा)	IS : 3319-1973 शल्य चिकित्सा के वियोज्य ब्लेड (डार्ड पार्कर नुमा) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	1000 ब्लेड	(1) रु० 3.00 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिए (2) रु० 2.00 प्रति इकाई 1001वीं से 2000 तक की इकाइयों के लिए (3) रु० 1.00 प्रति इकाई 2001 वी और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1979-12-01
7.	औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) दिनांक 1969-06-07	एस०ओ०- 2237 दिनांक 1969-05-20	पारे वाले रक्त-दाब मापी	IS : 3390-1977 पारे वाले रक्तदाबमापी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक यंत्र	(1) 1.00 प्रति इकाई पहली 2000 इकाइयों के लिए, और (2) 50 पैसे प्रति इकाई 2001 वी इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1979-12-01
8.	औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक : 1968-10-19	एस० ओ० 3676 दिनांक 1968-09-25	हेक्सेन खाद्य ग्रेड	IS: 3470-1966 हेक्सेन खाद्य ग्रेड की विशिष्टि	एक किलो लिटर	रु० 1.00	1979-12-01
9.	उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) 1976-11-27	एस०ओ०- 4502 दिनांक 1976-11-05	मेलामीनफार्मेल्डी-हाइड ढलाई सामग्रियां	IS: 3669-1966 मेलामीन फार्मेल्डीहाइड ढलाई सामग्रियों की विशिष्टि	एक मीटरी टन	रु० 10.00	1979-12-01
10.	औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) दिनांक 1968-09-14	एस० ओ० 3149 दिनांक 1968-08-23	दाब वाले क्षैतिज बेलनाकार और क्षैतिज आयताकार भाप (स्टैरिलाइजर) निर्जमिल	IS : 3829-1966 दाबवाले क्षैतिज बेलनाकार और क्षैतिज आयताकार भाप निर्जमिलों की विशिष्टि	एक निर्जमिल	रु० 25.00	1979-12-01
11.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक : 1973-04-07	एस० ओ० 1006 दिनांक 1973-03-22	ओ-क्लोरोऐनिलीन	IS: 4334-1967 ओ-क्लोरोऐनिलीन की विशिष्टि	एक कि० ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01
12	,,	—	--	एम-क्लोरोऐनिलीन	IS: 4335-1967 एम-क्लोरोऐनिलीन की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01
13.	,,	—	--	पी-क्लोरोऐनिलीन	IS: 4336-1967 पी-क्लोरोऐनिलीन की विशिष्टि	एक कि० ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय	भाग II खंड-3 उप-खंड (ii) दिनांक 1969-05-03	एस० ओ० 1638 दिनांक 1969-04-14	उच्च गति निर्जर्मिल	IS: 4510-1968 वाव वाले उच्च गति क्षैतिज बेलनाकार भाप निर्जर्मिल (स्टेरिलाइजर)	एक निर्जर्मिल	रु० 25.00	1979-12-01
15.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II खंड-3, उप-खंड (ii) दिनांक: दिनांक: 1973-03-22 1973-04-07	एस० ओ० 1006 दिनांक:	2,5-डाइक्लोरो-ऐनिलीन	IS : 4526-1968 2,5, डाइक्लोरोऐनिलीन की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01
16.	औद्योगिक विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	भाग-II, खंड 3 उप-खण्ड-(ii) दिनांक दिनांक 1973-08-11 1973-07-26	एस०ओ० 2215	जूता उद्योग के लिए रबड़-आधारित स्थायी चेपक	IS : 4663-1968 जूता उद्योग के लिए रबड़ आधारित स्थायी चेपकों की विशिष्टि	100 लिटर	(1) रु० 2.00 प्रति इकाई पहली 1500 इकाइयों के लिए (2) रु० 1.00 प्रति इकाई 1501 वीं इकाई से 3000 तक की इकाइयों के लिए (3) 50 पैसे प्रति इकाई 3001 वीं इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1979-12-01
17.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग-II, खंड-3, उपखंड (iii) दिनांक दिनांक 1973-03-22 1973-07-07	एस० ओ० 1006	पी-ऐनिसिडीन	IS: 5646-1970 पी ऐनिसिडीन की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01
18.	,,	—	—	पी-टालुइडीन	IS: 5647-1970 पी टालुइडीन की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01
19.	,,	—	—	ओ-टालुइडीन	IS : 5649-1970 ओ.-टालुइडीन की विशिष्टि	एक कि० ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01
20.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय	भाग-II, खंड 3 उपखंड-(ii) दिनांक 1977-12-19 1978-01-14	एस०ओ० 72	निर्धर्षण चूर्ण	IS: 6047-1970 निर्धर्षण चूर्ण की विशिष्टि	एक मीटरी टन	(1) रु० 5.00 प्रति इकाई इकाई पहली 500 इकाइयों के लिए और (2) रु० 2.00 प्रति इकाई 501 वीं और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1978-06-01
21.	उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग-II. खंण्ड-3, उपखंण्ड (ii) दिनांक 1976-1976-11-27 11-05	एस० ओ० 4502	निर्वात रक्त दाब मापी	IS : 7652-1975 निर्वात रक्तदमापी की विशिष्टि	एक अदद	(1) रु० 1.00 प्रति इकाई पहली 2000 इकाइयों के लिए और (2) 50 पैसे प्रति इकाई 2001 वीं इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए	1979-12-01

S.O. 2444.—In partial modification of the notifications, details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the marking fees, pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from the dates shown against each in Col. 9:

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Ministry	Reference to the Govt. of India Gazette No.	Reference to Notification No.	PRODUCT	IS: No. & Title of the Specification	Unit	Marking Fee Per Unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Ministry of Commerce and Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1961-09-23	S.O. 2283 dated 1961-09-13	Rectified spirit	IS: 323—1959 Specification for rectified spirit. (revised)	1000 Litres	(i) Rs. 5.00 per unit for the first 1000 units and (ii) Rs. 2.00 per unit for the 1001st unit and above	1978-11-01
2.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-09-09	S.O. 3126 dated 1967-08-24	Acetic acid	IS: 695—1975 Specification for acetic acid (second revision)	One Kg	10 Paise	1979-04-01
3.	Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Deptt. of Civil Supplies & Cooperation)	..	..	Leaf spring for automobile suspension	IS:1135—1973 Specification for leaf spring for automobile suspension (second revision)	One Tonne	(i) Rs. 3.00 per unit for the first 1500 units; (ii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st to 3000 units and (iii) Re. 1.00 per unit for the 3001st unit and above	1980-05-01
4.	Ministry of Industrial Development.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-12-04	S.O. 5283 dated 1971-11-11	Common proofed canvas/duck and paulins (tarpaulins)	IS: 2089—1972 Specification for common proofed canvas/duck and paulins (tarpaulins) (first revision)	100m²	Re. 1.00	1979-12-01
5.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-08-01	S.O. 2597 dated 1964-07-17	Domestic pressure cookers	IS: 2347—1974 Specification for domestic pressure cookers. (second revision)	One Cooker	(i) 20 Paise per unit for the first 20000 units and (ii) 10 Paise per unit for the 20001st unit and above	1979-12-01
6.	Ministry of Industrial Development, Science and Technology	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1974-02-02	S.O. 305 dated 1974-01-18	Blades, surgical detachable (Bard Parker type)	IS: 3319—1973 Specification for blades, surgical detachable (Bard Parker type) (first revision)	1000 Blades	(i) Rs. 3.00 per unit for the first 1000 units; (ii) Rs. 2.00 per unit for the 1001st to 2000 units and (iii) Re 1.00 per unit for the 2001st unit and above;	1979-12-01
7.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1969-06-07	S.O. 2237 dated 1969-05-20	Sphygomomanometer mercurial	IS: 3390—1977 Specification for sphygmomanometer mercurial (first revision)	One Meter	(i) Re. 1.00 per unit for the first 2000 units and (ii) 50 Paise per unit for the 2001st unit and above	1979-12-01
8.	Ministry of Industrial, Development and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1968-10-19	S.O. 3676 dated 1968-09-25	Hexane, food grade	IS: 3470—1966 Specification for hexane, food grade	One Kilolitre	Re. 1.00	1979-12-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Ministry of Industry (Deptt. of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-11-27	S.O. 4502 dated 1976-11-05	Melamine formaldehyde moulding materials.	IS: 3669—1966 Specification for melamine formaldehyde moulding materials.	One Tonne	Rs. 10.00	1979-12-01
10.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1968-09-14	S.O. 3149 dated 1968-08-23	Horizontal-cylindrical and horizontal rectangular steam sterilizer, pressure type.	IS: 3829—1966 Specification for horizontal-cylindrical and horizontal rectangular steam sterilizer, pressure type.	One Sterilizer	Rs. 25.00	1979-12-01
11.	Ministry of Industrial Development.	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1973-04-07	S.O. 1006 dated 1973-03-22	O—Chloroaniline.	IS: 4334—1967 Specification for O-Chloroaniline	One Kg	5 Paise	1978-11-01
12.	-do-	-do-	-do-	m-Chloroaniline	IS: 5335—1967 Specification for m—Chloroaniline	One kg	5 Paise	1978-11-01
13.	-do-	-do-	-do-	p—Chloroaniline	IS: 4336—1967 Specification for p—chloroaniline	One kg	5 Paise	1978-11-01
14.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.	Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1969-05-03	S.O. 1638 dated 1969-40-14	High speed sterilizers.	IS: 4510—1968 Specification for horizontal cylinderical high speed steam sterlizers pressure type.	One Sterilizer	Rs. 25.00	1979-12-01
15.	Ministry of Industrial Development.	Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1973-04-07	S.O. 1006 dated 1973-03-22	2, 5—dichloroaniline	IS: 4526—1968 Specification for 2, 5-dichloroaniline.	One kg.	5 Paise	1978-11-01
16.	Ministry of Industrial Development, Science and Technology.	Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1973-08-11	S.O. 2215 dated 1973-07-26	Permanent rubber based adhesives for footwear industry	IS: 4663—1968 Specification for permanent rubber-based adhesives for footwear industry.	100 Litres	(i) Rs. 2.00 per unit for the first 1500 units; (ii) Re. 1.00 per unit for the 1501st to 3000 units and (iii) 50 Paise per unit for the 3001st unit and above.	1979-12-01
17.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1973-04-07	S.O. 1006 dated 1973-03-22	p—anisidine	IS: 5646—1970 Specification for p—anisidine.	One kg	5 Paise	1978-11-01
18.	-do-	-do-	-do-	p—toluidine.	IS: 5647—1970 Specification for p—toluidine.	One kg	5 Paise	1978-11-01
19.	-do-	-do-	-do-	o—Toluidine	IS: 5649—1970 Specification for o—toluidine.	One kg	5 Paise	1978-11-01
20.	Ministry of Civil Supplies and Co-operation.	Part-II, Section-3, Sub-sectin (ii) dated 1978-01-14	S.O. 72 dated 1977-12-19	Scouring powders	IS: 6047—1970 Specification for scouring powders.	One Tonne	(i) Rs. 5.00 per unit for the first 500 units and (ii) Rs. 2.00 per unit for the 501st unit and above.	1978-06-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Ministry of Industry (Deptt. of Industrial Development).	Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 1976-11-27	S.O. 4502 dated 1976-11-05	Sphygmomanometer, aneriod type	IS: 7652—1975 Specification for sphygmomanometer, aneriod type.	One piece	(i) Re 1.00 per unit for the first 2000, units, and (ii) 50 Paise per unit fo the 2001st unit and above.	1979-12-01

[No. CMD/13:10]

का० आ० 2445—निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं, उनके आंशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिए गए विभिन्न उत्पादों से सम्बन्धित मुहर लगाने का शुल्क का स्तम्भ 7 और 8 में उल्लेख के अनुसार पुनरीक्षण किया गया है । मुहर लगाने का पुनरीक्षित शुल्क दिनांक 1979-07-01 से लागू होगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या का संदर्भ	अधिसूचना का संदर्भ	उत्पाद	विशिष्टि की IS : संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खंड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1970-11-14	एस ओ 3702 दिनांक 1970-10-26	सामान्य कार्यों के लिए प्लाईवुड	IS : 303-1975 सामान्य कार्यों के लिए प्लाईवुड की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	10 मी^{2}	25 पैसे
2.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II, खंड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1960-10-29	एस ओ 2607 दिनांक 1960-10-18	लवण कांचाभ स्टोनवेयर के पाइप और फिटिंग	IS : 651-1971 लवण कांचाभ स्टोनवेयर के पाइप और फिटिंग की विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	75 पैसे
3.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खंड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1966-07-09	एस०ओ० 2038 दिनांक 1966-06-30	जहाजरानी (प्लाईवुड)	IS : 710-1976 जहाजरानी प्लाईवुड की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	10 मी^{2}	50 पैसे
4.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1964-05-09	एस०ओ० 1533 दिनांक 1964-04-30	पानी के मीटर (घरेलू टाइप)	IS : 779-1978 पानी के मीटरों (घरेलू टाइप) की विशिष्टि (पांचवां पुनरीक्षण)	एक अदद	(1) 50 पैसे, प्रति इकाई पहली 10000 इकाइयों के लिए (2) 25 पैसे प्रति इकाई 10001वीं इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए
5.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1971-06-19	एस०ओ० 2409 दिनांक 1971-06-10	आग बुझाने के नलके, खड़े स्तम्भ टाइप	IS : 908-1975 आग बुझाने के नलके खड़े स्तम्भ टाइप की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	एक अदद	रु० 3.00
6.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-10-21	एस०ओ० 3317 दिनांक 1972-09-25	स्लूस वाल्व वाले भूमिगत आग बुझाने के नल	IS : 909-1975 स्लूस वाल्व वाले भूमिगत आग बुझाने के नल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक अदद	रु० 3.00
7.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-2 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-01-02	एस०ओ० 56 दिनांक 1970-12-04	लकड़ी के दिलहेदार एवं चिकने किवाड़	IS : 1003 (भाग 1) 1966 लकड़ी के दिलहेदार एवं चिकने किवाड़ों की विशिष्टि भाग 1 किवाड़ (पहला पुनरीक्षण)	1 मी^{2}	25 पैसे

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-05-09	एस०ओ० 1533 दिनांक 1964-04-30	शीत खिचे प्रतिबल मुक्त तार और खिचे तार	1. IS : 1785 (भाग 1) 1966 पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए सादे सकल खिचे इस्पात के तारों की विशिष्ट भाग 1 शीत खिचे प्रतिबल मुक्त तार (पुनरीक्षित) 2. IS : 1785 (भाग 2) 1967 पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए सादे सकल खिचे इस्पात के तारों की विशिष्ट भाग II खिचे तार (पुनरीक्षित)	एक मीट्री टन	रु० 2.00
9.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-05-22	एस०ओ० 2012 दिनांक 1971-04-27	लकड़ी के समतल किवाड़ (कोणीय तथा खोखले कोर वाले) (ऊपर प्लाईवुड के तख्ते लगे)	IS : 2191 (भाग 1)—1973 लकड़ी के समतल किवाड़ों की विशिष्टि (कोणीय तथा खोखले कोरवाले) भाग 1 ऊपर प्लाईवुड के तख्ते लगे (दूसरा पुनरीक्षण)	1 मी० ^{2}	20 पैसे
10.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-04-16	एस०ओ० 1169 दिनांक 1966-03-30	लकड़ी के समतल किवाड़ (ठोस कोर वाले) ऊपर प्लाईवुड के तख्ते लगे	IS : 2202 (भाग 1) 1973 लकड़ी के समतल किवाड़ (ठोस कोर वाले) की विशिष्टि भाग 1 ऊपर प्लाईवुड के तख्ते लगे (दूसरा पुनरीक्षण)	1 मी ^{2}	20 पैसे
11.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-06-24	एस०ओ० 1553 दिनांक 1972-04-21	मूत्रालयों के लिए स्वतः चालित फ्लश की टंकियां	IS : 2326-1970 मूत्रालयों के लिए स्वतः चालित फ्लश की टंकियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक टंकी	(1) 75 पैसे प्रति इकाई पहली 10,000 इकाइयों के लिए, (2) 50 पैसे प्रति इकाई 10001 वीं इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए
12.	उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1975-09-13	एस०ओ० 3068 दिनांक 1975-08-08	पानी के मीटर (राशि टाइप)	IS : 2373—1973 पानी के मीटर (राशि टाइप) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मदद	रु० 3.00
13.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-07-08	एस०ओ० 1632 दिनांक 1972-06-01	(1) लम्बाई के गेज खण्ड 5.2 (ख) के अनुसार (2) मोटाई के गेज खण्ड 4.2 (ख) के अनुसार, और (3) बेलनाकार धातु माप खण्ड 3, 2 (ख) के अनुसार	IS : 2386 (भाग 1 से 3) —1963 कंक्रीट की रोड़ी की परीक्षण पद्धतियां भाग 1 कण आकार आकृति भाग II हानिकर सामग्रियां और कार्बनिक अशुद्धताओं का आकलन भाग 3 आपेक्षिक घनत्व घनत्व, रिक्तियां अवशोषण एवं राशि रूप में लगाना	एक मदद	रु० 2.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-10-07	एस० ओ० 2776 दिनांक 1972-07-25	इस्पात के हथ ठेले एक पहिए वाले	IS : 2431-1963 इस्पात के हथ ठेले (एक पहिया वाले) की विशिष्टि	एक पहिया हथ ठेला	75 पैसे
15.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-02-15	एस०ओ० 542 दिनांक 1964-02-05	अंग्रेजी टट्टियों के लिए प्लास्टिक की सीट और उनके ढक्कन	IS : 2548-1967 अंग्रेजी टट्टियों के लिए लिए प्लास्टिक की सीट और उनके ढक्कन (दूसरा पुनरीक्षण)	एक सदद	(1) 25 पैसे प्रति इकाई पहली 10,000 इकाइयों के लिए, (2) 15 पैसे प्रति इकाई 10001वी इकाई और उससे अधिक इकाइयों के लिए
16.	उद्योग और पूर्ति मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-09-05	एस०ओ० 3007 दिनांक 1964-08-25	सफाई के कार्बाभ उपकरण (कार्बाभ चीनी मिट्टी)	IS : 2556- सफाई के कार्बाभ उपकरण (कार्बाभ चीनी मिट्टी के)	एक मीटरी टन	रु० 2,00
					IS : 2556 (भाग 1)-1974 समान्य अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS: 2556 (भाग 2)—1973 बहाने वाले डब्ल्यू सी की विशिष्ट अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 3)—1973 कब्जमचे वाली टट्टियों की विशिष्ट अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 4)—1972 वाश बेसिन की विशिष्ट अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 5)—1967 प्रयोगशाला सिंकों की विशिष्ट अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 6/अनुभाग 1)—1974 मूत्रदानियों की विशिष्टि अपेक्षाएं अनुभाग 1 वाउल वाली (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 6/अनुभाग 2)-1974 मूत्रदानियों की विशिष्टि अपेक्षाएं अनुभाग 2 हाफ स्टॉल्स मूत्रदानी (दूसरा पुनरीक्षण)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					IS : 2556 (भाग 6/अनु-भाग 3) 1974—मूत्रदानियों की विशिष्ट अपेक्षाएं अनुभाग 3 कदमचे वाली (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 6/अनु-भाग 4)—1974 मूत्र-दानियों की विशिष्ट अपेक्षाएं अनुभाग 4 विभाजन स्लेब (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 6/अनु-भाग 5)—1974 मूत्र-दानियों की विशिष्ट अपेक्षाएं अनुभाग 5 अपशिष्ट फिटिंग वाली (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 6/अनु-भाग 6)-1974 मूत्र-दानियों की विशिष्ट अपेक्षाएं अनुभाग 6 हाफस्टाइल मूत्रदानी के लिए जल प्रसारित (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 1)—1973 अर्ध गोल ना-लियों (चेनेल) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 8)—1973 नीचे बहाने वाली साइफन वार डब्ल्यू सी की वि-शिष्ट अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 9)—1972 बीडेटों की विशिष्ट अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग 10)—1974 पांवदानों की विशिष्ट अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)		
					IS : 2556 (भाग II)—1972 पुहारा रोज की विशिष्टि		
					IS : 2556-(भाग 12)—1973 फर्श के ट्रेपों की विशिष्ट अपेक्षाएं		
					IS : 2556 (भाग 13)—1973 कदमचे वाली टट्टियों के ट्रेपों की विशिष्टि		

1	2	3	4	5	6	7	8
					IS : 2556 (भाग 14)—1974 समेकित कदमचे वाली टट्टियों की विशिष्टि अपेक्षाएं IS : 2556 (भाग 15)-1974 सचित्रिक डब्ल्यू-सी की विशिष्ट अपेक्षाएं ।		
17.	औद्योगिक विकास एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1968-10-19	एस०ओ० 3676 दिनांक 1968-09-25	औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट	IS : 2925–1975 औद्योगिक सुरक्षा हेलमेटों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक हेलमेट	10 पैसे
18.	नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय	भाग II, खंड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-12-08	एस०ओ० 4734 दिनांक 1976-11-25	पी०वी०सी० (विनाइल) एस्बेस्टास फर्श टाइल	IS : 3461–1966 पी० वी० सी० (विनाइल) ऐस्बेस्टास फर्श टाइलों की विशिष्टि	100 मी^{2}	रु० 2.50
19.	औद्योगिक विकास एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खंड-3 उपखंड (ii) दिनांक 1967–10–28	एस०ओ० 3830 दिनांक 1967-10-10	डोरक्लोजर (द्रवनियंत्रित)	IS : 3564–1975 डोर क्लोजरों (द्रवनियंत्रित की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक अवव	30 पैसे
20.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-11-27	एस० ओ० 4503 दिनांक 1976-11-05	स्लूस वाल्वों के सतह बक्स	IS : 3950–1966 स्लूस वाल्वों के सतत बक्स की विशिष्टि	एक पेटी	75 पैसे
21.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-01-02	एस०ओ० 56 दिनांक 1970-12-04	लकड़ी के दरवाजों की खिड़कियों और रोशनदानों के चौखटे	IS : 4021–1976 लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों के चौखटों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मी "	25 पैसे
22.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-10-07	एस०ओ० 2776 दिनांक 1972-07-25	लोहे के हथ ठेले (दो पहियों वाले)	IS : 4484–1964 लोहे के हथठेलों (दो पहिए वालों (की विशिष्टि)	एक हथ ठेला	75 पैसे
23.	"	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-06-24	एस०ओ० 1559 दिनांक 1972-05-09	सप्लाई से पानी भरने के लिए उच्च घनत्व वाले पोलीइथाइलीन पाइप	IS : 4984–1978 पानी की सप्लाई से पानी भरने के लिए उच्च घनत्व वाले पोलीइथालीन पाइपों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक कि०ग्रा०	2 पैसे
24.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय औद्योगिक विकास (विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-01-02	एस०ओ० 55 दिनांक 1970-12-04	सप्लाई से पानी भरने के लिए अनम्य पी० वी०सी० के पोलीइथाइलीन पाइप	IS: 4985–1968 सप्लाई से पानी भरने के लिए अनम्य पी०वी०सी० के पोलीइथाइलीन के पाइपों की विशिष्टि	एक मीटर	2 पैसे

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II' खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-11-27	एस०ओ० 4502 दिनांक 1976-11-05	ढलवां तांबा मिश्रत ट्रेप	IS : 2519. (भाग I) 1969 ढलवां तांबा-मिश्र ट्रेपों की विशिष्टि भाग I "पी" और "एस" ट्रेप	एक अदद	10 पैसे
26.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1972-06-24	एस०ओ० 1554 दिनांक 1972-04-21	बिकर उपकरण	IS : 5513–1962 बिकर उपकरण की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक अदद	रु० 1.50
27.	औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1974 01 26	एस०ओ० 230 दिनांक 1974-01-08	पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट के लिए खांच पड़ तार	IS : 6003–1970 पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट के लिए खांच पड़े तार की विशिष्टि	मीटरी टन	रु० 2.00
28.	उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-11-20	एस० ओ० 4391 दिनांक 1976-1027	कांच रेशे कोल तार डामर और बिट्यूमेन के नमदे	IS : 74–1974 कांच वाले कोलतार डामर और बिटूयूमेन के नमदों की विशिष्टि	100 मीटर	रु० 2.00

[सं० सी० एम० डी०/13/10]
ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

S.O. 2445.—In partial modification of the notifications, details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1979-070-01 :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Ministry	Reference to the Govt. of India Gazette No.	Reference to Notification No.	Product	IS : No. & Title of the specification	Unit	Marking fee per unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1970-11-14	S.O. 3702 dated 1970-10-26	Plywood for general puruposes	IS : 303-1975 Specification for plywood for general purposes (second revision)	$10m^2$	25 Paise
2.	Ministry of Commerce and Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 1960-10-29	S.O. 2607 dated 1960-10-18	Salt glazed stoneware pipes and fittings	IS : 651-1971 Specification for salt glazed stoneware pipes and fittings (third revision)	One Tonne	75 Paise
3.	Ministry of Industry	Part-II, Sectin-3, Sub-section (ii) dated 1966-07-09	S.O. 2038 dated 1966-06-30	Marine plywood	IS : 710-1976 Specification for marine plywood (first revision)	$10m^2$	50 Paise
4.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-05-09	S.O. 1533 dated 1964-04-30	Water meters (domestic type)	IS : 779-1978 Specification for water meters (domestic type) (fifth revision)	One Piece	(i) 50 Paise per unit for the first 10,000 units and (ii) 25 Paise per unit for the 10001st unit and above

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-06-19	S.O. 2409 dated 1971-06-10	Fire hydrant, stand post type	IS : 908-1975 Specification for fire hydrant, stand post type (second revision)	One Piece	Rs. 3.00
6.	Ministry of Industrial Development	Part-II, section-3, Sub-section- (ii) dated 1972-10-21	S. O. 3317 dated 1972-09-25	Underground fire hydrant, sluice-valve type	IS : 909-1975 Specification for underground fire hydrant, sluice-value type (second revision)	One Piece	Rs. 3.00
7.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development)	Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-01-02	S.O. 56 dated 1970-12-04	Timber panlled and glazed shutters	IS : 1003 (Part I)—Specification for timber panelled and glazed shutters : Part I Door shutters (first revision)	One m^2	25 Paise
8.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section dated 1964-05-09	S.O.1533 dated 1964-04-30	Cold drawn stress-relieved wire and as drawn wire	(i) IS: 1785 (Part I—1966 Specification for plain hard drawn (ii) steel wire for prestressed concrete Part I Cold drawn stress-relieved wire (revised) and (ii) IS : 1785 (Part II)—1967 Specification for plain hard drawn steel wire for prestressed concrete : Part II—As drawn wire (revised)	One Tonne	Rs. 2.00
9.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-05-22	S.O.2012 dated 1971-04-27	Wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) plywood face panels	IS : 2191 (Part I)—1973 Specification for wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) : Part I Plywood face panels (second revision)	One m^2	20 Paise
10.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-04-16	S.O.1169 dated 1966-03-30	Wooden flush door shutters (solid core type); plywood face panels	IS : 2202 (Part I)—1973 Specification for wooden flush door shutters (solid core type) : Part I Plywood face panels (second revision)	One m^2	20 Paise
11.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-06-24	S.O.1553 dated 1972-04-21	Automatic flushing cisterns for urinals	IS : 2326-1970 Specification for automatic flushing cisterns for urinals (first revision)	One cistern	(i) 75 Paise per unit for the first 10000 units and (ii) 50 Paise per unit for the 10001 stunit and above
12.	Ministry of Industry and Civil Supplies (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1975-09-13	S.O. 3068 dated 1975-08-08	Water meters (bulk type)	IS : 2373-1973 Specification for water meters (bulk type) (second revision)	One Piece	Rs. 3.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-07-08	S.O. 1632 dated 1972-06-01	(i) Length gauge as per clause 5.2 (b), (ii) Thickness gauge as per clause 4.2 (b) and (iii) Cylindrical metal measure as per clause 3.2 (b)	IS : 2386 (Parts I to III)—1963 Methods of test for aggregates for concrete : Part I Particle size and shape Part II Estimation of deleterious materials and organic impurities Part III Specific gravity, density, voids, absorption and bulking	One Piece	Rs. 2.00
14.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-10-07	S.O. 2776 dated 1972-07-25	Steel wheel barrows (single wheel type)	IS : 2431-1963 Specification for steel wheel barrows (single wheel type)	One wheel-barrow	75 Paise
15.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-02-15	S.O. 542 dated 1964-02-05	Plastic water-closet seats and covers	IS : 2448-1967 Specification for plastic water-closet seats and covers (second revision)	One Piece	(i) 25 Paise per unit for the first 10000 units and (ii) 15 Paise per unit for the 10001st unit and above
16.	Ministry of Industry and Supply	Part-II, Secition-3, Sub-section (ii) dated 1964-09-05	S.O. 3007 dated 1964-08-25	Vitreous sanitary appliances (vitreous china)	IS : 2556 Vitreous sanitary appliances (vitreous china) IS : 2556 (Part I)—1974 General requirements (second revision) IS : 2556 (Part II)—1973 Specific requirements of washdown water closets (second revision) IS : 2556 (Part III)—1973 Specific requirements of squatting pans (second revision) IS : 2556 (Part IV)—1972 Specific requirements of wash basins (second revision) IS : 2556 (Part V)—1967 Specific requirements of laboratory sinks (first revision) IS : 2556 (Part VI/Sec 1)—1974 Specific requirements of urinals, Section 1 Bowl type (Second revision) IS : 2556 (Part VI/Sec 2)—1974 Specific requirements of urinals, Section 2 Half stall urinals (second revision) IS : 2556 (Part VI/Sec 3)—1974 Specific requirements of urinals, Section 3 Squatting plates (second revision) IS : 2556 (Part VI/Sec 4)—1974 Specific requirements of urinals, Section 4 Partition slabs (second revision)	One Tonne	Rs. 2.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					IS : 2556 (Part VI/Sec.5)—1974 Specific requirements of urinals, Section 5 Waste fittings (second revision) IS : 2556 (Part VI/Sec 6)—1974 Specific requirements of urinals, Section 6 Water spreaders for half stall urinals (second revision) IS : 2556 (Part VII)—1973 Specific requirements of half-round channel (second revision) IS : 2556 (Part VIII)—1973 Specific requirements of siphonic wash-down water closets (second revision) IS : 2556 (Part IX)—1972 Specific requirements of bidets (second revision) IS : 2556 (Part V)—1974 Specific requirements of foot rests (second revision) IS : 2556 (Part XI)—1972 Specific requirements for shower rose IS : 2556 (Part XII)—1973 Specific requirements for floor traps IS : 2556 (Part XIII)—1973 Specific requirements of traps for squatting pans IS : 2556 (Part XIV)—1974 Specific requirements of integrated squatting pans IS : 2556 (Part XV)—1974 Specific requirements of universal water closets		
17.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1968-10-19	S.O. 3676 dated 1968-09-25	Industrial safety helmets	IS : 2726-1975 Specification for industrial safety helmets (first revision)	One Helmet	10 Paise
18.	Ministry of Civil Supplies and Co-operation	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-12-08	S.O. 4734 dated 1976-11-25	PVC (vinyl) asbestos floor tiles	IS : 3461-1966 Specification for PVC (vinyl) asbestos floor tiles	100 m^2	Rs. 2.50
19.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-10-28	S.O. 3830 dated 1967-10-10	Door closers (hydraulically regulated)	IS : 3564-1975 Specification for door closers (hydraulically regulated) (second revision)	One Piece	30 Paise
20.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-11-27	S.O. 4503 dated 1976-11-05	Surface boxes for sluiced valves	IS : 3950-1966 Specification for surface boxes for sluice valves	One Box	75 Paise

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-01-02	S.O. 56 dated 1970-12-04	Timber door, window and ventilator frames	IS : 4021-1976 Specification for timber door, window and ventilator frames (first revision)	One m^2	25 Paise
22.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-10-07	S.O. 2776 dated 1972-07-25	Steel wheel barrows (with two wheels)	IS : 4184-1967 Specification for steel wheel-barrows (with two wheels)	One Wheel barrows	75 Paise
23.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-06-24	S.O. 1559 dated 1972-05-09	High density polyethylene pipes for potable water supplies	IS : 4984-1978 Specification for high density polyethylene pipes for potable water supplies (first revision)	One kg	2 Paise
24.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-01-02	S.O. 55 dated 1970-12-04	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies	IS : 4985-1968 Specification for unplasticized PVC pipes for potable water supplies.	One Metre	2 Paise
25.	Ministry of Industry (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-11-27	S.O. 4502 dated 1976-11-05	Cast copper alloys traps	IS : 5219 (Part I)—1969 Specification for cast copper alloys traps : Part I 'P' and 'S' traps	One Piece	10 Paise
26.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1972-06-24	S.O. 1554 dated 1972-04-21	Vicat apparatus	IS : 5513-1976 Specification for vicat apparatus (first revision)	One Piece	Rs. 1.50
27.	Ministry of Industrial Development, Science and Technology	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1974-01-26	S.O. 230 dated 1974-01-08	Indented wire for prestressed concrete	IS : 6003-1970 Specification for indented wire for prestressed concrete	One Tonne	Rs. 2.00
28.	Ministry of Industry (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1976-11-20	S O. 4391 dated 1976-10-27	Glass fibre base coal tar pitch and bitumen felts	IS : 7193-1974 Specification for glass fibre base coal tar pitch and bitumen felts	100 Metres	Rs. 2.50

[No. CMD/13 : 10]
A. P. BANERJI, Addl. Director General

नई दिल्ली, 1980-08-28

का०आ० 2446.—अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में दिए गए हैं, भारतीय मानक संस्था की ओर से यह अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में निर्विष्ट विभिन्न उत्पादों से संबन्धित मुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 7 और 8 में दिए गए वर्णनानुसार पुनरीक्षित किया गया है । मुहर लगाने का पुनरीक्षित शुल्क 1977-07-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम सं०	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या सन्दर्भ	अधिसूचना संख्या का संदर्भ	उत्पाद	विशिष्टि की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग)	भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-27	एस०ओ० 669, दिनांक 1965-02-17	संरचना इस्पात (मानक किस्म)	IS : 226—1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म) की विशिष्टि (पांचवां पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
2.	,,	,,	,,	जस्तेदार इस्पात की चद्दरें (सादी और पनारीदार)	IS : 277—1969 जस्तेदार इस्पात की चद्दरों (सादी और पनारीदार) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग)	भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) दिनांक 1965-08-28	एस०ओ० 2671 दिनांक 1965-08-09	तार एवं टेलीफोन कार्यों के लिए जस्तेदार इस्पात के तार	IS : 279—1962 तार एवं टेलीफोन कार्यों के लिए जस्तेदार इस्पात के तारों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
4.	,,	,,	,,	सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मृदु इस्पात के तार	IS : 280—1972 सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए मृदु इस्पात के तारों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
5	,,	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-17	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-02-17	कंक्रीट प्रबलन के लिए मृदु इस्पात और मध्यम तनाव के सरिये और सख्त खिंचे इस्पात के तार	IS : 432 (भाग 1 और 2) 1966 कंक्रीट प्रबलन के लिए मृदु इस्पात के और मध्यम तनाव इस्पात के सरिये और सख्त खिंचे इस्पात के तारों की विशिष्टि भाग I मृदु इस्पात और मध्यम तनाव इस्पात के सरिये भाग II सख्त खिंचे इस्पात के तार (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
6.	,,	,,	,,	शीत वेल्लित कार्बन इस्पात की चद्दरें	IS : 513—1973 शीत वेल्लित कार्बन इस्पात की चद्दरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
7.	औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-01-30	एस०ओ० 566 दिनांक 1971-01-08	चुम्बकीय परिपथों के लिए नान ओरियंटेड विद्युत इस्पात की चद्दरें	IS : 648—1970 चुम्बकीय परिपथों के लिए नॉन ओरियंटेड विद्युत इस्पात की चद्दरों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
8.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-27	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-02-17	संरचना इस्पात (उच्च तनाव)	IS : 1961—1975 संरचना इस्पात (उच्च तनाव) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
9.	,,	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-03-20	एस०ओ० 896 दिनांक 1965-03-10	गर्म वेल्लित इस्पात की पत्तियां (गांठों वाली)	IS : 1029—1970 गर्म वेल्लित इस्पात की पत्तियां (गांठों वाली) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
10.	,,	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-27	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-02-17	गर्म वेल्लित कार्बन इस्पात की चद्दर और पत्तियां	IS : 1079—1973 गर्म वेल्लित कार्बन इस्पात की चद्दर और पत्ती की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे

1	2	3	4	5	6	7	
11.	उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-10-15	एस०ओ० 3063 दिनांक 1966-10-04	कंक्रीट प्रबलन के लिए गर्म वेल्लित मृदु इस्पात मध्यम तनाव वाले इस्पात एवं उच्च पराभव सामर्थ्य वाले विकृत इस्पात के सरिये	IS : 1139–1966 कंक्रीट प्रबलन के लिए गर्मवेल्लित मृदु इस्पात मध्यम तनाव वाले इस्पात एवं उच्च पराभव सामर्थ्य वाले विकृत इस्पात के सरियों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एक मीटरी टन	30 पैसे
12.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-27	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-02-17	संरचना कार्यों के लिए गर्म वेल्लित इस्पात के रिवेट सरिये (40 मिमी व्यास तक)	IS : 1148–1973 संरचना कार्यों के लिए गर्म वेल्लित इस्पात के रिवेट सरियों (40 मिमी व्यास तक) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
13.	,,	,,	,,	संरचना कार्यों के लिए उच्च तनाव वाले इस्पात के रिवेट सरिये	IS : 1149–1973 संरचना कार्यों के उच्च तनाव वाले इस्पात के रिवेट सरियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
14.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-08-14	एस०ओ० 3020 दिनांक 1971-07-15	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे मरोड़े इस्पात के सरिये	IS : 1786–1966 कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडे मरोड़े इस्पात के सरियों की विशिष्टि	एक मीटरी टन	30 पैसे
15.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग मंत्रालय)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-03-20	एस० ओ० 896 दिनांक 1965-03-10	गढ़ी वस्तुओं के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट ब्लूम, स्लैब और सरिये	IS : 1875–1971 गढ़ी वस्तुओं के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट ब्लूम, स्लैब और सरियों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
16.	,,	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-27	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-02-17	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)	IS : 1977–1975 संरचना इस्पात (साधारण किस्म) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरीटन	30 पैसे
17.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1969-12-27	एस०ओ० 5044 दिनांक 1969-12-15	बॉयलरों के लिए इस्पात के रिवेट एवं रोक छड़ें	IS : 1990–1973 बॉयलरों के लिए इस्पात के रिवेट एवं रोक छड़ों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
18.	औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1969-03-01	एस०ओ० 778 दिनांक 1969-02-19	बॉयलरों के लिए इस्पात के प्लेट	IS : 2002–1962 बॉयलरों के लिए इस्पात के प्लेट की विशिष्टि	एक मीटरी टन	30 पैसे
19.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विकास)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-02-27	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-02-17	संरचना इस्पात (संगलन वेल्डन किस्म)	IS : 2062–1969 संरचना इस्पात (संगलन वेल्डन किस्म) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
20.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-03-10	एस०ओ० 669 दिनांक 1965-03-10	संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में पुनर्बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम और पट्टियां	IS : 2830–1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म) के रूप में पुनर्बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट ब्लूम और पट्टियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
21.	,,	,,		संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनर्बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम और पट्टियां	IS : 2831–1975 संरचना इस्पात (साधारण किस्म) के रूप में पुनर्बेल्लन के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम और पट्टियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	30 पैसे
22.	औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-04-29	एस०ओ० 1535 दिनांक 1967-04-17	इस्पात की चैकर नमूने की प्लेट	IS : 3502–1966 इस्पात की चैकर नमूने की प्लेटों की विशिष्टि	एक मीटरी टन	30 पैसे

[सं० सी० एम० डी०/13 : 10]

New Delhi, the 28th August, 1980

S.O. 2446.—In supersession of the notifications, details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1977-07-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Ministry	Reference to Govt. of India Gazette No.	Reference to Notification No.	Product	IS : No. & Title of the Specification	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)	Part-II Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dt. 1965-02-17	Structural steel (Standard quality)	IS: 226–1975 Specification for structural steel (standard quality) (Fifth revision)	One Tonne	30 Paise
2.	-do-	-do-	-do-	Galvanized steel sheet (plain and corrugated)	IS: 277–1969 Specification for galvanized steel sheets (plain and corrugated) (second revision)	One Tonne	30 Paise
3.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-08-28	S.O. 2671 dated 1965-08-09	Galvanized steel wire for telegraph and telephone purposes	IS: 279–1972 Specification for galvanized steel wire for telegraph and telephone purposes. (second revision)	One Tonne	30 Paise
4.	-do-	-do-	-do-	Mild steel wire for general engineering purposes	IS: 280–1972 Specification for mild steel wire for general engineering purposes (second revision)	One Tonne	30 Paise

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dated 1965-02-17	Mild steel and medium tensile steel bars and hard-drawn steel wire for concrete-reinforcement	IS: 432 (Parts I and II)—1966 Specification for mild steel and medium tensile steel bars and hard-drawn steel wire for concrete reinforcement Part I Mild steel and medium tensile steel bars (second revision) Part II Hard drawn steel wire (second revision)	One Tonne	30 Paise
6.	-do-	-do-	-do-	Cold rolled carbon steel sheets	IS: 513–1973 Specification for cold rolled carbon steel sheets (second revision)	One Tonne	30 Paise
7.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-01-03	S.O. 566 dated 1971-01-08	Non-oriented electrical steel sheets for magnetic circuits	IS: 648–1970 Specification for non-oriented electrical steel sheets for magnetic circuits (second revision)	One Tonne	30 Paise
8.	Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dated 1965-02-17	Structural steel (high tensile)	IS: 961–1975 Specification for structural steel (high tensile) (second revision)	One Tonne	30 Paise
9.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-03-10	S.O. 896 dated 1965-03-10	Hot rolled steel strips (baling)	IS: 1029–1970 Specification for hot rolled steel strips (baling) (first revision)	One Tonne	30 Paise
10.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dated 1965-02-17	Hot rolled carbon steel sheet and strip	IS: 1079–1973 Specification for hot rolled carbon sheet and strip (third revision)	One Tonne	30 Paise
11.	Ministry of Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-10-15	S.O. 3063 dated 1966-10-04	Hot rolled mild steel, medium tensile steel and high yield strength steel deformed bars for concrete reinforcements	IS: 1139–1966 Specification for hot rolled mild steel, medium tensile steel and high yield strength steel deformed bars for concrete reinforcements (revised)	One Tonne	30 Paise
12.	Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dated 1965-05-17	Hot rolled steel rivet bars (up to 40 mm diameter) for structural purposes	IS: 1148–1973 Specification for hot rolled steel rivet bars (up to 40 mm diameter) for structural purposes (second revision)	One Tonne	30 Paise
13.	-do-	-do-	-do-	High tensile steel rivet bars for structural purposes	IS: 1149–1973 Specification for high tensile steel rivet bars for structural purposes (second revision)	One Tonne	30 Paise
14.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3 Sub-section (ii) dated 1971–08-14	S.O. 320 dated 1971-07-15	Cold twisted steel bars for concrete reinforcement.	IS: 1786–1966 Specification for cold-twisted steel bars for concrete reinforcement.	One Tonne	30 Paise

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-03-20	S.O. 896 dated 1965-03-10	Carbon steel billets blooms, slabs and bars for forgings	IS: 1875-1971 Specification for carbon steel billets, blooms, slabes and bars for forgings (third revision)	One Tonnes	30 Paise
16.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dated 1965-02-17	Structural steel (ordinary quality)	IS: 1977-1975 Specification for structural steel (ordinary quality) (second revision)	One Tonne	30 Paise
17.	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated 1969-12-27	S.O. 5044 dated 1969-12-15	Steel rivet and stay bars for boilers	IS: 1990-1973 Specification for steel rivet and stay bars for boilers (first revision)	One Tonne	30 Paise
18.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1969-03-01	S.O. 778 dated 1969-02-19	Steel plates for boilers	IS: 2002-1962 Specification for steel plates for boilers.	One Tonne	30 Paise
19.	Ministry of Industry and Supply (Department of Industry)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-02-27	S.O. 669 dated 1965-02-17	Structural steel (fusion welding quality)	IS: 2062-1969 Specification for structural steel (fusion welding quality) (first revision)	One Tonne	30 Paise
20.	Ministry of Industry and Supply (Departmet of Industry)	Part-II, Section-2, Sub-section (ii) dated 1965-03-20	S.O. 896 dated 1965-03-10	Carbon steel billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (standard quality)	IS: 2830-1975 Specification for carbon steel billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (standard quality) (first revision)	One Tonne	30 Paise
21.	-do-	-do-	-do-	Carbon steel billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (ordinary quality)	IS: 2831-1975 Specification for carbon steel billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (ordinary quality) (second revision)	One Tonne	30 Paise
22.	Ministry of Industrial Development and Company Affirs (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-04-29	S.O. 1535 dated 1967-04-17	Steel chequered plates	IS: 3502-1966 Specification for steel chequered plates	One Tonne	30 Paise

[No. CMD/13:10]

का० आ० 2447.—जिन अधिसूचनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में दिए गए हैं, उनका अतिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में दिए गए विभिन्न उत्पादों पर मुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 7 और 8 में बताए अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। मुहर लगाने के पुनरीक्षित शुल्क स्तम्भ 9 में प्रत्येक के सामने दिखाई गई तिथियों से लागू होंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	भारत के राजपत्र की संख्या का संदर्भ	अधिसूचना संख्या का संदर्भ	उत्पाद	विशिष्टि की IS संख्या और उसका शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क	लागू होने की तिथि
1.	औद्योगिक विकास एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-08-26	एस ओ 2948 दिनांक 1967-08-14	नाइट्रिक अम्ल	IS: 264-1976 नाइट्रिक अम्ल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक कि०ग्रा०	10 पैसे	1979-04-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	औद्योगिक विकास एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-08-14	एस ओ 2948 दिनांक 1967-08-14	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	IS : 265-1976 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक कि०ग्रा०	10 पैसे	1979-04-01
3.	"	"	"	सल्फ्यूरिक अम्ल	IS : 266-1977 सल्फ्यूरिक अम्ल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक कि०ग्रा०	10 पैसे	1979-04-01
4.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1963-07-20	एस ओ 2039 दिनांक 1963-07-09	तारपीन की गोंद-स्पिरिट (तारपीन का तेल)	IS : 533-1973 तारपीन की गोंद स्पिरिट की विशिष्टि (तारपीन तेल) (पहला पुनरीक्षण)	1000 लिटर	रु० 2.00	1979-12-01
5.	"	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) 1963-02-09	एस ओ 415 दिनांक 1963-01-30	नैफ्थालीन	IS : 539-1974 नैफ्थालीन की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	100 कि०ग्रा०	रु० 5.00	1979-12-01
6.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1963-06-15	एस ओ 1652 दिनांक 1963-06-04	बरोजा (गोंद बरोजा)	IS : 553-1969 बरोजा (गोंद बरोजे की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	(1) रु० 2.00 प्रति इकाई पहली 1000 इकाइयों के लिए और (2) 50 पैसे प्रति इकाई 1001वी इकाई और अगली इकाइयों के लिए	1979-12-01
7.	औद्योगिक विकास एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1971-05-01	एस ओ 1764 दिनांक 1971-04-22	कार्बन टेट्राक्लोराइड	IS : 718-1977 कार्बन टेट्राक्लोराइड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 5.00	1979-12-01
8.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1963-08-10	एस ओ 2031 दिनांक 1963-07-29	पाइरेथम सार	IS : 1051-1973 पाइरेथम सार की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 लिटर	रु० 10.00	1979-09-16
9.	"	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1961-11-11	एस ओ 2649 दिनांक 1961-10-31	कटाई में प्रयुक्त घुलनशील तेल	IS : 1115-1973 कटाई में प्रयुक्त घुलनशील तेल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एक किलो लिटर	रु० 10.00	1978-11-01
10.	"	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1963-09-07	एस ओ 2530 दिनांक 1963-08-27	फिजालीय संचन सामग्रियां	IS : 1300-1966 फिजालीय संचन सामग्रियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एक मीटरी टन	रु० 10.00	1979-12-01
11.	उद्योग एवं पूर्ति मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1964-10-03	एस ओ 3493 दिनांक 1964-09-23	अनुरेखण वस्त्र	IS : 2037-1962 अनुरेखण वस्त्र की विशिष्टि	100 मी^{2}	रु० 1.00	1979-12-01
12.	औद्योगिक विकास मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1973-04-21	एस ओ 1132 दिनांक 1973-04-06	बी-आक्सीनैफ्थाइक अम्ल (बॉन अम्ल)	IS : 3242-1965 बी-आक्सीनैफ्थाइक अम्ल (बॉन अम्ल) की विशिष्टि	एक कि०ग्रा	5 पैसे	1978-11-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	औद्योगिक विकास एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1969-02-15	एस ओ 590 दिनांक 1969-01-30	कपूर तकनीकी	IS : 3584-1966 कपूर तकनीकी की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	(1) 1 पैसा प्रति इकाई पहली 500000 इकाइयों के लिए और (2) 1/2 पैसा प्रति-इकाई 500001 वीं इकाई और इससे अधिक इकाइयों के लिए	1979-12-01
14.	औद्योगिक विकास विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय	भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1974-05-11	एस ओ 1179 दिनांक 1974-04-24	ओ-एनिसाइडीन	IS : 5648-1970 ओ-एनिसाइडीन की विशिष्टि	एक कि०ग्रा०	5 पैसे	1978-11-01

[सं० सी०एम०डी/13 : 10]

ए० पी० बनर्जी, उप महानिदेशक

S. O. 2447.—In supersession of the notifications, details of which are given in Col 1 to 4 of the following schedule, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees, pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 have been revised as mentioned in Col. 7 and 8 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from the dates shown against each in Col. 9.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Ministry	Reference to the Govt. of India Gazette No.	Reference to Notification No.	Product	IS : No. & Title of the Specification	Unit	Marking Fee Per Unit	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3 Sub-section (ii) dated 1967-08-14	S.O. 2948 dated 1967-08-14	Nitric acid	IS : 264—1976 Specification for nitric acid (second revision)	One kg.	10 Paise	1979-04-01
2.	-do-	-do-	-do-	Hydrochloric acid	IS : 265—1976 Specification for hydrochloric acid (second revision)	One kg	10 Paise	1979-04-01
3.	-do-	-do-	-do-	Sulphuric acid	IS : 266—1977 Specification for sulphuric acid (second revision)	One kg	10 Paise	1979-04-01
4.	Ministry of Commerce and Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1963-07-20	S.O. 2039 dated 1963-07-09	Gum spirit of turpentine (oil of turpentine)	IS : 533—1973 Specification for gum spirit of turpentine (oil of turpentine) (first revision)	1000 Litres	Rs. 2.00	1979-12-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Ministry of Commerce and Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1963-02-09	S.O. 415 dated 1963-01-30	Napthalene	IS : 539—1974 Specification for naphthalene (second revision)	100 kg	Rs 5.00	1979-12-01
6.	-do-	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1963-06-15	S.O. 1652 dated 1963-06-04	Rosin (gum rosin)	IS : 553—1969 Specification for rosin (gum rosin) (first revision)	One Tonne	(i) Rs. 2.00 per unit for the first 1000 units and (ii) 50 Paise per unit for the 1001st unit and above	1979-12-01
7.	Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Deptt. of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1971-05-01	S.O. 1764 dated 1971-04-22	Carbon tetrachloride	IS : 718—1977 Specification for carbon tetrachloride (first revision)	One Tonne	Rs. 5.00	1979-12-01
8.	Ministry of Commerce and Industry	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1963-08-10	S.O. 2031 dated 1963-07-29	Pyrethrum extracts	IS : 1051—1973 Specification for pyrethrum extracts (first revision)	100 Litres	Rs. 10.00	1979-09-16
9.	-do-	Part-II Section-3, Sub-section (ii) dated 1961-11-11	S.O. 2649 dated 1961-10-31	Oil cutting, soluble	IS : 1115—1973 Specification for oil cutting, soluble (first revision)	One Kilo Litre	Rs. 10.00	1978-11-01
10.	-do-	Part-II, Section-3 Sub-section (ii) dated 1963-09-07	S.O. 2530 dated 1963-08-27	Phenolic moulding materials	IS : 1300—1966 Specification for phenolic moulding materials (second revision)	One Tonne	Rs. 10.00	1979-12-01
11.	Ministry of Industry and Supply	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1964-10-03	S.O. 3493 dated 1964-09-23	Tracing cloth	IS : 2037—1962 Specification for tracing cloth	$100m^2$	Re 1.00	1979-12-01
12.	Ministry of Industrial Development	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1973-04-21	S.O. 1132 dated 1973-04-06	B-Oxynaphthoic acid (bon acid)	IS : 3242—1965 Specification for B-oxynaphthoic acid (bon acid)	One kg	5 Paise	1978-11-01
13.	Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development)	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1969-02-15	S.O. 590 dated 1969-01-30	Camphor, technical	IS : 3584—1966 Specification for camphor, technical	One kg	(i) One Paise per unit for the first 500000 units and (ii) 1/2 Paise per unit for the 500001st unit and above	1979-12-01
14.	Ministry of Industrial Development, Science and Technology	Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1974-05-11	S.O. 1179 dated 1974-04-24	O—anisidine	IS : 5648—1970 Specification for O—anisidine	One kg	5 Paise	1978-11-01

[No. CMD/13 : 10]

A. P. Banerji, Addl. Director General

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1980

का० आ० 2448.—पेटेन्ट्स अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 31 के खण्ड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा क्रोग्रम के सम्बन्ध में 4 सितम्बर से 6 सितम्बर 1980 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाली तकनोलोजीकल प्रदर्शनी पर उक्त धारा 31 के उपबंधों को लागू करती है ।

[संख्या 8(18)/79-पी०पी०एण्डसी०]

मोहिन्दर सिंह, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 3rd September, 1980

S.O. 2448.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 31 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby extends the provisions of the said section 31 to the Technological Exhibition to be held at Pragati Maidan, New Delhi from 4th September to 6th September, 1980 in connection with CHOGRAM meeting to be held in New Delhi.

[No. 8(18)/79-PP&C]

MOHINDER SINGH, Director

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1980

का० आ० 2449.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यतः इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट प्रक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन प्रक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	प्रक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	मोटा-थावरिया	1924	21-6-75	31-5-79

[सं० 12020/18/80-प्रो]

वि० वि० प्रजापति, गुजरात राज्य के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Petroleum Department)

New Delhi, the 1st September, 1980

S.O. 2449.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mthura

Name of Ministry	Name of Village	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Mota-Thavaria	1924	21-6-75	31-5-79

[No. 12020/18/80-Prod.]

V. V. PRAJAPATI, Competent Authority Under the Act, for Gujarat State.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

का० आ० 2450.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "एम० डी० (जनरल मेडिसिन)", प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (पेथोलाजी)	एम० डी० (पेथीलाजी)
मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)	एम० एस० (जनरल सर्जरी)
डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियो डाइग्नोसिस)	एम० डी० (रेडियो डाइग्नोसिस)
डाक्टर आफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक्स)	एम० डी० (पीडियाट्रिक्स)
डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ	डी० सी० एच०
मास्टर आफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स)	(एम० डी० आर्थोपेडिक्स)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थोपेडिक्स"

2. भोपाल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

*"डाक्टर ऑफ मेडिसिन (सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव	एम० डी० सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन)

*30 अप्रैल, 1981 या इससे पूर्व प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।

3. बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (माइक्रोबायोलाजी) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर ऑफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)	एम० एस० (जनरल सर्जरी)
मास्टर ऑफ सर्जरी (अनाटोमी)	एम० एस० (अनाटोमी)
* डाक्टर आफ मेडिसिन सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन	—एम० डी० (सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन)
* 30 अप्रैल, 1981 या इससे पूर्व प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।	
डाक्टर आफ मेडिसिन (ऐनेस्थीसिआलोजी)	एम० डी० (ऐनेस्थीसिआलोजी)
डिप्लोमा इन ऐनेस्थीसिआलोजी	डी० ए०"

4. बंगलौर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर ऑफ मेडिसिन (फिजीआलोजी)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन क्लिनिकल पेथालोजी	डी० सी० पी०

5. कालीकट विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन आप्थालमालोजी" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाए, अर्थात् :—

"डाक्टर ऑफ मेडिसिन (डर्माटालोजी एण्ड वेनरोलाजी	एम० डी० (डर्माटालोजी एण्ड वेनरोलाजी)
मास्टर ऑफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स)	एम० एस० (आर्थोपेडिक्स)
डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक्स	डी० आर्थोपेडिक्स"

6. दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन लारिंगोलाजी एण्ड ओटोलाजी" प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजिआलाजी)	एम० डी० (फिजिआलाजी)
* डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन	—डी० एच० ई०
* केवल चिकित्सा स्नातकों द्वारा प्राप्त करने पर ।	

7. जम्मू विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डाइग्नोसिस	डी० एम० आर० डी०"

8. जबलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (सर्जरी) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (अनाटोमी)	एम० एस० (अनाटोमी)
डाक्टर आफ मेडिसिन (पेडियोलाजी)	एम० डी० (पेडियोलाजी)

9. बकटिया विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (ई०एन०टी०)	एम० एस० (ई०एन०टी०)
डिप्लोमा इन आप्थलमालोजी	एम० ओ०
* मास्टर आफ सर्जरी (जनरल सर्जरी)	एम० एस० (जनरल सर्जरी)
* 30 अप्रैल, 1981 या इससे पूर्व प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।"	

10. मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन आप्थलमालोजी" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (आल्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनाकालोजी)	एम० डी० (आल्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनाकालोजी)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन)	एम० डी० (सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन)
मास्टर आफ सर्जरी (न्यूरो सर्जरी)	एम० एस० (न्यूरो सर्जरी)

11. महर्षी दयानन्द विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में ("डाक्टर आफ मेडिसिन (ऐनेस्थीसिआलोजी) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियो डाइग्नोसिस)	एम० डी० (रेडियो डाइग्नोसिस)
डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजियोलाजी)	एम० डी० (फिजियोलाजी)
डाक्टर इन आप्थलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन जेनरल डिजीजिज	डी० डी० डी"

12 रोहतक विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में डाक्टर आफ मेडिसिन (मेडिसिन) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (रेडियो डाइग्नोसिस)	एम० डी० (रेडियो डाइग्नोसिस)
डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजियोलाजी)	एम० डी० (फिजिओलाजी)
डिप्लोमा इन आप्थलमिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ओ० एम० एस०
डिप्लोमा इन जेनरल डिजीजिज	डी० डी० डी०"

13. मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ पीडिया ट्रिक्स	एम० डी० (पीडियाट्रिक्स)"

14. नागपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डिप्लोमा इन ट्यूबरक्लोसिस एण्ड चेस्ट डिजीजिज" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

* डाक्टर आफ मेडिसिन (माइक्रोबायोलाजी)	एम० डी० (माइक्रोबायोलाजी)
* 30 अप्रैल, 1981 या इससे पूर्व प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।"	

15 पटना विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (बायोकैमिस्ट्री)" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (अनाटामी)	एम० डी० (अनाटामी)"

16. उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (आटो रिनो लारिंगोलाजी) प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (अनाटामी)	एम० एस० (अनाटामी)
डिप्लोमा इन आप्थलमालोजी	डी० ओ०
डिप्लोमा इन आटो रिनो लारिंगोलाजी	डी० एल० ओ०"

17. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "बेचलर आफ मेडिसिन एण्ड बेचलर आफ सर्जरी" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

* "डाक्टर आफ मेडिसिन (सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन)	एम० डी० (सोशल एण्ड प्रीवेन्टिव मेडिसिन)
* 30 अप्रैल, 1981 या इससे पूर्व प्रदान करने पर यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ।"	

18 राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से संबंधित प्रविष्टियों में "मेम्बरशिप आफ नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिसिन साइंसिस (डर्माटालाजी एण्ड वेनेरिओलाजी" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, अर्थात् :—

"मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईसिस	एम० एन० ए० एम० एस० (न्यूरो सर्जरी)

मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईंसिस (न्यूरोलाजी)	एम० एस० ए० एम० एस० (न्यूरोलाजी)
मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईंसिस (पाडियाट्रिक्स सर्जरी)	एम० एस० ए० एम० एस० (पाडियाट्रिक्स सर्जरी)
मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईंसिस (पेथोलाजी)	एम० एस० ए० एम० एस० (पेथोलाजी)
मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईंसिस (रेडियोरेडी डिजीजिज)	एम० एस० ए० एम० एस० (रेडियोरेडी डिजीजिज)
मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईंसिस (जेनीटो-यूरीनरी-सर्जरी)	एम० एस० ए० एम० एस० (जेनीटोयूरीनरी-सर्जरी)
मेम्बरशिप आफ दी नेशनल ऐकेडमी आफ मेडिकल साईंसिस (कार्डियो-थोरेसिम-सर्जरी)	एम० एस० ए० एम० एस० (कार्डियो-थोरेसिम-सर्जरी)

[सं० वी 11015/2/80 एम ई (पी)].

के० वेणुगोपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2450.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule :—

(i) in the entries relating to Aligarh Muslim University, after the entry "M.D. (General Medicine)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor or Medicine (Pathology)..... .....M.D.(Path.)

Master of Surgery (General Surgery).....M.S. (Gen.Surg.)

Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis)..M.D. (Radio-Diag.)

Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed).

Diploma in Child Health.....D.C.H.

Master of Surgery (Orthopaedics) .....M.S. (Ortho.)

Diploma in Orthopaedics.....O. Orth."

(ii) in the entries relating to Bhopal University, after the entry "Diploma in Orthopaedics", the following entry shall be inserted; namely :—

"Doctor of Medicine (Social & Preventive.....M.D. (Soc. & Prev.)

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on before 30th April, 1981."

(iii) In the entries relating to University of Bombay, after the entry "Doctor of Medicine (Microbiology)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Mater of Surgery (General Surgery)....M.S. (Gen. Surg).

Master of Surgery (Anatomy)..... M.S. (Anat.)

Doctor of Medicine (Social Preventive Medicine).. .....

M. D. (Soc. & Prev. Med.)

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on or before 30th April, 1981.

Doctor of Medicine (Anaesthesiology).... M.D. (Anaes.)

Diploma in Anaesthesiology .....D.A."

(iv) in the entries relating to Bangalore University, after the entry "Doctor of Medicine (Physiology.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Clinical Pathology.....D.C.P."

(v) in the entries relating to Calicut University, after the entry "Diploma in Ophthalmology", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Dermatology and Venerology).... M.D. (Derm. & Ven.)

Master of Surgery (Orthopaedics).....M.S. (Orth.)

Diploma in Orthopaedics.....D. (Orth)"

(vi) in the entries relating to University of Delhi after the entry "Diploma in Laryngology and Otology", the following entries shall be inserted, namely :—

Doctor of Medicine (Physiology).....M.D, (Phy.)

Diploma in Health Education.....D.H.E.

When held by medical graduates only."

(vii) in the entries relating to Jammu University, after the entry "Diploma in Child Health", the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Medical Radio Diagnosis.....D.M.R.D."

(viii) in the entries relating to Jabalpur University, after the entry "Master of Surgery (Surgery), the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anat.)

Doctor of Medicine (Padiology).....M.D. (Padiology).

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on or before 30th April, 1981".

(ix) in the entries relating to Kakatiya University, after the entry "Doctor of Medicine (Genl. Medicine)", the following entries shall be inserted namely :—

"Master of Surgery (E.N.T.).....M.S. (E.N.T.)

Diploma in Ophthalmology.....D.O.

Master of Surgery (General Surgery)..M.S. (Nerro-Surg.)"

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on before 30th April, 1981."

(x) in the entries relating to University of Madras, after the entry "'Diploma in Ophthalmology", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology)..M.D. (Obst. & Gynae.)

Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine).... M. D. (Soc. & Prev. Med.)

Master of Surgery (Neuro-Surgery)..M.S. (Neuro-Surg.)"

(xi) in the entries relating to Maharshi Dayanand University, after the entry "Doctor of Medicine (Anaesthesiology), the following entries shall be inserted namely :—

"Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis)....M.D. (Radio-Diag.)

Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Phy.)

Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery...D.O.M.S.

Diploma in Veneral Diseases.....D.V.D.".

(xii) in the entries relating to Rohtak University, after the entry "Doctor of Medicine (Medicine), the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis).....M.D. (Radio-Diag.)

Doctor of Medicine (Physiology).....M.D. (Phy.)

Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery..... D.O.M.S.

Diploma in Veneral Diseases.....D.V.D."

(xiii) in the entries relating to Mithila University, after the entry "Doctor of Medicine (Forensic Medicine)", the following entry shall inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Paediatrics).....M.D. (Paed.)"

(xiv) in the entries relating to Nagpur University after the entry "Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Microbiology).....M.D. (Micro.)

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on or before 30th April, 1981".

(xv) in the entries relating to Patna University after the entry "Doctor of Medicine (Biochemistry)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy).....M.D. (Anat.)"

(xvi) in the entries relating to Osmania University, after the entry "Master of Surgery (Oto-Rhino-laryngology), the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy).....M.S. (Anat.)
Diploma in Ophthalmology.....D.O.
Diploma in Oto-Rhino-Laryngology.....D.L.O.".

(xvii) in the entries relating to South Gujarat University, after the entry "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Social and Preventive Medicine)... M.D. (Soc. & Prev. Med.)

This qualification shall be a recognised medical qualification when granted on or before 30th April, 1981".

(xviii) in the entries relating to National Board of Examinations, after the entry "Membership of National Academy of Medicine Sciences (Dermatology and Venereology)", the following entries shall be inserted, namely :—

"Membership of the National Academy of Medical Sciences (Neuro-Surgery).....M.N.A.M.S. (Neuro-Surg.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Neurology)... M.N.A.M.S. (Neurology.)

Membership of the National Academy of Medicine Sciences (Paediatrics Surgery).....M.N.A.M.S. (Paed. Surg.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Pathology).....M.N.A.M.S. (Path.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Respiratory Diseases)....M.N.A.M.S. (Resp. Diseases).

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Plastic Surgery)....M.N.A.M.S.S. (Plastic Surg.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Genito-Urinary-Surgery).....M.N.A.M.S. (Genito-Urinary-Surg.)

Membership of the National Academy of Medical Sciences (Cardio-Thoracic-Surgery)....M.N.A.M.S. (Cardio-Thoracic-Surg.)"

[No. V. 11015/2/80-ME(Policy)]

K. VENUGOPAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1980

का०आ० 2451.—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खंड (viiia) के अनुसरण में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 783(E) दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार डा० सन्तोष कुमार सेन गुप्ता, सहायक महानिदेशक (जन स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, को उन राज्य क्षेत्रों के लिए, जिन्हें उक्त अधिनियम लागू होता है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० पी० 15014/7/80-पी०एच० (एफ० एण्ड एन०) पी०एफ०ए०]

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

New Delhi, the 11th September, 1980

S.O. 2451.—In pursuance of clause (viiia) of Section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 783(E) dated 4th December, 1979, the Central Government hereby appoints Dr. Santosh Kumar Sengupta, Assistant Director General (Public Health), Directorate General of Health Services, as the Local (Health) Authority for the territories to which the said Act applies.

[No. P. 15014/7/80-PH(F&N)PFA]

G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

इस्पात और खान मन्त्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1980

का०आ० 2452—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपनी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधिन प्रधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता
1	2
कार्मिक प्रबन्धक, मोसाबानी खानें, पी०ओ० मोसाबानी खान, जिला सिंहभूम, बिहार।	(जो उपाबन्ध में है उसे यहां सम्मिलित करें)

	प्लॉट नं०	थाना नं०	क्षेत्र एकड़ में	दखल का स्वरूप
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. मुसाबनी कालोनी एवं खान स्थल	1335	162	147.30	अर्जित भूमि
	1493	"	6.36	"
उ० निजी जमीन	1494 सड़क	"	0.37	"
द० निजी जमीन	1511	"	28.95	"
पू० निजी जमीन	1334	"	4.40	अनुशात्मक दखल
प० निजी जमीन	1446	"	0.03	"
	1447	"	0.03	"
	1462	"	0.38	"
	1510 खंड	"	0.24	"
	428	163	54.25	अर्जित भूमि
	385	"	0.43	अनुशात्मक दखल
	412	"	28.12	"
	411 खंड	"	10.23	"
	1561	164	0.54	"
	1615	"	24.13	"
	1616	"	0.33	"
	1552 खंड	"	6.25	"
	1557	"	0.30	"
	1558	"	33.49	"
	1559	"	0.07	"
	1560	"	0.90	"
	1612	"	0.12	"
	1613	"	0.17	"
	1614	"	1.15	"
	1712	"	0.35	"
	1	166	31.72	अर्जित भूमि
	21	"	19.10	"
	2525	"	10.15	अनुशात्मक दखल
	33 खंड	"	0.20	अर्जित भूमि
	40	"	42.86	"
	62	"	25.50	"
	95	"	26.60	"
	280	"	0.04	"
	292 सड़क	"	0.16	"
	631	166	0.05	अनुशात्मक दखल
	632	"	0.15	"
	633	"	0.17	"
	635	"	0.04	"
	758	"	82.50	अर्जित भूमि
	857	"	1.15	अनुशात्मक दखल
2. मुसाबनी से बदिया तक लोको ट्रैक उपलब्ध नहीं है।		166	2.2	
उ० मुसाबनी				
द० बदिया				
पू० निजी जमीन				
प० निजी जमीन				
3. पोर्टर शाफ्ट क्षेत्र	934 खंड	166	0.20	अनुशात्मक दखल
उ० निजी जमीन	935 "	"	3.38	"
द० खास जमीन	936 "	"	1.78	"
पू० रोड	2914 "	"	0.27	"
प० खास जमीन	2284 "	"	0.22	"

1	2	3	4	5
4. बिचियन शाफ्ट क्षेत्र	2285 खंड	166	0.03	अनुज्ञात्मक दखल
उ० निजी जमीन				
द० निजी जमीन				
पू० निजी जमीन				
प० रोड़				
5. बचिया अपशिष्ट पारण-क्षेत्र	3953	166	0.63	अनुज्ञात्मक दखल
	2224 खंड	,,	0.10	,,
उ० निजी जमीन				
द० निजी जमीन				
पू० खास जमीन				
प० खास जमीन				
6. एनस शाफ्ट क्षेत्र	2222 खंड	,,	1.30	अनुज्ञात्मक दखल
उ० खास जमीन	2223 ,,	,,	0.15	,,
द० खास जमीन	3390 ,,	,,	5.18	,,
प० रोड़				
7. बालू भराई स्टेशन	2717	,,	9.00	,,
उ० निजी जमीन				
द० खास जमीन				
पू० रोड				
प० निजी जमीन				
8. ईंटा क्षेत्र, पम्प स्टेशन एवं बालू पट्टा क्षेत्र	2909 खंड	,,	6.15	अनुज्ञात्मक दखल
	2920 ,,	,,	1.25	,,
उ० निजी जमीन	2948 ,,	,,	2.40	,,
द० निजी जमीन	2957 ,,	,,	0.05	,,
पू० नदी तट	2958 खंड	166	1.10	अनुज्ञात्मक दखल
प० निजी जमीन	2959 ,,	,,	0.85	,,
	2960 ,,	,,	0.23	,,
	2961 ,,	,,	0.95	,,
	2962 ,,	,,	4.08	,,
	2964 ,,	,,	1.73	,,
	2969 ,,	,,	0.13	,,
	2963 ,,	,,	14.58	,,
	2905 ,,	,,	5.30	,,
	2910 ,,	,,	0.07	,,
	2911 ,,	,,	0.02	,,
	2912 ,,	,,	0.02	,,
	2913 ,,	,,	0.10	,,
	2914 ,,	,,	0.02	,,
	2915 ,,	,,	0.25	,,
	2906 ,,	,,	12.26	,,
	1599 ,,	165	0.77	,,
	1384 ,,	1683	0.47	,,
(पुराना माप-चित्र) नं०	281 ,,	168	5.49	,,
	282 ,,	,,	9.47	,,
	353 ,,	,,	3.70	,,
9. बालू स्टाक एंव बालू पट्टा	1563 ,,	165	0.63	निजी बन्दोबस्ती
	1564 ,,	,,	0.07	,,
	1565	,,	0.29	,,
उ० खास जमीन	1566	,,	1.08	,,
द० नदी तट	1567	,,	0.38	,,
पू० रोड				
प० खास जमीन एवं नदी	1595	,,	0.27	,,

1	2	3	4	5
	1596	165	0.65	निजी बन्दोबस्ती
	1597	,,	0 70	,,
	1598	,,	1.06	,,
	1604 खंड	,,	0.47	,,
	1605	,,	0.52	,,
	1838	,,	0.70	,,
	1599	,,	15.55	अनुज्ञात्मक दखल
10. पुराना प्लॉट नम्बर	1	168	19.57	,,
धोबानी पातन शाफ्ट क्षेत्र	1003	1096	0.96	,,
उ०	1004	,,	0.31	,,
द०	1050	,,	0.03	,,
पू०	1051	,,	0.08	,,
प०	1052 खण्ड	,,	0.76	,,
11. पाथरगोड़ा नं० 2	रोड	1096	0.10	,,
शाफ्ट क्षेत्र	1142 खण्ड	160	0.06	
उ० खास जमीन				
द० खास जमीन				
पू० खास जमीन				
प० खास जमीन				
12. पाथरगोड़ा मुख्य शाफ्ट क्षेत्र	1035	,,	0.05	निजी बन्दोबस्ती
उ० निजी जमीन	1044	,,	0.02	,,
द० निजी जमीन	1045	,,	0.04	,,
पू० निजी जमीन	1048	,,	4.93	अनुज्ञात्मक दखल
प० निजी जमीन	1078	,,	0.16	निजी बन्दोबस्ती
	1079	,,	1.33	अनुज्ञात्मक दखल
	1080 रोड	,,	0.28	निजी बन्दोबस्ती
	1100 खंड	,,	0.06	,,
	1101 ,,	,,	0.02	,,
	1102 ,,	,,	1.17	अनुज्ञात्मक दखल
	1138 ,,	,,	0.87	निजी बन्दोबस्ती
	1139 ,,	,,	0.68	,,
	1140 ,,	,,	0.32	अनुज्ञात्मक दखल
	1156 ,,	,,	0.12	,,
13. पाथरगोड़ा वेंटीलेशन शाफ्ट क्षेत्र	760 ,,	,,	0.27	,,
उ० निजी जमीन	761 ,,	,,	0.23	,,
द० निजी जमीन				
पू० निजी जमीन				
14. प० रोड सुरवा नं० 4 शाफ्ट क्षेत्र	114 ,,	1102	1.73	अनुज्ञात्मक दखल
	115 ,,	,,	0.13	,,
उ० खास जमीन	136 रोड	,,	0.07	,,
द० निजी जमीन	135 खंड	,,	0.07	,,
पू० निजी जमीन	137 ,,	,,	0.13	,,
प० निजी जमीन	138 ,,	,,	0.25	,,
	139 ,,	,,	0.25	,,
	140 ,,	,,	0.10	,,
	141 ,,	,,	1.02	,,
	142 ,,	,,	0.02	,,
15. सुरवा कर्मचारी कालोनी	103 ,,	,,	0.55	,,
उ० खास जमीन	105 ,,	,,	9.84	,,
द० खास जमीन				
पू० खास जमीन				
प० वन भूमि				

1	2	3	4	5
16. सुरदा स्टाफ कालोनी एवं खान स्थल	846 पुराना प्लाट नं०	101	55.18	अनुज्ञात्मक दखल
उ० वन भूमि	314	101	4.80	,,
द० वन भूमि	313	,,	0.07	,,
पू० निजी जमीन	304 खंड रोड	,,	0.20	,,
प० वन भूमि	305	,,	0.55	,,
	306 रोड	,,	0.10	,,
	307	,,	0.23	,,
	277 खंड	,,	2.33	,,
	278	,,	0.05	,,
	279 रोड खंड	,,	0.07	,,
	280	,,	0.35	,,
	281	,,	0.22	,,
	385	,,	0.01	,,
17. चिरकीह शाफ्ट क्षेत्र		1098	1.05	,,
उ० वन भूमि				
द० वन भूमि				
पू० वन भूमि				
प० वन भूमि				

राजपत्र अधिसूचना में समाविष्ट करने के लिये अतिरिक्त भूमि की सूची

1	प्लॉट नं० 2	थाना नं० 3	क्षेत्र एकड़ में 4	दखल का स्वरूप 5
1. मुसाबनी कालोनी एवं खान स्थल	1279 खंड	162	1.54	निजी बन्दोबस्ती
उ० निजी जमीन	1281 खंड	,,	0.23	,,
द० निजी जमीन				
पू० निजी जमीन	1282 खंड	,,	0.22	,,
उ० निजी जमीन	1283 खंड	,,	0.32	,,
	389	163	0.38	,,
2. ईंट क्षेत्र, पम्प स्टेशन एवं बालू पट्टा क्षेत्र	3 खंड	1083	0.42	,,
उ० और द० निजी जमीन				
पू० नदी तट				
प० निजी जमीन				
3. सुरदा नं० 4 शाफ्ट मैगेजीन	वन खंड भू-भाग	1098	1.16	अनुज्ञात्मक दखल
उ०, द०, पू०, एवं प० वन भूमि				
4. सुरदा उत्तर वेंटीलेशन फैन	,,	1098	3.00	,,
उ०,द०,पू० एवं प० वन भूमि				
5. सुरदा स्टाफ कालोनी एवं खान स्थल	273	101	1.65	,,
	276	,,	2.56	,,
उ० खास एवं निजी जमीन	277 खंड	,,	1.18	,,
द० निजी जमीन				
पू० निजी जमीन				
प० निजी जमीन	272 खंड	,,	1.88	,,
6. सुरदा बाजार क्षेत्र	344 खंड	,,	1.83	,,
उ० एवं द० खास जमीन				
पू० निजी जमीन				
प०—पी०डब्ल्यू०डी० रोड				
7. सुरदा उत्पादन शाफ्ट क्षेत्र	606	101	1.10	निजी बन्दोबस्ती
	572	,,	0.57	,,
उ० खास एवं निजी जमीन	573	,,	0.47	,,
द० निजी जमीन	574	,,	0.32	,,
पू०निजी जमीन	576	,,	0.07	,,
प० पी० डब्ल्यू० डी० रोड	577	,,	0.15	,,

1	2	3	4	5
	579	101	0.51	निजी बन्दोबस्ती
	580	,,	1.12	,,
	582	,,	0.32	,,
	584	,,	0.76	,,
	575	,,	0.46	,,
	581	,,	0.09	,,
	583	,,	0.10	,,
	1291	,,		
	603	,,	0.04	,,
	561	,,	0.32	,,
	565	,,	0.57	,,
	567	,,	0.83	,,
	569	,,	1.47	,,
	568	,,	0.06	,,
	657	,,	0.14	,,
	667	,,	0.11	,,
	688	,,	0.18	,,
	689	,,	0.29	,,
	668	,,	0.11	,,
	375 खंड	,,	2.12	अनुज्ञात्मक दखल
	593	,,	0.19	,,
	562	,,	0.38	,,
	590	,,	0.59	,,
	560	,,	3.06	,,
	558	,,	1.48	,,
	557	,,	0.61	,,
	556	,,	1.85	,,
	566	,,	5.04	,,
	672	,,	0.04	,,
	670	,,	0.25	,,
	570	,,	0.17	,,
	571	,,	0.12	,,
	578	,,	0.43	,,
	681	,,	2.17	,,
	687	,,	4.45	,,
	721	,,	2.87	,,
	666	,,	5.65	,,
	661 खंड	,,	0.45	,,
	585	,,	0.52	,,
	619 खंड	,,	33.30	,,
	663	,,	0.07	,,
	664	,,	0.05	,,
	604	,,	0.25	,,
	605	,,	0.53	,,
	134 खंड	,,	1.25	,,
	685	,,	0.24	निजी बन्दोबस्ती
	686	,,	2.49	,,
8. सुरक्षा नगर (टप्उनशिप)क्षेत्र	4	,,	29.50	अनुज्ञात्मक दखल
	153 खंड	,,	12.05	,,
उ० कनकरना नाला	154 ,,	,,	3.62	,,
द० खास एवं निजी जमीन	152	,,	0.80	,,
पू० खास एवं निजी जमीन	155 खंड	,,	0.45	,,
प० कनकरना नाला	136 ,,	,,	0.65	,,
रोड एवं वन भूमि	150 ,,	,,	9.98	,,

	प्लॉट नं०	थाना नं०	क्षेत्र एकड़ में	दखल का स्वरूप
	135 ,,	101	0.30	अनुज्ञात्मक दखल
	618 ,,	,,	0.75	,,
	17	100	5.63	,,
	15 खंड	,,	0.18	,,
	1283 खंड	,,	0.05	,,
	34	,,	56.00	,,
	1281	,,	0.50	,,
	25 खंड	,,	2.50	,,
	236	,,	0.17	,,
	41 खंड	,,	51.10	,,
	40 ,,	,,	7.15	,,
	38	,,	0.31	,,
	1282	,,	0.36	,,
	1368	100	8.93	,,
	1369	,,	3.60	,,
	1367	,,	0.72	,,
	225 खंड	,,	49.95	,,
	237	,,	0.13	,,
9. दक्षिण केन्दाडीह खान	1409 खंड	99	5.00	,,
उ० एवं द० वन भूमि				
पू०—निजी जमीन				
प० वन भूमि				
10. केन्दाडीह आवासीय कालोनी	1233	,,	6.82	,,
	1006 खंड	,,	2.05	,,
उ०,द०,पू० एवं प० खास जमीन				
11. केन्दाडीह खान स्थल	1408 खंड	,,	10.25	,,
	26	,,	9.75	,,
उ० गरगरीया नाला	24	,,	1.25	,,
द० वन एवं निजी जमीन	25	,,	1.65	,,
पू० निजी जमीन	27	,,	1.10	,,
प० वन भूमि	29	,,	0.05	,,
	30	,,	0.10	,,
	127 खंड	,,	0.35	,,
	131	,,	0.75	,,
	132	,,	0.60	,,
	135	,,	0.25	,,
	1112 खंड	,,	2.00	,,
	28	,,	1.66	निजी बन्दोबस्ती
	128	,,	0.28	,,
	1114	,,	0.90	,,
12. केन्दाडीह मैंगेजीन	236 खंड	98	14.63	अनज्ञात्मक दखल
उ० वन भूमि	238	,,	4.50	,,
द० गरगरीया नाला				
पू० खास एवं निजी जमीन				
प० वन भूमि				

[फा० सं० 22/43/79-मेटल-III

जे० ए० चौधरी, निदेशक

MINISTRY OF STEEL & MINES
(Department of Mines)

New Delhi, the 1st September, 1980

S.O. 2452.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government, to be an Estate Officer for the purposes of said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers and duties imposed by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Personnel Manager, Mosaboni Group of Mines, P.O. Mosaboni Mines, Distt : Singhbhum, Bihar.	(Here incorporate what is contained in the Annexure).

ANNEXURE

	Plot No.	Thana No.	Area in acres	Type of occupation
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mosaboni Colony and	1335	162	147.30	Acquired land
Mines site	1493	162	6.36	,,
N. Private land	1494 Road	162	0.37	,,
S. Private land	1511	162	28.95	,,
E. Private land	1334	162	4.40	Permissive possession
W. Private Land	1446	162	0.03	,,
	1447	162	0.03	,,
	1462	162	0.38	,,
	1510 Portion	162	0.24	,,
	428	163	54.25	Acquired land
	385	163	0.43	Permissive possession
	412	163	28.12	,,
	411 Portion	163	10.23	,,
	1561	164	0.54	,,
	1615	164	24.13	,,
	1616	164	0.33	,,
	1552 Portion	164	6.25	,,
	1557	164	0.30	,,
	1558	164	33.49	,,
	1559	164	0.07	,,
	1560	164	0.90	,,
	1612	164	0.12	,,
	1613	164	0.17	,,
	1614	164	1.15	,,
	1712	164	0.35	,,
	1	166	31.72	Acquired land
	21	166	19.10	,,
	2575	166	10.15	Permissive possession
	33 Portion	166	0.20	Acquired land
	40	166	42.86	,,
	62	166	25.50	,,
	95	166	26.60	,,
	280	166	0.04	,,
	292 Road	166	0.16	,,
	631	166	0.05	Permissive possession
	632	166	0.15	,,
	633	166	0.17	,,
	635	166	0.04	,,
	758	166	82.50	Acquired land
	857	166	1.15	Permissive possession
2. Loco Track MSB to Badia not available		166	2.2	
N. Mosaboni				
S. Badia				
E. Private land				
W. Private land				

1	2	3	4	5
3. Porter shaft area	934 Portion	166	0.20	Permissive possession
N. Private land	935 ,,	166	3.38	,,
S. Khas land	936 ,,	166	1.78	,,
E. Road	2914 ,,	166	0.27	,,
W. Khas land	2284 ,,	166	0.22	,,
4. Vivian Shaft area	2285 ,,	166	0.03	,,
N. Private land				
S. Private land				
E. Private land				
W. Road				
5. Badia waste pass area	3953	166	0.63	Permissive possession
	2224 portion	166	0.10	,,
N. Private land				
S. Private land				
E. Khas land				
W. Khas land				
6. Anan Shaft area	2222 portion	166	1.30	Permissive possission
N. Khas land	2223 ,,	166	0.15	,,
S. Khas land	3390 ,,	166	5.18	,,
W. Road				
7. Sand filling station	2717	166	9.00	,,
N. Private land				
S. Khas land				
E. Road				
W. Private land				
8. Brick field, pump station and sand lease area	2909 portion	166	6.15	Permissive possession
	2920 ,,	166	1.25	,,
N. Private land	2948 ,,	166	2.40	,,
S. Private land	2957 ,,	166	0.05	
E. River Bank	2958 Portion	166	1.10	Permissive possession
W. Private land	2959 ,,	166	0.85	,,
	2960 ,,	166	0.23	,,
	2961 ,,	166	0.95	,,
	2962 ,,	166	4.08	,,
	2964 ,,	166	1.73	,,
	2969 ,,	166	0.13	,,
	2963 ,,	166	14.58	,,
	2905 ,,	166	5.30	,,
	910 ,,	166	0.07	,,
	2911 ,,	166	0.02	,,
	2912 ,,	166	0.02	,,
	2913 ,,	166	0.10	,,
	2914 ,,	166	0.02	,,
	2915 ,,	166	0.25	,,
	2906 ,,	166	12.26	,,
	1599 ,,	165	0.77	,,
	1384 ,,	1683	0.47	,,
(Old Plan No.)	281 ,,	168	5.49	,,
	282 ,,	168	9.47	,,
	353 ,,	168	3.70	,,
9. Sand stock and sand lease	1563 ,,	165	0.63	Private settlement
	1564 ,,	165	0.07	,,
	1565	165	0.29	,,
N. Khas land	1566	165	1.08	,,
S. River Bank	1567	165	0.38	,,
E. Road				
W. Khas land and river	1595	165	0.27	,,
	1596	165	0.65	,,
	1597	165	0.70	,,
	1598 ,,	165	1.06	,,
	1604 Portion	165	0.47	,,
	1605	165	0.52	,,
	1838	165	0.70	,,
	1599	165	15.55	Permissive possession

1	2	3	4	5
10. Old Prot No.	1	168	19.57	,,
Dhobani fell shaft area	1003	1096	0.96	,,
N	1004	1096	0 31	,,
S	1050	1096	0 03	,,
E	1051	1096	0.08	,,
W	1052 Portion	1096	0.76	,,
11. PGR No. 2 shaft	Road	1096	0.10	Permissive possession
area	1142 Portion	160	0.06	
N. Khas land				
S. Khas land				
E. Khas land				
W. Khas land				
12. PGR Main Shaft area	1035	160	0.05	Private settlement
N. Private land	1044	160	0.02	,,
S. Private land	1045	160	0.04	,,
E. Private land	1048	160	4.93	Permissive possession
W. Private	1078	160	0.16	Private settlement
	1079	160	1.33	Permissive possession
	1080 Road	160	0.28	Private settlement
	1100 Portion	160	0.06	,,
	1101 ,,	160	0.02	,,
	1102 ,,	160	1.17	Permissive possession
	1138 ,,	160	0.87	Private settlement
	1139 ,,	160	0.68	,,
	1140 ,,	160	0.32	Permissive possession
	1156 ,,	160	0.12	,,
13. PGR Vent. saft area	760 ,,	160	0.27	,,
N. Private land	761 ,,	160	0.23	,,
S. Private land				
E. Private land				
14. W. Road Surda No. 4 shaft area	114 Portion	102	1.73	Permissive possession
	115 ,,	102	0.13	,,
N. Khas land	136 Road	102	0.07	,,
S. Private land	135 Portion	102	0.07	,,
E. Private land	137 ,,	102	0.13	,,
W. Private land	138 ,,	102	0.25	,,
	139 ,,	102	0.25	,,
	140 ,,	102	0.10	,,
	141 ,,	102	1.02	,,
	142 ,,	102	0.02	,,
15. Surda workmen colony	103 ,,	102	0.55	,,
N. Khas land	105 ,,	102	9.84	,,
S. Khas land				
E. Khas land				
W. Forest land				
Surda Staff				
16. Colony & mine site	846 Old plot No.	101	55.18	Permissive possession
N. Forest land	314	101	4.80	,,
S. Forest land	313	101	0.07	,,
E. Private land	304 Portion	101	0.20	,,
	Road			
W. Forest land	305	101	0.55	,,
	306 Road	101	0.10	
	307	101	0.23	,,
	277 Portion	101	2.33	,,
	278	101	0.05	,,
	279 Road portion	101	0.07	,,
	280	101	0.35	,,
	281	101	0,22	,,
	385	101	0.01	,,
17 .Chirudih shaft area		1098	1.05	,,
N. Forest land				
S. Forest land				
E. Forest land				
W. Forest land				

List of additional land to be incorporated in the Gazette Notification

	Plot No.	Thana No.	Area in Acres	Type of Occupation
1. Mosaboni Colony & Mine Site	1279 Portion	162	1.54	Private settlement
N. Private land	1281 Portion	162	0.23	,,
S. Private land				
E. Private land	1282 Portion	162	0.22	,,
N. Private land	1283 Portion	162	0.32	,,
	389	163	0.38	,,
2. Brick Field, Pump Station & Sand Lease Area	3 Portion	1083	0.42	,,
N. & S Private land				
E. River Bank				
W. Private land				
3. Surda No. 4 Shaft Magazine	Forest Block Portion	1098	1.16	Permissive possession
N, S, E, & W Forest land				
4. Surda North Ventilation Fan	Forest Block Portion	1098	3.00	,,
N, S, E & W Forest land				
5. Surda Staff Colony & Mine Site	273	101	1.65	,,
	276	101	2.56	,,
N Khas & Private land	277 Portion	101	1.18	,,
S. Private land				
E. Private land				
W. Forest land	272 Portion	101	1.88	,,
6. Surda Market Area	344 Portion	101	1.83	,,
N & S Khas land				
E. Private land				
W. P.W.D. Road				
7. Surda Production Shaft Area	606	101	1.10	Private settlement
	572	101	0.57	,,
N Khas & Private land	573	101	0.47	,,
S Private land	574	101	0.32	,,
E Private land	576	101	0.07	,,
W PWD Road	577	101	0.15	,,
	579	101	0.51	,,
	580	101	1.12	,,
	582	101	0.32	,,
	584	101	0.76	,,
	575	101	0.46	,,
	581	101	0.09	,,
	583	101	0.10	,,
	1291			
	603	101	0.04	,,
	561	101	0.32	,,
	565	101	0.57	,,
	567	101	0.83	,,
	569	101	1.47	,,
	568	101	0.06	,,
	657	101	0.14	,,
	667	101	0.11	,,
	688	101	0.18	,,
	689	101	0.29	,,
	668	101	0.11	,,
	375 Portion	101	2.12	Permissive possession
	593	101	0.19	,,
	562	101	0.38	,,
	590	101	0.59	,,
	560	101	3.06	,,
	558	101	1.48	,,
	557	101	0.61	,,
	556	101	1.85	,,
	566	101	5.04	,,

	Plot No.	Thana No.	Area in Acres	Type of Occupation
7. Surda Production Shaft Area (Contd.)	672	101	0.04	Permissive possession
	670	101	0.25	,,
	570	101	0.17	,,
	571	101	0.12	,,
	578	101	0.43	,,
	681	101	2.17	,,
	687	101	4.45	,,
	721	101	2.87	,,
	665	101	5.65	,,
	661 Portion	101	0.45	,,
	585	101	0.52	,,
	619 Portion	101	33.30	,,
	663	101	0.07	,,
	664	101	0.05	,,
	604	101	0.25	,,
	605	101	0.53	,,
	134 Portion	101	1.25	,,
	685	101	0.24	Private settlement
	686	101	2.49	,,
8. Surda Township Area	4	101	29.50	Permissive possession
	153 Portion	101	12.05	,,
N Kankarana Nallah	154 Portion	101	3.62	,,
S Khas & Privatel and	152	101	0.80	,,
E Khas & Private land	155 Portion	101	0.45	,,
W Kankarana Nallah	136 ,,	101	0.65	,,
Road & Forest land	150 ,,	101	9.98	,,
	135 ,,	101	0.30	,,
	618 ,,	101	0.75	,,
	17	100	5.63	,,
	15 Portion	100	0.18	,,
	1283 Portion	100	0.05	,,
	34 ,,	100	56.00	,,
	1281	100	0.50	,,
	25 Portion	100	2.50	,,
	236	100	0.17	,,
	41 Portion	100	51.10	,,
	40 ,,	100	7.15	,,
	38	100	0.31	,,
	1282	100	0.36	,,
	1368	100	8.93	,,
	1369	100	3.60	,,
	1367	100	0.72	,,
	225 Portion	100	49.95	,,
	237	100	0.13	,,
9. South Kendadih Mine	1409 Portion	99	5.00	,,
N & S Forest land				
E. Private land				
W. Forest land				
10. Kendadih Housing Colony	1233	99	6.82	,,
	1006 Portion	99	2.05	,,
N, S, E & W Khas land				
11. Kendadih Mine Site	1408 Portion	99	10.25	,,
	26 ,,	99	9.75	,,
N Gadgadiya Nallah	24 ,,	99	1.25	,,
S Forest and Private land	25 ,,	99	1.65	,,
E Private land	27 ,,	99	1.10	,,
W Forest land	29 ,,	99	0.05	,,
	30	99	0.10	,,
	127 Portion	99	0.35	,,
	131	99	0.75	,,
	132	99	0.60	,,
	135	99	0.25	,,

	Plot No.	Thana No.	Area in Acres	Type of Occupation
11. Kendadih Mine Site (Contd.)	1112 Portion	99	2.00	Permissive possetssion
	28	99	1.66	Private settlement
	128	99	0.28	,,
	1114	99	0.90	,,
12. Kendadih Magazine	236 Portion	98	14.63	Permissive possession
N Forest land	238	98	4.50	,,
S Gadgadiya Nallah				
E Khas & Private land				
W Forest land				

[F.No. 22/43/79-MET.III]
J. A. CHOWDHURY, Director

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1980

का०आ० 2453.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—(1) इस आदेश का नाम शीतागार आदेश, 1980 है ।

(2) इसका विस्तार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का छोड़कर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस संबंध में छूट देती है, सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "शीतागार" से ऊष्मारोधी और प्रशीतन मशीनरी द्वारा यांत्रिकतः शीतलित तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए प्रयुक्त कोई कोष्ठ अभिप्रेत है किन्तु इसमें 25 घन मीटर से कम क्षमता वाले प्रशीतित कैबिनेट या शीतलित सम्मिलित नहीं है;

(ख) "शीतागार रसीद" से ऐसी कोई रसीद अभिप्रेत है जो अनुज्ञप्तिधारी, शीतागार में भण्डारकरण के लिए किसी अवक्रेता से प्राप्त खाद्य पदार्थ के प्रतीकस्वरूप उसे जारी करता है;

(ग) "खाद्य पदार्थ" के अन्तर्गत हैं—

(i) फल, चाहे वे ताजे हैं, सुखाए गए हैं, निर्जलीकृत हैं, या परिरक्षित हैं;

(ii) सब्जियां, जिनके अन्तर्गत बीज के आलू भी हैं, चाहे वे ताजे हैं, सुखाए गए हैं, निर्जलीकृत हैं या परिरक्षित हैं;

(iii) मांस, चाहे वह ताजा है, हिमशीतित है, सुखाया गया है या परिरक्षित है;

(iv) मछली, चाहे वह ताजी है, हिमशीतित है या सुखाई गई है;

(v) अंडे, चाहे वे खोलयुक्त हैं चाहे खोल रहित है;

(vi) दुग्ध और दुग्ध-उत्पाद;

ii) मसाले; और

(viii) कोई अन्य खाद्य या खाद्य उत्पाद, जिसे केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(घ) "प्रारूप" से इस आदेश से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "अवक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए किसी शीतागार में स्थान के किराये के संदाय पर लेता है;

(च) "अनुज्ञप्ति" से इस आदेश के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(छ) "अनुज्ञप्तिधारी" से किसी अनुज्ञप्ति का धारक कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "अनुज्ञापन अधिकारी" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के उप कृषि विपणन सलाहकार की पंक्ति से नीचे का नहीं है या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जिसे उसने समय समय पर यथा अधिसूचित इस आदेश के अधीन सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करने या सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए सशक्त किया है, भी सम्मिलित हैं;

(झ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है;

(ञ) "अनुसूची" से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. अनुज्ञा के बिना नए शीतागार के सन्निर्माण या विद्यमान शीतागार के विस्तार पर प्रतिषेध—कोई व्यक्ति—

(क) खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए शीतागार का सन्निर्माण या किसी विद्यमान शीतागार की अनुज्ञप्तिधारिता का विस्तार नहीं करेगा; या

(ख) किसी शीतागार में, अनुज्ञप्ति की शर्तों और निबन्धनों के अधीन और उनके अनुसार पर के सिवाय किसी खाद्य पदार्थ को न तो भण्डारित करेगा और न भण्डारकरण के लिए स्वीकार करेगा या स्वीकार करने का वचन देगा :

परन्तु यदि अनुज्ञापन अधिकारी का, इस संबंध में प्ररूप 'क' में कोई आवेदन किए जाने पर, किसी अस्पताल, होटल या होस्टल या किसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी शीतागार के बारे में ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा शीतागार केवल ऐसे स्थापन के सद्भावी प्रयोग के लिए आशयित है तो वह उसे छूट दे सकता है ।

4 किसी शीतागार के सन्निर्माण, विस्तार या चालू करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी शीतागार का सन्निर्माण या विद्यमान शीतागार में विस्तार करने का इच्छुक है तो वह प्ररूप 'ख' में (दो प्रतियों में) आवेदन करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी शीतागार को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक है तो वह अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप 'ग' में, दो प्रतियों में, आवेदन करेगा।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ खण्ड 5 में विनिर्दिष्ट फीस और, यथास्थिति, शीतागार भवन रेखांक की या, विद्यमान शीतागार भवन के विस्तार के ब्लू प्रिंटों की, तीन प्रतियां, दी जाएंगी।

(4) यदि आवेदक का एक से अधिक शीतागारों के सन्निर्माण का या एक से अधिक शीतागारों के विस्तार का प्रभाव है तो वह ऐसे प्रत्येक शीतागार के लिए पृथकतः आवेदन करके, पृथक-पृथक अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा।

5. अनुज्ञप्ति के लिए फीस—आवेदन फीस और अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित रूप में होंगी :—

(क) आवेदन फीस :

(1) किसी शीतागार के सन्निर्माण या किसी शीतागार के विस्तार की अनुज्ञा के लिए आवेदन फीस।	आवेदन के साथ 25 रु० का संदेय किया जावेगा।
(2) अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन फीस।	10.00 रु०

(ख) अनुज्ञप्ति फीस/नवीकरण फीस : प्रति कलेण्डर वर्ष या उसके किसी भाग के लिए संदेय—

(1) ऐसे शीतागार जिनकी भण्डारण क्षमता 10,000 घन मीटर से अधिक है।	500.00 रु.
(2) ऐसे शीतागार, जिनकी भण्डारण क्षमता 2500 घन मीटर से अधिक किन्तु 10,000 घनमीटर से अधिक नहीं है।	300.00 रु०
(3) ऐसे शीतागार जिनकी भण्डारण क्षमता 25 घन मीटर से कम नहीं है किन्तु 3500 घन मीटर से अधिक नहीं है।	100 रु०

6. अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या अनुदत्त करने से इंकार करने के लिए विचार में ली जाने वाली बातें—अनुज्ञापन अधिकारी, कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या अनुदत्त करने से इंकार करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(1) उस क्षेत्र में, जिसमें उस शीतागार के जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, सन्निर्माण, या विस्तार का प्रस्ताव है, पहले से क्रियाशील शीतागारों की संख्या और ऐसे शीतागार में भण्डारकरण के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता;

(2) ऐसे शीतागार के जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रशीतन, ऊष्मा, रोधन और स्वच्छता की स्थिति;

(3) संयंत्र के परिचालन के लिए नियोजित या नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मचारिवृन्द की अर्हताओं/अनुभव की उपयुक्तता; और

(4) अन्य कोई बात जिसे अनुज्ञापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

7. अनुज्ञप्ति का अनुदान—(1) यदि खण्ड 4 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन अधिकारी का खण्ड 6 में विनिर्दिष्ट बातों के बारे में समाधान हो जाता है कि आवेदक को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने में कोई आपत्ति नहीं है तो वह आवेदक को प्ररूप 'घ' में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकता है।

(2) यदि खण्ड 6 में विनिर्दिष्ट बातों को विचार में रखते हुए, अनुज्ञापन अधिकारी की यह राय है कि आवेदक को अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जानी चाहिए तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इंकार कर सकता है किन्तु ऐसे इंकार के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगा और उसकी एक प्रति आवेदक को देगा।

(3) यदि आवेदक को अनुज्ञप्ति दिए जाने से इंकार कर दिया जाता है तो आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संदत्त आवेदन फीस, उसे वापस कर दी जाएगी।

8. अनुज्ञप्ति की शर्त शिथिल करना—खण्ड 7 के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी :

परन्तु इस आदेश के प्रारम्भ से पहले से ही विद्यमान किसी शीतागार की दशा में, यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी किसी शर्त का अनुपालन व्यावहारिक नहीं है तो वह उसे शिथिल कर सकता है।

9. अनुज्ञप्ति रद्द करना—यदि अनुज्ञापन अधिकारी, का यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने,—

(क) शीतागार पर से अपना नियंत्रण पूर्णतः या भागतः हटा लिया है या

(ख) अपना शीतागार चलाना बन्द कर दिया है, या

(ग) खण्ड 30 के अधीन अनुज्ञात प्रभारों से अधिक कोई प्रभार उद्ग्रहण किया है, या

(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों और निबन्धनों का या इस आदेश के उचित कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का उल्लंघन किया है या उसके अनुपालन में वह असफल रहा है, तो वह उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है :

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को रद्द करने से पूर्व, अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसे आधारों का उल्लेख करते हुए जिन पर अनुज्ञप्ति का रद्दकरण प्रस्तावित है, अनुज्ञप्ति धारी को स्पष्ट बस दिन की सूचना देगा और अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति रद्द न कि जाने की बाबत कारण बताने का अवसर देगा :

परन्तु यह और कि यदि लोक हित में तुरन्त कार्रवाई अपेक्षित है तो अनुज्ञापन अधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करके, अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताने का अवसर दिए बिना भी, अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है।

10. अनुज्ञप्तिधारी प्रतिकर या अनुज्ञप्ति फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं— यदि कोई अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रतिकर का या ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए उसके द्वारा संदत्त फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

11. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि—प्रत्येक अनुज्ञप्ति, जब तक कि उसे पहले ही रद्द नहीं कर दिया जाता, उस वर्ष के, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है, 31 दिसम्बर, को समाप्त हो जाएगी।

12. अनुज्ञप्ति का नवीकरण—(1) अपनी अनुज्ञप्ति नवीकृत कराने का इच्छुक प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, 31 अक्तूबर को या उससे पूर्व, खण्ड 5 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप 'ङ' और प्ररूप 'च' में, दो प्रतियों में आवेदन करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त तारीख के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो वह अनुज्ञप्ति के अवसान के पूर्व किसी भी समय खण्ड 5 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ दिसम्बर के प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए प्रति सैकड़ा एक रुपया के हिसाब से संगणित शास्ति का संदाय कर आवेदन कर सकेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन अधिकारी या तो अनुज्ञप्ति नवीकृत कर सकता है या उसे नवीकृत करने से इंकार कर सकता है। यदि नवीकरण से इंकार कर दिया जाता अवसर है तो अनुज्ञप्तिधारी की सुनवाई का दिया जाएगा और ऐसे इंकार

के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति आवेदक को दी जाएगी और आवेदक से प्राप्त नवीकरण की फीस उसे वापस कर दी जाएगी ।

(iii) यदि अनुज्ञप्तिधारी उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो उसके लिए अपनी अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख के पश्चात अपना शीतागार चलाना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक कि वह उस संबंध में नवीकृत अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं कर लेता ।

13. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना—यदि अनुज्ञप्ति खो जाती है, विनष्ट हो जाती है, फट जाती है, विरूपित हो जाती है या विकृत हो जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन कर सकता है । ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ खण्ड 5 के उपखण्ड (क) (iii) में विनिर्दिष्ट फीस दी जाएगी । ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति अनुदत्त करेगा ।

14. अनुज्ञप्ति का विनियमन और अन्तरण—(i) इस आदेश के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ii) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी कोई शीतागार किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय करता है या अन्यथा उसका अन्तरण करता है या छह मास से अधिक के लिए शीतागार का परिचालन निलम्बित करता है तो वह ऐसे विक्रय या अन्तरण या निलम्बन से एक मास के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर देगा ।

(iii) भागीदारी में कोई परिवर्तन होने की दशा में उसकी अधिसूचना ऐसे परिवर्तन के एक मास के भीतर, अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी ।

(4) यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती, इस आदेश के अनुसार, अनुज्ञापन अधिकारी को, नई अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन करेगा ।

(5) शीतागार के नाम, अभिनाम या अवस्थापन में कोई परिवर्तन होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी को ऐसा परिवर्तन प्रज्ञापित करेगा और प्रज्ञापन की तारीख से एक मास के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन अधिकारी को आवश्यक परिवर्तन किए जाने के लिए अग्रेषित करेगा ।

15. अग्रक्रेता के साथ करार या संविदा—अनुज्ञप्तिधारी, इस आदेश के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में, किसी अग्रक्रेता के साथ कोई संविदा या करार नहीं करेगा ।

16. अतिभराई—कोई अनुज्ञप्तिधारी शीतागार को उसकी अनुज्ञप्तिधारिता से अधिक नहीं भरेगा ।

17. खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के बारे में उपबन्ध—(i) यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित शीतागार प्रभारों का संदाय करने को तैयार है और यदि ऐसे खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए शीतागार में स्थान उपलब्ध है तो कोई अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति द्वारा निविदत्त किसी खाद्य पदार्थ को शीतागार में भण्डारकरण के लिए स्वीकार करने से इंकार नहीं करेगा :

परन्तु यदि भण्डारकरण के लिए निविदत्त खाद्य पदार्थ से शीतागार में भण्डारकृत किन्हीं अन्य खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचने की संभावना है या इस प्रकार निविदत्त खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए, भण्डारकृत अधिकांश खाद्य पदार्थों के लिए सामान्यतः अपेक्षित तापमान की रेंज से भिन्न रेंजों का तापमान अपेक्षित है, तो अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रकार निविदत्त खाद्य पदार्थों को भण्डारकरण के लिए स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा ।

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के खाद्य पदार्थ का भण्डारकरण लोक हित में नहीं है तो वह सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसा भण्डारकरण प्रतिषिद्ध कर सकता है और तब अनुज्ञप्तिधारी ऐसे खाद्य पदार्थ के भण्डारकरण से इंकार कर देगा :

(ii) यदि कोई अवक्रेता, अनुज्ञप्तिधारी के शीतागार में भण्डारकृत अपने पूर्ण परिषेण या उसके किसी भाग के परिदान की मांग करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, खण्ड 20 के अधीन नियत प्रभारों के संदाय पर, ऐसी मांग के चौबिस घंटे के भीतर, अवक्रेता के यथास्थिति, सम्पूर्ण परिषेण या उसके किसी भाग का परिदान करेगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक अवक्रेता द्वारा भण्डारकृत परिषेण का या प्रत्येक भण्डारकरण रसीद के अन्तर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों के परिषेण का, अलग-अलग भण्डारण करेगा जिससे कि उनकी आसानी से पहचान हो सके और सम्बद्ध अवक्रेताओं को आसानी से परिदान किया जा सके ।

18. शीतागार रसीदें 2(ख) में परिभाषित—(i) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक अवक्रेता द्वारा शीतागार में भण्डारकृत खाद्य पदार्थ के लिए, प्ररूप 'च' में एक शीतागार रसीद जारी करेगा ।

(2) रसीद, जब तक कि उस पर अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी और धारक सम्यक अनुक्रम में उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का उसी प्रकार हकदार होगा मानो वह मूल अवक्रेता हो; और

(3) यदि शीतागार रसीद खो जाती है, नष्ट हो जाती है, फट जाती है, विरूपित हो जाती है या अन्यथा अपठनीय हो जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी, अवक्रेता के आवेदन पर, रसीद की द्वितीय प्रति जारी करेगा ।

19. शीतागार में स्थान के अधिग्रहण की शक्ति—(1) अनुज्ञापन अधिकारी, लोक हित में, किसी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित आदेश तामील करके, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और आदेश के खण्ड 20 के अधीन नियत प्रभारों के संदाय पर, अनुज्ञप्तिधारी के शीतागार में सम्पूर्ण स्थान या उसके किसी भाग का अधिग्रहण कर सकता है ।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी इस प्रकार अधिगृहीत स्थगन, आदेश में, विनिर्दिष्ट एक या अधिक व्यक्ति(यों) को खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए आबंटित कर सकता है ।

20. भण्डारकरण के लिए प्रभारों का नियतन—अनुज्ञापन अधिकारी, मशीनरी की लागत, मूल्य ह्रास, विद्युत प्रभार आदि को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर राजपत्र में आदेश द्वारा, ऐसे अधिकतम प्रभार नियत कर सकेगा जो अनुज्ञप्तिधारी शीतागार में खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण के लिए या उससे संबद्ध किसी अन्य सेवा के लिए प्रभारित कर सकता है ।

21. निरीक्षण सुविधाएं आदि :—(1) अनुज्ञप्तिधारी, अपनी अनुज्ञप्ति शीतागार के परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और मांगे जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, किसी भी समय शीतागार के परिसर मशीनरी उपस्कर, उसमें भण्डारित खाद्य पदार्थों, बहियों, अभिलेखों और लेखाओं के निरीक्षण के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और उसकी सहायता करेगा ।

22. अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणियां प्रस्तुत करना—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में खाद्य पदार्थों के भण्डारकरण से संबंधित लेखे, खाते और अभिलेख प्ररूप छ-1 से छ-4 तक में रखेगा और प्ररूप छ-1 से छ-4 पर अनुज्ञापन अधिकारी को विवरणियां और विवरण प्रस्तुत करेगा ।

23. जानकारी आदि मंगाने की शक्ति— इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी,—

(क) किसी अनुज्ञप्तिधारी से, शीतागार में उसके द्वारा भण्डारकृत खाद्य पदार्थों की बाबत ऐसी सूचना जो उसके कब्जे में है, देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(ख) ऐसे किसी परिसर में, जहां चलाए जाने के लिए शीतागार संस्थापित है, अपना यह समाधान करने के लिए कि इस आदेश की अपेक्षाओं का अनुपालन हो रहा है, किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

(ग) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि इस आदेश का अतिलंघन हुआ है, और भण्डारकरण या व्ययन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(घ) लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किसी व्यक्ति को प्रचालक के रूप में नियुक्त करने से उस दशा में प्रतिषिद्ध कर सकेगा जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति के पास प्रचालन कार्य के लिए अपेक्षित अर्हता या ज्ञान या अनुभव नहीं है।

(ii) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अपेक्षित जानकारी देने के लिए और उपखण्ड (1) के पैरा (ख) के अधीन उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए आबद्ध होगा।

(iii) इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तलाशी से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक भी संभव हैं, इस खण्ड के अधीन तलाशियों को लागू होंगे।

24. अपील—इस आदेश के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से कथित कोई व्यक्ति ऐसे किसी अधिकारी को, अपील कर सकेगा जिसे केन्द्रीय सरकार ने विरोध विषेश आदेश द्वारा समय समय पर नियुक्त किया है और जो केन्द्रीय सरकार के, जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो।

25. प्रत्यायोजन—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अनुज्ञापन अधिकारी की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, योग या निर्वहन यह राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, कर सकेगा।

26. निरसन और व्यावृत्ति—शीतागार आदेश, 1964, उन बातों के सिवाय निरसित किया जाता है जो ऐसे निरसन के पूर्व उसके अधीन की गई हैं या जिनके किए जाने में लोप हुआ है।

अनुसूची

(खण्ड 8 देखिए)

भाग 1

स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं :

1. वह परिसर जहां शीतागार संस्थापित किया गया है, साफ होगा। शीतागार में प्रति 4645 वर्ग मीटर के लिए एक बाट की दर से विद्युत दीपों की व्यवस्था की जाएगी। शीतागार का रोगाणुनाशन या निर्गन्धीकरण, फिर भी, जब और जैसे अपेक्षित हो, कराया जाएगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी उत्पाद को, जिसकी गन्ध, शीतागार में भण्डारकृत खाद्य पदार्थ की गन्ध के विरुद्ध या विजातीय है, भण्डारकृत नहीं करेगा।

3. उस परिसर के, जहां शीतागार संस्थापित है, सभी प्रांगण, उपगृह, भण्डार और सभी पहुंच मार्ग साफ और स्वच्छ रखे जाएंगे।

4. ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे कोई संक्रामक या सांसर्गिक रोग है, शीतागार में कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। शीतागार में काम करने वाले दैनिक संदेय मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों को, यह जांच करने के लिए कि वे किसी संक्रामक, सांसर्गिक या अन्य रोगों से ग्रस्त तो नहीं हैं, वर्ष में एक बार परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

5. हिमांक से ऊपर क्रियाशील शीतागार में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, शीत से उनके संरक्षण के लिए, उचित वस्त्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। जो कर्मचारी ऐसे शीतागार में कार्य करते हैं जो हिमांक से नीचे क्रियाशील हैं, उनके लिए बूटों की भी व्यवस्था की जाएगी।

6. परिसर के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग और पर्याप्त शौचगृह सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

7. सभी सीढ़ियों और गेंगवे का अच्छा सन्निर्माण कराया जाएगा, उचित रूप से रखरखाव किया जाएगा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलिंग की व्यवस्था की जाएगी।

भाग 2

परिचालन विषयक अपेक्षाएं

1. शीतागार के द्वारों में पर्याप्त ऊष्मारोधन की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें युक्तियुक्त रूप से वायुरोधी रखा जाएगा। द्वारों की डिजाइन ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति उसे भीतर और बाहर से खोल सकता हो।

2 यदि रैकों की व्यवस्था की जाती है तो उनका सन्निर्माण इस प्रकार कराया जाएगा कि उन पर लदाई और उतराई कार्य शीतागार में कार्य कर रहे कर्मचारियों के जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सके।

3. वायु के वितरण और परिचालन के लिए और वस्तुतः लदाई उतराई कार्य के लिए निम्नलिखित निदेशों का पालन किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) रैकों की पंक्तियों के बीच रास्ता 0.76 मीटर से कम नहीं होगा।

(ख) रैकें दीवारों और फर्श से कम से कम 20 सेंमी० दूर रखी जाएंगी।

(ग) प्रत्येक रैक के शीर्षस्थ शैल्फ में रखे गए माल के ऊपरी स्तर, और छत के बीच कम से कम 30 सें० मी० खाली जगह रखी जाएगी।

(घ) किसी रैक की प्रत्येक शैल्फ पर शैल्फ में रखे गए माल और उससे ऊपर के शैल्फ के बीच कम से कम 7.5 सें० मी० खाली जगह रखी जाएगी।

4. शीतागार में प्रशीतन के संवाहन के लिए विसारक या सीधे विस्तार पाइप इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि तापमान में शीतागार के प्रत्येक स्थान पर, जहां खाद्य पदार्थ भण्डारकृत किया जाता है, ±10 सें० की अधिकतम अनुज्ञेय विभिन्नता और सापेक्ष आर्द्रता की प्रतिशतता में ±5 प्रतिशत अनुज्ञेय विभिन्नता के साथ उचित तापमान रखा जा सके।

5. शीतागार में शुल्क बल्ब और आर्द्र बल्ब तापमान रीडिंग थर्मामीटरों की व्यवस्था की जाएगी। थर्मामीटरों की संख्या और अवस्थान, शीतागार के आकार और धारिता पर आश्रित होगी और कैसी होगी जैसी अनुज्ञापन अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रथम या उत्तरवर्ती निरीक्षण के समय अनुदिष्ट करे।

6. मूलगति उत्पादकों के सभी गतिमान हिस्से और मूलगति उत्पादकों में लगे संयुक्त गतिपालक चक्रों के साथ उचित रक्षा पट्टों की व्यवस्था की जाएगी।

7. संपीड़क की चूषक पाइप लाइनें अच्छी तरह से विद्युतरोधी की जाएंगी।

8. प्रत्येक भण्डारकरण कक्ष में भीतर की ओर आपात स्थिति की दशा में प्रयोग के लिए स्विच के साथ अलार्म घंटी की व्यवस्था की जाएगी।

9. मशीनकक्ष में प्राथमिक उपचार पेटिका रखी जाएगी।

10. शीतागार कक्षों से संलग्न, उपकक्ष या वायु पर्दा की व्यवस्था की जाएगी।

11. प्रशीतन प्रणाली के अभिग्राही या द्रवणित्र के साथ उपयुक्त रेंज के दाब मापी की व्यवस्था की जाएगी।

12 प्रत्येक शीतागार इस अनुसूची के उपाबन्ध 1 म यथा विनिर्दिष्ट यांत्रिक प्रशीतन संबंधी सुरक्षा संहिता का पालन करेगा।

भाग 3

लाग बुक और अग्रिम बुकिंग का विवरण रखना

(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस आदेश के उपाबन्ध II में उपवर्णित प्ररूप में, तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के अनुरक्षण के लिए और शीतागार के परिचालन के दौरान रात दिन चार-चार घंटे में तब तक संपीडक के दाब पन्न को रखने के लिए एक लाग बुक रखेगा जब तक कि स्वचल अभिलेखन उपकरण संस्थापित नहीं कर दिया जाता और उस पर अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा। अनुज्ञापन अधिकारी या उसके द्वारा इस बारे में सम्यक्तः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, प्रत्येक निरीक्षण में, अभिलेखों के वैयक्तिक सत्यापन के पश्चात् लाग बुक पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी शीतागार के कार्यकरण को लगातार 24 घंटे से अधिक के लिए रोक दिए जाने की रिपोर्ट अनुज्ञापन अधिकारी को तुरन्त तार द्वारा करेगा और पत्र द्वारा उसकी पुष्टि करेगा। ऐसे ब्रेक डाउन के कारण लाग बुक में अभिलिखित किए जाएंगे और अनुज्ञापन अधिकारी को रिपोर्ट किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अग्रिम बुकिंग का विवरण रखेगा और यह विवरण निरीक्षक कर्मचारिवृन्द को जब से उसकी अपेक्षा करें, प्रस्तुत करेगा।

उपाबंध 1

(अनुसूची का खण्ड 12 देखिए)

यांत्रिक प्रशीतन के लिए भारतीय मानक सुरक्षा संहिता (पुनरीक्षित)

1. व्याप्ति

1.1 इस संहिता में, वाष्प संपीडन टाइप की यांत्रिक प्रशीतन प्रणाली, जिसमें संयंत्र कक्ष में कार्यकरण परिस्थितियां, जो शीतागार में जीवन, स्वास्थ्य और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए युक्तियुक्ततः आवश्यक समझी जाती है, भी सम्मिलित हैं, की डिजाइन, सन्निर्माण, संस्थापन, संक्रियण और निरीक्षण में सुरक्षा संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है।

2. शब्दावली

2.0 इस संहिता के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

2.1 संपीडक—वह उपस्कर है जिसमें द्रावण से पूर्व प्रशीतक के दाब को बढ़ाने के लिए उसे प्रशीतन मशीन में संपीडित किया जाता है।

2.2 द्रवणित्र—प्रशीतन प्रणाली का वह भाग है जहां उच्च दाब प्रशीतक गैस का उच्च दाब द्रव में द्रवित्र किया जाता है।

2.3 द्रवण एकक—निम्न दाब गैस को उच्च दाब द्रव में संपरिवर्तित करने के लिए उपस्करों का एक संयोजन है, जिसमें मुख्यतः संपीडक, द्रवणित्र और द्रव अभिग्राही (जहां अपेक्षित है) सम्मिलित हैं।

2.4 वाष्पित्र—प्रशीतन प्रणाली का वह भाग है जहां शीतलन के लिए द्रव प्रशीतक को वाष्पित किया जाता है।

2.5 प्रसार वाल्व—वह वाल्व है जो द्रव प्रशीतक का उच्च दाब से भिन्न दाब को प्रसार करता है और प्रशीतक का प्रवाह नियंत्रित करता है।

2.6 संगलनीय प्लग—विशेष संगलनीय मिश्रधातु निर्मित वह प्लग है जो पूर्वविधारित तापमान पर संगलित हो जाता है और प्रशीतन प्रणाली में दाब को मुक्त कर देता है।

2.7. उच्च दाब स्विच—उच्च दिशा में अधिक दाब के विरुद्ध एक स्वचल संरक्षा युक्ति है यह किसी संपीडक या किसी द्रवण एकक को, जब उच्च दिशा में दाब पूर्वविधारित परिसीमा से अधिक हो जाता है, स्वयंमेव रोक देती है।

2.8. निम्न दाब स्विच—निम्न दिशा में अत्यधिक निम्न दाब के विरुद्ध एक स्वचल संरक्षा युक्ति है। यह किसी संपीडक या किसी द्रवण एकक को, जब निम्न दिशा में दाब पूर्वविधारित परिसीमा से कम हो जाता है, स्वयंमेव रोक देती है।

2.9. संयंत्र कक्ष—वह कक्ष है, जिसमें घरेलू प्रशीतन साधित्रों से जैसे प्रशीतित्र, वहनीय, वातानुकूलक आदि (जो निवास कक्ष में संस्थापित हैं), भिन्न प्रशीतक संयंत्र संस्थापित हैं और चलाया जाता है।

2.10. दाब निर्मोचन युक्ति—ऐसा दाब प्रवर्तित वाल्व या युक्ति है जो इसके स्थापन से अधिक दाब को स्वयं निर्मुक्त कर देती है।

2.11. दाब वाहिका—यह एक अभिग्राही है, जिसमें दाब के अधीन प्रशीतक रहता है।

2.12. अभिग्राही—प्रशीतन प्रणाली की भागरूपी वाहिका जो द्रव प्रशीतक के लिए पात्र के रूप में कार्य करती हैं।

2.13. प्रशीतक—एक रासायनिक एजेन्ट, जो प्रशीतन प्रणाली में उच्च दाब द्रव से निम्न दाब गैस में विस्तार द्वारा शीतलन उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है।

2.14. प्रशीतक आधान—द्रव प्रशीतक के भण्डारकरण के लिए एक वाहिका।

2.15. प्रशीतन प्रणाली—एक उपस्कर है, जिसमें द्रवणित्र एकक और वाष्पित्र, जिसमें ऊष्मा के अपकर्षण और अन्तरण के लिए प्रशीतक परिचालित किया जाता है, अन्तर्विष्ट हैं।

3. संस्थापन अपेक्षाएं

3.1. संयंत्र कक्ष

3.1.1. द्वार, विभाजन और मुखद्वार—प्रत्येक प्रशीतन प्रणाली के संयंत्र कक्ष में एक द्वार की व्यवस्था की जाएगी और भवन के अन्य भागों में प्रशीतकों के निकल जाने को रोकने के लिए विभाजक या मुखद्वार नहीं होंगे।

3.1.2. संयंत्र कक्ष द्वार में भीतर से अभिबंधन युक्तियां नहीं होंगी। फिर भी, उसे भीतर से बोल्ट करने की सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है।

3.1.3. प्रत्येक संयंत्र कक्ष में उपयुक्त संवातन व्यवस्था की जाएगी। अपेक्षित संवातन साधारणतः सारणी 1 के अनुसार होगी। अपेक्षित संवातन अभिप्राप्त करने के लिए, बाहर की ओर खुलने वाली खिड़कियों और दरवाजों या शक्ति चालित निर्वातक पंखों की व्यवस्था की जा सकेगी। खिड़कियों और दरवाजों का आकार और निर्वातक पंखों की वायु निर्वातन क्षमता सारणी 1 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार होगी यदि निर्वातक पंखों का प्रयोग किया जाता है, तो उस वायु को, जो पंखे द्वारा निर्वातित की जा रही है, प्रतिस्थापित करने के लिए वायु के भीतर आने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। निर्वातक पंखा या पंखों से संबद्ध क्षेत्र, सारणी 1 में दिए न्यूनतम वाहिनी क्षेत्रों के अनुसार होगा।

3.1.4. आपात निकास और अग्नि शामक--प्रत्येक संयंत्र कक्ष में आपात निकासों और उपयुक्त आकार के अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी । (भा० मा० 2190--1962 वहनीय प्राथमिक वायु अग्नि साधित्रों के चयन, संस्थापन और अनुरक्षण की संव्यवहार संहिता देखिए) ।

3.1.5. प्राथमिक उपचार उपस्कर--प्रत्येक संयंत्र कक्ष में कारखाना अधिनियम, 1948 और तद्धीन बनाए गए नियमों में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुसार, प्राथमिक उपचार उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी ।

3.1.6. गैस मास्क—एक या अधिक गैस मास्क या उपयुक्त आकार के श्वसन उपकरण संयंत्र कक्ष के ठीक बाहर ऐसे स्थान पर रखे जाएंगे जहां आसानी से पहुंचा जा सके । गैस मास्कों के केनिस्टरों का कालिक नवीकरण किया जाएगा ।

3.2. द्रवणित्र एककों या संपीड़क एककों या अन्य प्रशीतक उपस्करों के लिए आधार और आलंब का सन्निर्माण ऐसे किया जाएगा कि वे काफी मजबूत, कम्पन अवशोषी और अदाह्य हों ।

3.2.1. सभी चल मशीनरी, कारखाना अधिनियम, 1948 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार संरक्षित की जाएंगी ।

3.3. द्रवणित्र एककों या संपीड़क एककों के निरीक्षण और संरक्षी सेवा के लिए उपयुक्त स्पष्ट जगह की व्यवस्था की जाएगी ।

सारणी 1—न्यूनतम वायु वाहिनी क्षेत्र और मुखद्वार

(खण्ड 3.1.3)

प्रणाली में प्रशीतक का भार कि० ग्रा०	वायु का यांत्रिक विसर्जन मी3 मिनि०	वाहिनी क्षेत्र मी2	खुली खिड़की द्वार का क्षेत्र मी2
(1)	(2)	(3)	(4)
10	3.9	0.025	0.44
25	7.1	0.03	0.70
50	11.3	0.05	1.0
75	14.8	0.07	1.2
100	18.0	0.07	1.4
125	20.8	0.10	1.6
150	23.5	0.10	1.7
200	28.5	0.12	2.0
250	33	0.12	2.2
300	37	0.14	2.4
350	41	0.18	2.6
400	45	0.18	2.8
450	49	0.18	3.0
500	53	0.20	3.1
600	59	0.20	3.4
700	66	0.20	3.7
800	72	0.20	4.0
900	78	0.20	4.2
1000	83	0.20	4.4
1250	97	0.28	5.0
1500	109	0.35	5.4
2000	132	0.40	6.3
2500	154	0.55	7.0
3000	173	0.50	7.7
3500	192	0.54	8.3
4000	210	0.58	8.8
4500	227	0.60	9.4
5000	244	0.65	9.9
6000	275	0.70	10.8
7000	305	0.72	11.7
8000	333	0.75	12.5
9000	361	0.78	13.3
10000	387	0.81	14.0
12000	437	0.83	15.3
14000	484	0.84	16.6
16000	529	0.86	17.7
18000	572	0.88	18.8
20000	614	0.90	20.0

टिप्पण वायु का यांत्रिक विसर्जन और खुला क्षेत्र, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, जो डी आई एन 8975, प्रशीतन संयंत्र, उनके सन्निर्माण, उपस्कर और उद्धर्षण के लिए सुरक्षा सिद्धान्त से लिया गया है, निकाला गया है ।

खुली खिड़की या द्वार क्षेत्र, मी^{2} $0.14\sqrt{3}$ जी

वायु का यांत्रिक विसर्जन, मी^{3} $50^3\sqrt{2}$

यहां 'जी' इंजनकक्ष में प्रशीतक के सबसे लम्बे बन्द परिपथ का किलोग्राम में भाज है ।

टिप्पण 2—मध्यवर्ती मान गणना द्वारा अभिप्राप्त किए जा सकते हैं ।

3.4 बाड़े के भीतर की द्रवणित्र या संपीड़ित एकक निरीक्षण और संरक्षी सेवा के लिए सुगमता से पहुंच के भीतर होंगी ।

3.5. द्रवणित्र या संपीड़ित एककों और अन्य प्रशीतन उपस्करों के निरीक्षण और संरक्षी सेवा के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी ।

3.6. जलपूर्ति संयोजन भवन में जलपूर्ति के लिए व्यवहार संहिता के भा० मा० 2065–1963 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार किए जाएंगे ।

3.6.1 प्रशीतन प्रणाली से ऊष्मा हटाने के लिए प्रयुक्त जल ऐसे किसी जल प्रवाह में नहीं छोड़ा जाएगा जिसका प्रयोग मानव या पशु के उपभोग के लिए हो सकने की संभावना है ।

3.7 विद्युत वायरिंग और विद्युत उपस्कर का संस्थापन, भारतीय विद्युत अधिनियम की और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा और वह यथा लागू भा० मा० 732 –1963 विद्युत वायरिंग संस्थापन (650 वोल्ट से अनधिक वोल्टता प्रणाली) (पुनरीक्षित) व्यवहार संहिता, भा० मा० 2274–1963 विद्युत वायरिंग संस्थापन (650 वोल्ट से अधिक वोल्टता प्रणाली) व्यवहार संहिता और भा० मा० 302–1960 हल्के विद्युत साधनों के लिए साधारण सुरक्षा अपेक्षा, जो भी लागू हों, में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप भी होगा ।

3.7.1 यह सिफारिश की जाती है कि संपीड़क का संघटक जल पम्प और शीतकृत टावर पंखे (जहां दिया गया हो) के साथ विद्युत अंतर्पाशन भली प्रकार कर दिया जाए । संपीड़क मोटर का स्विच पंपिंग सेट और पंखे के साथ इस रीति से अन्तर्पाशन होना चाहिए कि संपीड़क मोटर तब तक चालू न हो सके जब तक कि संघटक जल पम्प और पंखा चालू नहीं हो जाता ।

3.7.2 यह सिफारिश की जाती है कि जहां तक हो सके उच्च दाब स्विच, निम्न दाब स्विच और यांत्रिक प्रशीतन प्रणाली के संबंध में प्रयुक्त अन्य विद्युत नियंत्रण उपकरण अधिक से अधिक 250 वोल्टता पर प्रचालित किए जाएं ।

3.8 किसी ऐसे संयंत्र कक्ष में, जिसमें एक या अधिक प्रशीतन मशीनें जिनका कुल प्रशीतक चार्ज कक्ष आयतन के प्रति घन मीटर के लिए सारणी–2 में उल्लिखित से अधिक है, खुली ज्वाला या उसे उत्पादित करने वाला उपकरण या 425° से० से अधिक उष्ण सतह अनुज्ञेय नहीं होगी ।

3.9. किसी भी प्रशीतन प्रणाली या प्रशीतक वाहिका में, जब प्रणाली या वाहिका में प्रशीतक भरा हो, खुली ज्वाला उपयोज्य नहीं होगी ।

3.10 ऐसी प्रशीतन प्रणाली की दशा में, जिनमें ज्वलनशील प्रशीतक जैसे मिथील क्लोराइड, एथीन आदि प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रशीतन प्रणाली के लिए सभी विद्युत संस्थापन साधारणतः नीचे दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।

सारणी 2

ज्वलनशील प्रशीतकों की अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा

(खण्ड 3.8)

नाम	रासायनिक सूत्र	अधिकतम मात्रा मा०/मी^{3}
ब्यूटेन	$सी_4$ $एच_{10}$	40
एथेन	$सी_2$ $एच_6$	40
एथिल क्लोराइड	$सी_2$ $एच_5$ $सी_1$	100
एथिलीन	$सी_2$ $एच_4$	32
आइसोब्यूटेन	(सी एच$_3$) $_2$ सी एच	40
मैथाइल क्लोराइड	सी एच$_3$ सी आई	160
मैथाइल फारमेट	एच सी 00 सी एच$_3$	110
प्रोपेन	$सी_3$ $एच_8$	40

भा० मा० : 1646—1961 भवनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए व्यवहार संहिता (साधारण) विद्युत संस्थापन में अधिकथित, यथा लागू, और समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित अन्य अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं ।

3.11. किसी प्रशीतन प्रणाली या पाइपिंग का संस्थापन, द्वार मार्गों, सीढ़ियों के नीचे या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर, सिवाय तब के जब कि उनका उपयुक्त संरक्षण कर दिया जाए, नहीं किया जाएगा ।

3.12. प्रशीतक चार्ज करना—चार्ज करते समय प्रशीतक आधान और मशीन के बीच, यह जानने के लिए कि प्रणाली किस दाब पर चार्ज की जा रही है, एक गेज की व्यवस्था की जाएगी । यह दाब उस विसर्जन दाब से अधिक नहीं होना चाहिए जिस पर किसी विशिष्ट प्रकार के प्रशीतक के साथ संपीड़क को कार्य करना है ।

3.13. प्रशीतन प्रणाली के प्रत्येक संस्थापन के लिए, निम्नलिखित जानकारी, किसी फ्रेम में मढ़ कर, संयंत्रकक्ष में भली प्रकार लगा दी जानी चाहिए :

(क) संघानित्र एकक का नाम और मेक;

(ख) संघानित्र एकक का माडल ;

(ग) प्रशीतक का नाम और पूर्ण चार्ज;

(घ) तेल का पूर्ण चार्ज;

(ङ) प्रणाली में चार्ज किए गए प्रशीतक और तेल की मात्रा तथा चार्जन की तारीख;

(च) वह दाब जिस पर संस्थापन के पश्चात् प्रणाली का परीक्षण किया जाना है; और

(छ) प्रशीतक कब बदला गया है, तारीख बताएं ।

4. प्रशीतन प्रणाली और उपस्कर:

4.1. प्रशीतन प्रणाली के संभ्रमण और संस्थापन में प्रयुक्त प्रशीतक पाइप, वाल्व, फिटिंग, उनसे संबंद्ध हिस्से और सभी अन्य सामग्री प्रयुक्त प्रशीतक के लिए उपयुक्त होगी । ऐसी कोई सामग्री, जो प्रशीतक की रासायनिक प्रक्रिया या तेल या दोनों के संयोग और आर्द्रता के कारण क्षय हो सकती है, प्रयोग नहीं की जाएगी । मैथाइल क्लोराइड के संस्पर्श में एल्युमिनियम, जस्ता या मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा । मैग्नीशियम मिश्र धातुएं मैथेन और एथेन के क्लोरो-फ्लुओरो व्युत्पन्नों के संस्पर्श में प्रयोग नहीं की जाएंगी । तांबा और ताम्र मिश्र धातुओं का अमोनिया के संस्पर्श में प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

4.2. सभी जोड़ सुगम पहुंच में होंगे ।

4.3. रांगा या अन्य मिश्रधातुओं से विनिर्मित प्रशीतक ताबे के पाइप और फिटिंग के जोड़ों का गलनांक निम्नलिखित होगा :—

(क) 32 मि० मी० तक के आकार वाले पाइप के लिए कम से कम 260° सें०, और

(ख) 32 मि० मी० से अधिक आकार वाले और उष्ण गैस लाइनों पर सभी आकार वाले पाइपों के लिए 540° स ।

4.4. रोक वाल्व, उन प्रणालियों से भिन्न, जिनमें अपकेन्द्री संपीड़क का प्रयोग होता है, ऐसी सभी प्रणालियों में, जिनमें 10 कि० ग्रा० से अधिक प्रशीतक है, संस्थापित किया जाएगा । रोक वाल्व 4.4.1 में बताए गए लाइन पर लगाए जाएंगे ।

4.4.1. रोक वाल्व, प्रत्येक संपीड़क, अनिग्राही और वाष्पित्र के प्रवेश और निकास शिरों पर लगाए जाएंगे ।

4.5. दाब परीक्षण—सभी रोक वाल्वों, पाइपिंग, जोड़ों, फ्लेंजों और फिटिंग का संस्थापन पूर्ण होने के पश्चात् और प्रचालन से पूर्व दाब परीक्षण किया जाएगा ।

4.6 पूर्ण प्रशीतक पाइपिंग, हेंगर, ब्रेकेट स्टेप क्लेंप या पेडस्टल द्वारा इस रीति से सम्बद्ध की जाएगी कि जोड़ों को अपहानिकर विकृति और कम्पनों से युक्त रखा जा सके ।

4.7 प्रशीतक पाइप लाइनों का वर्ण अभिनिर्धारण भा० मा० 2379—पाइप लाइनों का रंग अभिनिर्धारण संहिता में दिए गए रंग अभिनिर्धारण के अनुसार होगा ।

4.8. आपात निर्गम लाइन—अमोनिया और सल्फर डाइआक्साइड की प्रत्येक प्रशीतन प्रणाली में, जिनमें 10 कि० ग्रा० या अधिक चार्ज है, एक आपात निर्गम लाइन लगाई जानी चाहिए । आपात में निर्गम लाइन सीधे अभिग्रही या संधानित्र अभिग्राही के शीर्ष से संयोजित कर दी जानी चाहिए ।

सारणी 3—न्यूनतम फील्ड प्रशीतक

दाब रिसन परीक्षण (खण्ड 4.5 और 5.3)

प्रशीतक का नाम	रासायनिक सूत्र	न्यूनतम फील्ड प्रशीतक दाब रिसन परीक्षण	
		कि० ग्रा० 1 से० मी० 2	
		उच्च दाब विशा	निम्न दाब विशा
1	2	3	4
अमोनिया	एन० एच०$_3$	20	10.5
*कार्बन डाइआक्साइड	सीओ$_2$	100	70
डाइक्लोरो डिफ्लुओरोमेथेन	सीसीआई$_2$ एफ$_2$	16	10
डाइक्लोरोएथेन	सी$_2$एच$_4$सीआई$_2$	2	2

*नये संस्थापन के लिए सिफारिश नहीं की गई है ।

1	2	3	4
डाइक्लोरोमेथेन (मेथीलिन क्लोराइड)	सी एम$_2$सीआई$_2$	2	2
डाइक्लोरो मोनोफ्लूरोमेथेन	सीएचसीआई$_2$ एफ$_4$	5	3
डाइक्लोरो टेट्राफ्लूरेथेन	सी$_2$सीआई$_2$एफ$_4$	3.5	3.5
*मेथाइल क्लोराइड	सीएच$_3$ सी आई	15	8.5
एथेन	सी०एच$_6$	85	50
मोनोक्लोरोडिफ्लूरोमेथेन	सीएचसी आईएफ$_2$	20	10.5
सल्फर डाइआक्साइड	एस ओ$_2$	12	6
ट्राइक्लोरोमोनोफ्यूरोमेथेन	सीसीआई$_3$ एफ	2	2
ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लूरोमेथेन	सी$_2$सीआई$_3$एफ$_3$	2	2

*नए संस्थापन के लिए सिफारिश नही की गई है ।

वाल्व संयंत्र के ठीक बाहर होना चाहिए और आपात वाल्व तथा अभिग्राही के बीच कोई वाल्व नहीं होना चाहिए जिसके कि आपात् स्थिति में, संयंत्र कक्ष में प्रवेश किए बिना, बाहर से ही वाल्व के प्रचालित किया जा सके । यह देखने के लिए पर्याप्त पूर्वविधानियां बरती जानी चाहिए कि कोई अनधिकृत व्यक्ति वाल्व में हस्तक्षेप न कर सके । आपात् वाल्व अधिमानतः कांच मुख वाले बक्से से ढका होना चाहिए । आपात् निर्गम पाइप को भवन के बाहर इस प्रकार संयोजित किया जाना चाहिए कि वह आसपास के क्षेत्र को प्रभावित न कर सके ।

5. दाब उक्तियां

5.1. उच्च दाब स्विच ।

5.1.1. सामान्यतः घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किए जाने वाले आकार से बड़े सभी संधानित्र एककों या संपीड़क एककों में स्वचल उच्च दाब स्विच लगाए जाएंगे ।

5.1.2. उच्च दाब स्विच सदैव, निर्गम आफ वाल्व के पूर्व, संपीड़क की निर्गम दिशा में लगाया जाएगा ।

5.1.3. 7.5 कि० वा० से ऊपर के संधानित्र एककों के लिए उच्च दाब स्विच की कट इन साइकल स्वचालित नही होगी, अर्थात् ट्रिपिंग के पश्चात् संपीड़क मोटर का हस्तचालन अपेक्षित होगा ।

5.2. निम्न दाब स्विच—निम्न दाब स्विच, इन संपीड़कों से, जिनका प्रयोग घरेलू प्रशीतकों में होता है, भिन्न सभी संपीड़कों में, जब उनका प्रयोग 0° सें० से नीचे निम्न ताप स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाये, जहां भी साध्य हो, लगाया जाना चाहिए ।

5.3. दाब निर्मुक्ति युक्तियां या संगलनीय प्लग—ये सभी संधानित्र एककों पर प्रशीतक द्रव स्तर से ऊपर उच्च स्तर पर लगाए जाएंगे । निर्मुक्ति वाल्व के लिए निर्गम इस प्रकार संयोजित किए जाने चाहिए कि उसका भवन के बाहर उसके आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव पड़े बिना विसर्जन हो जाए । अमोनिया और सल्फर डाइआक्साइड प्रशीतकों का विसर्जन ऐसी वाहिकाओं, जिनमें क्रमशः जल और लवण जल हो, किया जाएगा । दाब निर्मुक्ति वाल्व, सारणी 3 में दिए गए (उच्च दाब दिशा) न्यूनतम क्षेत्र प्रशीतक, दाब रिसन परीक्षण में विनिर्दिष्ट दाब के पचहत्तर से अस्सी, प्रतिशत के बीच दाब पर से नीचे लगाए जाएंगे ।

6. दाब वाहिकाएं

6.1. दाब वाहिकाओं वाले सभी प्रशीतकों को, कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित रूप में कालिक द्रवस्थितिक रूप में परीक्षण और पूर्ण परीक्षा की जाएगी ।

6.2. दाब वाहिकाओं वाले सभी प्रशीतकों में, जिनका शुद्ध आयतन 0.15 एम^3 या अधिक है और जिन्हें वाल्व द्वारा शट-आफ किया जा सकता है दाब निर्मुक्ति युक्तियां या संगलनीय प्लग लगाए जाएंगे ।

7. अनुरक्षण

7.1. संस्थापन के पश्चात् प्रत्येक प्रशीतन प्रणाली की, हर तीन मास के पश्चात् प्रशीतक रिसन के लिए जांच की जाएगी ।

7.2. दाब युक्तियां, दाब गेजों और उच्च तथा निम्न दोनों दिशाओं में अन्य सभी प्रशीतकों नियंत्रणों की कालिक जांच की जाएगी । ऐसे दो निरीक्षणों के बीच अन्तराल कुछ मास से अधिक का नहीं होगा । संगलनीय प्लगों का निरीक्षण हर तीन मास में एक बार किया जाएगा ।

7.3. स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से रासायनिक प्रक्रिया और संक्षारण की बाबत सांचों, कैनों, टैंकों आदि की बार-बार जांच की जाएगी ।

7.4. विद्युत संस्थापन की भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और भा० मा० 732—1963 विद्युत वायरिंग संस्थापन (650 वोल्ट से अनधिक वोल्टता प्रणाली) (पुनरीक्षित) व्यवहार संहिता और भा० मा० 2274—1963 विद्युत वायरिंग संस्थापन (650 वोल्ट से अधिक वोल्टता प्रणाली) व्यवहार संहिता के अनुसार विद्युत रोधन, रिसन आदि की बाबत कालिक जांच की जाएगी ।

7.5. सभी मरम्मतें सम्यकतः अभिलिखित की जाएंगी और मरम्मत के पश्चात् किए गए सभी परीक्षणों का अभिलेख रखा जाएगा । अभिलेख पर मैकेनिक और इंजीनियर या भारसाधक अधिकारी हस्ताक्षर करेगा ।

7.6. उचित पूर्वविधानी रखी जाएगी जिससे कि इस गैस से भिन्न जो कि प्रणाली में है, अन्य गैस न चार्ज हो जाए ;

7.7. किसी गैस सिलैण्डर पर या प्रणाली में, जब उसमें प्रशीतक हो, खुली ज्वाला का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

7.8. उस संयंत्र कक्ष में, जिसमें 25 कि० ग्रा० से अधिक प्रशीतक रखने वाली प्रशीतन प्रणाली संस्थापित है, संपीड़कों के निकट सहजदृश्य स्थान पर एक कार्ड रखा जाएगा, जिसमें प्रशीतन प्रणाली के प्रचालन के लिए निदेशों का जिनके अन्तर्गत ब्रेकडाउन या रिसन की दशा में बरती जाने वाली पूर्वविधानियों का उल्लेख भी है, और आपात स्थिति में प्रशीतन प्रणाली को बन्द कर देने के लिए अनुदेशों का उल्लेख किया गया हो ।

उपाबन्ध II

(अनुसूची का भाग III देखिए)

शीतागार								इंजन कक्ष लाग				
								शीत कक्ष				टिप्पणियां
समय	संपीडक सं०			परिदान दाब गेज	क्रैंके तेल दाब	लवण जल ताप	सं० 1		सं० 2		
	वोल्ट	एम्पियर	चूषण दाब गेज				डी०बी०	डब्ल्यू० बी०	डी०बी०	डब्ल्यू० बी०	
12 बजे अर्धरात्रि											
4 बजे											
8 बजे											
12 बजे दोपहर											
4 बजे											
8 बजे											

[फा० सं० 18-5/71-ए एस]

के० एल० गुप्ता, अवर सचिव

प्ररूप 'क'

[खण्ड 3(ख) देखिए]

शीतागार आदेश, 1980 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने में छूट के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम

1. (क) संस्था के भागीदारों/निदेशकों/ प्रधान का नाम और पता ।

2. किए जा रहे कारबार का स्वरूप

3. अवस्थान

4 शीतागार कक्ष (क्षों) की संख्या और आकार

(क) शीतागार चालू होने की तारीख और वर्ष

(ख)

लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	ऊंचाई मीटर में	धारिता घन मीटर में

(ग) ऊष्मा रोधन का प्रकार और मोटाई

(घ) संस्थापित मशीनरी की विशिष्टियां

(ङ) भण्डारकृत किए जाने वाले खाद्य पदार्थ (थों) का नाम

(च) अवधि, जिसमें सामान्यतः किसी अवधि के लिए खाद्य पदार्थों का भण्डारण किया जाता है ।

(छ) भण्डारकृत किए जा रहे खाद्य पदार्थ का अन्तिम प्रयोग ।

5. अवधि, जिसके लिए छूट अपेक्षित है ।

6. शीतागार आदेश, 19———के अधीन छूट के लिए औचित्य ।

7. मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि —

(1) यदि छूट दी जाती है तो हम/मैं यह सुनिश्चित करता हूं/करते हैं कि उचित स्वास्थ्यप्रद स्थिति में खाद्य पदार्थ का भण्डारण किया जाएगा ।

(2) किसी भी समय आदेश के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए परिसर खुला रहेगा ।

(iii) मैं/हम शीतागार में भण्डारकृत खाद्य पदार्थ की बाबत कोई जानकारी या शीतागार आदेश, 19———के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली कोई अन्य जानकारी देने के लिए आबद्ध हूं/है ।

(iv) मैं/हम ऊपर क्रम संख्यांक 2 में वर्णित रूप में कारबार में पूर्णतः अन्तिम प्रयोग के लिए खाद्य पदार्थ का भण्डारण करूंगा/करेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रतिफल पर या अन्यथा कोई अन्य खाद्य पदार्थ भण्डारण के लिए स्वीकार नहीं करूंगा/करेंगे ।

आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख

प्ररूप 'ख'

[खण्ड 4(1) देखिए]

भाग-क

(संलग्न अनुदेशों के अनुसार आवेदक स्वयं भरें)

नया शीतागार बनाने/विद्यमान शीतागार का विस्तार करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

1. (i) आवेदक का नाम और पता
(साफ अक्षरों में)

(ii) स्वत्वधारियों, भागीदारों, निदेशकों आदि के नाम और पते (फर्म के रजिस्ट्रीकरण/भागीदारी विलेख की प्रति संलग्न की जाए)

2 भूमि की विशिष्टियां :

(i) अवस्थान

(ii) निकटतम रेल स्टेशन

(iii) निकटतम राजमार्ग,

(iv) क्षेत्रफल, वर्गमीटरों में

(v) क्रय की तारीख (क्रीत भूमि की दशा में, क्रय विलेख की एक प्रति या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

3. मशीनरी, ऊष्मारोधन आदि की विशिष्टियां

(i) क्रीता/क्रय की जाने वाली मशीनरी का ब्यौरा
(यदि चाहें तो एक अलग से सूची अनुलग्न करें)

(ii) उपायन का स्रोत

(iii) ऊष्मा रोधन सामग्री मोटाई (मिलीमीटरों में)

मुख्य दीवार	
सामान्य दीवार	
फर्श	
छत	

(i) प्रस्तावित प्रशीतक

4. शीतागार की धारिता :

(i) प्रस्तावित शीतागार कक्ष(क्षों) की संख्या

(ii) प्रत्येक कक्ष की ऊंचाई सहित आन्तरिक विमाएं

(iii) सभी कक्षों की जिनके लिए आवेदन किया गया है, कुल भण्डारकरण धारिता, घन मीटरों में,

(iv) संनिर्माण प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तारीख

(v) क्या रेखांकों का सेट अनुलग्न है ? हां/नहीं

5. शीतागार के लिए खाद्य पदार्थ की उपलब्धता

(i) भण्डारकृत किए जाने वाले खाद्य पदार्थ (थों) का नाम

(ii) उपायन का स्रोत ।

6. शीतागार के प्रस्तावित स्थल पर या उससे 40 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर विद्यमान शीतागारों की संख्या

7. प्रस्तावित शीतागार बनाने/विद्यमान शीतागार का विस्तार करने का औचित्य

8. शक्ति (पावर) की उपलब्धता :

(i) अपेक्षित वैद्युत की मात्रा

(ii) अपेक्षित वैद्युत की मात्रा के लिए प्रबन्ध, यदि मंजूरी अभिप्राप्त हो गई है, तो मंजूर की गई मात्रा और मंजूरी की तारीख का उल्लेख करें ।

9. जल की उपलब्धता :

(i) जल की अपेक्षित मात्रा

(ii) जल पूर्ति के लिए किया गया प्रबन्ध ।

10. वित्तीय स्रोत

बैंक/राज्य वित्त निगम द्वारा वित्तपोषण की दशा में, आवेदित/मंजूर किए गए ऋण की रकम और मंजूरी की तारीख ।

11. प्रस्तावित शीतागार /शीतागार के विस्तार की अर्थव्यवस्था

क. (i) स्थिर पूंजी

(ii) भूमि की लागत

(iii) भवन की लागत

(iv) मशीनरी की लागत

(v) ऊष्मारोधन की लागत

(vi) रेक की लागत

(vii) किसी अन्य सामग्री की लागत

ख. कामकाज पूंजी

ग. व्यय

(i) चालान व्यय (वैद्युत शक्ति) पानी, प्रशीतक गैस, स्नेहक कार्यशाला, मरम्मत, और अनुरक्षण के प्रभार, लदाई और उतराई, श्रेणीकरण और पैकिंग आदि की मजदूरी, परिवहन फीस, पूंजी परिव्यय पर ब्याज, बीमा अवक्षयण आदि)

(ii) स्थापन : कर्मचारिवृन्द और कार्यालय व्यय

(iii) उपरि व्यय।

घ लाभ और हानि लेखा

(i) प्राप्तियां

(ii) व्यय

(iii) प्रस्तावित किराया दर

(iv) कुल पूंजी परिव्यय पर लाभ का प्रतिशत ।

आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख

अनुलग्नक (जो संलग्न हैं उस पर (√) चिन्ह लगा दें)

1. भागीदारी विलेख (अनुप्रमाणित प्रति)/ संगम का ज्ञापन और अनुच्छेद।
2. स्वत्तता के अनुसमर्थन में शपथपत्र ।
3. भूमि क्रम विलेख (अनुप्रमाणित प्रति) ।
4. फर्म के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (अनुप्रमाणित प्रति) ।
5. स्थानीय प्राधिकरण /नगर निगम से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' ।
6. उत्पादन के बारे में कृषि अधिकारी का पत्र ।
7. निम्नलिखित ड्राइंगे :
   (i) प्रधान रेखांक
   (ii) स्थल रेखांक
   (iii) विस्तृत रेखांक
   (iv) अनुभागीय ब्यौरे

टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें ।

भाग 'ख' (इसे कार्यालय में भरे)

विपणन और निरीक्षण निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालय की रिपोर्ट

विशिष्टियां	ठीक है या नहीं, यदि नहीं तो कमियों का उल्लेख करें
1	2
1. प्रधान रेखांक	
2. स्थल रेखांक	
3. विस्तृत रेखांक	
4. अनुभागीय ब्यौरे	
5. (i) भागीदारी विलेख।	
(ii) शपथपत्र (स्वत्यता के अनुसमर्थन में)	
(iii) संगम का ज्ञापन और अनुच्छेद	
6. भूमि क्रम-विलेख	
7. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र।	
8. स्थानीय प्राधिकरण/नगर निगम से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र'	
9. उत्पादन की बाबत कृषि अधिकारी का पत्र	
10. शक्ति की मात्रा अनुमोदित है या नहीं।	
11. परियोजना सुविधा है या नहीं	
12. अनुज्ञा देने के लिए सिफारिश	
13. प्रारूप 'ख'	

हस्ताक्षर
तारीख

भाग 'ग'

शीतागार के संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाने की बाबत आवेदन भरे जाने के लिए अनुदेश

शीतागार आदेश, 19 . के अधीन किसी नए शीतागार के स्थापन या विद्यमान शीतागार के विस्तार का इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञा अनुदत्त की जाने के लिए कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद को आवेदन करेगा । आवेदन विहित प्रारूप में निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिए :

प्रदेश का नाम	प्रदेश का क्षेत्रफल	मुख्यालय
	(1) जम्मू और काश्मीर	
	(2)	
	(3)	
1. उत्तरी प्रदेश	(4) राजस्थान	दिल्ली
	(5) हिमाचल प्रदेश	
	(6) दिल्ली और	
	(7) चण्डीगढ़	
2. पश्चिमी प्रदेश	(1) महाराष्ट्र	मुम्बई
	(2) गुजरात	
	(3) मध्य प्रदेश	
	(4) गोआ, दमन और दीव और	
	(5) दादरा और नागर हवेली	
3. पूर्वी प्रदेश	(1) बिहार,	पटना
	(2) उड़ीसा	
	(3) असम	
	(4) मेघालय	
	(5) मनीपुर	
	(6) त्रिपुरा	
	(7) नागालैण्ड	
	(8) नेफा और	
	(9) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	
4. दक्षिणी प्रदेश	(1) तामलनाडु	मद्रास
	(2) आन्ध्र प्रदेश	
	(3) मैसूर,	
	(4) केरल,	
	(5) पाण्डिचेरी	
	(6) लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनी दीवी द्वीप समूह	

2. कैसे आवेदन करें ?

आशयित पक्षकारों को, किसी नए शीतागार का सन्निर्माण या किसी विद्यमान शीतागार का विस्तार प्रारम्भ करने से पूर्व, विहित प्ररूप 'ख' पर निम्नलिखित संलग्नकों के साथ, अनुज्ञा के लिए आवेदन करना चाहिए।

1. भूमि-क्रय-विलेख की अनुप्रमाणित प्रति ।
2. भागीदारी विलेख/स्वत्वधारिता का शपथपत्र/संगम के ज्ञापन और अनुच्छेद की अनुप्रमाणित प्रति ।
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति ।
4. जिला कृषि अधिकारी से चालू के और/या अन्य आवश्यक वस्तुओं के जिनका प्रस्तावित शीतागार में भण्डारकरण किया जाना है, उत्पादन के बारे में प्रमाणपत्र / यदि प्रस्तावित शीतागार टर्मिनल बाजार में पत्तन शहरों या मैट्रोपोलिटन शहरों में, जो मुख्य खपत के शहर हैं अवस्थित किया जाना है तो प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है । दुग्ध शीतागार या मछली शीतागार के मामले में भी यह प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है ।
5. रेखाचित्रों का सैट ।
6. राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला पत्र । और
7. नगरपालिका समिति/नगर निगम से या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से शीतागार के सन्निर्माण के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' या विकल्पतः एक ऐसी घोषणा कि शीतागार का स्थल किसी स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर नहीं है ।
8. उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि निम्नलिखित दस्तावेज भी, जहां कहीं ये लागू हों, प्रस्तुत की जाएंगी :—
   1. 30 कि० मी० के भीतर क्रियाशील शीतागारों की संख्या ।
   2. शीतागार स्थापित करने के लिए न्यायौचित्य-विवरण ।
   3. बैंक/वित्त निगम से प्राप्त पत्र की प्रति या वित्तीय सहायता के लिए आशय-पत्र ।
   4. मशीनरी और ऊष्मारोधन की सूची ।
   5. अनुज्ञाप्राप्त रजिस्ट्रीकृत इंजीनियर/वस्तुविद् से विस्तृत से निर्माण प्राक्कलन ।

आवेदन प्ररूप भरने और रेखांक चित्र तैयार करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को भली प्रकार समझ लिया जाए

आवेदन प्ररूप 'ख'

भूमि (आवेदन का स्तम्भ 2): आवेदन प्ररूप के साथ, भूमिक्रम-विलेख की अनुप्रमाणित प्रति/निश्चित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए भूमि-क्रय करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार कर लिया जाना चाहिए :—

(क) भूमि स्पष्ट हक वाली होनी चाहिए और स्वामित्व किसी प्रकार विवादग्रस्त नहीं होना चाहिए,

(ख) भूमि उच्च स्तर पर और बरसात के दौरान बाढ़ आदि से सुरक्षित होनी चाहिए ,

(ग) भूमि, प्रस्तावित कक्षों, भावी विस्तारों, शुष्कन शेडों, कर्मकारों की साधारण सुख सुविधाओं आदि के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, और

(घ) प्रस्तावित शीतागार का पहुंच मार्ग स्वतंत्र होना चाहिए । अन्य व्यक्ति के खेतों से होकर पहुंच मार्ग अनुमोदित नहीं किया जाएगा ।

मशीनरी, ऊष्मारोधन आदि की विशिष्टियां : (आवेदन का स्तम्भ 3) :

उद्यमकर्ता किसी ख्यातिप्राप्त फर्म से प्रस्तावित मशीनरी की सूची के साथ व्यापक स्कीम प्रस्तुत करेगा । यदि प्रस्तावित मशीनरी में बाद में कभी कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह निदेशालय को सूचित करके उसकी बाबत अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली जानी चाहिए । ऐसा करने में असफल होने से अनुज्ञा अनुदत्त की जाने में देरी हो सकती है ।

ऊष्मारोधन : निम्नलिखित मानक ऊष्मारोधी सामग्रियों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है । प्रत्येक मामले में अपेक्षित न्यूनतम मोटाई उसी के सामने दिखा दी गई है :—

	दीवार	फर्श	छत
1. कार्क	80 मिमी	40 मिमी	1005 मिमी
2. फाइबर ग्लास	80 मिमी	50 मिमी	100 मिमी
3. थर्मोकोल	80 मिमी	50 मिमी	100 मिमी
4. धान की भूसी	30 मिमी	30 मिमी	45 मिमी
5. बुरादा	30 मिमी	30 मिमी	45 मिमी

धान की भूसी/बुरादा प्रयुक्त होने की दशा में, जलरोधक का आनवार्यतः प्रयोग किया जाना चाहिए ।

ऐसे शीतागार की, जिसमें कुक्कट, मछली या दुग्ध उत्पाद भण्डारकृत किए जाने हैं, न्यूनतम अपेक्षित मोटाई निम्नवत् है:—

	—10 फा० ताप के लिए		—40 फा० ताप के लिए	
	दीवार	छत	फर्श	
फाइबर ग्लास	150 मिमी	200 मिमी	100 मिमी	200 मिमी चारों ओर
थर्मोकोल	150 मिमी	200 मिमी	100 मिमी	मिमी —यथोक्त

धान की भूसी/बुरादे की ऊष्मारोधन, ऐसे शीतागार में, जिसमें उप शून्य तापमान से नीचे उत्पाद भण्डारकृत किए जाते हैं, स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

सिंडर ऊष्मारोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

प्रशीतक:— एफ 12, एफ 22 या अमोनिया गैस को सामान्यतः प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

शीतागार की धारिता (आवेदन का स्तम्भ 4) :

स्तम्भ 4 में वर्णित आन्तरिक विमा ऊष्मारोधन के पश्चात् की स्पष्ट विमाएं होनी चाहिए । विमा मीटरी प्रणाली में दी जानी चाहिए ।

रेखाचित्र :

रेखाचित्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:—

(क) प्रधान रेखांक—प्रधान रेखांक में, सान्निध्य के महत्वपूर्ण भू-चिह्नों के साथ प्रस्तावित अवस्थान उपदर्शित किया जाना चाहिए । यदि प्रधान रेखांक ग्राम या नगरपालिका मानचित्र पर प्रस्तुत किया जाता है तो अनुज्ञा अनुदत्त करने की प्रक्रिया में शिथिलता की जा सकती है किन्तु जब कभी ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो प्रधान रेखांक अनिवार्यतः महत्वपूर्ण राजमार्ग, महत्वपूर्ण भवन, राजमार्ग पर किलोमीटर के पत्थर आदि के संदर्भ से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी अवस्थिति का पता लगा सके जो परिक्षेत्र से सुपरिचित नहीं है ।

(ख) स्थल रेखांक —स्थल रेखांक में, भूमि का प्रस्तावित भूखंड और पार्श्व के भूखंडों के स्वामियों का नाम दर्शित किया जाना चाहिए । कक्षों का, पूर्व शीतलन कक्षों का, शुष्कन शेडों, का संयानित्रों का, मशीन कक्ष का, कार्यालय का और अन्य उपयोज्य भवनों का, जैसे , गौशालाओं, कर्मकार आवासी

क्षेत्र आदि का परिक्षेत्र स्पष्टतः चिह्नित किया जाना चाहिए। पहुंच मार्ग स्पष्टतः चिह्नित किया जाना चाहिए। शुष्कन शेड अवश्य दर्शित किया जाना चाहिए। शुष्कन शेड का न्यूनतम क्षेत्र, भण्डारकरण क्षमता के प्रति 2 वर्ग फुट (0.1 वर्गमीटर) के हिसाब से होना चाहिए। शीतागार कक्ष इस प्रकार अवस्थित होने चाहिएं कि दीवारें भूखण्ड की चाहार दीवारों की सम्पाती न हो जाए।

(ग) विस्तृत रेखांक :—विस्तृत रेखांक में भवन की पूरी-पूरी विभाएं/विवरण, सन्निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, रैंक संरचना का ब्यौरा, क्षैतिविक/उच्चाधर रैंक संरचना / प्रस्तावित गैलरी/मार्गों की संख्या और आकार उपदर्शित किया जाना चाहिए। गैलरी इस प्रकार अवस्थित की जानी चाहिए कि अल्प सूचना पर थैले बाहर निकाले जा सकें और सभी थैलों का निरीक्षण कारबार अन्तरालों पर किया जा सके। वांछनीय यह है कि दो गैलरियों के बीच 5 से 6 मीटर तक की दूरी बनी रहे। शी आ० 19 के अनुसार गैलरियों की न्यूनतम चौड़ाई 0.76 मीटर है। दीवारों और थैलों के बीच तथा फर्श और थैलों के बीच 20 सें मी० वायुरोध की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी कक्षों में अनिवार्यतः वायु तालकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) काट संबंधी ब्यौरे :—एक अनुप्रस्थ काट खींचा जाना चाहिए जिससे कि उसमें अधिकतम ब्यौरे दर्शित किए जा सकें। इसमें कक्षों की नीव के ब्यौरे उनकी भीतरी और बाहरी ऊंचाई उपदर्शित की जानी चाहिए। सामान्यतः, शीतागार में छह से अधिकतम प्रक्रमों की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए।

खाद्य पदार्थ की उपलभ्यता (आवेदन का स्तम्भ 5) : जिला कृषि अधिकारी से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जा सकता है। इस प्रमाणपत्र में खेती के अधीन क्षेत्र तथा शीतागार में भण्डारकरण के लिए आशयित आलू की और / या अन्य फसलों की कुल प्राप्ति दर्शित की जानी चाहिए।

शीतागार कक्ष (क्षेत्रों) की संख्या (आवेदन का स्तम्भ 6) :

स्तम्भ 6 में, 30 कि० मी० के भीतर या इसके आसपास क्रियाशील शीतागारों की सूची संलग्न की जानी चाहिए।

शीतागार के स्थापन का न्यायोचित्य (आवेदन का स्तम्भ 7) : संबंधित क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की उपलभ्यता और विद्यमान शीतागारों के विशेष संदर्भ में अतिरिक्त शीतागार के परिनिर्माण के न्यायोचित्य के बारे में एक अलग पत्र अनुलग्न करें।

शक्ति की उपलभ्यता (आवेदन का स्तम्भ 8) : शक्ति की समुचित उपलभ्यता विनिश्चित कर ली जानी चाहिए। राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त आश्वासन पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यदि आपात उपयोगी (स्टेण्ड बाई) जनित्र सेटों की प्रस्थापना का प्रस्ताव है तो उसे भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।

जल की उपलभ्यता (आवेदन का स्तम्भ 9) : यह वांछनीय है कि ट्यूबवेल से जल की अविच्छिन्न उपलभ्यता बनी रहे। जल की कठोरता का परीक्षण सुनिश्चित कर लिया जाए जिससे कि संचारित पाइप में बार-बार जल के जम जाने को रोका जा सके। जल के कठोर होने की दशा में, अभिक्रिया संयंत्र की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

वित्त स्रोत (आवेदन का स्तम्भ 10) : यदि कोई ऋण मंजूर किया जाता है तो बैंक/वित्त निगम से प्राप्त पत्र की एक प्रति संलग्न की जा सकती है। यदि अनुज्ञा की प्रत्याशा में ऋण मंजूर नहीं किया जा सकता है तो उस दशा में एक आशय-पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

प्रस्तावित शीतागार का अर्थतंत्र (आवेदन का स्तम्भ 11) : प्राक्कलन को सावधानी से निर्धारित किया जाना चाहिए। अप्रसामान्य उच्च/निम्न लागतों की दशा में, आंकड़े किसी ख्यातिप्राप्त / अनुज्ञप्त फर्म के प्राक्कलन से समर्थित हों।

शीतागार प्राप्तियों की संगणना करते समय, केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई विद्यमान दरों को ध्यान में लिया जा सकता है।

प्रपत्र 'ग'

[खण्ड 4(2) देखिए]

शीतागार आदेश, 19····के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता :
2. शीतागार का अवस्थान : डाकघर
   : जिला
   : पिन कोड
3. शीतगारों की संख्या और आकार,—
   (i) प्रत्येक शीतागार का आकार
   ···· ···· ऊंचाई
   (ii) सभी शीतागारों की कुल घन धारिता
   योग·····घनमीटर
4. हिमीकरण संयंत्र की प्रति 24 घंटे में प्रशीतन धारिता, टनों में
5. विशिष्टियों सहित मशीनरी की सूची
6. मोटर (रों०) अन्य मूलगति उत्पादक (कों) की कुल अश्व शक्ति
7. उन खाद्य पदार्थ(थों) का / के नाम, जिनको शीतागार में भण्डारकरण के लिए मैं / हम स्वीकार करने का आशय रखता हूं/रखते हैं।
8. मैं/हम, शीतागार आदेश, 19···· के उपबन्धों के अनुसार देय अनुज्ञप्ति फीस की बाबत·····रु० की रकम का बैंक ड्राफ्ट सं० ····· तारीख·····अग्रेषित करता हूं / करते हैं।
9. मैं/हम शीतागार आदेश, 19—— के सभी उपबन्धों के अनुपालन का वचनबद्ध करता हूं/करते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख———

प्रपत्र 'घ'

(खण्ड 7 देखिए)

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन और निरीक्षण निदेशालय

भारत सरकार

शीतागार आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति
अनुज्ञप्ति सं०····· ····श्री०आ०

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता
2. शीतागार का अवस्थान

यह अनुज्ञप्ति, शीतागार आदेश, 19···· के उपबन्धों के (जिनके अन्तर्गत उस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तें और निबन्धन भी हैं) अधीन रहते हुए, अनुदत्त किया जाता है, और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

स्थान :

तारीख : अनुज्ञापक अधिकारी]

विधिमान्यता की अवधि

विधिमान्यता की अवधि	संदत्त अनुज्ञप्ति फीस	शीतागार की कुल धारिता (घन मीटरों में)	अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ङ'

[खण्ड 12(1) देखिए]

शीतागार आदेश के अधीन वर्ष .... की बाबत अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

1. शीतागार का नाम और पता
2. अनुज्ञप्ति संख्यांक
3. यदि मशीनरी में कोई बड़ा परिवर्तन किया गया है तो वह उपदर्शित किया जाए।
4. मैं/हम शीतागार आदेश, 19... के सभी उपबन्धों का अनुपालन करने को वचनबद्ध करता हूं/करते हैं।
5. मैं/हम, शीतागार आदेश, 19.... के उपबन्धों के अनुसार देय नवीकरण फीस की बाबत ....रु० की रकम का बैंक ड्राफ्ट सं० ....तारीख...... अग्रेषित कर रहा हूं/रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

प्ररूप 'च'

[खण्ड 18(1) देखिए]

शीतागार रसीद—परक्राम्य/अपरक्राम्य

क्रम संख्यांक..........

शीतागार का नाम और अवस्थान

शीतागार अनुज्ञप्ति सं०..........जो..........तक विधिमान्य है।

.... से निम्नलिखित

(निक्षेपकर्ता का नाम और पता)

वर्णन का खाद्य पदार्थ प्राप्त हुआ है।

नाम	वर्ग या मानक क्वालिटी और/या श्रेणी	लाटों या/पैकेजों की संख्या	भार (कि०ग्रा० में) या माप आदि में शुद्ध मात्रा	भारकर्ता/मापकर्ता/श्रेणीकर्ता/नमूनाकार के हस्ताक्षर और अनुज्ञप्ति संख्यांक

1. माल की स्थिति: (1) अच्छा, (2) उचित, (3) औसत,
2. पैकेज पर अवक्रेता का प्राइवेट चिन्ह, यदि कोई है
3. भण्डारकरण की दर और अन्य प्रभार
4. अग्नि/बिल्वे/अन्य आकस्मिकताओं के विरुद्ध बीमाकृत (तारीख आदि की बाबत विशिष्टियों सहित पालिसी सं०)
5. बीमाकृत और बीमा कम्पनी का नाम
6. कितनी रकम के लिए बीमाकृत है
7. भण्डारकरण के लिए कृषि उत्पाद..........से..........तक के लिए स्वीकार किया गया है।
8. निक्षेप के समय बाजार दर.......मूल्य..........
9. निक्षिप्त खाद्य पदार्थ पर पृष्ठांकन द्वारा हस्तान्तरण से धारणाधिकार, बन्धक या अन्य विल्लंगम सर्जित करने वाली विशिष्टियां।

यह रसीद, शीतागार आदेश, 19... के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

अवक्रेता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर
तारीख..........	तारीख..........

नीचे उल्लिखित और वर्णित खाद्य पदार्थ को शीतागार से परिदान के लिए प्राप्ति से निर्मुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थ का अनिर्मुक्त अतिशेष निर्मुक्त भाग पर असंदत्त प्रभारों और अग्रिम के लिए धारणाधिकार के अधीन है।

तारीख	निर्मुक्त खाद्य पदार्थ का नाम और उसकी मात्रा	अवक्रेता के हस्ताक्षर	रसीद पर देय खाद्य पदार्थ का नाम और उसकी मात्रा	अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

फल, सब्जी और अन्य वस्तुओं के भण्डारकरण की शर्तें

1. ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वे अपने बोरों को तौलवा लें। उचित तोल न हो सकने पर जिम्मेवारी ग्राहक की होगी।
2. शीतागार प्राकृतिक जल शुष्कन या अन्य कारणों से हुई सिकुड़न या भार में कमी के कारण होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा किन्तु यह तब जब वह सकल भार के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।
3. शीतागार, प्रबन्ध के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भण्डारकृत माल को हुई क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। शीतागार को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह क्षतिग्रस्त माल का, यदि उसे लिखित प्रज्ञापना जारी किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर हटा नहीं लिया जाता, निपटान कर दे। प्रज्ञापना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी।
4. न्यूनतम भण्डारकरण प्रभार एक मास के लिए होगा। उत्तरवर्ती अवधि में, एक पक्ष या उसके किसी भाग के लिए 15 दिन का किराया प्रभारित किया जाएगा।
5. संदाय कर दिए जाने पर ही भण्डारकृत माल का परिदान किया जाएगा।

प्ररूप छ-I

पृष्ठ सं०
शीतागार का नाम
पता

दैनिक अतिशेष रजिस्टर

तारीख	वस्तु	पिछला अतिशेष	दिन के दौरान प्राप्ति	दिन के दौरान निर्गम	अग्रनीत अतिशेष

प्रबन्धक/स्वत्वधारी के हस्ताक्षर
तारीख .....

प्ररूप छ- II

पृष्ठ सं०
शीतागार का नाम
पता

लदाई रजिस्टर

रसीद संख्यांक	सेब	आलू*	सन्तरे*	किराना*	अन्य मदें*	पक्षकार का नाम	रैक संख्यांक	रैक संख्यांक, यदि बदली गई है

*जहां लागू न हो, काट दें ।

प्रबन्धक/स्वत्वधारी के हस्ताक्षर

प्ररूप छ-III

पृष्ठ सं०
शीतागार का नाम
निक्षेपकर्ता(ओं) का नाम

स्टाक खाता

प्राप्ति/निर्गम की तारीख	मात्रा	गेट पास संख्यांक	अवधि, जिसके लिए किराया देय है	शोध्य रकम	टिप्पणियां

प्रबन्धक/स्वामी के हस्ताक्षर
तारीख .....

प्ररूप छ-IV

पृष्ठ.....का लेखा
शीतागार का नाम और पता

(रोकड़) खाता

तारीख	विशिष्टियां	फोलियो	नामे	जमा	अतिशेष

प्रबन्धक/स्वामी के हस्ताक्षर
तारीख .....

प्ररूप छ-V

पृष्ठ
शीतागार का नाम और पता

रोकड़ बही

मास और तारीख	विशिष्टियां	खाता फोलियो	रकम	योग

प्रबन्धक/स्वामी के हस्ताक्षर
तारीख .....

प्रकप छ-VI

तारीख .....

शीतागार का नाम

पता

गेट पास संख्यांक

मैसर्स ..... को निम्नलिखित माल का निर्गमन किया

विशिष्टियां	मात्रा	रसीद सं०	टिप्पणियां

उपर्युक्त माल अच्छी और सन्तोषजनक स्थिति में और इस गेट पास की एक प्रति प्राप्त की ।

ग्राहक के हस्ताक्षर

तारीख .....

भण्डारी

तारीख

प्रकप 'ञ'

(शीतागार आदेश, 19... का खण्ड 12(1) देखिए)

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता
2. शीतागार का अवस्थान और पता
3. शी० आ० अनुज्ञप्ति सं० शी० आ० ..... और शीतागार की कुल धारिता, घन मीटरों में .....
19... के दौरान शीतागार में भण्डारकृत खाद्य पदार्थ की मात्रा का उपदर्शक विवरण

क्रम सं०	भण्डारकृत खाद्य पदार्थ का नाम	भण्डारकृत खाद्य पदार्थ की मात्रा (मीटरी टनों में)	वह तापमान और सापेक्ष आर्द्रता, जिस पर खाद्य पदार्थ भण्डारकृत किया गया है	भण्डारकृत खाद्य पदार्थ के भण्डारण प्रभार, प्रति क्विंटल प्रति मौसम	प्रति यूनिट विद्युत प्रभार	प्रति 1000 गैलन जल प्रभार	शीतागार की कुल धारिता में से उपभोग की गई धारिता का प्रतिशत और अनुपयोजित धारिता के कारण, यदि कोई है	टिप्पणियां

प्रबन्धक/स्वत्वधारी के हस्ताक्षर

तारीख .....

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1980

S.O. 2453.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Cold Storage Order, 1980;

(2) It extends to the whole of India except the States/Union Territories exempted in this regard by the Central Government;

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires ;

(a) "Cold Storage" means any chamber or chambers insulated and mechanically cooled by refrigeration machinery and used for storing foodstuffs but does not include refrigerated cabinets or coolers having capacity of less than 25 cubic metres;

(b) "Cold Storage receipt" means a receipt issued by a licensee in token of having received foodstuffs from a hirer for storage in a cold storage;

(c) "Foodstuffs" includes,—

(i) fruits, whether fresh, dried, dehydrated or preserved;

(ii) vegetables including seed potatoes, whether fresh, dried, dehydrated or preserved;

(iii) meat, whether fresh, frozen, dried or preserved;

(iv) fish, whether fresh, frozen or dried;

(v) eggs, whether shelled or unshelled;

(vi) milk and milk products;

(vii) species and condiments; and

(viii) any other food or food products which the Central Government may, by notified order, specify from time to time.

(d) "form" means a form appended to this Order.

(e) "hirer" means any person who hires on payment, space in a Cold Storage for storing foodstuffs;

(f) "licence" means a licence granted under this Order;

(g) "licensee" means a person holding a licence;

(h) "Licensing Officer" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India and includes any other officer of the Central Government, not

below the rank of the Deputy Agricultural Marketing Adviser, Government of India, or the officer of the State Government not below the rank of the Deputy Secretary to Government, empowered by him, as notified from time to time, to exercise all or any of his powers or to discharge all or any of his functions under this Order;

(i) "Notified Order" means an Order notified in the Official Gazette.

(j) "Schedule" means the Schedule appended to this Order.

3. Prohibition of construction of new cold storage or expansion of existing cold storage without permission.—No person shall—

(a) construct a cold storage or expand the licensed capacity of any existing cold storage for storing foodstuffs; or

(b) store accept or undertake to accept for storage in any cold storage, any foodstuff, except under and in accordance with the terms and conditions of a licence :

Provided that the Licensing Officer may, on an application made in this behalf in Form 'A' exempt a cold storage run by a hospital, hotel or a hostel or an institution, if he is satisfied, after making such enquiries as he may consider necessary, that the cold storage is intended for the bonafide use of such establishment only.

4. Application for permission to construct, expand of commission a cold storage.—(1) Any person desiring to construct a cold storage, or expand an existing old storage, shall make an application in Form 'B' (in duplicate);

(2) Any person desiring to obtain a licence for running a cold store shall make an application to the Licensing Officer in Form 'C' (in duplicate);

(3) Every such application shall be accompanied with the fees specified in clause 5 and three copies of the blue prints of the cold storage building plant or, as the case may be of blue prints of the expansion of the existing cold storage building ;

(4) Where the applicant proposes to construct more than one cold storage or to expand more than one cold storage he shall obtain a separate licence for each such cold storage by applying separately for each such cold storage.

5. Fee for licence.—Application fee and licence fee shall be as follows :—

(a) Application fee :

(i) Application fee for permission to construct a cold storage or expansion f cold storage.	: Rs. 25.00 to be paid with the application.
(ii) Application fee for issue of duplicate licence.	: Rs. 10.00

(b) Licence fee Renewal fee.—payable per calender year or part thereof :

(i) Cold storage with a storage capacity exceeding 10, cubic metres.	: Rs. 500.00
(ii) Cold storage with a storage capacity exceeding 2,500 cubic metres but not exceeding 10,000 cubic metres	: Rs. 300.00
(iii) Cold storage with a storage capacity of not less than 25 cubic metres but not exceeding 2,500 cubic meter	: Rs. 100.00

6. Factors to be considered in granting or refusing a licence :—In granting or refusing a licence, the Licensing Officer shall have regard to the following factors namely :—

(i) the number of cold storage already operating in the area in which the cold storage in respect of which the licence is applied for is proposed to be constructed or expanded and the availability of foodstuffs for storage in such cold storage;

(ii) the refrigeration insulation and sanitary conditions of the cold storage, as specified in the Schedule in respect of which the licence is applied for;

(iii) suitability of qualifications/experience of the staff employed or proposed to be employed for manning the plant; and

(iv) any other matter which the Licensing Officer may consider necessary for the purpose.

7. Grant of licence :—(i) On receipt of an application under clause 4, the Licensing Officer may, if he is satisfied having regard to the factors specified in clause 6 that there is no objection to grant a licence to the applicant, he may grant the applicant a licence in form 'D';

(ii) Where having regard to the factors specified in clause 6 that Licensing Officer is of opinion that the applicant should not be granted the licence, he may, after giving applicant opportunity of being heard, refuse to grant the licence recording in writing the reasons for such refusal and furnish a copy thereof to the applicant;

(iii) Where the applicant is refused a licence, the licence fee paid by the applicant with his application shall be refunded to him.

8. Relaxation of conditions of licence.—Every licence granted under clause 7 shall be subject to the terms and conditions specified in the Schedule :

Provided that in the case of a cold storage already in existence before the commencement of this Order, the Licensing Officer may relax any condition if he is satisfied that the compliance with such a condition is not practicable.

9. Cancellation of licence.—The Licensing Officer may cancel any licence if he is satisfied that the licensee has,—

(a) parted in whole or in part, with his control over the cold storage, or

(b) ceased to run his cold storage, or

(c) levied any charges in excess of the charges permitted under clause 20, or

(d) contravened or failed to comply with any of the terms and conditions specified in the Schedule or any directions which may be issued by the Licensing Officer for the proper implementation of this order :

Provided that, before cancelling any licence, the Licensing Officer shall given ten clear day's notice to the licensee stating the grounds on which it is proposed to cancel the licence and shall give the licensee an opportunity to show cause for not cancelling the licence :

Provided further that where immediate action is required in the public interest the Licensing Officer may, for reasons to be recorded in writing without giving the licensee an opportunity to show cause cancel the licence.

10. Licensee not entitled to compensation or refund of licence fee.—Where any licence is cancelled the licensee shall not be entitled to any compensation or refund of fee paid by him for such licence.

11. Period of validity of licence.—Every licence shall, unless cancelled earlier, expire on the 31st day of December of the year in which the licence is granted.

12. Renewal of licence :—(1) Every licensee desiring to get his licence renewed shall on or before the 31st day of October, make an application in Form 'E' and Form 'H' (in duplicate) to the Licensing Officer accompanied with the fee

specified in clause 5. Where a licensee fails to make an application within the date aforesaid he may make an application with the fee specified in sub-clause (b) of clause 5 at any time before the expiry of the licence on payment of a penalty calculated at rupees one hundred for the delay of every month or part thereof.

(2) On receipt of an application for the renewal of licence the Licensing Officer may either renew the licence or refuse to renew it. Where renewal is refused the licensee shall be given an opportunity of being heard and the reasons for such refusal be recorded in writing and a copy thereof shall be furnished to the applicant and the renewal fee received from the applicant shall be refunded to him.

(3) Where the licensee fails to apply for renewal before the date specified in sub-clause (1) it shall not be lawful for the licensee, after the date of expiry of his licence to run his cold storage unless he obtains renewed licence in that behalf.

13. Issue of duplicate licence :—(1) Where a licence is lost, destroyed, torn, defaced or mutilated the licensee may apply for a duplicate copy of the licence. Every such application shall be accompanied with the fee specified in sub-clause (a) (iii) of clause 5. On receipt of an application the licensing Officer shall grant a duplicate copy of licence to the licensee.

14. Regulation and transfer of licence.—(i) A licence granted under this Order shall not be transferred to any other person without the prior approval of the Licensing Officer.

(ii) Where a licensee sells or otherwise transfers a cold storage to another persons or persons or suspends operation of the cold storage for a period exceeding six months the licensee shall surrender the licence to the Licensing Officer within one month of such sale or transfer or suspension.

(iii) Any charge in partnership shall be notified to the Licensing Officer within one month of such a change.

(iv) The purchaser or the transferee, as the case may be, shall apply to the Licensing Officer for the grant of new licence in accordance with this Order.

(v) In the event of any change in the name, style or location of the cold storage the licensee shall forthwith intimate the change to the Licensing Officer and within one month from the date of intimation forward his licence to the licensing Officer along with the necessary documents for effecting the necessary change.

15. Contract of agreement with hirer.—The licensee shall not enter into a contract or agreement with any hirer in contravention of any of the provision of this Order.

16. Overloading.—No licensee shall load the cold storage beyond the licensed capacity.

17. Provisions regarding storage of foodstuffs.—(i) No licensee shall refuse to accept for storage in the cold storage any foodstuffs tendered by any person if such person offers to pay the required cold storage charges and if the accommodation for storage of such foodstuffs in the cold storage is available :

Provided that, if the foodstuffs tendered for storage are likely to cause damage to any other foodstuffs stored in the cold storage or if for the storage of the foodstuffs so tendered, maintenance of different ranges of temperature than are normally required for the foodstuffs stored in bulk is required, then the licensee may refuse to accept for storage, the foodstuffs so tendered :

Provided further that, if the Licensing Officer is satisfied that storage of any particular category of foodstuff is not in the public interest, he may by a public notice prohibit such storage and thereupon the licensee shall refuse to store such foodstuff.

(ii) Where any hirer demands delivery of the whole or any part of his consignment stored in the licensee's cold storage, the licensee shall on payment of the charges fixed under clause 20 within twenty four hours of such demand, deliver the whole or, as the case may be, the part of the consignment to the hirer.

(iii) Consignments of foodstuffs stored by each hirer or covered by each storage receipt shall be stored by the licensee separately so as to ensure their easy identification and easy delivery to the hirers concerned.

18. Cold storage receipts.—Defined in 2(b).—(i) For the foodstuff stored in a cold storage by each hirer, the licensee shall issue a cold storage receipt in Form 'F'.

(ii) The receipt shall, unless it is otherwise specified thereon be transferably by endorsement and delivery and shall entitle the holder in due course to receive the goods specified in it as if he were the original hirer; and

(iii) If a cold storage receipt is lost, destroyed, torn, defaced or otherwise becomes illegible, the licensee shall, on an application made by the hirer issue a duplicate receipt.

19. Power to requisition the storage.—(i) The Licensing Officer may, in the public interest by order in writing served on any licensee requisition the whole or a part of the space in the licensee's cold storage for the period specified in the order and on payment of charges fixed under clause 20 of the Order.

(ii) The space so requisitioned may be allotted by the Licensing Officer for storing the foodstuffs to one or more persons specified in the order.

20. Fixation of charges for storage.—Keeping in view the cost of the machinery, depreciation electric charges, etc., the Licensing Officer shall, by order in the Official Gazette, from time to time, fix the maximum charges which a licensee may charge for storing foodstuffs in the cold storage or for any other service connected therewith.

21. Inspection facilities, etc.—(i) The licensee shall keep his licence in safe custody in cold storage premises and produce it on demand to the Licensing Officer.

(ii) Every licensee shall provide all facilities and assistance to the Licensing Officer for inspecting the cold storage premises, machinery, equipment foodstuffs, stored therein, books, records and accounts at any time.

22. Maintenance of records and submission of returns.—Every licensee shall,—Maintain accounts, books and records relating to storage of foodstuffs at the licensed premises in the Forms G-I to G-VI, and submit to the Licensing Officer returns and statements in the Forms G-I to G-VI.

23. Power to call for information, etc.—(i) The Licensing Officer may with a view to securing compliance with this Order,—

(a) require any licensee to give any information in his possession with respect to the foodstuffs stored by him in the cold storage.

(b) enter, inspect and search any premises where the cold storage is installed to run at any time with a view to satisfy himself that the requirement of this Order are being complied with.

(c) prohibit by an order in writing further storage or disposal of any foodstuffs in respect of which he has reason to believe that any contravention of this Order has taken place.

(d) prohibit a licensee by an order in writing from appointing a person to act as an operator if he has reason to believe that the person has not got the requisite qualification or knowledge or experience of the job.

(ii) Every licensee shall be bound to furnish such information as may be required by the Licensing Officer and afford all necessary facilities to him for the purpose of exercising his powers under paragraph(b) of sub-clause (1).

(iii) Subject to the provision of this clause the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search, so far as may be, apply to searches under this clause.

24. Appeal.—Any person aggreived by an order of the Licensing Officer made under this Order may prefer an appeal to the Officer of the Central Government not below the rank of the Joint Secretary appointed by the Central Government in this behalf by special order from time to time.

25. Delegation.—The Central Government, may be a notified order direct that such of the powers and functions of the Licensing Officer as may be specified in the Order, may be exercised or, as the case may be, discharged by any State Government or such officer or authority subrodinate thereto as may be specified in the order within the territorial limits of that State.

26. Repeal and Saving.—The Cold Storage Order, 1964, is hereby repealed, except in respect of things done or omitted to be done thereunder before such repeal.

SCHEDULE

(See Clause 8)

PART I

SANITARY REQUIREMENTS :

1. The premises where the cold storage is installed shall be clean. Inside the cold storage electric lights shall be provided at the rate of 1 watt per 4645 sq. cm. The disinfecting or deodourising of the cold storage shall, however, be carried out as and when required.

2. The licensee shall not store any product which may be repugnant or alient to the smell of the foodstuffs stored in the cold storage. Products having repugnant smell shall, however, be stored in separate chambers of the cold storage.

3. All yards, outhouses, stores and all approaches of the premises where the cold storage is installed shall be kept clean and sanitary.

4. No person suffering from any infectious or contagious disease shall be allowed to work in the cold storage. Arrangements shall be made for examination of the employees other than daily paid labourers working in the cold storage once a year to check that they are free from any infectious contagious or other diseases.

5. The employees working inside the cold storage operating above freezing point shall be adequately provided with proper clothes to protect them from cold. The employees working in a cold storage which operates below freezing point shall also be provided with boots.

6. Adequate toilet facilities shall be provided separately for males and females within the premises.

7. All steps stairs and gangways shall be of sound construction and properly maintained and provided with hand rails to ensure safety.

PART II

REQUIREMENTS AS TO OPERATION :

1. The doors of the cold storage shall be provided with adequate insulation and shall be kept reasonably air-tight. The design of the doors shall be such that a person shall be able to open it from inside as well as outside.

2. Whether racks are provided they shall be so constructed that loading and unloading operations shall be carried out without endangering the lives of the employees working in the cold storage.

3. For the distribution and circulation of air and for actual operation of loading and unloading, the following directions shall be adhered to namely :—

(a) The passage between the rows of the racks shall not be less than 0.76 metres.

(b) The racks shall be kept away at least 20 cms. from the walls and floor.

(c) A gap of at least 30 cm. shall be maintained between the ceiling and the top level of the load in the top most shelf of every racks.

(d) A gap of at least 7.5 cm. shall be maintained on every shelf of a rack between the load on the shelf and the succeeding shelf.

4. The diffusers or direct expansion pipes for conveying the refrigerant shall be so arranged in the cold storage so as to maintain proper temperature with maximum allowable variation of $\pm$ C and percentage of relative humidity with an allowable variation of ± 5 per cent in every location of the cold storage where foodstuffs are stored.

5. The cold storage shall be provided with thermometres reading dry bulb and wet bulb temperatures. The number and location of thermometres shall be dependent on the size and capacity of the cold storage and shall be as instructed by the Licensing Officer or the Officer authorised by him in this behalf at the time of the first or subsequent inspection.

6. All moving parts of prime movers and fly wheels connected to the prime movers shall be provided with proper belt guards.

7. The suction pipe line of the compressor shall be properly insulated.

8. An alarm bell with switch inside each storage chamber shall be provided for use in case of an emergency.

9. 'First Air Box' shall be maintained in the machine room.

10. Attached to cold storage chambers, an ante-chamber or air-curtain shall be provided.

11. The receiver or condenser of the refrigerating system shall be provided with a pressure gauge with suitable range.

12. A cold storage shall satisfy safety code for mechanical refrigeration as specified in Annexure I to this Schedule.

PART III

MAINTENANCE OF LOG BOOK AND STATEMENT OF ADVANCE BOOKING :

1. Every licensee shall maintain a 'Log Book' in the form set out in the Annexure II to this Order for the maintenance of temperature and relative humidity as well as the pressure reading of the compressor on four hourly basis all throughout night and day during the operation of the cold storage unless automatic recording instruments are installed and shall be signed by the Licensee or a responsible person duly authorised by him. The Licensing Officer or any person duly authorised by him in this behalf shall sign the Log Book at every inspection after personal verification of the records.

2. Any stoppage of function of the cold storage continuously for more than 24 hours shall be reported immediately to the Licensing Officer by telegram and confirmed by letter by the licensee. The reasons for such break down shall be recorded in the Log Book and reported to the Licensing Officer.

3. Every licensee shall maintain statement of advance booking and shall furnish this statement to inspectorate shall as and when required by him.

ANNEXURE-I

(See clause 12 of Schedule)

INDIAN STANDARD

SAFETY CODE FOR

MECHANICAL REFERIGERATION

(Revised)

1. SCOPE.

1.1 This code covers safety features in the design, construction, installation operation and inspection of mechanical refrigeration system of vapour compression type, including

working conditions in the plant room which are considered reasonably necessary to safeguard life, health and property in the cold storage.

2. TERMINOLOGY

2.0 For the purpose of this code, the following definitions shall apply :

2.1 Compressor.—The equipment in which refrigerant in a refrigerating machine is compressed to increase its pressure before liquefaction.

2.2 Condensor.—A part of the refrigerating system where high pressure refrigerant gas is condensed to high pressure liquid.

2.3 Condensing unit.—A combination of equipment consisting mainly of compressors, condensers and liquid receivers (when required) for converting low pressure gas to high pressured liquid.

2.4 Evaporator.—A part of the refrigerating system where liquid refrigerant is evaporated to poduce cooling.

2.5 Expansion Valve.—A valve which makes the liquid refrigerant to expand from a high pressure to a low pressure and controls the flow of the refrigerant.

2.6 Fusible Plug.—A plug made of special fusible alloy which fuses at a predetermined temperature and relieves pressure in the refrigerating system.

2.7 High Pressure Switch.—An automatic protective device against excessive pressure on the high side. It automatically stops a compressor or a condensing unit when the pressure on the high side exceeds a predetermined limit.

2.8 Low Pressure Switch.—An automatic protective device against excessively low pressure on the low side. It automatically stops a compressor or a condensing usit when the pressure on the side falls below a predetermined limit.

2.9 Plant Room.—Room in which a refrigerating plant, other than domestic refrigerating appliances such as refrigerators, portable air conditioners, etc. (which are installed inside the living room) is installed and operated.

2.10 Pressure Relief Device.—A pressure actuated valve or device which automatically relieves the pressure in excess of its setting.

2.11 Pressure Vessel.—It is a receiver containing refrigerants under pressure.

2.12 Receiver.—A vessel forming a part of refrigerating system acting as a receptacle for liquid refrigerant.

2.13 Refrigerant.—A chemical agent used to produce cooling, by expansion from high pressure liquid to low pressure gas in a refrigerating system.

2.14 Refrigerant container.—A vessel for storage of liquid refrigerant.

2.15 Refrigerating system.—An equipment consisting of condensing unit and evaporator in which refrigerant is circulated to extract and transfer heat.

3. INSTALLATION REQUIREMENTS :

3.1 Plant Room.

3.1.1 Doors, partitions and openings.—The plant room of each refrigerating system shall be provided with a door(s) and shall have no partition or openings so as to avoid escape of refrigerants to other parts of the building.

3.12 No plant room door shall have locking devices from inside. However, facilities for bolting from inside may be provided.

3.1.3 Adequate ventilation shall be provided for each plant room. The ventilation required shall generally be in accordance with Table-1. To achieve the required ventilation, windows or doors opening to outside air or power driven exhaust fans may be provided. The sizes of the windows and doors and air displaying capacity of the exhaust fans shall be in accordance with the requirements given in Table-1. When exhaust fans are used, provisions should be made for inlet of the air to replace the air that is being exhausted by the fan. The area connected to the exhaust fan or fans shall be in accordance with the minimum duct areas as given in Table-1.

3.1.4 Emergency exist and fire extinguisher.—Each plant room shall be provided with emergency exists and fire extinguishers of suitable type (see IS 2190-1962 Code of Practice for Selection, Installation and Maintenance of Portable First-Air-Fire Appliances).

3.1.5 First Air Equipment.—First-aid equipment shall be provided in each plant room in accordance with the requirements laid down in the Factories Act, 1948, and Rules thereunder.

3.1.6 Gas Masks.—One or more gas masks or breathing apparatus of suitable type shall be kept immediately outside the plant room in an accessible portion. Canisters of the gas masks shall be renewed periodically.

3.2 Foundation and supports provided for condensing units or compressor units or other refrigeration equipment shall be substantially sound and vibration absorbing and of non-combustible construction.

3.2.1 All moving machinery shall be guarded in accordance with the provisions of the Factories Act, 1948, and the Rules thereunder.

3.3 Adequate clear space for inspection and servicing of condensing units or compressor units shall be provided.

TABLE—1

MINIMUM AIR DUCT AREA AND OPENINGS

(Clause 3.1.3.)

Weight of the refrigerant in the system kg	Mechanical discharge of air m^3/min	Duct area m^2	Open window of door area m^2
(1)	(2)	(3)	(4)
10	3.9	0.025	0.44
25	7.1	0.05	0.70
50	11.3	0.05	1.0
75	14.8	0.07	1.2
100	18.0	0.07	1.4
125	20.8	0.10	1.6
150	23.5	0.10	1.7
200	28.5	0.12	2.0
250	33	0.12	2.2
300	37	0.14	2.4
350	41	0.18	2.6
400	45	0.18	2.8
450	49	0.18	3.0
500	53	0.20	3.1
600	59	0.20	3.4
700	66	0.20	3.7
800	72	0.20	4.0
900	78	0.20	4.2
1000	83	0.20	4.4
1250	97	0.28	5.0
1500	109	0.35	5.4
2000	132	0.40	6.3
2500	154	0.45	7.0
3000	173	0.50	7.7
3500	192	0.54	8.3
4000	210	0.58	8.8
4500	227	0.60	9.4

1	2	3	4
5000	244	0.65	9.9
6000	275	0.70	10.8
7000	305	0.72	11.7
8000	333	0.75	12.5
9000	361	0.78	13.3
10000	387	0.81	14.0
12000	437	0.83	15.3
14000	484	0.84	16.6
16000	529	0.86	17.7
18000	572	0.88	18.8
20000	614	0.90	20.0

Note :—Mechanical discharge of air and open area have been derived from the following formula taken from DIN 8975 Refrigeration Plants, Safety Principles for their Construction, Equipment and Erection :

Open Window or door area, $m^2 = 0 \quad 14/\sqrt{G}$

Mechanical Discharge of air, $m^3 = 50^3 \quad /\sqrt{G2}$

Where

'G' is the charge in kgs. of the largest closed circuit of refrigerant in the engine room.

Note 2 :—Intermediate values may be obtained by calculation.

3.4 Condensing units or compressor units within enclosures shall be readily accessible for inspection and servicing.

3.5 Adequate illumination for inspection and servicing of condensing units or compressor units and other refrigeration equipment shall be provided.

3.6 Water supply connections shall be made in accordance with the requirements given in IS : 2065—1963 Code of Practice for Water Supply in Building.

3.6.1 Water used for removing heat from the refrigating system shall not be discharged into any water supply which is likely to be used for human or animal consumption.

3.7 Electrical wiring and installation of the electrical equipment shall be in accordance with the requirements of the Indian Electricity Act, and Rules thereunder and shall also conform to the requirements laid down in IS : 732—1963 Code of Practice for Electrical Wiring Installations (System Voltage Not Exceeding 650 Volts) (Revised), IS : 2274—1963 Code of Practice for Electrical Wiring Installations (System Voltage Exceeding 650 Volts) and IS : 302—1960 General Safety Requirement for Light Electrical Appliance, as applicable.

3.7.1 Electrical interlocking of the compressor with condensing water pump and cooling tower fan (where provided) is strongly recommended. The switch of the compressor motor should be interlocked with the pumping set and fan in such a way that the compressor motor will not start until the condensing water pump and fan have started.

3.7.2 It is recommended that as far as practicable the high pressure switches, low pressure switches, and other electrical control apparatus used in connection with a mechanical refrigeration system be operated on a voltage not exceeding 250.

3.8 No open flame or apparatus to produce open flame or hot surface above 425°C shall be permitted in a plant room having one or more refrigeration machines with a total refrigerant charge exceeding that mentioned in Table-2 for each cubic metre of room volume.

3.9 No open flame shall be applied to refrigerating system or refrigerant vessel when the system or vessel is charged with refrigerant.

3.10 In the case of refrigerating system using inflamable refrigerants, such as methyl chloride, ethane, etc., all electrical installations for refrigerating system shall generally conform to the requirements given.

TABLE 2—MAXIMUM PERMISSIBLE QUANTITIES OF INFLAMMABLE REFRIGERANTS

(Clause 3.8)

Name	Chemical formula	Maximum quantity q/m^3
Butane	C_4H_{10}	40
Ethane	C_2H_6	40
Ethyl Chloride	$C_2H_5C_1$	100
Ethylene	C_2H_4	32
Isobutane	$(CH_3)3CH$	40
Methyl	CH_3Cl	160
Methyl Format	$HCOOCH_3$	110
Propane	C_3H_8	40

IN IS : 1646—1961 Code of Practice for Fire Safety of Buildings (General), Electrical Installations, where applicable, and any other fire safety requirements laid down by the appropriate authority.

3.11 No refrigerating system or piping shall be installed in a passage doorway, below a staircase, or in any public place, except when suitably guarded.

3.12 Charging Refrigerant.—While charging a gauge should be provided between the refrigerant container and the machine to know the pressure at which the system is being charged. This pressure should not exceed the discharge pressure at which the compressor has to work with particular type of refrigerant.

3.13 For each installation of refrigerating system the following information mounted on a frame, should be clearly posted in the plant room :

(a) Name and make of the condensing unit;

(b) Model of condensing unit;

(c) Name and full charge of refrigerant;

(d) Full charge of oil;

(e) Quantity of refrigerant and oil charged in the system with date of charging;

(f) Pressure at which the system is tested after installation; and

(g) Change of refrigerant, if any, with date.

4. REFRIGERATING SYSTEM AND EQUIPMENT :

4.1 Refrigerant piping valves, fittings, their related parts and all material used in the construction and installation of refrigerating system shall be suitable for the refrigerant used. No material which could deteriorate due to chemical action of the refrigerant or the oil or the combination of both and moisture shall be used. Aluminium, zinc or magnesium shall not be used in contact with methyl chloride, Magnesium alloys shall not be used in contact with chloro-fluori derivatives of methane and ethane. Copper and copper alloys shall not be used in contact with ammonia.

4.2 All joints shall be readily accessible.

4.3 Joints from refrigerant copper pipe and fittings made with solder or other alloys shall have melting point of :

(a) not less than 260°C for pipe sizes up to 32mm; and

(b) 540°C for pipe sizes above 32 mm and for all the size on hot gas lines.

4.4 Stop valves shall be installed on all systems other than those using centrifugal compressors containing more than 10 kg. of refrigerant. The location of the stop valves shall be as given in 4.4.1.

4.4.1 Stop valves shall be provided at the inlet and outlet ends of each of compressor, receiver and evaporator.

4.5 Test Pressures.—All stop valves piping, joints flanges and fittings shall withstand test pressures as given in Table-3 after completion of installation and before operation.

4.6 All refrigerant piping should be supported by means of hangers, bracket straps, clamps or pedestals in such a manner as to relieve joints of harmful strains and vibrations.

4.7 Colour identification of refrigerant pipe lines shall be in accordance with the colour identification given in IS : 2379-Colour Code for identification of pipe lines.

4.8 Emergency Discharge Line.—Each refrigeration system of ammonia and sulphur dioxide having a charge of 10 kg. or more should be equipped with emergency discharge line. The discharge line should be connected directly in top of the receiver or the condenser receiver in the emergency.

TABLE 3—MINIMUM FIELD REFRIGERANT LEAK TEST PRESSURE

(Clause 4.5 and 5.3)

Name of refrigerant	Chemical formula	Minimum field refrigerant leak test pressure Kg/CM$_2$ Gauge	
		High pressure side	Low pressure side
Ammonia	NH_3	20	10.5
*Carbn Dioxide	CO_2	100	70
Dichlorodifluoromethane	CCl_2F_2	16	10
Dichlordethlene	$C_2H_2Cl_2$	2	2
Dichoromethane (Methylene Chloride)	CH_2Cl_2	2	2
Dichloromonofluoromethane	$CHCl_2F_4$	5	3
Dichlorotetrafluoriethane	$C_2Cl_2F_4$	3.5	3.5
Ethane	C_2H_6	85	50
*Methyle Chloride	CH_3Cl	15	8.5
Monochlorodifluoromethane	$CHClF_2$	20	10.5
*Sulphur Dioxide	SO_2	12	6
Trichloromonofluoromethane	CCl_3F	2	2
Trichlorotrifluoromethane.	$C_2Cl_3F_3$	2	2

*Not recommended for the installations.

Valve should be placed immediately outside the plant and there should be no valve between the emergency valve and the receiver so that in case of an emergency the valve can be operated from outside without entering the plant room. Adequate precautions should be taken to see that the emergency valve is not tempered with by an unauthorised person. The emergency valve should be covered preferably with a glass fronted box. There emergency discharge pipe should be so connected outside the building that it does not affect the surrounding locality.

5. PRESSURE DEVICES :

5.1 High Pressure Switch.

5.1.1 All condensing units or compressor units above the size normally used for domestic refrigerators shall be fitted with automatic high pressure switches.

5.1.2 The high pressure switch shall always be fitted on to the discharge side of the compressor before the discharge shut-off valve.

5.1.3 For condensing units above 7.5 kw the cut-in cycle of the high pressure switch shall not be automatic, that is after tripping, the compressor motor shall require to be started manually.

5.2 Low Pressure Switch.—Low pressure switch should be fitted wherever practicable, to all compressors other than those used for domestic refrigerators when the compressors are used for producing low temperature conditions below 0°C.

5.3 Pressure Relief Device or Fusible Plugs.—These shall be provided on the high side above the refrigerant liquid level on all condensing units. The discharge for the relief valve should be so connected that it should discharge without affecting the surrounding locality outside the building. Ammonia and sulphur dioxide refrigerants shall be discharged in vessels containing water and brine, respectively. The pressure relief valves shall be set to blow at pressures 75 to 80 per cent of those specified for minimum field refrigerant leak test pressures (on the high pressure) given in Table-3.

6. PRESSURE VESSELS :

6.1 All refrigerant containing pressure vessels shall be hydrostatically tested and thoroughly examined periodically as required under the Factories Act, 1948, and the Rules made thereunder.

6.2 All refrigerant containing pressures vessels having a net volume of 0.15m3 or more, and which may be shut-off by valves, shall be equipped with pressure relief devices or fusible plugs.

7. MAINTENANCE :

7.1 Each refrigerating system after installation shall be checked for refrigerant leaks every three months.

7.2 Pressure devices, pressure gauges and all other refrigerant controls on both the high side, and low side shall be checked periodically, the time between two such inspections not exceeding six months. Fusible plugs shall be inspected once every three months.

7.3 Moulds, cans, tanks, etc. shall be checked frequently for chemical action and corrosion from hygienic and sanitary point of view.

7.4 Electrical installation shall be checked periodically for insulation leakage, etc. in accordance with the Indian Electricity Act, 1910, and the rules made thereunder and IS : 732—1963 Code of practice for Electrical wiring Installations (System Voltage Not Exceeding 650 volts) (Revised) and IS : 2274—1963 Code of Practice for Electrical Wiring Installation (System Voltage Exceeding 650 volts).

7.5 All repairs shall be duly recorded and record of all tests carried out after repairs shall be maintained. The record should be signed by the mechanic and the engineer or officer-in-charge.

7.6 Proper precaution shall be taken that no gas other than what is in the system is charged.

7.7 Open flame shall never be applied to the gas cylinder or to the system when it is charged with refrigerant.

7.8 In a plant room in which refrigerating system containing more than 25 kg of refrigerant is installed, a card shall be placed conspicuously near the compressors giving directions for the operation of the refrigerating system including precautions to be taken in the case of a breakdown or leak and instructions for shutting down the refrigerating system in case of emergency.

ANNEXURE-II

(See Part III of Schedule)

Cold storage : Engine Room Log :

Timing	Compressor No.			Delivery pressure gauge	Crankcase oil pressure	Brine temperature	Cold chambers				Remarks
	Volts	Amps	Suction pressure gauge				No. 1		No. 2		
							DB	WB	DB	WB	
12 Midnight											
4 A.M.											
8 A.M.											
12 Noon.											
4 P.M.											
8 P.M.											

[F. No. 18-5/71-AM]
K. L. GUPTA, Under Secy.

FORM 'A'

(See Clause 3(b))

APPLICATION FOR SEEKING EXEMPTION FROM GRANT OF LICENCE UNDER THE COLD STORAGE ORDER, 1980.

1. Name of the Establishment.

1. (a) Name and address of the partners/directors/head of the institution.

2. Nature of business being carried out.

3. Location.

4. Number and size of the cold storage chamber(s).

(a) Date and year of commissioning the cold storage.

(b) Length in metre.	Breadth in metre.	Height in metre.	Capacity in cubic metres.

(c) Type and thickness of insulation.

(d) Particulars of machinery installed.

(e) Name of the foodstuff(s) being stored.

(f) Duration for which the foodstuff(s) are normally stored.

(g) End use of the foodstuff being stored.

5. Period for which exemption is required.

6. Justification for seeking exemption under the Cold Storage Order, 1980.

7. I/we hereby undertake that :—

(i) If given an exemption we shall ensure the storage of foodstuff in a proper hygienic conditions.

(ii) Premises shall be offered for inspection by the Licensing Officer under Order or any of his authorised representative at any time.

(iii) I/We shall be bound to give any information regarding the foodstuffs stored in the cold storage or any other information as and when asked for by the Licensing Officer under the Cold Storage Order, 1980.

(iv) I/We shall store the foodstuff entirely for the end use of the business as detailed in S. No. 2 above and shall under no circumstances accept any foodstuff for storage from any other person for any consideration or otherwise.

Signature of the applicant.
Date :

FORM 'B'

(See clause 4(i))

PART-A

(To be filled in by the applicant as per instructions enclosed)

APPLICATION FORM FOR GRANT OF PERMISSION TO SET UP A NEW COLD STORAGE/FOR EXPANSION OF EXISTING COLD STORAGE

1. (i) Name and address of the applicant (in capital letters).

(ii) Names and addresses of the proprietors, partners, directors, etc. (copy of firm's registration/partnership deed to be enclosed).

2. PARTICULARS OF LAND :

(i) Location.

(ii) Nearest Railway Station.

(iii) Nearest Highway.

(iv) Area in squire metres.

(v) Date of purchase (in case it is a purchased land, attested copy of Purchase Deed or other documentary proof to be enclosed).

3. PARTICULARS OF MACHINERY, INSULATION, ETC :

(i) Details of machinery purchased/to be purchased (a separate list may be attached, if desired).

(ii) Source of procurement.

(iii) Insulation :

	Material	Thickness in mm.
Main wall.		
Common wall.		
Floor.		
Ceiling.		

(iv) Refrigerant proposed.

4. CAPACITY OF THE COLD STORAGE :

(i) Number(s) of proposed cold storage chamber(s).

(ii) Internal dimensions including height of each chamber.

(iii) Total storage capacity in cubic metres of all chambers for which application being furnished.

(iv) Proposed date of starting the construction.

(v) Set of drawings are attached ? Yes/no.

5. AVAILABILITY OF THE FOODSTUFFS FOR THE COLD STORAGE :

(i) Name of the foodstuff(s) to be stored.

(ii) Source of procurement.

6. Number of cold storages operating at the place and within the radius of 40 km from the proposed site of cold store.

7. Justification for setting up of the proposed cold storage/ expansion of the existing cold storage.

8. AVAILABILITY OF POWER :

(i) Electrical load required.

(ii) Arrangements made for required electrical load, if sanction is obtained, please mention the sanctioned load with its date of sanction.

9. AVAILABILITY OF WATER :

(i) Quantity of water required.

(ii) Arrangements made for water supply.

10. SOURCE OF FINANCE :

In case financing is done by bank/state financial corporation amount of loan applied for/sanctioned with date of sanction.

11. ECONOMICS OF PROPOSED STORAGE/EXPANSION OF THE COLD STORAGE :

A. (i) Fixed capital.

(ii) Cost of land.

(iii) Cost of building.

(iv) Cost of machinery.

(v) Cost of insulation.

(vi) Cost of rack.

(vii) Cost of any other matter.

B. Working Capital.

Total :—

C. Expenditure :

(i) Running expenses (charges for electrical power, water, refrigerant gas, lubricant, workshop, repair and maintenance, labour for loading and unloading, grading and packing, etc. transport fees, interest on capital outlay, insurance, depreciation, etc.

(ii) Establishment : Staff and office expenses, etc.

(iii) Over heads.

Total :

D. Profit and loss account :

(i) Receipts.

(ii) Expenditure.

(iii) Proposed rental rate.

(iv) Percentage of profit on the total capital outlay.

Signature(s) of the applicant.
Date.

Enclosures (Tick mark which is enclosed)

1. Partnership Deed (attested copy)/Memorandum and Article of Association.

2. Affidavit in support of proprietorship.

3. Land Purchase Deed (attested copy).

4. Certificate of registration of firm (attested copy).

5. 'No Objection Certificate' from local authority/Municipal Corporation.

6. Letter from the Agricultural Officer regarding production.

7. Following drawings :

(i) Key Plan.

(ii) Detailed Plan.

(iii) Site Plan.

(iv) Sectional Details.

Note :—Strike out whichever is not applicable.

PART 'B'

(to be filled in by the office)

REPORT OF THE REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTRATE OF MARKETING AND INSPECTION

Particulars	Whether in order, if not, note the discrepancies.
1. Key Plan.	
2. Site Plan	
3. Detailed Plan.	
4. Sectional Details.	
5. (i) Partnership Deed. (ii) Affidavit (In support of proprietorship). (iii) Memorandum & Article of Association	
6. Land Purchase Deed.	
7. Certificate of registration	
8. 'No Objection Certificate from the Local Authority/ Municipal Corporation.	
9. Letter from the Agricultural Officer regarding production.	
10. Whether power load has been approved.	
11. Whether project feasible.	
12. Recommendation for grant of permission.	
13. Form 'B'.	

Signature
Date

PART 'C'

INSTRUCTIONS

FILLING APPLICATION FOR GRANT OF PERMISSION FOR CONSTRUCTION OF COLD STORAGE

Any person desirous of establishing a new cold storage of expansion of existing cold storage under the Cold Storage Order, 1980, shall apply for the grant of permission to the Agricltural Marketing Adviser to the Government of India, Faridabad. Application on the prescribed forms should be submitted in the following manner :

Name of the region	Area of the region	HQ
1	2	3
1. Northern Region	(1) Jammu & Kashmir (2) Punjab (3) Haryana (4) Rajasthan (5) Himachal Pradesh (6) Delhi; and (7) Chandigarh.	New Delhi.

1	2	3
2. Western Region :	(1) Maharashtra (2) Gujarat (3) Madhya Pradesh (4) Goa, Daman and Diu; and (5) Dadra Nagar Haveli	Bombay
3. Eastern Region :	(1) Bihar (2) Orissa (3) Assam (4) Meghalaya (5) Manipur (6) Tripura (7) Nagaland (8) NEFA; and (9) Andaman and Nicobar Islands.	Patna
4. Southern Region :	(1) Tamil Nadu (2) Andhra Pradesh (3) Karnataka (4) Kerala (5) Pondicherry (6) Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	Madras

2. HOW TO APPLY :

Intending parties should, before starting construction of a new cold storage, or expansion of the existing one, apply for permission on the prescribed Form 'B' alongwith the following enclosures :

1. Attested copy of Land Purchased Deed.
2. Attested copy of Partnership Deed/Affidavit for Proprietorship/Memorandum & Article of Association.
3. Attested copy of Certificate of Registration.
4. A certificate from the District Agriculture Officer regarding the production of potatoes and/or other commodities to be stored in the proposed cold storage. In case, where the proposed cold storage is to be located in terminal market, port cities or in metropolitan cities which are the main consuming city certificate shall not be necessary. In case of Milk Cold Storage or Fish Cold Storage also this certificate is not necessary.
5. Set of drawings.
6. A letter from the State Electricity Board assuring the availability of sufficient electric load, and
7. 'No Objection Certificate' from the Muhicipal Committee/ Corporation or other local authority for construction of the cold storage, or alteratively a declaration that the site of the cold storage does not fall within the jurisdiction of any local authority.
8. In addition to the above documents, it is necessary that following documents should also be submitted wherever applicable :
   1. Number of cold stores operating within 30 Km. radius.
   2. Justification sheet for setting up of a cold storage.
   3. Copy of letter from the bank/financial corporation or a letter of intent for financial assistance.
   4. List of machinery and insulation
   5. Detailed building estimate from a licensed/registered Engineer/Architect.

BEFORE FILLING IN THE FORM OF APPLICATION AND PREPARING THE DRAWINGS THE FOLLOWING POINTS MAY BE STUDIED COMPLETELY:

APPLICATION FORM 'B'

Land (Column 2 of the application).—An attested copy of Land Purchase Deed should invariably be submitted alongwith the application form. Before purchasing the land following points should be taken into consideration :

(a) The land should be of clear title and the ownership should in no way be disputed;

(b) The land should be on a high level and should be safe from flooding, etc., during the rains;

(c) The land should be sufficient for accommodating the proposed chambers, future expansion, drying sheds' general amenities to the workers, etc.; and

(d) The approach to the proposed cold storage should be independent. Approach road through the fields of other person shall not be approved.

PARTICULARS OF MACACHINERY, INSULATION ETC. : (Column 3 of the applicant).—The entrepreneurs shall submit a comprehensive scheme alongwith the proposed list of machinery from a firm of repute. Any change in the proposed machinery at a letter stage should be intimated to the Directorate and permission obtained. Failure to do this is likely to delay the grant of permission.

INSULATION:—Any of the following standard insulation materials may be used. The minimum thickness required in case of each is shown against the same :

	Wall	Floor	Celling
1. Cork	80.mm	50 mm	100 mm
2. Fibre Glass	80 mm	50 mm	100mm
3. Thermocole	80 mm	50mm	100 mm
4. Rice husk	30 cms	30 cms	45 cms
5. Saw dust	30 cms	30 cms	45 cms

In case rice husk/saw dist is employed, water barrier should invariably be used.

For a cold storage storing poultry, fish or milk products the minimum thickness required is as under :

	For temp.—10—F			For temp—40—F
	Walls	Ceiling	Floor	
Fibre glass	150 mm	200 mm	100 mm	200 mm al round
Thermocole	150 mm	200 mm	100 mm	-do-

Rice husk/saw dust insulation shall not be accepted in a cold storage, which are storing produce below sub-zero temperature.

Cinder insulation shall not be accepted.

REFRIGERANT: F-12, F-22 or Ammonia gas may normally be used as refrigerant.

CAPACITY COLD STORAGE (Column 4 of the application).—Internal dimension shown in column 4 should be clear dimensions after insulation. Dimension should be given in metric system.

DRAWING:—While preparing the drawings following points should be kept in view,—

(a) Key Plan:—Key plan should show the proposed location with respect to important land marks in the vicinity. The process of granting permission would be expedited if the Key Plan is submitted on a village or municipal map but whenever if not possible the Key Plan should invariably be submitted with reference to important highway, important buildings, kilometer stone on the highway, etc., so that the location may be ascertained even by a person who is not familiar with the locality.

(b) Site Plan.—Site Plan should show the proposed plot of land and names of owners of adjoining plots. Location of chambers, precooling chambers, drying shed, condensors, machine room office and the other utility building like toilets, workers residential areas, etc. should be clearly marked. The approach road should be marked clearly. Drying shed should invariably be shown. The minimum area of the drying shed should be at the rate of 2 sq. ft. (0.1 sq. meter) of storage capa ity. The cold storage chambers should be so located that walls do not coincide with the boundary walls of the plot.

(c) Detailed Plan:—Detailed Plan should show the complete dimensions/details of the building, the material to be used in the construction, details of racking structure, size of horizontal/vertical members of the racking structure/proposed galleries/passages. Galleries should be so located that every bag can be taken out at a short notice and the inspection of all the bags can be done at frequent intervals. It is desirable that the distance between two gallaries should remain between 5 to 6 metres. The minimum width of the galleries as per C.S.O., 1980, is 0.76 metres. Air gap of 20 cms between the walls and the bags and between the floor and the bags should be provided. Air lock should be provided to all the chambers invariably.

(d) Sectional Detail.—A cross section should be drawn so that the maximum number of details can be shown therein. This should show the internal as well as external height of the chambers foundation details. Normally, more than 6 stages should not be provided in a cold storage.

Availability of Foodstiff.—(Column 5 of the applicant).—A certific.te from the District Agricultural Officer may be obtained. This certificate should indicate the area under cultivation and the total yield of potatoes and/or other crops proposed to be stored in the Cold Storage

Number of Cold Storage Chamber(s).—(Column 6 of the application).—In column 6 a list of cold storages operating within 30 km or around may be enclosed.

Justification for setting of a cold storage.—(Column 7 of the application).—A separate sheet may be attached justifying the erection of additional cold storage with special reference to the availability of foodstuff and the existing cold storages within the area.

Availability of Power.—(Column 8 of the application).—Adequate availability of power should be ensured. Assurance letter from the State Electricity Board should be enclosed. In case it is proposed to install stand-by generating sets, the same should also be indicated.

Availability of Water.—(Column 9 of the application).—It is desirable that an uninterrupted arrangement of water by a tubewell should be available. It may be ensured that the water is tested fo its hardness so as to avoid frequent scaling of the condensor pipes. In case the water is hard, treatment plants may also be provided.

Source of Finance (Column 10 of the application).—If a loan has been sanctioned, a copy of letter from bank/financial corporation may be enclosed. In case the loan cannot be sanctioned in anticipation of the permission, a letter of intent may be enclosed.

Economics of the Proposed Cold Storage.—(Column 11 of the application.)—The estimates should be carefully assessed. In case of any abnormally high/low costs, the figures will have to be substantiated with an estimate from any firm of repute/licensed architect.

While calculating the receipts for the storage, the prevailing rates as fixed by the Centre/Centre Governments may be taken into consideration.

FORM 'C'

(See clause 4(2)

APPLICATION FOR LICENCE UNDER THE COLD STORAGE ORDER, 1980

1. Name and address of the applicant.

2. Location of the cold storage :
   Post Office.
   : Dist.—
   : Pin Code.—

3. Number and size of cold storage(s).—
   (i) Size of the individual old storage
   .... height

   (ii) Total cubic capacity of all the cold storage(s)
   Combined.... .... Cu.M.

4. Capacity of freezing plant in tons of refrigeration per 24 hours.

5. List of machinery with particulars.

6. Total H.P. of the motor(s) other prime movers.

7. Name(s) of the foodstuff(s) I/We intend to accept for storing in Cold Storage.

8. I/We hereby forward a Bank Draft No..... dated.....for a sum of Rs.....in respect of licence fee due according to the provisions of the Cold Storage Order,1980.

9. I/We hereby undertake to comply with all the provisions of the Cold Storage Order, 1980.

Signature of the applicant.

Date.....

FORM 'D'

(See clause 7)

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION
GOVERNMENT OF INDIA

Licence under the Cold Storage Order, 1980.

Licence No. ....C.S.O.

1. Name and address of the licensee.
2. Location of the cold storage.

This licence is granted under, and is subjected to, the provisions of the Cold Storage Order, 1980 (including the terms and conditions specified in the Schedule to that Order), all of which shall be complied with by the licensee.

Place : Licensing Officer

Date :

PERIOD OF VALIDITY

Period of validity	Licence fee paid	Total capacity in cubic metre of the cold storage	Signature of the Licensing Officer.

FORM 'E'

[See Clause 12(1).]

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE UNDER THE COLD STORAGE ORDER FOR THE YEAR

.Name and address of the Cold Storage

.Licence number.

Any major change in the machinery should be indicated.

.I/We hereby unertake to comply with all the provisions of the Cold Storage Order , 1980.

I/We hereby forward a Bank Draft No..... dated.....for a sum of Rs..... in respect of the renewal fee due according to the provisions of the Cold Storage Order 1980.

Signature of the applicant
Date.

FORM 'F'

(See Clause 18(1).)

COLD STORAGE RECEIPT—NEGOTIABLE/NON-NEGOTIABLE

Serial No. .....

Name and location of the cold storage.

Cold Storage Licence No.....Valid up to.....

received from (Name and address of the depositor) .....

.....

.....

.....

.....

.....

Foodstuff of the following description :

Name	Class or standard quality and/or grade.	Number of packages or lots.	Net quantity in kilogram by weight by measure, etc.	Signature and Licence No. of the Weighter/ Measurer/ Grader/ Sampler.

1. Conditions of goods : (1) Good, (2), Fiar, (3) Average.....
2. Private marks of the hirer on the package, if any.....
3. Rate of storing and other charges.....
4. Insured for fire/riot/other contingency (with particulars regarding policy No., date, etc.....
   .....
   .....
   .....
   .....).
5. Insured, name of Insurance Co.....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
6. Insured for the amount of Rs.....
   .....
   .....
   .....
7. The agricultural produce is accepted for storage from.... ..... to .....
8. Market rate at the time of deposit..... valuation.....
9. Particulars regarding transfer by endorsement creating liens, mortgages or other encumbrances on the foodstuff deposited.....

This receipt is issued subject to the provisions of the Cold Storage Order, 1980.

Signature/thumb impression of the hirer or his agent.

Signature of the licencee of his authorised agent

Date :

Date :

The foodstuff mentioned and described below is hereby released from the receipt for delivery from the Cold Storage. Any unreleased balance of foodstuff is subject to a lien for unpaid charges and advance on the released portion :

Date	Name and quantity of food stuff released.	Signature of hirer.	Name and quantity of foodstuff due on receipt.	Signature of the licensee or his authorised agent.

CONDITIONS FOR STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES AND OTHER COMMODITIES

1. Customers are advised to get their bags weighed. In the absence of proper weighment, the responsibility shall rest with the customer.
2. Cold Storage shall not be responsible for the shrinkage or loss of weight due to natural dehydration or any other causes up to 5 per cent of the gross weight.
3. Cold Storage shall not be responsible for the damage to the goods stored caused due to circumstances outside the Management's control. Cold Storage shall be at liberty to dispose of the damaged stock if not withdrawn within seven days of the date of issue of the written intimation. This intimation shall be sent under registered cover.
4. The minimum storages charges shall be one month. Rent of 15 days shall be charged for the fortnight or part thereof on subsequent period.
5. Delivery of the stored goods shall be against payment.

FORM G-I

Page
Name of the Cold Storage
Address.

DAILY BALANCE REGISTER

Date	Commodity	Last balance brought up	Receipt during the day	issue during the day	balance carried over

Signature of Manager/Proprietor
Date.

FORM G-II

Page
Name of the Cold Storage.
Address.

LOADING REGISTER

Receipt No.	Apple	Potato*	Orange*	Kirana*	Any other item*	Name of the party	Rack No.	Rack No. if shifted

*Delete whichever is not applicable.

Signature of the Manager/Proprietor.
Date.

FORM G-III

Page
Name of the Cold Storage.
Name of the depositors.

STOCK LEDGER

Date of Receipt/Issue	Quantity	Gate Pass No.	Period for which rent due	Amount due	Remarks.

Signature of Manager/Proprietor
Date.

FORM G-IV

Page
Account of.....
Name & address of Cold Storage

(CASH) LEDGER

Date	Particulars	Folio	Debit	Credit	Balance

Signature of Manager/Proprietor.
Date.

FORM. G-V

Page
Name of Cold Storage
Address.

CASH BOOK

Month & date	Particulars	Ledger folio	Amount	Total

Signature of Manager/Proprietor
Date.

FORM G-VI

Name of the Cold Storage.
Address.
Gate Pass No.

Date.

Issued the following goods to M/s.....

Particulars	Quantity	Receipt No.	Remarks

Received the above goods in good and satisfactory condition with the copy of this gate pass.

Store Clerk
Date

Signature of Customer
Date.

FORM-'II'

(See clause 12(i) of the Cold Storage Order, 1980)

1. Name and address of the licensee.
2. Location and address of the Cold Storage.
3. C.S.O. Licence No. CSO/.....and total capacity of the Cold Storage in Cu. metres.....

STATEMENT SHOWING THE QUANTITIES OF FOOD STORED IN COLD STORAGE DURING TERM, 19 .

Sr. No.	Name of the food stuff stored.	Quantity of the food stuff stored in metric tonnes.	Temperature & the relative humidity at which the food stuff was stored	Storage charges for the foodstuff stored per quintal per season.	Electricity charges per unit	Water charges per 1000 gallons	% of the capacity utilised to the total capacity of the cold storage & reasons for unutilised capacity if any.	Remarks

Signature of the Manager/Proprietor.
Date.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का०आ० 2454.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना अनुभाग, 10वी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दे। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें।

संशोधन

"0.141 हैक्टर (0.348 एकड़) क्षेत्रफल जो क्षेत्र डी-2 (माता सुन्दरी क्षेत्र) में स्थित है और उत्तर में 12.19 मीटर (40 फुट) चौड़े मार्ग, दक्षिण में अब्दुल नबी मस्जिद, पूर्व में दिल्ली प्रशासन बहु मंजिला कार्यालय भवन और पश्चिम में बहादुरशाह जफर मार्ग से घिरा है का भूमि उपयोग "ऐतिहासिक स्मारक एवं धार्मिक भवन" से "शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान" में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।"

2. रविवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि०वि०प्रा० के कार्यालय (मुख्य योजना अनुभाग), 10वी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा।

[सं० एफ 3(285)/69 एम०पी० पार्ट]

हरी राम गोयल, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2454.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address :

MODIFICATION

"The land use of an area measuring 0.141 hectare (0.348 acre), located in Zone D-2 (Mata Sundri

area) and bounded by 12.19 mts. (40 ft.) wide road in the north, Abdul Nabi Mosque in the south Delhi Admn.'s Multistoreyed Officer Building in the east and Bahadur Shah Zafar Marg in the west, is proposed to be changed from 'Historical Monuments and Religious Buildings' to 'Educational & Research Institutions'."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(285)/69-MP-Pt.]

H. R. GOEL, Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1980

का०आ० 2455—वायुयान नियम, 1937 के नियम 160 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को उक्त नियमों की अनुसूची II के खंड "बी" के पैरा 6 के उप-पैरा (ख) के अनुपालन की आवश्यकता से इस हद तक छूट देती है कि अनुमादित "सिंथेटिक डिवाइस" पर प्रशिक्षण अनुभव 8 घंटे से अधिक का नहीं होगा ।

[फा० सं० ए०वी० 11012/7/79-ए/ए आर/1937(1)]

एस० एकाम्बरम, निदेशक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 26th August, 1980

S.O. 2455.—In exercise of the powers conferred by rule 160 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby exempts Air India and Indian Airlines from compliance with sub-para (b) of para 6 in Section P of Schedule II to the said Rules to the extent that the training experience on an approved synthetic device shall not be more than 8 hours.

[F. No. A.V.11012/7/79-A/AR/1937(1)]

S. EKAMBARAM, Director

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1980

का०आ० 2456—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त इसके द्वारा, भारत सरकार, पुनर्वास विभाग की दिनांक 25-8-1980 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा अपर बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त अलवर और भरतपुर के जिला पुनर्वास अधिकारियों को, राजस्थान राज्य में उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, मुआवजा पूल की अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों/कृषि भूमियों/दुकानों तथा खाली स्थानों के बारे में, उक्त अधिनियम, के अधीन धारा 23 और 24 के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करने के प्रयोजन से अपनी शक्तियां सौंपते है ।

[संख्या 1(2)/वि०सै०/78-एस०एस०-II]

गोविन्द जी मिश्र, मुख्य बंदोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 25th August, 1980

S.O. 2456.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the District Rehabilitation Officers of Alwar and Bharatpur appointed as Additional Settlement Commissioners vide Government of India, Department of Rehabilitation Notification of even number dated 25th August, 1980 his powers under Sections 23 and 24 of the said Act for the purpose of passing necessary orders under these Sections in respect of the acquired evacuee properties/agricultural lands/shops and vacant sites forming part of the Compensation Pool within their jurisdiction in the State of Rajasthan.

[No. 1(2)/Spl. Cell 78-SS.II]

G. J. MISRA, Chief Settlement Commissioner.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1980

का०आ० 2457—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, भारत सरकार, पुनर्वास विभाग द्वारा "एकमुश्त सौदे" अथवा "प्रशासकीय एवं वित्तीय व्यवस्थाओं" के अधीन, राजस्थान सरकार को सौंपे गए कार्यों के संबंध में राजस्थान राज्य में अलवर और भरतपुर के जिला पुनर्वास अधिकारियों को, जिला पुनर्वास अधिकारी के रूप में उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त, उनके अपने अपने अधिकारी क्षेत्र में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए अपर बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 1(2)/वि०सै०/78-एस०एस०-II]

New Delhi, the 25th August, 1980

S.O. 2457.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints District Rehabilitation Officers in Alwar and Bharatpur in the State of Rajasthan, to be Additional Settlement Commissioners for the purpose of performing, in addition to their own duties as District Rehabilitation Officers within their jurisdiction, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act in relation to the work entrusted to the Government of Rajasthan by the Government of India in the Department of Rehabilitation under the "Package Deal" or "Administrative and Financial Arrangements".

[No. 1(2)/Spl. Cell/78-SS.II.]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1980

का० आ० 2458—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4, 28 और 33 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग हरियाणा राज्य में स्थित अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों और भूमियों के संबंध में सचिव, हरियाणा सरकार, पुनर्वास विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा भी किया जाएगा किन्तु शर्त यह होगी कि वह इस प्रकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे मामले में नहीं करेंगे जिसमें उनके द्वारा किसी अन्य क्षमता में आदेश पारित किया गया हो ।

2. इससे अधिसूचना संख्या 1(14)/वि०सै०/75-एस०एस०-2 दिनांक 22-2-1980 का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(14)/वि०सै०/75-एस०एस०-II)]

New Delhi, the 27th August, 1980

S.O. 2458.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, (44 of 1954), the Central Government hereby directs that powers exercisable by it under Sections 24 Sub-Section 4, 28 and 33 of the said Act, shall be exercisable also by the Secretary to the Government of Haryana, Rehabilitation Department, Chandigarh, in respect

of proceedings pertaining to acquired evacuee properties and lands situated within the State of Haryana, subject to the condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him in any other capacity.

2. This supersedes Notification No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II., dated 22-2-1980.

[No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II]

का० आ० 2459.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का हरियाणा राज्य में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों तथा भूमियों के संबंध में, सचिव, पुनर्वास विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा तथा उन्हें धारा 16 के अधीन आवेदनों को स्वीकार करने तथा उनके निपटान करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है ।

2. इससे अधिसूचना संख्या 1(14)/वि०स०/75-एस०एस०-2 दिनांक 19-5-80 का अधिक्रमण किया जाता है ।

[संख्या 1(14)/वि०सै०/75-एस०एस०-II)]

एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव

S.O. 2459.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under Section 16 of the said Act, shall be exercised also by the Secretary, Rehabilitation Department, Government of Haryana, Chandigarh in respect of evacuee properties and lands situated in the State and he shall also be authorised to admit and dispose of applications under Section 16.

2. This supersedes Notification No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II., dated 19-5-80.

[No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II.]

N. M. WADHWANI, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1980

का०आ० 2460.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के प्रबन्ध से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित है :—

और कर्मकारों से, जिनका प्रतिनिधित्व राजस्थान बैंक एम्पलाइज यूनियन, जयपुर करता है, विवाद से संबंधित कार्यवाही को उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, से जयपुर स्थित औद्योगिक अधिकरण को अन्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

और अन्य पक्षकार अर्थात् स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर, जयपुर का प्रबंधतंत्र भी जयपुर में स्थित है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद से संबद्ध कार्यवाही को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली से वापस लेती है और उसे औद्योगिक अधिकरण जयपुर को अन्तरित करती है, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7क के अधीन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के रूप में गठित किया गया है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मुरलीधर चौधरी होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर और आगे कार्यवाही उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे अंतरित की जाती है और विधि के अनुसार उसका निपटारा करेगा ।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री मोहन दान, चौकीदार, सत्य नारायण सिंह, लिपिक, श्याम लाल, लिपिक और राधे श्याम गुप्ता, लिपिक की सेवाओं को 19-3-75, 10-6-72, 2-3-76 और 2-4-76 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ।

[सं० एस० 12011/112/78-डी० 2(ए)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 1980

S.O. 2460.—Whereas the industrial dispute existing between the employers in relation to the management of state Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi.

And whereas a proposal has been received from the workmen represented by the Rajasthan Bank Employees Union, Jaipur for transfer of the proceedings in the dispute from the said Central Government Industrial Tribunal to the Industrial Tribunal, Jaipur.

And whereas the management of the State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur the other party in the dispute is also located at Jaipur;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute from the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi and transfer the same to the Industrial Tribunal, Jaipur presided over by Shri Murlidhar Choudhary with headquarters at Jaipur which has been constituted into a Central Government Industrial Tribunal under Section 7A of the Industrial Disputes Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, Jaipur shall proceed with the same proceeding from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in terminating the services of S/Shri Mohan Dan, Chowkidar; Satyanarain Singh, Clerk; Shyamlal, Clerk; and Radheyshyam Gupta, Clerk with effect from 19-3-75, 10-6-72, 2-3-76 and 2-4-76 respectively is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

[No. L-12011/112/78-D.II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1980

का०आ० 2461.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और श्री सन्दीप चन्दुलाल पाटवा के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर०सी० इसरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय मुख्य कार्यालय भादरा, अहमदाबाद, के प्रबन्धतंत्र को श्री सन्दीप चन्दुलाल पाटवा, रोकड़िया की सेवा 30 सितम्बर, 1973 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है । यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०12012/24/79-डी-2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1980

S.O. 2461.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India, L.H.O., Ahmedabad and Shri Sandeep Chandulal Patwa in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of State Bank of India, Local Head Office, Bhadra, Ahmedabad in terminating the services of Shri Sandeep Chandulal Patwa, Cashier with effect from September, 30, 1973 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-12012/24/79-D.II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1980

का०आ० 2462.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री बी०वी० नरसिन्हम, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश के समक्ष लम्बित है ;

और श्री बी०वी० नरसिन्हम की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है ;

अतः, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 ख की अपधारा (1) के साथ पठित उसकी धारा 7-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रूपेन्द्र प्रसाद सहगल होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और अक्त श्री बी०वी० नरसिन्हम, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित उक्त विवादों से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उसे श्री रूपेन्द्र प्रसाद सैगल पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद को इस निदेश के साथ अंतरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाहिया उस प्रक्रम से करेगा, जिस पर वे उसे अंतरित की जाती है और विधि के अनुसार उसका निपटारा करेगा ।

अनुसूची

क्रम सं०	औद्योगिक विवाद सं०	संदर्भ	पक्षकारों के नाम
1	2	3	4
1.	औद्योगिक विवाद 1/78	शुद्धि पत्र सं० एल-12012/17/77-डी2-(ए) तारीख 17/23-3-78 के साथ पठित आदेश संख्या एल-12012/17/77-डी-2 (ए) दिनांक 15/25-2-78	भारतीय स्टेट बैंक की सात्तेनावल्ले शाखा के रोकड़िया श्री वी० श्री रामुलु बनाम भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद ।
2.	औद्योगिक विवाद 2/78	आदेश सं० एल-12012/14/77-डी-2(ए) तारीख 20-3-78	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रधान लिपिक, श्री पी० विश्वनाथन बनाम स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3.	औ० वि० 1/79	शुद्धि पत्र संख्या एल-12011/109/78 डी (1)(ए) तारीख 9-4-79 के साथ पठित आदेश एल-12011/109/78-डी 11(ए) तारीख 20-3-79	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के श्री वाई० नरेन्द्र और 14 अन्य बनाम सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, हैदराबाद

[सं० एल-12011/109/78-डी (II-ए)]

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1980

S.O. 2462.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri B.V. Narasimham, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad, Andhra Pradesh;

And Whereas the services of Shri B.V. Narasimham are no longer available;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A read with Sub-Section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby consitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri Rupendra Prasad Saighal with headquarters at Hyderabad and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri B.V. Narasimham Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and transfers the same to Shri Bhupendra Prasad Saighal, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad with the direction that the same Tribunal shall proceed with the proceedings from the state at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl.No.	I.D.No.	Reference	Parties to the dispute.
1	2	3	4
1.	I.D. 1/78	Order No. L-12012/17/77 D.II.A dated 15/25-2-78 read with Corrigendum No. L12012/17/77-D.II. A. dated 17/23-3-78.	Shri V. Sreeramulu, Cashier of Satterapalke Branch of the State Bank of India V/s. State Bank of India, Hyderabad.
2.	I.D. 2/78	Order No. L-12012/114/77-D. II.A. dated 20-3-78.	Shri P. Vishwanathan, Head Clerk, State Bank of Hyderabad V/s. State Bank of Hyderabad.
3.	I.D. 1/79	Order No.L-12011/109/78-D.II.A. dated 20-3-79 read wtih Corrigendum No. L-12011/109/78-D.II.A. dated 9-4-79.	Shri Y. Narender & 14 others of Central Bank of India, V/s. Central Bank of India, Hyderabad.

[No. L12011/109/78-D II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1980

का०आ० 2463.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, मनुगुर डिवीजन कोथागुडियम, हैदराबाद के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिंगरेनी कॉलियरीज कम्पनी लिमिटेड, मनुगुर खण्ड के मंडल अधीक्षक की श्री नक्का वेंकटा राव, फिटर, सिविल इंजीनियरी विभाग, मनुगुर खण्ड की सेवा 15 सितम्बर, 1979 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[एल-21012/23/79-डी-IV(बी)]
एस० एस० मेहता, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 2nd August, 1980

S.O. 2463.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Co. Ltd., Manugur Division Kothagudium Hyderabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (i) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivas Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Divisional Superintendent, Singareni Collieries Company Limited, Manugur Division in dismissing Shri Nakka Venkata Rao, Fitter, Civil Engineering Department, Manugur Division from service with effect from 15th September, 1979 is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-21012/23/79-DIV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1980

का०आ० 2464.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम०डी० चौधरी होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर, एस०एम०एस० हाईवे, मुख्यालय, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की अपनी बीकानेर स्थित पब्लिक पार्क शाखा के संबन्ध में श्री कैलाश सिंह को, जिससे उक्त शाखा के बैंक के साइकिल स्टैंड पर कार्य किया था, मजदूरी और भत्ते, जिनके लिए अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द हकदार हैं, 22 अप्रैल, 1976 से देने से इंकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[संख्या एल-12011/32/79-डी-2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1980

S.O. 2464.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. D. Choudhary shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, S.M.S. Highway, Head Office Jaipur in relation to its Public Park Branch at Bikaner in denying to Shri Kailash Singh who attended to the bank's cycle stand at the said branch, wages and allowances to which other subordinate staff are entitled, with effect from April 22, 1976 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

[No. L-12011/32/79-D.II(A).]

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2465.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-8-1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 182 of 1977

In re :

The Secretary, Reserve Bank Employees' Association,
C/o Reserve Bank of India,
New Delhi. ....Petitioner

Versus

The Manager, Reserve Bank of India,
Parliament Street,
New Delhi.

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to

Industrial Tribunal, Delhi in the following terms vide its order No. S. 12012/140/75/D. II/A dated the 17th November, 1975 :

'Is the management of the Reserve Bank of India New Delhi, justified in reducing the substantive pay and withholding the increment for two years with effect from the 4th September, 1973 of Shri M. L. Chopra, Coin-note Examiner-Grade-II. If not, to what relief is the said workman entitled ?'

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were sent to the parties. In pursuance whereof a statement of claim was filed on 4th February, 1976. Thereafter the Management filed a written statement on the 29th March, 1976. Finally a replication was filed on the 10th May, 1976. Upon the pleadings of the parties the following issues were framed by Industrial Tribunal, Delhi for trial :

1. Whether the domestic enquiry is vitiated for the reasons pleaded ?

2. As in the terms of reference.

3. Thereafter the case was adiourned for evidence of the parties to 1st November, 1976. On which date the Industrial Tribunal, Delhi passed the following orders :

'Parties have agreed that no oral evidence is needed at this stage on issue No. 1. Accordingly they close their respective evidence on No. 1. They also want to argue issue No. 1, which would be treated as a preliminary issue. Put up for arguments on issue No. 1 only on 27-11-76. Parties by agreement state that the documents filed would be treated as evidence without formal proof. The Management will file an affidavit regarding disposal of the note packet in question which was by the workman before 27th November, 1976.'

4. Before arguments could be heard the case was transferred to this Tribunal and it was ordered to be registered afresh and fresh notices were issued to the parties. The parties representatives appeared before me and on enquiry by this Tribunal they reiterated that the parties did not propose to lead any oral evidence on issue No. 1 and it was further agreed that the enquiry proceedings may be read into evidence without any formal proof and it was exhibited as Ex. M/1. It later on transpired that the notification transferring this case to this Tribunal was somewhat defective and therefore a fresh notification of transfer was necessitated and after the said fresh notification was published, the statements of parties representatives were recorded on 15th September, 1978 in which the parties representatives adopted all the proceedings held by this Tribunal and the case was adjourned for arguments.

5. I have gone through the pleadings and the evidence on record and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the following findings upon issue No. 1.

6. The contention of the workman in his statement of claim is that the workman Shri M. L. Chopra is employed in the Reserve Bank of India, New Delhi as coin/note examiner Grade II; that he was served with a memo dated 1-9-72 alleging that a packet of Rs. 100 re-issuable notes to the State Bank of India on 4-8-72 was found short of 11 notes as reported by the Receiving Office; that it was further alleged that the said packet had been examined by the workman on 1-8-72 and the workman was vide this memorandum called upon to explain the alleged shortage; that the workman submitted his reply dated upon the workman on the same grounds and the workman was charged with negligence, in-efficiency and indolence in the discharge of his duties and that he was liable to disciplinary action under regulation 47 of the Reserve Bank of India Staff Regulation, 1948; that the workman submitted reply to the said charge sheet vide his reply dated 10-1-1973 and denied the charges; that thereafter the workman was informed vide memo dated 19-1-1973 by the Manager of the Bank that an enquiry would be held into the charges framed against the workman and for the said purpose one Shri S. M. Taqi Hussain, Assistant Currency Officer had been appointed as the Enquiry Officer; that the enquiry proceedings against the workman commenced on 21-2-1973 and the workman was represented at the enquiry by the representative of the Association/Union and the Management was represented at the enquiry by the Enquiry Officer; that two witnesses Shri M. R. Patwardhan and Shri N. N. Sehgal were examined by the Management in support of the charges and two witnesses Shri R. K. Khanna and Indresh Mohan were examined by the workman at the enquiry proceedings; that at the conclusion of the enquiry workman submitted written arguments dated the 28th April, 1973; that thereafter the Enquiry Officer submitted his report on 5-6-1973 and it was held by the Enquiry Officer that the workman had failed to follow the procedure of examination of the notes as prescribed in para 90 of the Departmental Manual and had acted in a manner detrimental to the interest of the Bank and thus exhibited inefficiency and indolence in the discharge of his duties; that the said report of the Enquiry Officer was considered by the Manager of the Bank who had by order dated 9-7-1973 agreed with the Enquiry Officer, that the charges framed against the workman stood proved and in consequence the workman was served with a show cause notice dated 9-7-1973 purporting to inflict penalties namely degradation to a lower stage in the workman's incremental scale and recovery from the pay of the workman of 50 per cent of the alleged loss sustained by the Bank and the workman was informed that the workman could make a representation against the proposed penalties; that the workman submitted his reply to the said show cause notice vide reply dated 30-8-73 ; that the Manager of the Bank vide order dated 4-9-73 disposed of the matter by observing that he (Manager) saw no reason to alter the penalty tentatively proposed to be inflicted and accordingly passed the order; that the workman preferred an appeal to the Governor of the Bank against the said order dated 4-9-73 of the Bank Manager under regulation 48 of the said appeal and the said appeal was disposed of and dismissed the appeal; that the procedure adopted by the Enquiry Officer was wrong; that the enquiry was vitiated ; that the findings were unjustified and unsustainable ; that similarly the order of punishment was unjustified and unsustainable; that the order of the appellate authority was also invalid and as such the punishment is liable to be set aside.

7. The Bank has in reply stated that the enquiry was valid and justified and not vitiated; that the order of punishment was equally valid and justified and sustainable from the evidence produced before the Enquiry Officer; that the order of appellate authority was equally justified and sustainable and that the workman was not entitled to any relief what-so-ever.

8. The short question before this Tribunal is as to whether the enquiry is vitiated. From the details given by the workman in his statement of claim itself it cannot by any stretch of imagination be said that the enquiry is vitiated. It also cannot be said that the Enquiry Officer had mis-directed himself or the proceedings in any manner what-so-ever. Mere fact that the Enquiry Officer had himself acted as the representative of the Bank Management also does not vitiate the enquiry in any manner what-so-ever, in as much as there is nothing either in the I.D. Act or the statements or the Bank awards which lays down that the Enquiry Officer cannot act both the Enquiry Officer as the Presenting Officer on behalf of the Management From the perusal of the enquiry proceedings which are Ex. M/1 in this case it cannot be said that the workman had not been afforded proper opportunity before the Enquiry Officer. It also cannot be gathered from the enquiry that full opportunity was not afforded to the workman to cross examine the witness of the Management or to produce his evidence in any manner what-so-ever.

9. From the perusal of the enquiry proceedings I find that at page 1, is the copy of note addressed by the Agent at Faridabad Branch of State Bank of India on 9th August, 1972 to the Currency, Officer, Reserve Bank of India, Issue Department, New Delhi advising him about the short in hundred rupee notes. At page 2 thereof is the copy of memorandum dated the 1st September, 1972 served upon the workman in the instant matter by the Currency Officer. At page 3 is the copy of the reply dated the 8th September, 1972 submitted by the workman. At page 4 is the copy of the charge sheet dated 1st January, 1973 served upon the workman. From the perusal of this charge sheet I find that it is quite detailed one and conveys the full charge to the workman and nothing appears to have been withheld in the charge sheet so as to misguide the workman. At page 5 is the reply submitted to this charge sheet by this workman on 10th January, 1973. At page 6

thereof is the order of appointment of Shri S. M. Taqi Hussain as the Enquiry Officer passed by the Manager on 19th January, 1973. Pages 7 to 43 of Ex. M/1 are the enquiry proceedings. A perusal of these enquiry proceedings goes to show that the procedure of enquiry adopted by he enquiry officer was proper and a valid procedure. It shows that the full opportunity was afforded to the workman side at the enquiry stage. Each page of the enquiry proceedings is signed by the representative of the workman apart from the Enquiry Officer. Incidently it may be mentioned that at page 7 itself it is mentioned that Shri M. R. Patwardhan, Treasurer was present to represent the Bank in the enquiry. Even assuming that the witness of the Bank were examined by the Enquiry Officer there is nothing improper in the said procedure as long as the examination does not go to show that the Enquiry Officer had taken sides. I have gone through the entire proceedings of the enquiry and I do not find anything to indicate that the Enquiry Officer was biased against the workman or was better disposed towards the Bank—Management. Rather it only shows that the Enquiry Officer has acted in the best possible and in an impartial manner.

10. After the enquiry was completed a written statement by way of arguments was made on behalf of the workman which is at pages 44-45 of the enquiry proceedings. At pages 46, 47, 48 and 49 I find the report of the Enquiry Officer and from the perusal of the report I find that the Enquiry Officer has considered the matter dispassionately and from all possible angles. Almost all possible points raised by the workman in his representation dated 28-4-73 have been considered by the Enquiry Officer and it was thereafter that he has come to his findings. At page 50 is the copy of note purported to have been signed by the Manager on 9-9-73 agreeing with the findings of the enquiry officer. At page 51 is the show cause notice purporting the proposing the punishment on 9th July, 1973, it is signed by the Manager. The workman replied to the said show cause notice dated the 30th August, 1973 and it is at page 52 and 53 of the enquiry proceedings. Order of the Manager is dated the 4th September, 1973 and is at page 54 and 55 of the said file. At pages 56 to 59 I find the ground of appeal preferred by the workman on 10th December, 1973 and the said appeal was disposed of vide order dated 29-6-74 by the Executive Director and copy thereof is at pages 60 to 62 of the enquiry file.

11. I have referred in detail to the enquiry proceedings including the procedure adopted by the Enquiry Officer, punishing authority and the appellate authority and after giving my considered thought to the entire matter before me I have come to the conclusion that there is nothing in the enquiry which warrants a conclusion that the enquiry is vitiated in any manner what-so-ever or an any ground what-so-ever and I come to the conclusion that the enquiry is not vitiated.

12. It would be appropriate here to examine the question as to whether the fact that the Enquiry Officer had himself acted as a Presenting Officer on behalf of the Bank has in any manner effected the enquiry. I have already observed that by itself is not a ground to hold that the enquiry is vitiated. There is nothing which I have been able to gather from the perusal of the enquiry which goes to in any manner to show even remotely that the Enquiry Officer has acted prejudicially against the workman. From the perusal of various questions put to the witness on behalf of the workman I find that the same were in the nature of soliciting explanation for a particular situation, rather than with a view to inculpate the workman. Even on the examination of the workman by the Enquiry Officer I find that the Enquiry Officer's conduct was all along above board and there is nothing to suggest that he had acted is biased manner. Similar question was considered by a D.B. of Hon'ble Delhi High Court in RFA No. 489 of 1971 entitled Om Parkash Khurarina Vs. Reserve Bank of India, New Delhi a certified copy whereof has been placed on record by the Bank's counsel. At page 17 of the said Judgment it has been observed that at the enquiry there was no Presenting Officer on behalf of the Bank and there is nothing in the regulations making it obligatory for the Bank to appoint one (though to do so). In the absence of the Presenting Officer, the Enquiry Officer had no option but to put questions to the witnesses and himself. But this alone will not vitiate the enquiry. Their Lordships have then referred to a Judgment Hindustan Lever Ltd. Vs. Presiding Officer reported as 1970(2) LLJ-201 which was in turn based upon a Supreme Court Judgment Firestone Tyre and Rubber Co. Vs. Their workmen reported as 1967(2) LLJ-715 and another Judgment workmen in Buckingham & Carnatic Mills Madras Vs. Buckingham & Camatic Mills, Madras reported as 1970(1) LLJ-26. From the perusal of these observations I find that the position in the instant case is also identical. Their Lordships have later observed in the said Judgment that 'the govering test, the court said, would be whether the examination or the cross-examination or putting leading questions by the Enquiry Officer would indicate that he was not fair and that he was biased in the sense that he thereby acted not as an Enquiry Officer but went beyond his limits and played a role of a Prosecutor. The court also held that too much to the domestic enquiry and what was relevant was to see whether any prejudice was caused by such a conduct of the proceedings by the Enquiry Officer'. On a perusal of the enquiry proceedings in the instant case I do not find that the Enquiry Officer had relegated himself to the role of a Prosecutor or any prejudice was caused thereby to the workman. The questions put by the Enquiry Officer appears to have been put with the intention of giving all chances to the workman to explain the situation and to afford him full opportunity to exonerate himself and not with a view to inculpate him. The Enquiry Officer is to act like a impartial Judge and this is what he has done in the instant case. He has tried to discharge his main function of finding out the truth and whatever questions were put by him appear to have been put in this direction and to do justice between the parties. In view thereof I do not think that the Enquiry is vitiated on this ground.

13. Even though this is not open to this court to go into the reasons which led the Enquiry Officer to come to his conclusion but keeping in view the objections of the workmen I have gone through the relevant provision, of the Issue Departmental Manual of the Reserve Bank of India and I do find that the conclusion of the Enquiry Officer are as would be arrived at by a reasonable man. They are not perverse on the face of them and are not opposed to the principles of law of domestic enquiries in this behalf. There is no manifest error of law of which the Enquiry Officer can be said to be guilty of in arriving at his conclusion. He has observed all the principles of natural justice applicable to the Enquiry proceedings. This court would substitute its decisions for the findings of the Enquiry Officer and therefore it is held that the enquiry is not vitiated.

14. I have considered the matter from the angle of punishment as well, even though it is not open to this Tribunal to arrive at a conclusion of punishment inflicted. Keeping in view the gravity of the charge it cannot be said that the punishment is severe or harsh and is not keeping with the nature of mis-conduct.

15. In view of my discussions and findings above, this issue is decided against the workman and in favour of the Management.

16. Issue No. 2 :

In view of my findings, above on issue No. 1 I hold that the Management of the Reserve Bank of India, New Delhi, is justified in reducing the substantive pay and withholding the increment for two years w.e.f. the 4th September, 1973 of Shri M. L. Chopra, Coin/Note Examiner-Grade-II and that Mr. Chopra is not entitled to any relief in this reference.

17. For my discussions and findings upon issues above it is awarded that the Management of Reserve Bank of India, New Delhi is justified in reducing the substantive pay and withholding the increment for two years with effect from the 4th September, 1973 of Shri M. L. Chopra, Coin. Note Examiner-Grade-II and the workman is not entitled to any relief what-so-ever. Parties however would bear their own costs.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

Sd/-

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 30th June, 1980.

[No. L-12012/140/75-D. II(A)]

S.O. 2466.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th August, 1980.

BEFORE SHRI A. G. QURESHI, M.A.,LL.B., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.).

Case No. CGIT/LC(R)(4) of 1979

PARTIES :

Employers in relation to the management of Union Bank of India, Nagpur and their workmen, Represented through the Union Bank Staff Association (Regd. 614), Arun Bhavan, Temple Bazar Road, Sitabudi, Nagpur-440012.

APPEARANCE :

For Workmen .. Shri S. P. Chowdhury

For Management .. Shri S. C. Tipnis.

INDUSTRY : Union Bank of India.

DISTRICT : Nagpur (M.S.).

AWARD

In exercise of the powers conferred by Clause 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, Government of India, Ministry of Labour, has referred the following Industrial Dispute for adjudication to this Tribunal vide it's Order No. L-12012/106/78-D.IIA, dated 17th March, 1979 :—

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Nagpur in abolishing the post of Special Assistant of Ghat Road Branch Nagpur and transferring Shri L. H. Vaidya, Special Assistant to Rashim under order dated 5-1-1977 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The case of the Union in short is that Shri L. H. Vaidya was appointed in the Union Bank of India at Gandhibagh Nagpur Branch as a Clerk-cum-Typist in the year 1961. He was thereafter promoted as Head Clerk in May 1971 and was further promoted as Special Assistant on 17-7-1973. He was posted at Ghat Road Branch at Nagpur. From the date of his posting as Special Assistant Shri Vaidya worked at Ghat Road Branch Nagpur till his transfer to Rashim Branch by an order of the management dated 3-1-1977. On receipt of the transfer order dated 3-1-1977, Shri Vaidya made a representation to the Central Office on 17-1-1977 stating therein that his health does not permit him to proceed to Rashim Branch because his ailment requires specialised medical care which is not available at Rashim. For the same reasons, he had refused promotions on two occasions, as he could not go out of Nagpur. Because of the health reasons his staying at Nagpur was necessary for proper treatment. Other reason mentioned for staying at Nagpur was that his wife was serving in the Reserve Bank of India Nagpur and she could not be posted at Rashim where there is no branch of Reserve Bank of India. Because of the ill health it was not possible to live without his wife. The representation was accompanied by a Doctor's certificate. However, the management refused to consider Shri Vaidya's request and rejecting the representation of the workman the management informed him vide letter dated 29-1-1977 that he should join the new station by 10-2-1977 otherwise disciplinary action shall be taken against him. By the same letter it was also stated by the management that as the post of Special Asstt. at Ghat Road Branch was abolished Shri Vaidya was transferred to Rashim Branch. As regards the cancellation of transfer on the ground of ill health of Shri Vaidya, the management informed him that Shri Vaidya can get a proper treatment at Rashim and according to the advice of the medical Officer of the Bank the ailment of Shri Vaidya could not be a ground for cancellation of his transfer.

3. Thereafter, Shri Vaidya again made a request to the management that if the post of Special Asstt. was abolished at Ghat Road Nagpur Shri Vaidya was prepared to work in the clerical cadre. Therefore he may be reverted in the clerical cadre and kept at Nagpur. The aforesaid Memorandum was sent by Shri Vaidya on 29-1-1977. Still the Bank paid no heed to the request of Shri Vaidya. Thereafter Shri Vaidya made a request on 14-4-1977, praying therein that if he could not be posted at Nagpur he may be posted at Akola from where he could go to Nagpur for medical check up and treatment. The Bank accordingly transferred Shri Vaidya to Akola and he resumed his duties at Akola from 9-5-1977 where he is working since then. Again on 28-7-1977 Shri Vaidya made a representation to the Bank stating therein that in view of his ill health, he may be transferred to Nagpur Branch on humanitarian grounds and he is prepared for reversion to the post of clerk at Nagpur. But the management did not accept the request of Shri Vaidya and rejected his application vide management's letter dated 4-8-1977.

4. According to the Union, Shri Vaidya was the Vice President of the Union Bank Staff Association at the time of his transfer to Rashim Branch. The management was totally vindictive towards the Association and to curb the union activities Shri Vaidya was transferred to Rashim Branch contravening the provisions of para 535 of the Shastry Award. Before Shri Vaidya's transfer to Rashim branch the Bank had not notified the contemplated action of the management to abolish the post of Special Assistant at Ghat Road branch and to transfer Shri Vaidya to Rashim branch. The abolition of post at Ghat Road branch of Special Asstt. was a change in the condition of service of Shri Vaidya and the management could not have abolished the post without serving a notice under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act. The Union has also given the comparative figures of business at Ghat Road Branch of the Bank to show that the post of Special Assistant was necessary at Ghat Road Branch and it could not be abolished. But it was so abolished only to victimise Shri Vaidya for his union activities.

The union has therefore prayed that Shri L. H. Vaidya be transferred back to Ghat Road branch Nagpur and the abolition of the post of Special Assistant be declared illegal. Shri Vaidya be also awarded compensation for the illegal transfer and harrasment caused to him due to the malafide action of the management.

5. The management of the Union Bank of India filing the written statement-cum rejoinder has resisted the claim of the union on the grounds, that Chap. V of the Settlement on the Industrial Disputes between certain Bank Companies and their workmen dated 19th October, 1966 (hereinafter to be referred to as the Bipartie Settlement) provides for payment of Special Allowance to compensate the workman for performance or discharge of additional duties and functions requiring greater skill or responsibility over and above the routine duties and functions in the same cadre. As long as a workman is required to perform the duties of Special Assistant, he is paid the special allowance of Rs. 91 per month. The said bipartite settlement does not provide for norms as regards the entrustment of the special allowance duties, including that of a special Assistant The norms or entrustment of special allowance duties are set out in an understanding reached between the Union Bank of India and All India Union Bank Employees Federation dated 22-10-1975 which is known as Promotion Policy. Para 8.2 of Promotion Policy provides that creation/abolition of post carrying special allowance or filling up vacancies in such posts will be at the discretion of the management. Therefore creation or abolition of the port carrying special allowance including that of a special Asstt. is a function of the management. The creation or abolition of post being purely a managerial function, it cannot be a subject matter of Industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the I.D. Act, 1947. Therefore the Central Government was not competent to make a reference regarding the abolition of the post of Special Assistant at Ghat Road branch at Nagpur.

6. On merits, the claim has been resisted on the pleadings that the business at Ghat Road branch at Nagpur was depleting and therefore it was decided that it will not be profitable to continue the post of Special Assistant at the Branch. The decision was taken in December, 1976. The decision was without any malafide and was not with an intention to effect a transfer of Shri Vaidya from Nagpur. Further more, a notice under Sec. 9A of Industrial Disputes Act wa, also not necessary for the abolition of a post of Special Assistant at

Ghat Road Branch, because a notice under Sec. 9A is necessary only when there is a change in the service conditions in respect of items specified in Schedule IV and the abolition of post carrying special allowance is not detailed in the Schedule.

As regards the transfer, the plea of the management is, that because of the abolition of the post of Special Assistant at Ghat Road branch, it became necessary to transfer the workman to a branch where his services could be utilised as a Special Assistant. The immediate vacancy of special asstt. not being available at Nagpur and being available at Rashim, the workman was transferred to Rashim Branch. Consequently, he was relieved from Ghat Road branch on 15-1-1977. But the workman instead of joining the Rashim branch submitted representations to the management, inter alia, that on account of ill health he cannot report for duties at Rashim. The management consulted the authorised Doctor of the Bank who was authorised according to para 450(3) of the Sastry Award and para 11.20 of the Desai Award. The authorised Doctor had found that the workman was fit to report for duty at Rashim. The said opinion of the doctor was accepted by the management and communicated to the workman. Still the workman continued to absent himself from duty at Rashim. By his letter dated 15-4-1977 he requested that he be posted at Akola branch. The management considered the application of the workman sympathetically and promptly acceding to the request of the workman transferred him to Akola. Therefore the dispute, if any, about the transfer of Shri Vaidya to Rashim branch Nagpur came to an end because at the request of the workman himself the management posted him at a place of his choice i.e. Akola. As the workman was posted at Akola at his own request made by letter dated 15-4-1977 he is now estopped from raising any dispute as regards his transfer.

7. The management has further averred that although para 535 of the Sastry Award provides for a notice of five clear working days whenever transfer of the Union office bearer is contemplated. But in the same para there is a provision that in special circumstances such a notice is not necessary.

In the instant case, the abolition of the post of Special Assitt. at Ghat Road branch was a special case and therefore a notice of five days was not given. It has also been contended that para 535 of the Sastri Award is attracted only when a transfer is in the ordinary course of business of Bank and it has no application in case of a transfer arising out of creation or abolition of the post. As such, the management has not violated the provisions of para 535 of the Sastry Award. It has, therefore, been submitted that the reference may be dismissed in limine.

8. By way of rejoinder, the Union has averred that the so called Promotion policy is not binding on the workman so far as it is repugnant to the provisions of Sastry Award. The post of Special Assistant has been abolished at Ghat Road only in name's sake, but actually an officer of the Bank in the officers' grade has been posted at Ghat Road Branch. As regards the medical opinion, the Union has averred that the Doctor has never examined Shri Vaidya, therefore his opinion about Shri Vaidya's fitness to join Rashim branch is not genuine.

9. The Union has examined Shri G. T. Satokar, General Secretary of the Union and Shri Laxman Vaidya, the concerned workman, in support of its claim. Management has not examined any witness.

10. From the evidence of the Union witnesses it has been borne out that at the time of his transfer from Ghat Road Branch to Rashim Branch, Shri Vaidya was the Vice President of the Union Bank Staff Association Nagpur. The intimation of this fact was sent by the General Secretary of the Union to the Management of the Union Bank of India vide letter Ex. W/9 dated 27-4-1977. Earlier to this, intimation of the office bearers, for the year 1976 was sent by the Union Secretary to the management vide letter Ex. W/10 dated 18-10-1976. It is also not in dispute before me that Shri Vaidya was transferred to Ghat Road Branch as per order dated 3-1-1977 and that Shri Vaidya made representation against his transfer to the Bank authorities vide his representation dated 17-1-1977 stating therein that his health does not permit him to proceed to Rashim Branch; and for the same reasons he had earlier refused promotions on two occasions. As such, Shri Vaidya was an office bearer of the Union when he was transferred from Ghat Road Branch to Rashim Branch and this fact was within the knowledge of the management.

11. In view of the above pleadings the first point which falls for determination is, whether the action of the management was justified in transferring Shri Vaidya from Nagpur to Rashim.

The Bank has, defended its action on the ground that that para 535 of the Sastry Award is not applicable to the facts of the present case as Shri Vaidya was transferred from Nagpur due to the abolition of the post of Special Assistant at Ghat Road Branch and no post of Special Assistant was available at Nagpur for Shri Vaidya. The abolition of post being a Special case a notice as required by para 535 of the Sastry Award was not necessary before transferring Shri Vaidya to Rashim Branch.

12. In view of the aforesaid contention of the management let us examine the provision contained in para 535 of the Shastry Award. Para 535 of the Sastry Award reads as under :—

> "535. Policy regarding transfers is a constant source of friction between the banks and the workmen now organised into unions. The cry of victimization of office bearers and "activists" of trade unions is raised wherever such transfers are mooted. We have found that such allegations are easily made but not so easily substantiated transfers are rendered necessary by the exigencies of administration. The proper view to take is that transfers are normal incidents of the working of a bank and they must be left to the discretion of those who guide the policy of the bank and manage its affairs. It is possible that the discretion may be abused and transfers effected on considerations other than the needs of administration. The percentage of transfers as shown by the figures furnished by some of the banks in the course of arguments leads us to the conclusion that the question of transfer, even as it is, affects only a very small number of persons. This is conceded by the workmen also. Still wherever an activist of the trade union movement, as yet in its formative stage and liable to be crippled easily, is transferred a suspicion naturally arises that it is inspired by ulterior motives and the consequence thereof may be an industrial dispute. In order that such suspicions may be avoided as far as possible we, adopting the Sen award in this respect, give the following directions :—
>
> (1) Every registered bank employees' Union, from time to time, shall furnish the bank with the names of the President, Vice President and the Secretaries of the union ;
>
> (2) Except in very special cases, whenever the transfer of any of the above mentioned office bearers is contemplated, at least five clear working days' notice should be put up on the notice boards of the bank of such contemplated action ;
>
> (3) Any representations, written or oral, made by the union shall be considered by the bank ;
>
> (4) If any order of transfer is ultimately made, a record shall be made by the bank of such representations and the bank's reasons for regarding them as inadequate ; and
>
> (5) The decision shall be communicated to the union as well as the employee concerned.

Sub-para (2) of para 535 of the Sastry Award clearly lays down that whenever a transfer of any of the office bearers of the Union is contemplated, at least five clear working days' notice should be put on the notice board of the Bank of such contemplated action. This provision has been included in the award for giving an opportunity to the workman concerned or the union to make a written or oral submission against the action so contemplated and the Bank has to take that representation into consideration while making an order of transfer and has also to record the reasons for rejecting the representation.

13. As such, para 535 of the Sastry Award makes it obligatory on the Bank to give a notice of 5 clear working days of the intended transfer of an office bearer of the Union before actually transferring that workman and the management is also expected to apply its mind while taking a decision about the transfer to the representation made by workman or union and to record the reasons for rejecting the representation.

This provision of the Sastry Award, may not be followed by the Bank in very special cases. But the Bank should, in such cases, show that the circumstances were such that the Bank could not wait for five days for passing the transfer order and an immediate order of transfer was necessary in the interest of the proper functioning of the administration of the Bank or that in the event of delay of five days in transferring an employee, the Bank shall undergo some irreparable loss. Sastry Award has chosen the words "very special cases" which mean that ordinarily even in special case a transfer of a union office bearer cannot be effected without giving the union or the workman an opportunity to put a representation and that opportunity should be of a clear five working days.

14. It has been argued on behalf of the Bank that the abolition of the post of special asstt. was a special circumstance. According to the pleadings of the Bank itself it is clear that the business at Ghat Road Branch, Nagpur was depleting for a period of time and in view of the reduction of work at the Ghat Road Branch the Bank decided to abolish the post of Special Assistant around December, 1976. If the circumstances made it necessary to implement the decision of the Bank immediately and as a result of such abolition the transfer of Shri Vaidya from Ghat Road Branch to some other station was necessary, a notice as required by para 535 of the Sastry Award could have been given in the month of December itself and then an order of transfer could have been passed after considering the representation, if any. The Bank although took a decision to abolish the post of Special Assistant in Ghat Road Branch in December 1976, still did not give a notice of its intention to transfer Shri Vaidya from Nagpur till 3-1-1977, and all of a sudden transferred Shri Vaidya in flagrant breach of the provision contained in para 535 of the Sastry Award. As such, it cannot be said that abolition of the post of Special Assistant at Ghat Road branch was a very special case and therefore no notice of the action contemplated by the management was necessary.

15. It has further been argued on behalf of the Bank that as no post of Special Assistant is available at Nagpur Shri Vaidya cannot be posted at Nagpur.

It is undisputed before me that Shri Vaidya, in his representation, had clearly requested that he may be reverted back to his substantive post in case of the non-availability of the post of Special Assistant at Nagpur. The representation is dated 28-7-1977. According to para 5.9 of the Bipartite Settlement of 1966 a recepient of special allowance can make a request to give up the work and duties which entitle him to the Special Allowance and if his request is granted he shall cease to draw the special allowance. The Bank could have considered this request even after the passing of the transfer order and could have posted him at Nagpur after reverting him back to the substantive post of the Head Clerk. But the Bank did not accede to this request of the workman also. Had the Bank followed the procedure contained in para 535 of the Sastry Award it could have an opportunity of considering the request of Shri Vaidya for posting at Nagpur even after reversion to his substantive post and could have arrived at a decision whether the transfer of Shri Vaidya to some other station from Nagpur should be made or not. The Bank however did not give such an opportunity to the workman while effecting the transfer. Therefore, in all fairness, it could have sympathetically considered the request of the workman made after the transfer in the form of representation as discussed above. The management however rejected the representation of Shri Vaidya, without asking the workman to get himself examined by the authorised doctor of Bank and without assigning any reasons as to why Shri Vaidya could not be posted at Nagpur even on reversion to his substantive post.

Before the Tribunal also, the Management has not averred that the post of Head Clerk is not available at Nagpur in any of its branches. Therefore the contention of the management of non availability of a post for Shri Vaidya at Nagpur is also untenable.

16. Now we have to examine the justifiability of the abolition of the post of special Asstt. at Ghat Road Branch at Nagpur. The Union has very strenuously contended that the management has contravened the provisions of Section 9A of the Industrial Disputes Act, in abolishing the post of Special Assistant without giving a notice to the workman of the change in the condition of his service.

In my view, the contention of the Union of this point is without any force. According to para 8.2 of the Promotion Policy of the Bank, which has been carved out as a result of an understanding between the All India Employees Federation and the Union Bank of India dated 22nd April, 1975; the creation or abolition of the post carrying special allowance and for filling up vacancies in such post is within the discretion of the management. The management was therefore, empowered to abolish the post of Special Assistant carrying a special allowance Further, by abolishing the post of special Assistant at Ghat Road Branch the management did not change the service conditions of Shri Vaidya. It was not the condition of the service of Shri Vaidya, that all through his service tenure as a Special Assistant, he shall be entitled to work at Ghat Road Branch only. As a result of the abolition of the post of Special Assistant at Ghat Road Branch Shri Vaidya was not reduced in rank. He was transferred to the post of Special Assistant at Rashim Branch. Therefore a notice under Sec. 9A of the I.D. Act was not necessary even if Section 9A of the Industrial Disputes Act applied in the case of abolition of a post by the management.

17. Furthermore, in the instant case, Sec. 9A of the Industrial Disputes Act is not applicable. It is applicable only when a change in service condition is brought about in respect of the items specified in the Fourth Schedule to the Industrial Disputes Act. None of the items of the Fourth Schedule says that the creation or abolition of a post carrying special allowance requires a notice of change under Sec. 9A of the Industrial Disputes Act. Therefore the action of the management in abolishing the post of Special Asstt. at Ghat Road cannot be held to be illegal for contravention of Sec. 9A of the Industrial Disputes Act.

18. The management has raised a plea of estoppel. According to it, Shri Vaidya had made a request to post him to Akola and he has accordingly been transferred. Therefore, he should be deemed to have abondoned his claim for posting at Nagpur. This argument of the management cannot be accepted for the simple reason that all through, Shri Vaidya had been requesting the management to post him at Nagpur. His request for his transfer to Akola was only an alternative prayer, in case he could not be posted at Nagpur. Such an alternative prayer cannot be construed to mean that Shri Vaidya has abondoned his claim for posting at Nagpur.

19. In the result it is held that the action of the management of Union Bank of India in abolishing the post of Special Assistant of Ghat Road branch Nagpur was within the powers of the management and as such cannot be held to be unjustified. But transferring Shri Vaidya from Nagpur to Rashim was not justified, being in contravention of the provisions of the Sastry Award. The workman Shri Vaidya is therefore entitled to be posted at Nagpur on the post of Special Assistant, if it is available at any of the branches at Nagpur. In case the post of Special Assistant is not available then Shri Vaidya should be posted to his substantive post of the Head Clerk at any of the branches at Nagpur. The management shall pay a costs of Rs. 100 to the Union

16-8-80

A. G. QURESHI, Presiding Officer.

[No. L-12012/106/78-D.II.(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1980

का०आ० 2467.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० डी० चौधरी होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के प्रबन्धतंत्र की श्री बाबू सिंह सुपुत्र श्री लाल सिंह, अंशकालिक माली को 1, मई, 1978 से काम करने से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/105/79-डी-2(ए)]

एस० के० बिस्वास, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 8th September, 1980

S.O. 2467.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. D. Choudhury shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in stopping Shri Babusingh S/o Shri Lal Singh, Part Time Mali from work with effect from 1-5-1978 is justified ? If not, to what relief is the workmen concerned entitled ?

[No. L-12012/105/79-D.II(A)]

S. K. BISWAS, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1980

का०आ० 2468.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता-700071 के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदरसनम डैनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता 700071 के प्रबन्धतंत्र की श्री सी० आर० माने, सहायक को "अभिलेख पाल" के रूप में पुनः वर्गीकृत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है ?

[सं० एल० 17012/6/80-डी 4(ए)]

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1980

S.O. 2468.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd., Calcutta-700071 and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (i) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of National Insurance Company Limited, Calcutta-700071 in re-categorising Shri C. R. Mane, Assistant as 'Record Keeper' is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from which date ?

[No. L-17012/6/80-D.IV(A)]

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2469.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd September, 1980.

BEFORE MR. JUSTICE R. BHATTACHARYA, M.A.,B.L.,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 3 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. D. K. Mukherjee, Labour Officer.

On behalf of Workmen—Mr. Santosh Kar, Secretary, National Union of Waterfront Workers.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port

AWARD

The instant reference has come to this Tribunal by virtue of the Order No. L-32012(13)/76-D.IVA dated 26th August, 1977 of the Central Government under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for getting an adjudication on the following dispute :

"Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in imposing the punishment mentioned in their letter No. LO/C/85/WL/7867 dated the 11th May, 1976 on Shri Ram Nandan Giri, Store Khalasi, Chief Mechanical Engineer's Department ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The case in the written statement of the workmen represented by the National Union of Waterfront Workers, hereinafter referred to as the "Union", in short, is that Ram Nandan Giri, the concerned workman is a Store Khalasi at the Crane Repairing yard. He was elected delegate from the union. He was transferred to the Crane Repairing yard from Hydraulic Pumping Station, Kidderpore Docks. This transfer was mala fide. Ram Nandan Giri moved against the transfer and, therefore, the Engineer-in-charge A. N. Roy was very much annoyed with him and was trying to put him into difficulties. The Engineer-in-charge with the intention to trap Ram Nandan Giri invited him to come to his office on 18-10-75 for a discussion about the 20 point programme of the Prime Minister and when he came to the office of the Engineer-in-charge, a false case of trespass, abuse, etc. was set up. The said charges were baseless. An enquiry was held. The Enquiry Officer was biased. He did not examine A. N. Roy but accepted his written statement. The Enquiry Officer acted as both Prosecuting Officer and Enquiry Officer. The Enquiry was initially illegal and bad. The finding of the Enquiry Officer was not based upon proper evidence. The punishment meted out to Ram Nandan was untenable and illegal. In fact, the allegations made in the chargesheet against Ram Nandan have been denied and the enquiry held against him has also been challenged as improper. The case of the union is that it is a case of victimisation.

3. The case of the Calcutta Port Trust, hereinafter referred to as the "Port Trust", to be brief, is that it was alleged that on 18-10-75 at about 3.30 P.M. Ram Nandan Giri trespassed into the office of Engineer-in-charge, Hydraulic Pumping Station and abused the Engineer-in-charge in filthy language in front of others though Ram Nandan was off his duty at that time. On the particulars of these allegations a chargesheet was served upon Giri and an enquiry was held. Ram Nandan Giri was placed under suspension during the enquiry. The enquiry was held according to law giving all opportunities to the delinquent and there was no defect in the matter of enquiry as alleged by the union. The domestic enquiry was conducted legally and a report was submitted which was examined by the Chief Mechanical Engineer, the Punishing authority who went through the proceedings of the enquiry and accepted the findings of guilt arrived at by the Enquiry Officer. He inflicted punishment on Ram Nandan Giri saying that his pay should be reduced by two stages for a period of two years without affecting his future grade increments, that he should be warned and that the period of his suspension was to be treated as on suspension. Ram Nandan Giri was assisted at the enquiry by his chosen man and he got all opportunities for his defence. There was no bias on the part of the Enquiry Officer or anybody else. It is stated that the action of the Port Trust was bona fide and according to law and the workman concerned can get no relief.

4. When the case was taken up for hearing both the parties agreed that they would adduce evidence both regarding validity of the enquiry as well as on merits. There was, therefore, no occasion for hearing on preliminary point regarding the validity of the enquiry alone. Several documents have been exhibited on both sides. Both the parties examined witnesses regarding validity of the enquiry as well as the merits about allegations in the chargesheet. Mr. D. K. Mukherjee, Labour Officer appeared for the management of the Port Trust and Mr. Santosh Kar, Secretary of the Union appeared on behalf of the workmen.

5. The first question that arises for my consideration is whether domestic enquiry held against the delinquent Ram Nandan Giri was proper and valid. The union's case is that the enquiry was not based upon the principles of natural justice, that the Enquiry Officer acted as both Prosecuting Officer on behalf of the maangement of the Port Trust and the Enquiry Officer, that he was biased from the start and tha Ram Nandan Giri did not get proper and reasonable opportunity for his defence. It has also been alleged that the enquiry has not been conducted according to proper and bona fide procedure. On the other hand, Mr. Mukherjee for the Port Trust has contended that there was no bias in the present case and that the Enquiry Officer acted properly giving sufficient opportunity to Ram Nandan for his defence particularly when he was assisted by the Secretary of the Union before the Enquiry Officer.

6. I shall now deal with the evidence regarding the manner in which the domestic enquiry was held by the Enquiry Officer. The memorandum of charge served upon Ram Nandan Giri contains the allegations in the following manner :

"That the said Ram Nandan Giri trespassed into the office of Engineer-in-charge, Hyd. Pumping Station, Docks on 18-10-75 at about 15.30 hours and abused him in the filthy language in front of others though he was off from duty from 12.15 hours from Crane Repairing yard on the same day."

The charge was framed in the following words :

'That the said Sri Ram Nandan Giri is charged with misconduct inasmuch as he entered the office of Engineer-in-charge, Hyd. Pumping Station, Docks at about 15.30 hours on 18-10-75 and abused him in filthy language in presence of others though he was off from duty from 12.15 hours on the same day from Crane Repairing yard.

This action on the part of Sri Ram Nandan Giri amounts to gross insubordination and breach of official discipline and decorum."

On the above charge and allegation the delinquent was asked to submit a written statement of his defence.

7. Ram Nandan Giri submitted a written explanation dated 26-11-75 stating that he denied the allegations made against him, that he neither used any filthy language to nor abused the Engineer-in-charge on 18-10-75, that he being a delegate of a recognised union had gone to the work site and that he had gone to consult the Engineer-in-charge, that the Engineer-in-charge became furious and started abusing the delinquent, that R. N. Basu and P. N. Mondal, third and second engineers respectively and also one 'Dandabat started abusing Ram Nandan taking the side of the Engineer-in-charge, that A. N. Roy the Engineer-in-charge gave threats of victimising Ram Nandan and of teaching him a good lesson and that the names of the witnesses would be submitted during the course of enquiry.

8. Let me now consider the evidence of the Enquiry Officer. He is MW-1 Sunit Kumar Nandy. From his evidence we get that he started the domestic enquiry against Ram Nandan on 7-2-76. Ram Nandan was present being defended by the Secretary of the Union. The records of the enquiry has been collectively marked Ext. M-6a. On different dates he examined witnesses at the enquiry. After enquiry he prepared his decision and the copy of that has been marked Ext. M-5. The Enquiry Officer found Ram Nandan guilty of the charge. We also get from MW-1 that on perusal of the records of the enquiry and the finding of the Enquiry Officer, the Chief Mechanical Engineer who was the disciplinary authority passed the order of penalty. The order passed has been marked Ext. M-6b. We also get that after the examination of the witnesses the Secretary of the Union submitted a written argument on behalf of Ram Nandan. The Enquiry Officer went through the argument and then gave his decision. The Enquiry Officer has stated that he treated A. N. Roy as complainant against Ram Nandan but not as a witness on behalf of the management. Admittedly A. N. Roy was the Engineer-in-charge and he submitted a written complaint against Ram Nandan making the charge allegations. That complaint has been marked Ext. M-11. The witness further says that A. N. Roy gave evidence at the enquiry partly from his complaint and partly from his mind. He did not supply any copy of the complaint either to Ram Nandan or to the Secretary of the Union. Of course, he has stated that no objection was raised regarding the reading of the complaint by A. N. Roy. From

this witness we also get that there was no Prosecuting or Presentation Officer on behalf of the management at the time of enquiry to examine the witnesses against the delinquent. He has admitted that he examined the witnesses on the side of the prosecution and cross-examined the defence witness. The Enquiry Officer does not know whether there are Standing Orders of the Port Trust. He is not aware of any definition of misconduct, but according to him something which is not proper is misconduct according to the Enquiry Officer insubordination means not carrying out lawful orders or directions and trespass means to enter. The Enquiry Officer did not ask the management to engage any Presentation Officer for examining the witnesses on behalf of the management. For coming to his findings he did not rely on any rule. He has made a strange statement during cross-examination. He has stated that when prosecution witness did not mention about the economic discussion, he disbelieved the statement of the defence witness as he referred to 20-point economic programme. We also get from the Enquiry Officer that on the first day of hearing of the enquiry, no witness on behalf of the management against the delinquent was present. Ram Nandan was, however, present along with his defence counsel meaning the Secretory of the union. On that day the Enquiry Officer explained the chargesheet to Giri and thereafter he put several questions to Giri about the alleged guilt of the delinquent. The witness wanted to say that he put the questions not by way of cross-examination but he wanted to know the facts concerning the charge allegations, and that is why he examined Ram Nandan. I have gone through the questions put by the Enquiry Officer to the delinquent and I find that they were in the nature of sharp cross-examination in order discredit him and to put him to embarrassment and this was done before the examination of any witness against him. In answer to my question the Enquiry Officer has clearly stated that in this case he examined the witness of the management as if he was the Presentation Officer and this was done on behalf of the management. Of course, it struck him that the Enquiry Officer should not take the role of a Prosecuting Officer. The Enquiry Officer has fairly conceded in evidence that he should not have examined the prosecution witnesses when he was the Enquiry Officer acting as Judge. The Enquiry Officer thought that A. N. Roy was the most important witness to the occurrence but did not use him as witness on the ground that he was complainant. This is something queer and astonishing. He had admitted that he did not consult any rules of discipline of the Port Trust while coming to his findings. The rules will appear in Ext. M-12. The Enquiry Officer has stated that as it was a fact finding enquiry, he did not follow any prescribed procedure and, of course, he is not aware of any prescribed mode of enquiry as he admits himself.

9. In the above paragraph I have discussed the evidence of the Enquiry Officer and it will appear clearly that the enquiry was a farce. Before examination of any witness on the side of the management to prove the charges against the delinquent, the Enquiry Officer himself started cross-examining Ram Nandan as if to extort some answers which would go against him and to prove that the statement of the delinquent was false. Besides that, the Enquiry Officer has himself stated that he disbelieved the defence witness simply because the witnesses on the side of the management did not mention the story of 20 point economic programme. It may be stated that the case of Ram Nandan Giri was that he went to the chamber of the Engineer-in-charge to discuss on the 20-point economic programme. Without ascertaining whether the management's witnesses were speaking the truth and whether there was corroborative evidence to support the management's case, the Enquiry Officer jumped to the conclusion of guilt of the delinquent simply because the prosecution witnesses did not speak about the 20-point economic programme. This sort of finding of the Enquiry Officer is unacceptable. The reasoning is perverse. The Enquiry Officer could have asked the delinquent to ascertain the answer as to the charge framed against him and then after examination of the witnesses against the delinquent if was for him to ask for defence witnesses to be examined. In my view, in the present case Ram Nandan Giri did not get proper opportunity for defence at the enquiry and that the Enquiry Officer acted as the Prosecuting Officer as well as the Enquiry Officer which is highly objectionable. The story of bias set up by the union is very natural. It appears further that the Enquiry Officer had no idea about the disciplinary rules of Port Trust and the said rules are essentially to be followed in domestic enquiry. The procedure adopted by the Enquiry Officer is, therefore, highly objectionable. There was miscarriage of justice. The findings arrived at by him and the way in which he assessed the evidence are highly condemnable. Proper finding could not have been arrived at in the manner as indicated. The entire evidence and the facts and circumstances have not been looked into in proper perspective. I, therefore, hold without any further comment that the enquiry was improper and illegal and consequently the findings of the Enquiry Officer were bad and illegal.

10. Having held that the domestic enquiry against the delinquent was improper and illegal, I now consider whether the allegations of misconduct charged against Ram Nandan Giri have been proved on the basis of the evidence adduced before this tribunal by the parties. The complainant Amarendra Nath Roy, the engineer-in-charge of the Dock Engine House has been examined as MW-2. He has proved the complaint Ext. M-11. From his evidence we get that on 18-10-75 when he was in his office chamber on duty at about 3.30 P.M. Ram Nandan suddenly came inside his chamber and uttered some objectionable language to him. Ram Nandan first asked him why he did not answer to his letter. He stated that Amarendra Nath Roy had been garlanded with shoes and asked whether he would have garland of shoes even then. He repeated saying that Amarendra Nath Roy was to wear that garland of shoes and other things which have been mentioned in details in his evidence. Ram Nandan threatened him saying "Who would now save you ?" He did congress politics and he knew Umashankar Dikshit. He also demanded to Amarendra Nath Roy to know why the latter transferred the former and he went on shouting. Amarendra Nath Roy has stated that he remained completely quiet and that time three persons were inside his chamber. They were R. N. Bose, P. N. Mondal and Basudev Patra. That was a Saturday and as the Headquarters of Chief Mechanical Engineer was being closed and Sunday was a holiday, he sent the complaint on Monday to the Senior Mechanical Engineer who was the immediate boss of A. N. Roy. From this witness we get that on that day Giri was off his duty from 12.15 P.M. He was a Store Khalasi and his place of work was at a distance of 10 to 12 minutes' walk from his chamber. He has been cross-examined. MW 2 has admitted that an application of Ram Nandan was received in his department on 20-10-75. A copy of the said application has been marked Ext. W-1. A copy of the said application produced by the delinquent and admitted by him is marked Ext. W-1a. This is a complaint made by Ram Nandan to the Chief Mechanical Engineer received at the department on 20-10-75 making allegations against Mondal, second engineer of the Crane Repairing Yard stating that the said Mondal used bad language and behaved unmannerly with Giri as the latter did not salute him. A suggestion was made to this witness from the side of the delinquent that he set up a concocted report, namely the complaint Ext. M-11, on receipt of the complaint of Ram Nandan against Mondal, the second engineer. A further suggestion was given to Amarendra Nath Roy that as Giri was able to pursuade the workers of his department to follow his opinion, Amarendra Nath Roy concocted a false case to take vegeance upon him for the alleged reason. It was also suggested that Amarendra Nath Roy fabricated the false report against Giri to support the second engineer. The evidence shows that Ram Nandan was transferred to the Crane Repairing Yard from Dock Engine House but MW-2 Amarendra Nath Roy says in his evidence that it was not an actual order of transfer but an order for placing him from one point to another in the same section. According to him Crane Repairing Yard and Dock Engine House are in the same section. This placing, the witness says, was done according to the order of the superior officer, namely the Senior Executive Engineer. The next witness is MW-3 R. N. Bose referred to by MW-2 in his evidence as present at the time of occurrence. R. N. Bose has stated that on 18-10-75 at about 3.30 P.M. he was on duty in his office at the Dock Engine House along with P. N. Mondal, A. N. Roy and Basudev Patra. The witness has stated that Giri came and asked A. N. Roy why he was not answering his letter. Giri then stated that A. N. Roy had been garlanded with shoes at Calcutta Jetty and he also stated that he was a political worker and knew Uma Sankar Dikshit and also asked A. N. Roy to come out and he would show him and there was some haichai. During

cross-examination the witness has stated that Giri was outside the room and he made the statements already mentioned by him besides other words uttered by him. He has denied the suggestion that he has given tutored evidence. The last witness on the side of the management is Jagannath Modak. He has stated that on 18-10-75 at about 3.30 P.M. Ram Nandan Giri entered into the room of A. N. Roy and began shouting why he was transferred to Garighar meaning Crane Repairing Section. He was also demanding answer and was asking A. N. Roy why he was not answering. The witness stated that he does not remember any other words uttered by Giri as it was an incident of long ago. At that time he was in the room just contiguous to the room in which A. N. Roy was sitting and Giri had entered. In between the two rooms there was a thin partition.

11. As against the evidence on the side of the management as mentioned above, Ram Nandan examined himself as WW-1. His evidence is that on 18.10.75 after his duty hour was over, he had been to the Engine House, K. P. Docks at about 3 P.M. According to him A. N. Roy had made an appointment with him and as per that appointment he went to him. He asked A. N. Roy to allow 10 minutes for the workers to join duty after 7.30 A.M. According to him A. N. Roy told him that he could not decide on that point but he would ask his superior officers and then he would communicate their decision. He has further stated that on that very day at about 11 A.M. P. N. Mondal told him why he did not salute him and he asked Giri to clear out of his office and abused him in English which he could not follow. He, therefore, made a complaint against Mondal. He says he is a member of the Executive Committee of the union. During cross-examination he has stated that A. N. Roy was engineer-in-charge of Engine House. He has denied the suggestion that P. N. Mondal did not abuse him as alleged or that he did not go to A. N. Roy's office at 3 P.M. in connection with any previous engagement as stated by Giri. The witness has stated further that in reply to the chargesheet he stated that he was abused by Mondal and that he went to A. N. Roy with previous appointment. This was in reply to a question in cross-examination for the purpose of showing that the case of Giri was quite different from the story when chargesheet was served upon him. One defence witness has been examined on the side of Giri. He is WW-2 Haranath Das. He has stated that on 18-10-75 he was on leave and on that very day he was made unfit medically and he came to the office to make a note of it. At that time he saw altercation between Ram Nandan and A. N. Roy in the room of the later. The witness was standing on the verandah. Giri was complaining to A. N. Roy that he was insulted by P. N. Mondal and asked A. N. Roy to take some steps. A. N. Roy according to the witness asked Giri to submit a written report otherwise he was unable to do anything. Giri was to have discussion on 20-point formula made out by Prime Minister but A. N. Roy refused to have any discussion. The witness then says that Giri at that time was standing on the Verandah. During cross-examination he has stated that he was in 1975 in Dock Engine House and towards the end of the year he was transferred to Calcutta Jetty. In examination-in-chief he stated that A. N. Roy threatened him that if he gave evidence in favour of Giri he would be transferred. He has stated that he was transferred after his giving evidence before the Enquiry officer. But in fact the witness was transferred earlier towards the end of 1975 when there was no enquiry as alleged by him. At one time he stated that he was made unfit at the Dock hospital in the morning of 18-10-75 and thereafter he stated that he was made unfit in the afternoon. Again if he was made unfit in the morning there could be no occasion for him for making a note of it at 3.30 P.M. after so long a time although the Dock hospital was only at a distance of 100 yards from the Engine House. The evidence of WW-2 is most unreliable on the very face of it. I thoroughly reject the evidence of Ram Nandan Giri and his witness WW-2.

12. I have considered not only the evidence of all the witnesses examined before me but also their demeanour. The manner in which A. N. Roy gave his evidence is very straightforward and I find no reason to disbelieve his statement. He has given the details of the utterings of Ram Nandan Giri made to him. That will appear in the complaint which was made at the earliest opportunity after the occurrence and there is every reason to remember the utterances as they were very much insulting particularly when used by a subordinate worker under him. MW-3 has substantially corroborated the evidence of MW-2 to prove the fact that Ram Nandan Giri came inside the room where P. N. Mondal, A. N. Roy and Basudev Patra along with witness himself were on duty. It has been proved without any doubt that without ryhme or reason, or any provocation from the side of A. N. Roy, Giri entered into his office room and shouted and stated that A. N. Roy had been garlanded with shoes at Calcutta Jetty. Giri was also threatening him. There was some haichai due to the action on the part of Giri. MW-4 Jagannath Modak has also supported to say that Giri entered into the room of A. N. Roy at about 3.30 P. M. on 18-10-75 and shouted. This witness does not say anything about the wearing of garland of shoes by A. N. Roy etc. He has clearly stated that he does not remember all the words uttered by Ram Nandan Giri as it was an incident of long past. He gave evidence in the month of August, 1980 whereas the occurrence took place in October 1975 about 5 years ago. The witnesses MWs 3 and 4 may not remember the details of the happenings but MW A. N. Roy against whom abussive language was used by Giri has stated the facts in details and it is natural for him to remember because it was he who was insulted and was hit by the behaviour of Ram Nandan Giri, a subordinate in presence of several officers. I thoroughly accept the evidence of complainant A. N. Roy regarding the incident and he has been corroborated substantially by MWs 3 and 4 particularly in the matter of entrance into the office room by Giri and his shouting and saying that A. N. Roy had been garlanded with shoes previously.

13. On the other hand, regarding the evidence of Ram Nadan Giri I must say that it is utterly unacceptable. In this connexion the evidence shows that a complaint in writing was sent to the Chief Mechanical Engineer stating that on 18-10-75 at 11 A.M. Giri was insulted by Mondal, the Second Engineer as Giri did not salute him. This is Ext. W-1a, as I have already stated. Thereafter in reply to the chargesheet Ram Nandan Giri took the following grounds of defence :

(i) the allegations made in the chargesheet are denied ;

(ii) the defendant did not use any filthy language or abuse against Engineer-in-charge on 18-10-75;

(iii) Giri as a delegate of the union went to the work site and when Engineer-in-charge appeared before him Giri did not give him salute and as a result thereof Engineer-in-charge became furious and abused him and in this connection he referred to his complaint, Ext. W-1a ;

(iv) R. N. Bose, P. N. Mondal and Dandabat also started abusing him taking the side of Engineer-in-charge;

(v) Engineer-in-charge gave a threat of victimisation of Ram Nandan Giri.

Clearly, therefore, as against the charge on the basis of the complaint of A. N. Roy, his reply was that as he did not salute A. N. Roy, the Engineer-in-charge, he became furious and started abusing him. When A. N. Roy deposed before this Tribunal no such suggestion was made to him. On the other hand, it was suggested that as Mondal abused Giri and as Giri filed a complaint against Mondal, A. N. Roy started a false case. At the time of hearing before me it was argued on the side of Giri that at the appointment made by A. N. Roy with Giri, the latter had been to his room. Giri wanted to say that but in reply to the chargesheet as already stated there was no such case of appointment made by A. N. Roy with him. Neither was there any story of discussion about 20-point economic programme of the then Prime Minister. There was no suggestion at all during the hearing before me that A. N. Roy misbehaved with Ram Nandan. There can be no occasion, therefore, for A. N. Roy to set up a false story against Ram Nandan Giri. The suggestion that A. N. Roy fabricated the case because Ram Nandan Giri complained against P. N. Mondal is utterly unacceptable. Ram Nandan Giri himself admitted that he had been into the room of A. N. Roy at about 3 P.M. but it was according to him on an appointment. The presence of Ram Nandan Giri in the room of A. N. Roy at about 3.30 P.M. has not only been proved by the direct evidence adduced on the side of the management but has also been indirectly corroborated by the defence evidence. However, I am satisfied from the evidence on record that on 18-10-75 at about 3.30 P.M. while A. N. Roy was on duty in his room at Kidderpore Dock, Ram Nandan Giri uncalled for and

without any reasonable ground entered into that room, shouted, used filthy language, threatened A. N. Roy and in presence of other officers like R. N. Bose, Basudev Datta and P. N. Mondal insulted him saying that A. N. Roy had been garlanded with shoes previously. Giri did all these things when he was off his duty. The way in which he has behaved with A. N. Roy as stated in presence of other officers was certainly a breach of office discipline and decorum amounting to misconduct. Admittedly there are no Standing Orders of the Port Trust but there is one booklet called the Calcutta Port Commissioners' Employees (Discipline and Appeal) Rules, 1964. This has been marked Ext. M-12. At page 6 of the said rules there is Rule 9 in part V, headed as "Discipline". It speaks about the nature of penalties but there is no provision in these rules containing definition of misconduct. In absence of Standing Orders we have to fall back upon the Model Standing Orders in respect of the industrial establishments not being industrial establishments in coal mines appearing in Schedule I of the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946. In Rule no. 14 of the said Model Orders meant for disciplinary action for misconduct, we get in sub-rule (3) the acts and omissions which shall be treated as misconduct. Clause (h) of sub-rule (3) of Rule no. 14 says that ritious or disorderly behaviour during working hours at the establishment or any act subversive to discipline is to be treated as misconduct. In the case before me I, threfore, find that Ram Nandan Giri acted in a disorderly behaviour during working hours and committed an act subversive of office discipline by entering into the office chamber of A. N. Roy when he was on duty and by shouting and using abussive, filthy and insulting language towards A. N. Roy without any justification and provocation. This sort of behaviour on the part of Ram Nandan Giri, a subordinate worker under A. N. Roy, Engineer-in-charge was highly objectionable and the same amounts to misconduct. I thus hold that the charge allegation against Ram Nandan Giri has been proved and he is guilty of misconduct as already indicated.

14. Regarding the punishment meted out against Ram Nandan Giri it has been argued by Mr. Kar that of the three penalties inflicted upon Ram Nandan Giri in the present case, the last two are without jurisdiction and the first one is highly disproportionate and too harsh. In Ext. M-12 we get the provision of penalties under rule No. 9 of the Calcutta Port Commissioners' Employees' (Discipline and Appeal) Rules, 1964. There has been an anumeration of different kinds of penalties. In the present case Giri has been penalised in the following manner :

(i) his pay should be reduced by two stages for a period of two years without affecting his future grade increment.

(ii) he should be warned, and

(iii) the period of his suspension to be treated as on suspension.

With regard to the last two penalties, namely, warning and suspension to be treated as penalty, I do not find any such provision in Rule 9 of the Discipline and Appeal Rules. The period of suspension during enquiry will take its own effect according to rules of the Port Trust but it cannot be a part of penalty in view of Rule 9 of the Disciplinary Rules of the Port Trust. Similarly, there is no provision for warning as penalty. Therefore, the last two penalties cannot stand. Regarding the first penalty about reduction of the pay of Ram Nandan it has been argued by Mr. Kar that Ram Nandan works for the union and that he should be leniently dealt with particularly when there is no record of misconduct previous to this occurrence. It should be remembered that the misconduct in the present case proved against him cannot be lightly taken, particularly when he says that he does some union work. The facts of the present case show that he not only acted in breach of office discipline but also behaved with his superior officer in a most objectionable and ugly manner. It is not expected of any decent worker of a union to be indisciplined and uncourteous and rough to his superior officers. Giving my best consideration on the submissions of Mr. Kar for the workman, I deal with this case with some mercy and I believe this will be a lesson to Ram Nandan Giri for his future life. I propose to reduce the penalty of reduction of his pay by two stages for a period of two years to the minimum penalty of 'Censure' for his misconduct and I think this will be sufficient punishment of the delinquent for his misconduct.

15. I, therefore, find the guilt of Ram Nandan Giri in respect of his misconduct on the charge allegation as already indicated proved and for such misconduct his penalty should be 'Censure' to be recorded in his Service Book for his misconduct thus reducing the first penalty. The other two penalties are void. The effect of suspension during enquiry will be according to rules of the Port Trust. The penalty is thus modified.

I thus pass my award.

Dated, Calcutta.

The 25th August, 1980.

Sd-

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer

[No. L-32012/13/76-D-IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1980

का०आ० 2470—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेलमपाली डिवीजन, जिला आदीलाबाद, आन्ध्र प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र की—

(1) आकस्मिक श्रमिकों और मजदूर प्रशिक्षणार्थियों को, जो नियमित कर्मकारों की जगह काम कर रहे हैं, स्थायी न करने ; और

(2) आकस्मिक श्रमिकों और कर्मकार प्रशिक्षणार्थियों को आकस्मिक छुट्टी न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-21011(8)/80-डी-IV(बी)]

ORDER

New Delhi, the 14th August, 1980

S.O. 2470.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of S.C. Co. Ltd., Belampali Division, Adilabad District A.P. and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasan Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited

(1) in not confirming casual labour and worker-trainees who are working in place of regular workers and,

(2) in not granting casual leave to casual labour and worker-trainees, is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L-21011(8)/80/D.IV.(B)]

का०आ० 2471.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड रामकृष्णपुर डिवीजन II, डाकखाना रामकृष्णपुर, जिला अदीलाबाद, आन्ध्र प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० निवासा राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, रामकृष्णपुर डिवीजन II, रामकृष्णपुर (डाकखाना) व जिला अदीलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र की क्ले पिल मजदूरों के कार्यभार को बढ़ाने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-21011(3)/80-डी 4(बी०)]

एस० एस० मेहता, डेस्क अधिकारी

S.O. 2471.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company, Limited, Ramakrishnapur Division II, P. O. Ramakrishnapur, Adilabad District, A.P. and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs. Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur Division II, Ramakrishnapur (Post Office) Adilabad District (Andhra Pradesh) in enhancing the workload of Clay Pill Mazdoors is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[No. L-21011(3)/80-D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 1st September, 1980

S.O. 2472.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Girimint Colliery of Eastern Coalfields Limited, Post Office Charanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th August, 1980.

BEFORE MR. JUSTICE R. BHATTACHARYA, M.A.,B.L., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 11 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Girimint Colliery of Eastern Coalfields Limited,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers : Mr. B. N. Chatterjee, Dy. Chief Personnel Officer, with

Mr. D. K. Banerjee and

Mr. I. N. Srivastava, Senior Personnel Officers.

On behalf of Workmen : Mr. Sunil Mazumdar, General Secretary, Ningha Colliery Mazdoor Union.

State : Wesct Bengal Industry : Coal

AWARD

By Order No. L-19012(15)/77-D-IV(B), dated 17th September, 1977, the instant reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has been sent by the Central Government for adjudication of the following dispute :

"Whether the action of the management of Girimint Colliery of Eastern Coalfields Limited in not regularising the services of Shri Dewatanandan Singh as Pit Munshi in Clerical Grade III scale of pay, is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. When the case is taken up for hearing Mr. B. N. Chatterjee, Deputy Chief Personnel Officer of Girimint Colliery of Eastern Coal Fields Ltd., and Mr. Sunil Mazumdar, General Secretary, Ningha Colliery Mazdoor Union submit that the parties have come to a compromise and file a petition of compromise signed by the said General Secretary and also the workman concerned on the one hand and Mr. B. N. Chatterjee, Deputy Chief Personnel Officer, Mr. D. K. Banerjee, Sr. Personnel Officer and Mr. I. N. Srivastava, Senior Personnel Officer of the colliery on the other hand. Mr. Nikhilesh Das, Advocate has signed the said petition of compromise as witness. It is prayed by the parties that an award may be passed in terms of the petition of compromise filed.

3. I have gone through the said petition and I find that it is legal and the compromise contains terms for the benefit of the workman concerned.

4. In the circumstances I pass the award in terms of petition of compromise filed to-day which shall form part hereof as Annexure "A".

Sd/-

Dated, Calcutta.
The 14th August, 1980.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer.

[No. L-19012(15)/77-D.IV(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

ANNEXURE "A"

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 11 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Girimint Colliery of Eastern Coalfields Limited, Post Office, Charanpur, Dist. Burdwan.

AND

Their Workmen

The Employers and the workmen beg to state jointly that by mutual discussion held between the Parties, they have decided to settle the dispute which is the subject matter of this reference amicably on the following terms.

1. That it is agreed by the parties that the concerned workman Shri Dewta Nandan Singh will be placed in the post of pit Munshi in clerical Grade III of the Coal Wage Board recommendation with effect from 1st January 1979.

2. That the employers will pay a consolidated sum of Rs. 250 (Two hundred fifty) only to the concerned workman as ex-gratia payment and the concerned workman will not be entitled to claim any difference of wages or any other dues whatsoever from the Employer for the period prior to the date of this settlement.

3. The aforesaid sum of Rs. 250/- will be paid within 2 months from the date of this settlement.

4. That the parties will have no further claim against each other regarding the abovesaid reference and they will bear their respective cost of the reference.

The parties most humbly pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to accord its kind approval to this Settlement and to pass an award accordingly by treating this settlement as a part thereof.

Dated :—14-8-80.

Sd/- Sunil Majumdar
For Workmen
Sd/- Dewtanandan Singh
For Employers.

Concerned workman

B. N. Chaterjee, Dy. Chief Personnel Officer
D. K. Banerjee, Sr. Personnel Officer,
Sd./- I N. Sriwastava Sr. Personnel Officer
Witness :—
Nikhileshtan.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1980

का०आ० 2473.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रेनाइट खानों में नियोजन को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग I में जोड़ती है, उक्त धारा में की अपेक्षानुसार ऐसा करने के अपने आशय की सूचना भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 8 मार्च, 1980 के पृष्ठ सं० 665 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 561, तारीख 27 फरवरी, 1980 द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

[सं० एस०-32017/3/78-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]
आर०एस० देशपाण्डे, उप सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1980

S.O. 2473.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act, the employment in Granite mines, notice of its intention to do so having already been given by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 561, dated the 27th February, 1980, published at 665 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 8th March, 1980, as required by the said section.

[No. S-32017/3/78-WC(MW)]
R. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1980

का०आ० 2474.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि "मैगनेसाइट खनन" उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची में जोड़ना लोकहित में समीचीन है।

अतः, अब, औद्यो,क विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में मद (23) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ती है, अर्थात् :—

24. "मैगनेसाइट खनन"

[सं० एस० 11017/5/79 डी०1 (ए) (1)]

New Delhi, the 4th September, 1980

S.O. 2474.—Whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest to add to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the industry of 'Magnestie Mining'.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby adds the following item to the First Schedule to the said Act, after item (23) thereof, namely :—

"24. Magnesite Mining".

[No. S. 11017/5/79-D.I.(A)(i)]

का०आ० 2475.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि मैगनेसाइट खनन उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, लोकहित में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस०-11017/5/79-डी०1 (ए) (ii)]
एल० के० नारायण, डेस्क अधिकारी

S.O. 2475.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Magnesite Mining Industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declare with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/5/79-D.I(A)(ii)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1980

का० आ० 2476.—भारत के तारीख 7 जून, 1980 के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(ii) (का०आ० 1564) में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या यू-23013(10)/77 एल० डब्ल्यू०, तारीख 17 मई, 1980 में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, श्री ए० पूनन, उप सचिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, संयोजक शब्दों के स्थान पर श्री आर०पी० नरुला, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, संयोजक शब्द रखे जाएं।

[यू० 23013/10/77-एल० डब्ल्यू०]
पी०एस० हबीब मुहम्मद, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 4th September, 1980

S.O. 2476.—In modification of this Ministry's Notification No. U.23013(10)77-I.W. dated the 17th May, 1980 published in Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated the 7th June, 1980 (S.O. 1564), the Central Government hereby makes the following amendment namely :—

"In the said Notification, for the words and letter Shri A. Poonen, Deputy Secretary, Ministry of Labour, New Delhi—Convener, Shri R. P. Narula, Under Secretary, Ministry of Labour, New Delhi, Convener, may be substituted".

[U.23013/10/77-LW.]
P. S. HABEEB MOHAMED, Jt. Secy.

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2477.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Topa Colliery of Central Coalfields Limited Post Office Kuju, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th August, 1980.

BEFORE SHRI J. P. SINGH, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD.

Reference No. 92 of 1979

In the matter of a reference under S.10(1)(d) of the I.D. Act 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Topa colliery of Central Coalfields Limited, Post Office Kuju, District Hazaribagh.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri T.P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. Joshi, Advocate

State : Bihar. Industry : Coal

Dhanbad, 21st August, 1980.

AWARD

This is a reference under S.10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. L-20012| 183|77-D.III(A) dated 31-12-77 had referred this dispute to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3) Dhanbad for adjudication on the following terms.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Topa colliery of Central Coalfields Limited, Post office Kuju, District Hazaribagh in stopping Shri Dhannu, son of Shri Ratneshwar Pathak, Fitter Helper from work with effect from 5th October, 1976 is justified? If not to what relief is the said workman entitled?"

2. This reference was originally received by the Central Government Industrial Tribunal (No. 3) Dhanbad and registered as Reference No. 1 of 1978. On transfer this reference was received in this Tribunal on 7-7-79 and registered as Reference No. 92 of 1979. Thereafter the hearing has been concluded in this Tribunal.

3. The facts leading to stoppage of work of the concerned workman has been brought out in detail in the written statement of the management. Topa colliery was taken over by the Central Government on 31-1-73 under the Coal Mines (Taking over of management) Ordinance, 1973. The ordinance was replaced by an Act and eventually the mine was nationalised with effect from 1-5-73 and vested in Coal Mines Authority Ltd. The mines have since vested in the Central Coalfields Limited which is a subsidiary of the holding company Coal India Limited. This Topa colliery before take over was being worked through inclines besides quarries. Two of the inclines at the time of take over through which work was going on were 4|4A incline and 6|6A incline. At the time of take over the method of working was through contractors. After take over the Custodian allowed the contractors to deploy their men in the mines. The management followed a process of screening of genuine workmen.

4. One Dhannu Ganjhu son of Jitna Ganjhu of village Mangardhaha, P.O. Kuju P.S. Mandu District Hazaribagh was found to have worked for 4 days w.e.f. 7-2-73 at No. 4/4A incline and as such his name was entered in the Man Power list of that incline. In the Man Power list of 6|6A incline it was found that Dhannu Ganjhu son of Jitna Ganjhu of Mangardhaha, P.O. Kuju, P.S. Mandu, District Hazaribagh was purported to have been appointed on 2-2-72 has worked for 2 days in that incline w.e.f. 7-2-73, 6 days w.e.f. 21-2-73 and 5 days w.e.f. 21-3-73. Both these lists were certified by the manager of the colliery. According to the management's case therefore the same person named Dhannu Ganjhu son of Jitna Ganjhu has worked in 4|4A incline as well as in 6|6A incline. This Dhannu Ganjhu was screened in. But unfortunately due to inadvertance the above duplication of the same name in two screening lists went un-noticed with the result that the name of Dhannu Ganjhu was published in two places. While Dhannu Ganjhu in respect of incline No. 4/4A was Sl. No. 342 in the list, the same Dhannu Ganjhu was found in 6|6A incline with Sl. No. 432. The aforesaid screning was completed sometime in May, 1973. Dhannu Ganjhu with Sl. No. 432 in the screening list of 6|6A incline who was designated as hazri cooly was subsequently designated as category I mazdoor and he is still working in that colliery. The concerned workman Dhannu was found to be working under Sl. No. 342 of 4/4 incline w.e.f. 5-1-74.

5. According to the management sometime in September, 1973 there was a violent clash between two factions of the local union at Topa colliery as a result of which most of the workers fled away and for a considerable period there was great chaos and confusion. Taking advantage of the situation the concerned workman whose real name is Maheshwar Pathak son of Shri Ratneshwar Pathak of vilage P. O. Balsagra P.S. Mandu, District Hazaribagh got himself inducted with the help of his elder brother Shri Chandreshwar Pathak who was working in the colliery.

6. A complaint was received from a local M.P. that Dhannu, the concerned workman was an imposter. The Sub-Area Manager, West Bokaro Group of collieries, Kuju made an enquiry and found him to be an imposter. Thereafter w.e f. 5-10-76 under his letter dated 20|29-9-76 he was stopped from work.

7. On behalf of the concerned workman it was stated that he was correctly screened in and in course of employment he was deputed for training and identity card was also issued in his name. According to him he has been maliciously stopped from work on account of his being an active member of the union which was opposed to the union sponsored by the management.

8. In this reference we have to decide as to whether the action of the management in stopping the concerned workman from work with effect from 5-10-76 is justified. The management's only ground is that the concerned workman got his entry into the colliery by deceiptful means and was in fact an imposter. The reason for branding him an imposter is that his real name is Maheshwar Pathak son of Ratneshwar Pathak. In respect of 6/6A incline as well as 4/4A incline Dhannu Ganjhu had worked after the take over and so in the screening list the name of Dhannu Ganjhu in respect of both the sets of incline appears. Taking advantage of such a situation this concerned workman got himself entered as an employee under Sl. No. 432 of 6|6A incline. In this connection the management has shown through the screening list, Ext. M6 as well as Ext. M7 that in both the lists the name of Dhannu Ganjhu appears. According to the management Maheshwar Pathak entered as Dhannu and Dhannu was never his name. But subsequently he discloses in papers that he was Dhannu Pathak. This will appear from one attestation form. Ext. M3 filed filed in by the concerned workman which was received by the management on 22-10-76 in which surname is Pathak and his name as Dhannu. He has given his correct home address. His photograph has also been affixed on Ext. M3. Then there is Ext. M4 which is the statement of Dhannu Pathak with his LTI. In this statement also he is Dhannu Pathak son of Ratneshwar Pathak, village Balsagra, PS. Mandu District Hazaribagh. We have also Ext. M5 a letter from Shri Rajeshwar Singh, Pramuk addressed to Personnel Officer, West Bokaro

Group of collieries stating the name of the concerned workman to be Maheshwar Pathak son of Ratneshwar Pathak. The letter shows that in an earlier certificate he had described him as Dhannu Pathak without verification and at the instance of the concerned workman.

9. An enquiry was instituted against the concerned workman and 11 others. A true copy of the enquiry report is Ext. M1. The enquiry officer found the following :

"1. Dhannu Ganjhu.

On checking of the screening list of Topa East section of Topa colliery one Dhannu Ganjhu son of Jitan Ganjhu has been screened in at screening No. 342 and 432 as Bailing mazdoor and hazri cooli respectively. The person stopped from the work through the above office order, represented himself Dhannu Pathak son of Ratneshwar Pathak, village Balsagra, P.O. Balsagra P.S. Mandu, Dist. Hazaribagh against the sc. list 342. In reference to representation of Shri Dhannu Pathak son of Ratneshwar Pathak the sc. list No. 342 where the employee has been screened in has been checked and it is noted that at this sc. No. one person named Dhannu Ganjhu s|o Jitan Ganjhu has been published as Bailing mazdoor at 4|4A. incline at page No. 9 on Sc. list the attendance of the representing worker has been checked from the bonus register and it has been noted that he is found present continuously from 5-1-1974 to 14-12-1974 in the year 1974 and 4-1-1975 to 27-12-1975 in the year 1975 and onward. From the representation it is noted that there is no such person screened in as Dhannu Pathk s/o Rathneshwar Pathak as Bailing mazdoor at Screening list no. 342 as claimed.

Therefore, in view of this fact it may be seen that this case is quite a false case and it can be treated as imposter."

It will appear from the aforesaid document that in respect of Sl. No. 342 of incline No. 4|4A and Sl. No 432 of Incline No. 6/6A Dhannu Ganjhu son of Jitan Ganjhu has been mentioned. The concerned workman is on Sl. No. 342 of incline No. 4|4A and so he could not be Dhannu Ganjhu whose name was entered in the screening list. So apart from the question as to whether he is Dhannu Pathak or Maheshwar Pathak, he could not be Dhannu Ganjhu. The learned Advocate appearing on behalf of the concerned workman has argued that due to certain lacuna in the written statement of the concerned workman he was debarred from leading evidence on the point as to whether the mention of Dhannu Ganjhu son of Jitan Ganjhu against Sl. No. 342 of 4/4A incline was a mistake. What he meant to say was that if he was allowed to lead evidence on that point could have transpired that it was a mistake because the concerned workman was working in the colliery at the time of take over and continued to work against his Sl. No. 342 of 4|4A incline. He has further said that the consolidated screening list was not produced by the management which could have shown the name and father's name of Dhannu Pathak. Furthermore, he has said that the management should have produced the Form B register which could have conclusively proved the correct identity of the concerned workman. He has further argued that the concerned wokman has regularly worked and attained the status of a permanent wokman and so he could not be asked to stop work summarily as has been done in his case.

10. Now it could be easily ascertained from the documentary as well as oral evidence that the concerned workman is not Dhannu Ganjhu and he is also not an Adavasi as shown from the two screening list produced by the management. But Dhannu Ganjhu has gave evidence as MW-5. He has said that he was working in 4|4A incline and he worked for a few days in 6|6A incline. In 4|4A incline he was under Shri Jaiswal, contractor and in 6|6A incline he was working under a contractor of Chapra. In his cross-examination he has said that he all along worked in 4|4A incline and worked only for 2 days in 6|6A incline. The papers of the management would go to show that this Dhannu Ganjhu all along worked in 6/6A incline and he worked only for a few days in 4|4A incline. In fact according to the management the concerned workman Dhannu Pathak got into 4|4A incline because Dhannu Ganjhu was not actually working there. MW.5 Dhannu Ganjhu has therefore made a great confusion in the stand taken by the management. Consequently it has been argued on behalf of the concerned workman that Dhannu Ganjhu MW-5 could not have made the above statement if he was working at any time after the take over in 4|4A incline. The management's own case is that Dhannu Ganjhu had all along been working in 6/6A incline. The substance of his argument is that it was not Dhannu Ganjhu who was working in 4|4A incline but it was the concerned workman who was working there and due to mistake his name was shown as Dhannu Ganjhu. In this connection I have only to say that in a case like this where screening had taken place as far back as in 1973 when proper records were not maintained by the private collieries or their contractors a mistake of this type cannot be ruled out. It is apparent that from 5-1-74 the concerned workman has been shown to have worked in the colliery all along and continuously till certain allegations were made with regard to his being an imposter and was consequently forced to stop work. The learned Advocate for the management has argued that under the scheme of nationalisation the management was bound to give jobs to genuine persons already working in the colliery and not to an outsider and imposter. What he means to say is that an imposter or inductee could be summarily ousted at any time irrespective of the number of years put in by such workers because they had no right of entry. In this connection I have to say that the screening list is the only paper produced by the management to show that the concerned workman could not be Dhannu Ganjhu and therefore he is an imposter. While apparently a conclusion of this nature could be drawn out keeping in view of the fact that the concerned workman could not be Dhannu Ganjhu we cannot rule out the possibility of a genuine mistake being made in the screening list which was compiled at the time of screening. There is no explanation forthcoming for this important fact that from 5-1-74 the concerned workman has been working, and he has been shown to be Dhannu Pathak, Now not only he has gone on working but was selected for training wherein he was shown to be Dhannu Pathak son of Ratneshwar Pathak. Even the Gram Panchayat certificate has admittedly given his name to be Dhannu Pathak and there is the subsequent statement of the Gram Panchayat that the concerned workman is Maheshwar Pathak. But we have no reason to put reliance on such contradictory papers and statements for the simple reason that before the enquiry was instituted the concerned workman was working in this colliery as Dhannu Pathak. It is therefore difficult for me to hold on the basis of the screening list alone that the concerned workman is an imposter or inductee.

11. But apart from whatever I have said above it is noteworthy that the concerned workman has been shown to have worked from 5-1-74 continuously. There is no denying the fact that by virtue of serving for a number of years till 1976 he has earned the right to work permanently. It is an accepted position that if a workman has worked for 240 days in a calendar year he is entitled to be made permanent. This is a plea taken by him in the written statement which has not been challenged. Now this being the position the concerned workman could not be thrown out of employment summarily and he could be removed from service after a full-fledged domestic enquiry and by an order of dismissal.

12. Thus considering all aspects of the case, I hold that the action of the management of Topa colliery of Central Coalfields Limited, Post office Kuju, District Hazaribagh in stopping Shri Dhannu, son of Shri Ratheshwar Pathak, Fitter Helper from work with effect from 5th October, 1976 is not justified. Consequently, he should be deemed to have been reinstated with effect from 5th October, 1976 with full back wages and other emoluments.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012/183/77-D.III(A)]

New Delhi, the 8th September, 1980

S.O. 2478.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (1 4of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relaion to the management of

Jagdish Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundon, District Dhanbad and their orkmen, hich as received by the Central Government on the 25th August, 1980.

BEFORE SHRI P. RAMAKRISHNA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 5 of 1979

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jigidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Tundoo, Dist. Dhanbad.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workman—Shri J. D. Lal, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

INDUSTRY : Coal STATE : Bihar.

Dhanbad, the 18th August, 1980

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them u/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their Order No. L-20012/48/79-D.III(A), dated the 22nd September, 1979.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jogidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Tundoo, Dist. Dhanbad in dismissing Sri Mahabir Das, Miner from service is justified ? If not, to what relief is the workmen entitled ?

2. On behalf of the workman the Bihar Colliery Kamgar Union has filed a statement of claim stating that the concerned workman had put in 10 to 15 years of continuous blemishless service in Jogidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. The management issued the chargesheet dated 13th/20th June, 1974 alleging that he had on 12-6-74 instigated his co-workers not to perform their duties and that he had also threatened his superior officers. It is submitted that the accusation is false. The management ordered a departmental enquiry against the workman and as per the findings submitted by the Enquiry Officer he was dismissed from service with effect from 26-6-74. It is complained that the departmental enquiry was not fairly conducted and that the workman was not given sufficient opportunity to defend his case. It is also said that the findings of the Enquiry Officer are perverse and not based on any evidence. The Union takes the plea that the order of dismissal was not passed by the competent authority. The union prays that the workman may be ordered to be reinstated with full back wages.

3. The management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., filed their written statement stating that the workman herein along with certain others assaulted Mr. Mangleshwar Singh, First Class Asstt. Manager and Sri Gopalji Sahay, Overman at about 8.45 a.m. on 13-6-74 near the North Sinidih colliery office for which offence they were duly chargesheeted and tried departmentally. They say that the departmental enquiry was conducted fairly and in strict compliance with the principles of natural justice. They also say that the findings of the Enquiry Officer are based on proper evidence and that the punishment imposed is warranted by the gravity of the offence. They say that the order of dismissal is validly passed.

4. The management field a rejoinder denying the averments made in the workman's statement of claim.

5. On the above pleadings the issues that arise for consideration are —

(1) Whether the departmental enquiry is proper and consistent with the principles of natural justice ?

(2) Whether the findings recorded by the Enquiry Officer are based on proper evidence ?

(3) Whether the workman is entitled to reinstatement with full back wages ?

(4) To what relief ?

6. Issue (1).—By the order dated 15-5-80 this Court held this issue against the workman.

7. Issue (2).—The case against the workman is that on 13-6-74 at about 8.45 a.m. he and two others severely beat the First Class Asstt. Manager, Sri Mangleshwar Singh and the Overman, Sri Gopalji Sahay near the Sinidih Colliery office. It is also alleged that the workman and the two others threatened to kill the Asstt. Manager and the Overman if they tried to report the incident to the higher authorities. A chargesheet was served on the workman and the two others on 20-6-74. On the same day the three charge-sheeted employees submitted their explanation taking the plea that at the time of the alleged incident they were working inside the mine. An enquiry was held on 21-6-74 at which the injured officers, the Asstt. Manager and the Overman were examined. The chargesheeted employees declined to cross-examine them. The victims of the assualt spoke to the workman herein and two others beating them with lathis. The Overman also stated that when he went to the rescue of the Asstt. Manager he was severely beaten. The eye-witness Sri A. K. Chatterjee Overman corroborated the evidence of the victims. He identified the workman and the two other charge-sheeted employees as the assailents of the two injured persons. This witness also was not cross-examined by the Charge-sheeted employees. The other eye witness Sri A. B. Singh, Attendance Clerk also corroborated the evidence of the aforesaid witness. In his cross-examination nothing of importance has been elicited. The charge-sheeted employees set up a plea of alibi viz. that they were working underground at the time of the incident. The attendance register for the relevant date was not produced before the Enquiry Officer to show that this plea of alibi was false. But the Enquiry Officer during the course of his report Ext. M-6 dated 22-6-74 says that on examining the attendance register for the date 13-6-74 he was satisfied that the three charge-sheeted employees including the concerned workman went underground at 9 a.m. and not at 8 a.m. as pleaded by them. After considering the other evidence recorded by him he submitted a finding of guilty.

8. Sri J. D. Lal for the workman submitted that the evidence placed on the record is not sufficient to sustain a finding of guilty. He refers to the evidence of the victims of assault viz. the Asstt. Manager and the Overman. They say they were beaten with lathis. The Overman says he was severely injured on his head. The Asstt. Manager stated that his left hand, knee and back were injured. Both Mr. Sahay, the Overman and Mr. Singh, the Asstt. Manager were sent to the hospital for treatment. Sri Singh was discharged from the hospital after giving him first-aid and Sri Sahay was treated as an in-patient. Sri Sahay stated he went to the colliery dispensary and from there he was removed to the Regional Hospital, Katras. Till the date of his deposition in this enquiry (21-6-74) he was under treatment. It is argued by Sri J. D. Lal that unless the evidence of the victims of the assault is corroborated by wound certificates issued by the colliery hospital, the same cannot be believed. I do not agree. These witnesses were not even cross-examined by the charge-sheeted employees. It was not even suggested to them that they received no injuries on 13-6-74. The plea that on account of his illiteracy the concerned workman could not cross-examine the injured persons cannot be accepted. Sri Lal further submits that the Enquiry Officer consulted the attendance register behind the back of the charge-sheeted employees to find out if their plea of alibi was correct. In the course of his report he stated that a perusal of the attendance register showed that the workman went underground at 9 a.m. and not at 8 a.m. Sri Lal requested the Court to send for that attendance register to see if the statement made by the Enquiry Officer was correct. Though ample opportunity was given to the management to produce the attendance register for the relevant date, they failed to do so. It is argued that the management is deliberately suppressing the attendance register which was available at the time of enquiry. Sri Joshi for the management submit that the workman having kept quiet for a long time after the date of his

dismissal, has suddenly raised this dispute in the year 1978 or 1979 and that the management could not be expected to preserve their old records for more than three years. Still, I feel that the Enquiry Officer when he though it fit to refer to the attendance register to decide the truth or otherwise of the plea of alibi, he should have made that register a part of the enquiry file. In my view this is a great drawback in the case of the management.

9. Sri J. D. Lal also submits that Enquiry Officer failed to comply with the provisions of Section 17(4) of the Model Standing Orders for Coal Mining Industry which lays down that in awarding punishment under this Standing order the authority awarding punishment should take into account the gravity of the misconduct with previous record if any of the workman and any other extenuating or aggravating circumstances that may exist. In this case the order of dismissal Ext. M-4 does not comply with the above provisions of the Standing Order 17(4). The past record of service of the workman has not been considered at all. Reliance is placed on the decision of the Madras High Court reported in 1974 Lab. I. C. page 1496 for the proposition that where the competent authority does not consider the gravity of the misconduct and the record of the workman or any other extenuating or aggravating circumstances as required by the Standing Order, the Labour Court is justified in interfering with the punishment and directing reinstatement of the workmen. The above observations of the Madras High Court turned on the peculiar facts of that case. If the offience of assault on the Asstt. Manager and the Overman is made out it cannot be said that the punishment of dismissal imposed on the workman is liable to be interfered with just because the previous record of service of his is not considered. It is further argued that u/s 14(1) of the Coal Mines Nationalisation Act, 1973, it is either the Government Company or the Central Government that is competent to order dismissal of an employee. In this case the Manager of the colliery imposed the punishment of dismissal. It is argued that unless the order delegating the power of dismissal to this Manager is filed, his competence to pass such an order cannot be presumed. The management has filed an Office Order dated 20-12-76 showing delegation of such powers, Sri J. D. Lal does not dispute that the Office Order authorises the Colliery Manager to dismiss the workman. But he contends that the delegation of powers order now filed before Court is of the year 1976, whereas the order of dismissal is dated 26-6-74. He submits that unless the delegation of powers order obtaining in 1974 is filed, the validity of the order of dismissal in question cannot be properly determined. Sri Joshi for the Management merely stated that such powers were there even in 1974.

10. So the question is whether the evidence placed on the record is sufficient to sustain a finding of guilty. It is strongly pressed that in the absence of the wound certificates and the attendance register for 13-6-74, the guilt of the workman cannot be said to have been established beyond all reasonable doubts. In a departmental enquiry, the preponderance of evidence has to be considered and not whether the guilt of the accused has been established beyond all reasonable doubt. True the victims of the assualt and one of the eye-witness have not been cross-examined. It may also be noted that when this plea of alibi was taken at the earliest point of time, i.e., on the very date the chargesheet was served on the workman, the management should have made the attendance register available to the workman to prove his case. The Enquiry Officer should not have made use of a document (viz. Attendance Register) to decide the plea of alibi against the workman when it did not form part of the evidence adduced before him by the parties. On this score alone the finding of guilty recorded by the Enquiry Officer is liable to be set aside. Issue (2) held in favour of the workman.

11. Issue (3)—In the light of the finding on Issue (2) the concerned workman is entitled to reinstatement. The question is whether on the facts and in the circumstances of the case he should be given back wages from the date of dismissal in June, 1974 till the date of reinstatement. The order of dismissal was passed in June, 1974 and this dispute was raised in 1978 or 1979. There is no explanation forthcoming for this inordinate delay. The workman is charged with a very serious offence of assaulting his superiors. On account of some procedural regularity committed by the Enquiry Officer (in not placing the Attendance Register on the record) the workman is being given the benefit of doubt despite the unchallenged evidence of the 2 victims of the assault and an eye-witness. It is but proper that the claim for back wages should be rejected in toto. But the reinstatement will be with continuity of service. Issue (3) found accordingly.

12. Issue (4).—In the result it is held the Management of Jogidih Colliery is not justified in dismissing the workman concerned and that the workman is held entitled to reinstatement in service with continuity of service, but without back wages.

[No. L-20012/48/79-D.III(A)]

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

S.O. 2479.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Area No. VII of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th August, 1980.

BEFORE SHRI J. P. SINGH, PRESIDNG OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 107 of 1979

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Area No. VII of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Post Office Kusunda, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri J. D. Lal, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, 25th August, 1980

AWARD

This is a reference under Sec. 10 of the I.D. Act, 1947, The Central Government by its notification No. L-20012/66/79-D.III(A), dated 21st August, 1979 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Area No. VII of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad that Shri B. D. Saha should be placed in Technical Grade-B in the pay scale of Rs. 510-27-726-32-854 with effect from the 1st January, 1978 is justified ? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The concerned workman Shri B. D. Saha happens to be a qualified draftsman (Civil) since 1974 and has worked in different collieries and offices of Messrs Bharat Coking Coal Ltd. He is at present working in the office of the General Manager, Area No. VII, Post Office : Kusunda, District Dhanbad. He received diploma in Draftsmanship (Civil) from a recognised Institution. The Bharat Coking Coal Ltd. since 1973 upgraded the post of draftsman of all categories to that of technical Grade B of the Coal Wage Board recommendation. All qualified draftsmen who were in category VI were since upgraded to technical grade 'B' and similarly all new recruits of draftsmen have been placed in technical grade 'B' instead of category VI. The grievance of Shri B. D. Saha is that although he is qualified he has not been placed in technical grade 'B' inspite of representations filed by him. According to him the qualified draftsmen who newly entered the service were placed in technical grade 'B' while he has continued in category VI with no prospects whatsoever.

3. The union of the concerned workman made a representation dated 17-8-78 to the management demanding that Shri Saha should be placed in technical grade 'B' since he had been working as draftsman; but the management did not accede, to the demand of the union nor gave a reply to the union's representation. The union, therefore, raised an industrial dispute and on failure of conciliation the present reference was made.

4. The stand taken by the management in their written statement is that a cadre scheme has been drawn up under which the concerned workman has to work for 3 years in Technical Grade 'C' before he could be considered for promotion for technical grade 'B'. The other facts as given in the written statement of the concerned workman have been admitted by the management.

5. In the rejoinder the concerned workman took the stand that qualified draftsmen already working as employees could not be required to start their carrier from the bottom of the cadre scheme, but have to be fitted in the proper grade according to their qualification and experience.

6. The management has filed Ext. M-1 which is a cadre scheme evolved by the management in respect of appointment and promotion. On behalf of the workmen, Shri B. D. Saha examined himself as WW. 1. He has said that he has been working as draftsman (civil) since August, 1974. He started working as draftsman in Gadhur colliery and at present he is draftsman in Area No. VII. He passed Diploma Course in Civil Draftsmanship in B. B. C. Institute, Burdwan. He has produced his certificate Ext. W. 1. He had passed the draftsmanship examination in 1967. He was placed in category VI of the Wage Board recommendation when he was appointed as draftsman in 1974. His evidence is that other draftsmen in Bharat Coking Coal Ltd. were placed in technical grade 'B'. He has proved Ext. W. 2 which is a letter concerning Shri B. P. Sinha, draftsman who was placed in technical grade 'B' in the scale of Rs. 510—854. He has also deposed that one Shri Lakshman Prasad Singh who was working with him as draftsman has been regularised in technical grade 'B'. The letter concerning Shri Lakshman Prasad Singh has been marked Ext. W. 3. Similarly one Shri R. P. Parihar a draftsman was also allowed technical grade 'B' in 1973. He has proved Ext. W. 4 which is another appointment letter in respect of Shri Santi Bikash Pan who was appointed as draftsman (civil) in technical grade B. He has also proved one cyclostyled copy of order with the list of all draftsmen (mechanical, civil and electrical) which has been marked Ext. W. 5. He has proved Ext. W. 6 and W. 7 which are his representations to be placed in technical grade 'B' in the same manner as persons mentioned in Ext. W. 5. His case is that from January, 1978 he should be placed in technical grade 'B' with three increments.

7. I may, mention that the documentary evidence produced on behalf of the concerned workman has not been challenged by the management. In course of argument Shri T. P. Choudhury has virtually accepted that the concerned workman should be placed in technical grade 'B' like all others; but it has to be in due course. He could not explain to me as to what would be the due course to be followed in the case of the concerned workman. The written statement of the management shows that below the post of draftsmen there are various inferior posts. It does not stand to reason that the concerned workman should have to serve for a period of 3 years in technical grade 'C' before being placed in technical grade 'B'. Already the concerned workman by virtue of his being in category VI is drawing more pay than the starting scale of technical grade 'B'. So there is no question of his being placed in technical grade 'C' before being placed in technical grade 'B'. Shri T. P. Choudhury has conceeded this fact also. Moreover, none of the draftsmen mentioned in Ext. W. 5 were asked to serve in technical grade 'C' because they were straightway placed in technical grade 'B'. I see no reason why an exception should be made of this workman by the management in requiring him to be placed in technical grade 'C', before being placed in technical grade 'B'. Moreover, the management appears to have brought out a list of draftsmen due to be placed in technical grade 'B' which is a part of the cadre scheme, Ext. M-1. In this list the name of the concerned workman does not appear. Shri T. P. Choudhury was unable to explain the absence of his name and so it is clear that the management has not shown any intention to place him in technical Grade 'B'.

8. It is true that according to the Wage Board recommendation the concerned workman should be in category VI, and he is in that category. But the management has evolved a cadre scheme under which draftsmen have received better pay and have better prospects. According to that scheme a large number of draftsmen have been fitted into the scale and allowed technical Grade 'B'. The concerned workman has been working as draftsman in category VI since 1974 and he should have been normally fitted into the cadre scheme and placed in technical Grade 'B' from 1st January, 1978. This was denied to him inspite of representations filed by him as also by his union. Even during the conciliation proceeding the management took an adament attitude by refusing to place him in technical Grade 'B' for no apparent reason. It was not a question of promotion but a simple fitment into a corresponding scale. The evidence of the concerned workman is that he should be allowed three increments. Shri T. P. Choudhury, Advocate has nothing to say about this for the obvious reason that other draftsmen in their fitment in the technical Grade 'B' were allowed three increments.

9. Thus having discussed all aspects of this case. I have to hold that the demand of the workmen of Area No. VII of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad that Shri B. D. Saha should be placed in Technical Grade-B in the pay scale of Rs. 510-27-726-32-854 with effect from the 1st January, 1978 is justified. Consequently, the pay of Shri Saha from 1st January, 1978 will be fixed in the aforesaid scale after allowing him three increments. He will be further entitled to all back wages and other emoluments admissible to him.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012/66/79-D.III(A)]
S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 8th September, 1980

S.O. 2480.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bajrang Quartz Mine, Beawar, District Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd August, 1980.

BEFORE SHRI M. D. CHOUDHURY, PRESIDING OFFICER CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-1/1977

REFERENCE :

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi order No. L-29011/26/77-D.III.B dated 18-10-77.

In the matter of an industrial dispute

BETWEEEN

the management of Bajrang Quartz Mine, Beawar

AND

Their workmen represented by General Secretary, Khan Mazdoor Union, TLU Building, Beawar.

APPEARANCES

For the union.—Shri J. L. Shah

For the management.—Shri Manoj Sharma

Date of Award 22-7-1980

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute existed in between the management of Bajrang Quartz Mines, Beawar and their workmen (represented by the Khan Mazdoor Union, Beawar) in respect of the matters of payment of bonus, grant of festival holidays and casual leave with wages and reinstatement of 10 workmen named in the reference for adiudication to this Tribunal by its order referred above :

"1. Whether the demand of the union for payment of bonus for the year 1974, 1975 and 1976 is justified ? If so, what should be the rate of bonus ?

2. Whether the demand of the union for grant of festival holidays and Casual leave with wages to the employees is justified ? If so, what should be the number of Festival Holidays and Casual Leave.

3. Whether the demand of the union for re-instatement of S/Shri Moti Singh, Girdharisingh, Seshasingh, Kabirsingh, Doodsingh, Anupsingh, Kishansingh, Magsingh, Smt. Chunni W/o Moti Singh and Smt. Pepi with effect from 9-3-77 with back wages is justified ? If so, what should be the relief.

First dispute

The first dispute relates to the payment of bonus for the year 1974, 1975 and 1976. In respect of the first dispute the claim of the union is that the opposite party has been engaging 30 to 40 workmen regularly in its mine. It is excavating quartz from mines which is used in potteries and it is sold at high rates. The opposite party had earned good profits. It had not paid any bonus to its workmen in the year 1974, 1975 and 1976, so, a bonus @ 20 per cent of wages in each year should be awarded to the workmen.

This claim in respect of bonus has been opposed by the opposite party with the contention that the opposite party had not employed 20 or more workmen in its concern as such the provisions of the Payment of Bonus Act 1965 are not applicable. Besides the opposite party concern had not earned may profit in these years. It is owned by Shri Satya Narian Mathur in whose favour the lease of the mine was transferred by the Government with effect from 21-12-76, as such the opposite party is not liable to pay any bonus to the workmen for these years.

Shri Kalyansingh, Motisingh and Kabirsingh were examined on behalf of the union. Shri Satya Narian Mathur as examined in rebuttal. The union had also produced 7 documents. The opposite party did not prefer to produce any record and accounts of the cencern.

In the matter of bonus dispute the following are the main points for decision in the case :

(1) whether the opposite party concern had not employed 20 or more persons in the concern as such provisions of Payment of Bonus Act are not applicable to it ?

(2) whether the opposite party got the lease of mine in December 1976 and therefore he is not liable for the bonus of the year 1974, 1975 and 1976 ?

(3) whether the opposite party is liable to pay any bonus to its workmen, if so, at what rates ?

It is not disputed by the opposite party that the provisions of Bonus Act, 1965 are applicable to a concern if it employee 20 or more persons in the year. The case of the union is that the opposite party had employed 30 to 40 workmen in its mines. Shri Satya Narian proprietor of the mine had averred in the claim and also in his statement that 20 persons or more were never employed in the Bajrang Quartz mine. In the lease deed given in favour of the opposite party it has been provided that the transferee would observe and perform all the provisions and conditions of all convenant and stipulation contained in the lease. The opposite party had not preferred to submit the original lease granted in favour of lessee Shri Suganchand Mathur father of Satya Narian Mathur the present proprietor of the Bajrang Quartz Mines. In Rule No. 17 of the Rajasthan Minerals and Mines Concessions Rules 1959 in accordance which the lease is granted, it has been provided that the lessee shall keep correct and regular accounts of all minerals excavated from the mines and the quantity lying in deposit at the mines and the quantity dispatched therefrom and as also the number of persons employed thereat in the form given in schedule V. In the Mines Act 1952 there exists a similar provision in section 48 of the said Act that the mine owner shall keep the registers in prescribed form containing the detailed information of the persons employed in the mines. The opposite party must have kept the aforesaid record for the working of his mine, but he did not prefer to produce the same to prove his contention that he had not employed 20 or more persons in his mine. In absence of the above record the oral testimony of Shri S. N. Mathur cannot be relied to prove the abovesaid contention as his oral testimony is not sufficient to rebut the evidence given by the union. Shri Kalyansingh General Secretary of the union has stated that 30 to 40 persons were employed regularly in the above said years in the mine. Shri Motisingh who had worked there had also stated that in the mine 40 persons were employed where he was working. The above said contention was also not taken by the opposite party in the reply dated 19-5-77 Ex. W-4 given in reply to the demand charter of the union. It also shows that the contention of non-applicability of Bonus Act is an after thought. Besides in the first settlement Ex. W-1 dated 17-2-76 entered by Shri Suganchand Mathur previous occupier of mine and the union, it was narrated that on account of partial lock-out declared by Bajrang Quartz Mines 30 workmen were rendered idle. In another setdement Ex. W-3 dated 3-4-77 it has been narrated in clause No. 6 that 14 workmen would be taken on duty from 4th and 3 workmen would be taken on duty with effect from 6th April, 1977. From these settlement it is apparent that more than 20 workmen were working in the mines as such they support the version of the union and therefore oral testimony of Shri Satya Narian Mathur cannot be taken sufficient to rebut the evidence of the union. Hence it is held that more than 20 persons were employed in the opposite party concern in these years and therefore the provisions of Payment of Bonus Act are applicable to it.

Shri Satya Narain Mathur, the proprietor of the mine is the transferee of the lease of the mine with effect from 21-12-76 in respect of the mine leased to his father with effect from 26-12-63. It has been admitted by Shri Satya Narian Mathur that he is not the original lessee of the mine. As partners of transfer need he is laible for condition and convenant contained in the lease. In the statement Ex. W-7 given before the Payment of Wages Authority in case No. 58/77 he has admitted that he did not apply for lease to the Government. The lease was in favour of his father Shri Suganchand Mathur, Shri Suganchand Mathur father of Shri S. N. Mathur has also narrated in his statement Ex. W-6 given before the Payment of Wages Authority, Ajmer in the above case that he got the lease of mine transferred in favour of his son because of his old age. He did not charge any amount from his son for the transfer of the mine to him. From the above statements it is apparent that Shri S. N. Mathur is merely a transferee of lease of mine granted to his father. Under Section 25 FF of the Industrial Disputes Act the transferee of the undertaking is liable for the compensation of the workmen which they are entitled to get from the previous owner. In that case the employer of a concern even if he is transferee of the concern is liable to the payment of bonus to the workmen if it is payable. This view find support also from the case Artisian Press Ltd. Vs. Labour Appellate Tribunal of India 1954-II-LLJ-424 and the Bombay Garrage Ltd. Vs. Industrial Tribunal Bombay 1953-I-LLJ-page 14. In view of above it is held that the opposite party is liable for payment of bonus for the above said years if it is payable even though he is a transferee of the lease of mine with effect from 21-12-76.

The opposite party was required under the provisions of Mines Act to keep record of the produce of the mine worked by him. In other words he is required to maintain accounts of the mines worked by him. He did not prefer to produce the accounts. In that case it is not possible to work out the gross profit, allocable surplus and available surplus as per provisions of Payment of Bonus Act, but still the opposite party is liable to pay the minimum bonus to its workmen for the year 1974 and 1976 as the bonus is payable in these years even if the employer did not earn profit. In the year 1974 the minimum bonus was payable at the rate of 4% of the weges and in the year 1976 it was payable @ 8.33% of the wages. In the year 1975 the bonus was payable if the employer had allocable surplus. The above legal position has not been disputed by any of the parties. Hence it is held that the workmen of the opposite party concern are entitled to payment of minimum bonus for the year 1974 and 1976 as per provisions of Payment of Bonus Act.

Second dispute

The second dispute is relating to grant of Festival Holidays and casual leave with wages to the employees of the opposite party concern. The union had claimed that 10 festival holidays namely 26 January, Holi, Id, 15th August, Gandhi Jayanti, Deepwali, Dashera and 3 other festivals should be granted. It has also demanded 10 casual leave with wages. In reply to the claim it is admitted by the opposite party that 6 Festival Holidays for 26th January, 15th August, Holi, Deepwali,

Deshera and Id are being given to the workmen and any more such holiday cannot be given. The workmen are also not entitled to casual leave with wages as they are given weekly holidays and sickness leave.

In support of above demands the Secretary of the union had justified the demand on the contention that these festival holidays are given in every industrial undertaking throughout the State. Shri Satya Narian Mathur has stated that Festival holidays for Holi, Deepwali, 15th August and 26th January are being given to the employees working in his mine. In reply to the claim it has been admitted that 6 Festival holidays are being given to the workmen. Thus he had changed his version taken in the reply to the claim. In the circumstances it has to be relied that 6 festival holidays namely 26th January, 15th August, Holi, Deepwali, Deshera and Id are being given by the opposite party to its workmen. The union claimed 4 more festival holidays and it has been narated by Shri Kalyan Singh that Festival and National Holidays for 2nd October—Gandhi Jayanti is given to every workmen in each industrial undertaking. I do not find any reason why the holiday for 2nd October being Gandhi Jayanti should not be allowed as this holiday is given nearly in all the industrial undertaking in the memory of father of the nation. Therefore, it is deemed proper that 7 National and Festival holidays including holiday of Gandhi Jayanti should be allowed to the workmen of the opposite party concern.

The union had claimed 10 casual leave. Shri Satya Narian has also admitted in his cross-examination that 10 casual leave are being given to workmen who has worked the concern at least for one year. In view of above the workmen of the opposite party concern are held entitled 10 casual leave in a year with wages if such workmen had completed service of one year

Thus in respect of dispute No. 2 it is held that the workmen are entitled to 7 National and Festival Holidays of (1) 26th January, (2) 15th August, (3) Hoi, (4) Deepwali, (5) Deshera, (6) ID and (7) 2nd October, Gandhi Jayanti, and they are also held entitled to 10 casual leave in a year.

Third dispute

The 3rd demand relates to the reinstatement of 10 workmen namely, Sarvshri 1. Motisingh 2. Girdharisingh 3. Seshasingh 4. Kabirsingh 5. Doodsingh 6. Anupsingh 7. Kishansingh 8. Megsingh 9. Smt. Chunni W/o Motisingh and 10. Smt. Pepi with effect from 9-3-77 with back wages. It is narated in the claim in respect of this demand that the above said workmen were removed by the opposite party with effect from 9-3-77 by oral orders. They had not been paid retrenchment compensation and they had also not been served with notice or paid wages in lieu of notice. Therefore, they should be reinstated with full back wages. In reply to the claim it was averred by the opposite party that the opposite party had started the working of mine with effect from 25-12-76. These workmen were working as casual labourers and they had left the service after taking their wages, as such the union is not entitled to any relief in respect of this demand.

The union could not establish by its evidence that the workmen other than Motisingh and Kabirsingh had served the opposite party for more than one year as such they could not have been retrenched without payment of compensation and service of requisite notice under section 25(F) of the Industrial Disputes Act. Shri Kalyansingh Gen. Secretary of the union has admitted in his cross-examination that the service period of Doodsingh, Magsingh, Chunni and Pepi may be less than one year. He has further stated that he is also not definite about the service period of Anupsingh and Kishansingh, Girdharisingh and Seshasingh had service more than one year as per statement of Shri Kalyansingh, but his statement was not supported by examining Girdharisingh and Seshasingh. Therefore, it had to be taken that the union had failed to establish that the workmen named in the reference other than Motisingh and Kabirsingh had served in the opposite party mine for more than one year. In that case their retrenchment by the opposite party is to be considered valid.

Motisingh and Kabirsingh have been examined by the union. Motisingh has stated that he had served in the opposite party mine for 8 years continuously from 1967 before his removal. Shri Kabirsingh has stated that he had served the opposite party for 3 years from 1974 before his removal. Shri Kalyansingh has also corroborated the statements of these 2 witnesses. Shri Satya Narian had admitted that on the date of transfer of lease of mine in his favour these workmen were working in his concern. He has narrated that they were working as casual labourers, but he has not supported his version by any other reliable evidence. In the opposite party mines the record of the persons employed is expected to have been kept, as per provisions of the Mine Act 1962 and the terms and conditions provided in the lease. The evidence of the above nature has not been produced by the opposite party in the case. In that case I do not find any reason why the version of the union taken in the claim and supported by the evidence should not be relied. If the version of the union is taken reliable than these 2 workmen Motisingh and Kabirsingh could not have been retrenched without complying with the provisions of Section 25(F) of the I. D. Act. It is an admitted case of the opposite party that both the workmen were neither paid any compensation nor given any notice or paid wages in lieu of notice. In the circumstances the retrenchment of these 2 workmen is to be held invalid and therefore they are entitled to be reinstated with back wages. It is the contention of the opposite party that these workmen had served in the Golecha Mines, but it is not established by any evidence.

It has been further urged that as per settlement Ex. W-3 these workmen were to be kept in service with effect from 4-4-77 if they would have turned up to join the service. It is not established that they came on 4-4-77 as such the contention of the union that they should be reinstated on their jobs with effect from 9-3-77 should not be relied. The contention raise is not tenable as the case of the union is that these workmen were removed from service with effect from 9-3-77 by oral orders. If during the conciliation any interim settlement was reached and that was not acted upon by any of the parties to it, it does not disentitle the party to the relief established in the case. The retrenchment of both these workmen is held to be invalid. They were said to have been removed by oral orders on 9-3-77, in that case both these workmen are entitled to reinstatement on their jobs with back wages from 9-3-77.

Therefore an award is passed in the case as under :

(1) (i) that the demand of union for payment of bonus for the year 1974 and 1976 is justified, but its demand for the payment of bonus for the year 1975 is not justified;

(ii) that the workmen are entitled to the minimum bonus for the year 1974 and 1976 as per provisions of Payment of Bonus Act ;

(2) that the claim of the union for the grant of Festival and National Holidays and casual leave with wages to the employee is justified and the employees are entitled to the Festival and National Holiday for the days (i) 26th January, (ii) 15th August, (iii) Holi, (iv) Deepwali, (v) Dashera, (vi) Id and (vii) 2nd October, Gandhi Jayanti; and the workmen are held entitled to 10 casual leave with wages in a year after completion of service of one year ;

(3) That the demand of the union for the reinstatement of Motisingh and Kabirsingh with back wages from 9-3-77 is justified and it is directed that both these workmen should be reinstated with full back wages from 9-3-77. The demand of union in respect of reinstatement remaining 8 workmen namely, Girdharisingh, Seshasingh, Doodsingh, Anupsingh, Kishansingh, Magsingh, Smt. Chunni W/o Motisingh and Smt. Pepi is not justified and they are not entitled to any relief.

Let the award be submitted to the Central Government for publication under section 17(I) of the Industrial Disputes Act.

[No. L-29011/26/77-D.III(B)]

M. D. CHOUDHURY, Presiding Officer.

S.O. 2481.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Associated Stone Industries (Kotah) Limited, Ramganjmandi and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th August, 1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 54 of 1980

In re :

The President, Lime Stone Mazdoor Union,
Kumbhakot Mines, Ramganjmandi, Distt. Kota.
.....Petitioner

Versus

The Managing Director,
Associated Stone Industries (Kota)
Limited, Ramganjmandi-326519 (Kota).
....Respondent.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-29011/32/80-L.III.B dated the 19th June, 1980 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :

"Whether the action of the management of Associated Stone Industries (Kota) Limited Ramganjmandi in refusing to take back on duty Smt. Shanti Bhai female mazdoor is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and notices were issued to the parties for 5th of August, 1980. On 5th August, 1980 none of the parties appeared rather a registered letter was received from the Management and the union stating therein that the parties have settled their dispute vide settlement dated the 2nd August, 1980. Original settlement dated the 2nd August, 1980 has also been forwarded to this court. I have perused the original letter together with the original settlement both of which purport to have been signed by the Chairman and the Managing Director of the employer and the President of the workmen's union. From the perusal of the said settlement I find that as a result of deliberations between the parties the workman Shanti Bhai has been taken back on duty w.e.f. 2nd August, 1980 with continuity of service for the purposes of deduction of provident fund apart from payment of Rs. 300 as ex-gratia payment to her by the Management

3. In view of the settlement the dispute stands resolved between the parties amicably and as such a no dispute award is given in this matter leaving the parties to bear their own costs.

Further Ordered :

Requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

Dated : the 5th August, 1980.

[No. L-29011/31/80-D.III(B)]

S.O. 2482.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government industrial Tribunal-cum Labour Court No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. M. B. Mineral Industries, P.O. Mohammad Bazar, District Birbhum and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd August, 1980.

BEFORE MR. JUSTICE B. K. RAY, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 33 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to Messrs M. B. Mineral Industries, Post Office Mohammad Bazar, District Birbhum.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Sri M. D. Jajodia, Advocate, with Sri K. S. Majumdar, Manager.

For the Workmen—Shri R. Das Gupta, representative of the workman concerned.

STATE : West Bengal INDUSTRY : China Clay.

Dhanbad, dated, the 18th August, 1980

AWARD

By Order No. L-26012/11/74-I.RIV-D.03(B) dated, the 22nd February, 1975, the Central Government being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Messrs M. B. Mineral Industries, Post Office Mohammad Bazar, District Birbhum and their workmen in respect of the matter specified in the schedule attached to the order, have referred the dispute for adjudication to this Tribunal. The schedule to the order reads thus :

"Whether the dismissal of Shri Gadadhar Guin by Messrs M. B. Mineral Industries, owners of China Mine and Washery, Post Office Mohammad Bazar, District Birbhum, West Bengal, is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. After receipt of the reference parties were noticed to file their respective written statements. Accordingly they have filed their written statements as well as rejoinders. When the case was taken up for hearing on 12-8-1980 a joint petition is filed by the parties saying that the dispute between them has been settled as indicated in the petition. A prayer has been made in the petition to dispose of the reference in terms of the settlement. The settlement has been signed by Sri K. S. Majumdar, Manager, on behalf of the management and by the workman concerned Sri Gadadhar Guin. The same is also signed by witnesses, namely, Sri M. D. Jajodia, Advocate, for the management and Sri R. Das Gupta, representative of the workman. The terms of the settlement as has been held by me in my order dated 12-8-80 are fair and proper. In pursuance to the terms of settlement a sum of Rs. 5000 has also been paid by the management to the concerned workman before the Tribunal on 12-8-80. Six copies of the settlement have also been filed as required. In pursuance to the prayer made in the joint petition the following award is passed.

3. Messrs M. B. Mineral Industries shall pay a lump sum amount of Rs. 5,000 to Shri Gadadhar Guin in full and final settlement of all his upto date claims and dues financial or otherwise including claims if any for his reinstatement or re-employment by Messrs. M. B. Mineral Industries and such payment shall be made before the Tribunal. Shri Gadadhar Guin accepts as well as confirms that he having settled all his upto date claims and dues including claims for his reinstatement of re-employment by Messrs M. B. Mineral Industries on payment of the said lump sum amount of Rs. 5,000 by Messrs M. B. Mineral Industries which amount includes substantial ex-gratia amount, bonus payable to the concerned workman for the accounting years ended on 30-6-73 and 30-6-74, he will not make in future either individually or collectively through any trade union any claim whatsoever financial or otherwise for his reinstatement or re-employment by Messrs M. B. Mineral Industries. There will be no order for costs. Copy of the settlement do form part of the award.

B. K. RAY, Presiding Officer.

[No. L-26012/11/74-LR.IV/D.III(B)]

A. K. ROY, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the Matter of Reference No. 20 of 1975, as per the Government Order No. 26012/11/74-L.R.I.V. D.03 (B) dated 22-2-1975.

AND

In the Matter of Reference No. 33 of 1977 in terms of the Government Order No. S-11025(1)/77(1) S.IV(B) dated 22-2-1977.

AND

In the Matter of The Management of Messrs. M. B. Mineral Industries having its factory at Mohammed Bazar, P.O. Mohammed Bazar, Dist. Birbhum, West Bengal.

AND

Shri Gadadhar Guin P.O. Mohammed Bazar, Dist. Birbhum, W.B.

The humble joint petition on behalf of Messrs. M. B. Mineral Industries and Shri Gadadhar Guin most respectfully.

Sheweth :—

1. Messrs M. B. Mineral Industries (hereinafter referred to as Company) without prejudice to the jurisdictional issues raised in its pleadings filed before this Hon'ble Tribunal in the present case due to the suggestions made by this Hon'ble Tribunal had protracted negotiations with Shri Gadadhar Guin for settlement outside the Court and on such mutual negotiations settled all upto date matters, claims and dues of Shri Gadadhar Guin and Shri Gadadhar Guin also agreed and confirmed such settlement arrived at between the parties whereby it is agreed between the parties as follows :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. Messrs M. B. Mineral Industries without prejudice to the jurisdictional issues raised in its pleadings, filed before this Hon'ble Central Government Industrial Tribunal agrees to make payment of the lump sum amount of Rs. 5,000 (Rupees Five Thousand only) to Shri Gadadhar Guin in full and final settlement of all his upto date claims and dues financial or otherwise including claims if any for his reinstatement or re-employment of Messrs M. B. Mineral Industries and such payment will be made before this Hon'ble Tribunal when appropriate Orders are made disposing of the present case recording the mutual terms of settlement arrived at between the parties as mentioned in the present joint petition. II. Shri Gadadhar Guin accepts as well as confirms that he having settled all his upto date claims and dues including claims, if any, for his reinstatement or re-employment by Messrs M. B. Mineral Industries on the payment of the said lump sum amount of Rs. 5,000 (Rupees Five Thousand only) by Messrs M. B. Mineral Industries which amount includes substantial ex-gratia amount, bonus payment to him for the accounting years ended on 30-6-73 and 30-6-74 and he would not make in future either individually or collectively through any trade union any claim whatsoever financial or otherwise for his reinstatement or re-employment by Messrs M. B. Mineral Industries. III. The parties agree to submit a joint petition of compromise before this Hon'ble Central Government Industrial Tribunal with the joint submission of disposing of the pending reference in view of the mutual settlement referred to above arrived at between the parties without prejudice to the jurisdictional issues raised by the company.

2. Your Petitioners in view of the mutual settlement arrived at between the parties outside the Court confirm that the present reference be disposed of by this Hon'ble Central Government Tribunal recording the terms of settlement mentioned in the present joint petition of compromise.

Your petitioners, therefore, humbly pray that the present reference be disposed of by this Hon'ble Central Government Industrial Tribunal recording the terms of settlement mentioned in the present joint petition of compromise as well as recording the payment of Rs. 5,000 (Rupees Five Thousand) made by Messrs M. B. Mineral Industries to Shri Gadadhar Guin before this Hon'ble Tribunal at the time of making the Order in the present joint petition as jointly prayed for by the parties.

And your petitioners as in duty bound shall ever pray.

Dated, the 12th August, 1980.

Witnesses :

Sd/- Illegible
Representing Workers
Sd/- Illegible—Advocate
12-8-80.

Part of the Award

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2483.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th August, 1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 177 of 1977

In re :

1. The General Secretary, Beas Sutlej Link Project, Sunder Nagar.
2. The President, Beas Sutlej Link Project Ekta Union, Sunder Nagar.
3. The Beas Sutlej Link Project Workers Union, Sunder Nagar.
4. The Beas Sutlej Link Workers' Union, Beas Sutlej Link Project, Sunder Nagar. ..Petitioner.

Versus

The Chief Engineer, Beas Sutlej Link Project, Sunder Nagar.

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute u/s. 36-A of the I.D. Act, 1947 vide its order No. L-42011/4/76/DII(B) dated the 23rd April, 1976 to Industrial Tribunal, Delhi in the following terms :

'Whether the directions given by the Industrial Tribunal, Chandigarh, in the award in reference No. 2-C of 1971 govern the case of the categories of employees discussed in the said award only, or the said award is in respect of all categories of employees on the Project wherever either of the principles enunciated in the award was lacking ?

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were sent to the parties. In pursuance whereof a statement of claim was filed on behalf of the workman side and thereafter a written statement was filed. After a replication had been filed following one issue was framed by Industrial Tribunal, Delhi vide his order dated 15th October, 1976 :

Issue :

As in the terms of reference.

3. Thereafter the case was adjourned for evidence. But before any evidence could be recorded this case was transferred to this Tribunal by the appropriate Government on receipt of the case by transfer it was ordered to be registered and notices were issued to the parties. After the parties had put in appearance the question whether any evidence should be recorded or not was re-considered and vide my order dated the 7th April, 1978 following order was passed :

'It is urged on behalf of the BSL that the Project should be afforded an opportunity to lead evidence on the issue under reference. As against this the union representatives submit that they do not propose to lead any evidence. Prima facie considering the terms of reference the question involves only interpretation of the award and apparently it should be without any extreme help and therefore I do not think any evidence is called for. What is needed

is the perusal of the statement of claim, the written statement, the issue if any framed as the original reference and finally the award itself. Accordingly after giving my considered thought to the matter raised on behalf of the Management I hold that no evidence need be recorded and it is ordered accordingly.'

4. The matter was reagitated by the Management which was disposed of vide my order dated 5-6-79 which reads as under :

'In this reference u/s. 36-A a question is raised by the Management that the question referred cannot be decided without evidence. The representatives of union contests the claim. I have heard them and have given my considered thought to the matter before me. I have summoned the original file of reference u/s. 10 which contains the entire evidence recorded there as also the award. In the face thereof amount of evidence can explain the order of reference u/s 10 of the evidence recorded therein of the award. The reference u/s. 36-A is also before me. The only question on which requires adjudication u/s 36A is that of interpretation and therefore no evidence is called for this purpose. In view thereof the requisite objection of the management is over ruled.'

5. I have heard parties representatives at length at the main reference and have also gone through the original file in which original reference u/s. 10 was disposed of as also the present file and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the following findings :

6. The facts giving rise to this reference are that the Central Government as appropriate Govt. had referred an Industrial Dispute u/s. 10 of the I.D. Act between the employers in relation to the Beas Sutlej Link Project and their workmen vide its order No. 4/86/70-LRII dated the 4th March, 1971 in the following terms :

1. Revision of pay scales of work charged employees.
2. Regularisation of the services of work-charged employees.
3. Accident and retrenchment compensation to wrokmen drawing over Rs. 500 per month.
4. Gratuity Scheme.

The said reference was disposed of by Shri H. R. Sodhi, Industrial Tribunal (Chandigarh) vide its award dated the 15th May, 1974 which was duly published by the appropriate Govt.

7. The precise question in this reference is as to whether the directions given by the Industrial Tribunal (Central), Chandigarh in the award in reference No. 2-C of 1971 govern the case of category of employees discussed in the said award only, order the said award in respect of categories of employees on the Project wherever either of the principle enunicated in the award was lacking. In order to determine this point reference would have to be made primarily to the original order of reference u/s 10 of the I.D. Act. I have re-produced above the said order of reference. From the perusal of first para of the order of reference dated the 4th March, 1971 it would be found that the dispute was 'between the employers in relation to the Beas Sutlej Link Project and their workmen'. Thus from para No. 1 of the reference it is clear that the reference was not limited to only a particular category of workmen except where it is so specifically mentioned as in item No. 1 and Item No. 2 of the schedule attached to the said order of reference. This is further clear when we consider the endorsement of the said order of reference at page 2 thereof. Copy of the said order of reference was sent apart from the Chief Engineer, BSL Project Sunder Nagar to (1) The General Secretary, Beas Sutlej Link Project, Sunder Nagar, (2) The President, Beas Sutlej Link Project Ekta Union, Sunder Nagar (3) The Beas Sutlej Link Project Workers Union, Sunder Nagar (4) The BSL Workers' Union, BSL Project, Sunder Nagar. The fact that the copy of order of reference was endorsed to these four trade unions goes to show that all the workmen which were covered by these unions were intended to be covered by the award arising out of the award in reference No. 2-C of 1971. It may be mentioned here that item No. 3 and 4 of the schedule to the said order of reference are unqualified so far as the trade categories of various workmen was concerned. Item No. 3 refers to the 'accidents and retrenchment compensation to workmen drawing over Rs. 500 per month' and item No. 4 refers to 'gratuity schemes'. These two items are not in any manner qualified to a particular trade. Of course item No. 1 and 2 are limited to the revision of pay scales and regularisation of services of work-charged employees but here reference to particular type of employees without reference to their trade and therefore it would follow that the reference u/s 10 of the I.D. Act which was registered as reference No. 2-C/71 covered all trades of workmen employed by BSL Project and was not limited to any particular trade only and this would imply that the award in the said reference would essentially govern the case of all trades and categories of employees and would not only be limited to the categories which have been specifically discussed in the said award. There is nothing in the award which excludes the applicability of the award to the categories of employees which have not been specifically discussed in the award and therefore the award would essentially cover all categories of employees whether discussed or not discussed in the award. The non-discussion of certain specific categories would only go to show that they have nothing specific or special in their nature so as to call for a special discussion. My attention has been drawn to page 24 of the original award and from the perusal thereof I find that it is mentioned therein that 'in such a situation, I direct that the anomalies be removed and grades of different categories revised where necessary bearing in mind the following principles.....' This would show that there was no reservation regarding the removal of anomalies to only particular categories of workmen. In an earlier part of the same page it is observed that 'the workmen' on the other hand strenuously urged that for every categorry of wrokmen Rs. 20 should be added.' This itself shows that the Tribunal at the time of making the award was considering each and every category of workmen and not only certain categories of worokmen'. My attention similarly has been drawn to page 9 and 11 of the award. From the perusal thereof also it cannot be said that the reference was limited to only a particular trade or category of workmen or work charged employees. At page 22 of the award also it would be found that the contention on behalf of BSL Karamchari Sangh was for revision of the entire wage structure irrespective of trade or category of workmen. The accumulative effect of a reading of the entire is that the award is intended to cover all categories of workmen whatever be the trade and is not limited to certain specific trades discussed in the said award.

8. The contention of the workmen that the benefit of the revised pay scales should be extended only to the 14 specified categories is not born out from the perusal of the award or even from the order of reference. The scope of award dated 15-5-74 has to be worked out in the light of the order of reference dated 4th March, 1971 and not on any hypothetical basis. It is also urged on behalf of the Management that the BSL Transport Workers' Union, The ITI Workers' Association, the BSL Water Transport Workers' Union and the BSL Heavy Earth Moving Mechinery Operator Union were not party to the original dispute but I do not think that non-impleading of these unions as parties to the original reference would exclude the categories of workmen alleged to be trades of these unions. It was always open to these unions together come forward and take part in the proceedings before the Industrial Tribunal in the original reference. The more important criteria for determining the scope of award is the order of reference rather than the fact of these unions being or not being parties to the reference. In view of my discussions above. I hold that the award dated 15th May, 1974 covers all categories of employees and is not-limited to only 14 categories whose mention has been specifically made in the said award and this reference is answered accordingly. In view of the peculiar circumstances of the case the parties are left to bear their own costs.

Further ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-42011(4)/76-D.II(B)]

S. S. BHALLA, Desk Officer.

Dated : the 26th July, 1980.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980